

भारत का संविधान

भ्यवस्थापक भारत सरकार मुद्रशालय नई दिस्ली द्वारा मुद्रित तथा व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग दिल्ली द्वारा प्रकाशित १९५०

Price Rs. 2 As. 8 or 4sh.

शुद्धि-पत्र

पृ० सं०	अनु च् छेद	पं वित	अशुद्ध	
	Preface	१७ और १८	Schedule. Eighth	Eighth Schedule.
१०	१ ९ (२)	२२	को दुर्बल अथवा	को दुर्बल करने अथवा
१८	<i>३१</i> (४)	१५	तो उस संवि- धान में	तो इस संविधान में
२४	80	१५	औषधियों	ओषधियों
४१	•	हाशिया की प्रथम पंक्त	प्रें	μ
४७	९७	११	उस लिये	उस के लिये
% ረ	९ ९	ц	उस लिये	उस के लिये
६६	१२३ (२) (क)	Ę	दूसरे मे	से दूसरे
७१	१ ३१ परंतुक (१)	१०	संविदा	प्रसं विदा
८३	१५२ के बाद का शीर्षक		का र्यपालका	कार्यपालिका
८५	१५९	१५	संविधा	संविधान
८९	१६८ (१)(क)	१४	संयुक्त प्रान्त	युक्त प्रदेश
९६	१८१ (१)	२३	से कोई हटाने का संकल्प	से हटाने का कोई संकल्प
९८	१८४	द्धाशिया की ११वीं पंक्ति		श वि त
१२०	२१७ (१)	१४	को छोड़ अन्य	को छोड़. कर अन्य

	पृ० सं०	अनुच्छेद अनुसूची	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
	१३२	२३८ (५)	ų	शब्दों के स्थान में	शब्दों के बाद में
	१५०	२६४ (ग)	१५	निदेश	निर्देश
	१६४	२८७ (ख)	१७	कस्पनी	समवाय
	१८८	३२२	१०	निवृत्ति-वेतन भी यथास्थिति	निवृत्ति-वेतन भी हैं यथास्थिति
	१८९	३२४	हाशिया की ४थी पंक्ति		नियंत्रण
	<i>२</i> १५	3 £ { (R)	¥	उस के लिये	उन के लिये
	२ १ ६	३६३ (२)(ख)	३	मुखिया •	प्रमुख
:	२२०	३६६ (१८)	१५	को	के
	२२०	३६६ (२०)	१९	"रेल ["] में—	"रेल्र" के अन्तर्गत नहीं है—
	२२०	३६६ (२०) (क)	२०		अन्त में ''अथवा'' शब्द चाहिये
	२५२	हितीय अनुसूची भाग (घ)	२२	के अन्तर्गतः -	के अन्तर्गत है :—
	२५९	पंचम अनुस् ची भाग (ख)	२०	अनुसूची	अनुसूचित
	२७१	६ष्ठ अनुमुची की कण्डिका ८ की उपकण्डि क (३) का पद (ग)		मा ल	वस्तुओं

भारतं का संविधान

प्राक्कथन

भारतीय संविधान-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मुझे यह अधिकार दिया था कि मैं, अध्यक्ष की हैसियत से, संविधान का हिन्दी अन्वाद, २६ जनवरी १९५० ई० तक, तथा उस के वाद यथाशी झ अन्य भाषाओं में भी इस के अनुवाद प्रकाशित करा दू। मुझे यह वांछनीय प्रतीत हुआ कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में मंदिधान के जो अनुवाद तैयार किये जायें उन सब में, अगर सम्भव हो तो, संविधान में प्रयुक्त अग्रेजी गब्दों के लिये, जिन का कि विशेष संविधातिक या कानुनी अर्थ है, एक ही पर्याय प्रयोग में लाये जायें । इस लिये मैं ने भाषा-दिशेयकों का एक सम्मेलन बुलाया कि वह, जहां तक सम्भव हो. ऐसे पारिभाषिक शब्द प्रस्तुत करे जो प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त होते हों और जिन को हम विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले संविधान के अनुवादों में प्रयुक्त कर सके और अन्ततोगत्वा जिन को हम अन्य सरकारी, कान्नी, अदालती और जासन सम्बन्धी कामों मे भी प्रयुक्त कर सकें। यह सम्मेलन मध्य प्रान्तीय विधान-सभा के अध्यक्ष श्री घनव्यामसिंह गृत के सभापितत्व में समदेत हुआ । इस में अनुसूची ८ मे दी हुई सभी भाषाओं के प्रस्यात विद्वान् प्रतिनिधि स्वरूप स्रिमलिन हुए । इस सम्मेलन ने संविधान मे प्रयुक्त पारिसादिक कटदों का एक कोष तैयार किया और अनुवाद-समिति ने, जिसे कि संविधाल के हिन्दी रूपान्तर का काम सौंपा गया था, हिन्दी अनुवाद तैयार करने में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है।

संविधान के इस अनुवाद में प्रयुवत कई शब्द, संभव है, कुछ लोगों को फिलहाल विल्कुल नये से प्रतीत हों। पर इस सम्बन्ध में यह दाद रखना चाहिये कि ये शब्द भारत की अधिकांश भाषाओं के प्रतिनिधियों को स्वीकार्य है और इस लिये देश के अधिकांश लोगों को या तो अभी या निकट भविष्य में अवश्य बोधगम्य हो जायेंगे। कुछ शब्द इस में ऐसे भी मिलेगे जिन का प्रयोग उस से कुछ भिन्न अर्थ में हुआ है जिस में कि आम तौर पर इन का प्रयोग हिन्दी में हुआ करता है। मसलन 'जामिन' शब्द इस में 'bail' के अर्थ में प्रयुवत किया गया है किन्तु हिन्दी में 'जामिन' से साधारणतः वह व्यक्ति समझा जाता है

जो किसी की जमानत के लिये खड़ा हो। किन्तु यहां इस शब्द को भिन्न अर्थ में रखना इस लिये जरूरी समझा गया कि अधिकांश भारतीय भाषाओं में 'जामिन' शब्द 'bail' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत अनुवाद में आने वाले नये शब्दों में से कुछ तो ऐसे हैं, जो भाषा-सम्मेलन के निर्णय के फल स्वरूप, जिस ने कि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के पर्याय निश्चित करने के लिये विभिन्न भाषाओं के शब्दों पर विचार किया, यहां लिये गये हैं। उदाहरण के लिये 'पंचाट' शब्द काश्मीरी जुवान में 'award' के लिये प्रयोग में आता है और चूंकि यह शब्द सम्मेलन के सदस्यों को मान्य हुआ इस लिये इस अनुवाद में 'award' का अनुवाद 'पंचाट' किया गया है। आशा है कि जब भारतीय संघ और उस के अंगभूत राज्यों में सरकारी कामों के लिये हिन्दी बरती जाने लगेगी तो ये शब्द, जिन का कि इस अनुवाद में प्रयोग हुआ है, सरकारी कामों के लिये प्रामाणिक हिन्दी शब्द माने जायेंगे।

नई दिल्ली, २४ जनवरी १९५०.

राजेन्द्र प्रसाद

PREFACE

The Constituent Assembly of India had by resolution authorised me to publish under my authority a Hindi Translation of the Constitution by the 26th January 1950, and translations of the Constitution in other languages as soon afterwards as I could arrange. I felt it desirable that in the translations of the Constitution in the different languages of India the same equivalents, if possible, should be used for the English terms of legal and constitutional import that occur in that document. I, therefore, called a conference of language experts to evolve as far as possible a common terminology which could be used for the translations of the Constitution in the various languages and ultimately also in all official administrative, legal and judicial work of the country. It met under the Chairmanship of the Honourable Shri Ghanshyam Singh Gupta, Speaker, Central Provinces' Assembly. It had on it representatives of all the languages specified in the Eighth Schedule. The Conference prepared a glossary of the terms used in the Constitution and the Expert Translation Committee which had been entrusted with the work of translating the Constitution in Hindi has made use of these terms alone in preparing this translation.

Some of the terms used in this translation of the Constitution may appear at present to be rather new to some people. But it must be remembered that these terms have been found to be acceptable to the majority of the languages of India and as such will either command today or in the near future the greatest measure of intelligibility. Some words may also be found to be used in a sense in which they are not ordinarily Thus the word 'jamin' has been used to indiused in Hindi cate 'bail' whereas its ordinary significance in Hindi is 'the person who offers bail'. But this difference in the meaning of the term has been found to be necessary because the term 'jamin' is used for 'bail' in the majority of the Indian languages. Some of the new terms that may be found in the translation of the Constitution have come in as a result of the decision of the Language Conference which considered terms of different languages for the purpose of fixing equivalents of the English terms. The term 'pamcata', for example, is used in Kashmiri language for 'award' and it was found to be acceptable to the members of the Conference and consequently the term 'award' has been translated in this translation as 'pamcata'. It may be hoped that the terms used in this translation would become the standard Hindi terms for official use when Hindi begins to be used for official purposes in the Amon and the States.

NEW DELHI, 24th January 1950.

RAJENDRA PRASAD

भारत का संविधान

विषय-सूची

				पृष्ठ स	ांख्या
	प्रस्तावना	•••	•••	•••	१
•	·	भाग १			
अनुच	छेद संघ	और उस कार	ाज्य-क्षेत्र		7
8	संघ का नाम और राज्य-	क्षेत्र	•••	•••	२
२	नये राज्यों का प्रवेश या स		***	•••	२
₹	नये राज्यों का निर्माण अ	ौर वर्तमान राज्यों क	क्षत्रों, सीमाओं या नामो	i	
	का बदलना ,	•••	***	•••	२
8	प्रथम और चतुर्थ अनुसूर् और अानुषंगिक विष		या अनुपूरक, प्रासंगिक : २ और ३ के अधीन		
	निर्मित विधियां .		•••	•••	₹
भाग २ नागरिकता					
*4	इस संविधान के प्रारम्भ प	र नागरिकता	•••	•••	8
Ę	पाकिस्तान से भारत को प्र	व्रजन कर आये कुछ व	व्यक्तियों के नाग-		
	रिकता के अधिकार	•••	•••	•••	8
૭	पाकिस्तान को प्रव्नजन कर	·-		•••	4
4	भारत क बाहर रहने वा	•	के कुछ व्यक्तियों की		
	नागरिकता के अधिका	•		••	9
९	विदेशी राज्य की नागरि		ात करने वाले व्यक्ति		
	नागरिक न होंगे .		•••	•••	Ę
१०	नागरिकता के अधिकारों	का बना रहना	•••	•••	Ę
११	संसद् विघि द्वारा नागरिक	ता के अधिकार का वि	विनयमन करेगी	•••	Ę

	[२]		
अनुच	छेड	वहरू	संख्या
of .E	भाग ३	Ĭ.o	
	✓ मूल अधिकार साधारण		
	साधारण		
१२	परिभाषा	•••	6
१३	मूल अधिकारों से असंगत अथवा उन का अल्पीकरण करने वाली		
	विधियां	•••	6
	समता-अधिकार		
१४	विधि के समक्ष समता		c
१५		•••	
	प्रतिषेघ	•••	۵
१६	राज्याघीन नौकरी के विषय में अवसर-समता		6
१७	अस्पृश्यता का अन्त	•••	9
१८	खिताबों का अन्त	•••	9
	ृस्वातन्त्र्य-अधिकार		
१९	वाक्-स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण	•••	to
२०	अपराघों के लिये दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण	•••	१२
२१	प्राण और देहिक स्वाघीनता का संरक्षण	•••	१२
२२	कुछ अवस्थाओं में बन्दीकरण और निरोध से संरक्षण	•••	१२
	शोषण के विरुद्ध अधिकार		
२३	मानव के पण्य और बलात्श्रम का प्रतिषेध		१४
२४	कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने का प्रतिषेध	•••	१५
	•		``
	धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार		
२५	अन्तः करण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने		
	की स्वतन्त्रता	•••	84
२६	धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता	•••	१६
२७	किसी विशेष घर्म की उन्नति के लिये करों के देने के बारे में स्वतन्त्रता		
२८	कुछ शिक्षा-संस्थाओं में घार्मिक शिक्षा अथवा घार्मिक उपासना में		१६
	उपस्थित होने के विषय में स्वतन्त्रता		9.0

अनुच्छेद	·	पृष्ठ	संख्या -
	संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार		
२९	अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण	•••	१७
३०	शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का		
•	अधिकार	•••	१७
	सम्पत्ति का अधिकार		
₹ १	सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन	•••	१७
	साविधानिक उपचारों के अधिकार		
			0.0
३२	इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के उपचार	***	१९ .
३३	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों के लिये प्रयुक्ति की अवस्थ	ī	_
	में, रूपभेद करने की संसद् की शक्ति	•••	२०
38	जब किसी क्षेत्र में सेना-विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा दिये गये	•	२०
	अधिकारों पर निर्बन्धन	***	
३५	इस भाग के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिये विधान	•••	२०.
	भाग ४		
	राज्य की नीति के निदेशक-तत्त्व		
			<u></u>
३६	परिभाषा	•••	२२
३७	इस भाग में वर्णित तत्त्वों की प्रयुक्ति	•••	२२
36	लोक-कल्याण की उन्नति के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा	•••	२२
३९	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-तत्त्व	•••	२२
४०	ग्राम-पंचायतों का संघटन	•••	२३
४१	कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पान का अधिकार		२३
४२	काम की न्यारय तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति-सहायता		
	का उपबन्ध	•••	२३
४३	श्रमिकों के लिये निर्वाह-मजूरी आदि	•••	२३
88	नागरिकों के लिये एक समान व्यवहार-संहिता	•••	२३
४५	बालकों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध	•••	२४
४६	अन् सूचित जातियों, आदिमजातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों के शि	क्षा	
	और अर्थ सम्बन्धी हितों की उन्नति		58.
४७	आहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक	•	
	स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य	•••	२४
४८	कृषि और पशुपालन का संघटन	•••	२४
४९	राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों का संरक्षण	•••	58. ,

[8]

अनूच्छ	द्व			पृष्ठ	संख्या
40	कार्यनालिका से न्यायपालिका का	पृथक्करण	•••	•••	२५
५१	अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कं	ो उन्नति	•••	•••	२५
		भाग ५	•		
		संघ			
	अध्याय	१.—कार्यपालि	का		
	√राष्ट् प ति				
५२	भारत का राष्ट्रपति	• • •		•••	२६
43	संघ की कार्यपालिका शक्ति	***		•••	२६
48	राष्ट्रपति का निर्वाचन	•••	•••	•••	२६
५५	राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति	•••	•••	•••	२७
५६	राष्ट्रपति की पदाविध	•••	•••	•••	२८
५७	पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता	•••	•••	•••	२८
46	राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये	अर्हताएं	•••	•••	२८
49	राष्ट्रपति के पद के लिये शर्ते	. •••	•••	•••	२९
६०	राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	•••	•••	•••	३०
६१	राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने व	नी प्रक्रिया	•••	•••	३०
६२	राष्ट्रपति-पद की रिक्तता-पूर्ति	के लिये निर्वा	चन करने का समय		
	तथा आकस्मिक रिक्तता-पूर्ति	के लिये निर्वारि	चतव्यक्तिकी पदा-		
	विध	•••	•••	0.0.0	₹१
६३	भारत का उपराष्ट्रपति "	•••	•••	•••	३१
६४	उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-परि	षद् का सभापि	तं होना	•••	38
६५	राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक	रिक्तता अथवा	उस की अनुपस्थिति	ſ	
	में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति				
	कृत्यों का निर्वहन	•••	•••	•••	३२
६६	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन	•••	***	•••	३२
६७	उपराष्ट्रपति की पदावधि	* * *		CHANG	83
६८	उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता	-पूर्ति के लिये	निर्वाचन करने का		
	समय तथा आकस्मिक रिक्त				
	की पदाविघ	•••	•••	•••	३४
६९	उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिइ	गन			३४
. 60	अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति		नर्वहन	•••	३५
90.	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्व			•••	३५
	·				` `

अनुच्छे	े द	पृष्ठ	संख्या
७२	क्षमा, आदि की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्बन, परिह	ार	
	या लघूकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति	•••	३५
ও३	संघ की कार्यपालिका शिवत का विस्तार	•••	३६
	र्भित्र-परिषइ्		
198	राष्ट्रपति को सहायता और मन्त्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद्	•••	३७
હિલ	मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपवन्ध •••	•••	३७
	भारत का महान्यायवादी		
,७६	भारत का महान्यायवादी •••	***	३७
	सरकारी कार्य का संचालन		
७७	भारत सरकार के कार्य का संचालन	400	३८
ડ્રહ	राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विषयक प्रघान मंत्री के कर्तव्य	***	३८
	अध्याय २.—संसद्		
	साधारण साधारण		
७९	संसद् का गठन	•••	39
८०	राज्य परिषद् की रचना	•••	३९
.68	लोक-सभा की रचना	•••	४०
.८२	भाग (ग) में के राज्यों तथा राज्यों से अन्य राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधित	व	
	के बारे में विशेष उपवन्ध	•••	४१
८३	संसद् के सदनों की अवधि	***	४१
.८४	संसद् की सदस्यता के लिये अर्हता	•••	४२
64	संसद् के सत्तू, सत्तूावसान और विघटन	***	४२
८६	मदनों को सम्बोधन करने और संदेश भेजन का राष्ट्रपति का अधिक	ार	४३
29	संसद् के प्रत्येक सत्तृारम्भ में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण	•••	४३
.८८	सदनों विषयक मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार	•••	४३
1	संसद् के पदाधिकारी		
.८९	राज्य-परिषद् के सभापति और उपसभापति	•••	४३
९०	उपसभापति की पद-रिक्तता, पदत्याग, तथा पद से हटाया जाना	•••	88
÷	उनसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन	T	-
• •	करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की, शक्ति	•••	४४

अनुच्छेद				पुष्ठ	संख्या:
९२	जब उस के पद से हटाने का संकल्प	विचाराधीन हो	तब सभा-		
	पति या उपसभापति पीठासीन न	होगा	•••	•••	४५
९३	लोक-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष		•••		४५
९४	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तत	ा, पदत्याग तथा	पद से हटाया		
	जाना	•••	•••	•••	४५
९५	अध्यक्ष-पद के कर्तव्य पालन की, अध	ावा अध्यक्ष के रू	प में कार्य करने		
	की, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की	शवित	•••	•••	४६.
९६	जब उस के पद से हटाने का संकल्प	म विचारा <mark>धीन</mark> हो	तब अध्यक्ष		
	या उपाध्यक्ष लोक-सभा की बैठको	ों में पीठासीन न	होगा	•••	४६.
९७	सभापति और उपसभापति तथा अ	ध्यक्ष और उपा	ध्यक्ष के वेतन		
	और भत्ते	•••	•••	•••	४७
९८	संसद् का सचिवालय	•••	•••	•••	४७
	कार्य-स	संचालन			
					86.
९९		···	••• ਜੀ ਵਾਸ਼ੀ ਲੜਕੇ	•••	
१००	सदनों में मतदान, रिक्तताओं के हो की शक्ति तथा गणपूर्ति	त हुए मा सदना	का काथ परंग		86
	का शाक्त तथा गणपूर्त	•••	•••	•••	
	सदस्यों क	ो अनर्हताएं			
१०१	स्थानों की रिक्तता		••• '	•••	४९
१०२	सदस्यता के लिये अनर्हताएं	•••	•••	•••	40
१०३	सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्ने	ों पर विनिश्चयन	•••	•••	५०
१०४	अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ या प्री	तेज्ञान करने से पू	व अथवा अर्ह न		
	होते हुए अथवा अनर्ह किये जान	ने पर बैठने, और	मत देने के लिये		
	दंड	•••	•••	•••	५१
₹	iसद् और उस के सदस्यों की श	_{वितयां,} विशेषा	धिकार और उ	न्मुक्तिय	ri
१०५	संसद् के सदनों की तथा उस के सव	स्यों और समिति	यों की शवितयां.		
(- (विशेषाधिकार आदि			•••	५१
१०६	सदस्यों के वेतन और भत्ते	•••	•••	•••	47
	Carr	न-प्रक्रिया			
	विधा	ग-प्राक्षया			
-600	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण	विषयक उपबन्ध	•••	•••	५२
१०८	किन्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की	संयुक्त बैठक	•••	•••	५३

ં ઉ

	•				
अनुच्छे	=			पुष्ठ स	i र ूया
१०९	धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया	***	•••	•••	५५
११०	धन-विधेयकों की परिभाषा	•••	•••	•••	५६
१११	विघेयकों पर अनुमति	•••	•••	•••	५७
	वित्तीय विष	वयों में प्रक्रिया			•
११२	वार्षिक-वित्त-विवरण	•••	•••	•••	46
.883	संसद् में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिय	ग	•••		48
११४	विनियोग-विधेयक	/	•••	•••	६०
११५	अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान	•••	•••	•••	६०
११६	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवा		•••	•••	६१
२१७	वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध	-	•••	•••	६२
	साधारण	गतया प्रक्रिया			
११८	प्रिक्रया के नियम				६३
388	संसद् में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिय	••• । का विधि द्वारा (••• वेनियमन		44
१२०	संसद् में प्रयोग होने वाली भाषा			•••	६४
. 228	संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन	•••	•••	•••	<i><u>4</u></i>
? ??	न्यायालय संसद् की कार्यवाहियों की	जांच न करेंगे		•••	६५
	अध्याय ३,—-राष्ट्रप		शक्तियां		
१२३	संसद् के विश्रान्ति-काल में राष्ट्रपति	की अध्यादेश प्रख्य	गापन शक्ति	•••	६५
	√अध्याय ४	–संघ की न्यायपा	लिका		
१२४	उच्चतमन्यायालय की स्थापना और	गठन	•••	•••	६६
१२५	न्यायाधीशों के वेतन आदि	•••	•••	•••	६द
१२६	कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नि	ायु क्ति	•••	•••	६९
१२७	तदर्थं न्यायाधीशों की नियुक्ति	•••	•••	•••	६९
१२८	सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्चत	मन्यायालय की व	वैठकों में		
	उपस्थिति	•••	•••	100	90
१२९	उच्चतमन्यायालय अभिलेख-न्याया	ठय होगा	•••	•••	90
१३०	उच्चतमन्यायालय का स्थान	•••	•••	•••	७०
१३१	उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षे		***	•••	90 -
१३२	किन्हीं मामलों में उच्चन्यायालयों		च्चतम-		
	न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिका	₹ •••	•••	•••	७१

	[
अनुच्छ	द	पृष्ट	संख्याः
१ ३३	उच्चन्यायालयों से व्यवहार-विषयों के बारे की, अपीलों में		
	उच्चतमन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार	•••	७२
१३४	दंड-विषयों में उच्चतनन्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार	•••	७३
१३५	वर्तमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालय का क्षेत्रा-		
	धिकार और शक्तियों का उच्चतमन्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य		
	होना ••• •••	•••	७४
१३६	अपील के लिये उच्चतमन्यायालय की विशेष इजाजत	•••	७४
१३७	निर्णयों या आदेशों परं उच्चतमन्यायालय द्वारा पुर्निवलोकन	•••	७५
१३८	उच्चतमन्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि	•••	७५
१३९	कुछ लेखों के निकालने की शक्ति का उच्चतमन्यायलय की प्रदान	•••	, 9ષ્
१४०	उच्चतमन्यायालय की सहायक शिवतयां	•••	७५
१४१	उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को बन्धन-		
	कारी होगी	•••	७६
१४२	उच्चतमन्यायालय के आज्ञप्तियों और आदेशों का प्रवृत्त कराना		
	तथा प्रकटन आदि के आदेश	•••	७६
१४३	उच्चतमन्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति	•••	७६
१४४	असैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता		
	में कार्य करेंगे	•••	७ ७
१४५	न्यायालय के नियम आदि	•••	७७
१४६	उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक तथा व्यय	•••	७९
१४७	निर्वचन	•••	८०
	अध्याय ५.—भारत का नियन्त्रक-्महालेखापरीक्षक		
१४८	भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षकः		८१
१४९	नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तिया	•••	८२
१५०	लेखें के विषय में निदेश देने की नियंत्रक-महालेखापरिक्षक की शक्ति	•••	ं ८२
१५१		•••	८२
	***		•
	भाग ६		
	प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य		
	अध् याय १—साधारण		
१५२	परिभाषा।	, •••	45
٠,			

	[%]			r	
अनुच्छेव	•		पुष्ट	संख्या	
	•		-		
	अध्याय २.—कार्येपालिका				
	राज्यपाल				
१५३	राज्यों के राजपाल	•••	•••	८३	
१५४	राज्य की कार्यपालिका शक्ति	•••	•••	ሪ ३ .	
१५५	राज्यपाल की नियुक्ति	•••	•••	८३	
१५६	राज्यपाल की पदाविध	•••	•••	८३	
१५७	राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हनाएं	•••	•••	68	
१५८	राज्यपाल-पद के लिये शर्तें	•••	•••	८४	
१५९	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	•••	***	८६	
१६०	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्व	हन	•••	८५	
१६१	क्षमा की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निलम्स	वन,			
	परिहार या लघूकरए। करने की राज्यपाल की श	क्ति	•••	८५	
१६२	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	***	•••	८६	
	मंत्रि-परिपद्				
१६३	राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मा	न्त्र-परिपद		८६	
१६४	मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध	•••		८७	
		_			
	राज्य का महाधिवक्ता				
१६५	राज्य का महाधिवक्ता	•••	•••	८ ७	
	सरकारी कार्य का संचालन	•			
१६६	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन	•••	•••	66	
१६७	राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मं	त्री के कर्तव्य	•••	66	
	•				
	अध्याय ३.—राज्य का विधा	त-मडल			
	साधारण				
१६८	राज्यों के विधान-मंडलों का गठन	•••	•••	८९	
१६९	राज्यों में विधान-परिषद् का उत्सादन या सृजन	•••	•••	८९	
१७०	विधान-सभाओं की रचना	•••	•••	90	
१७१	विधान-परिषदों की रचना	•••	•••	९१	
१७२	राज्यों के विधान-मंडलों की अविध	•••	•••	93	
१७३	राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अर्हता		- •••	9₹	
१ ७४	राज्य के विधान-मंडल के सत्त्र, सत्त्रावसान और वि	घटन	***	.68	
. 5					

ॱअनु•छे	द			पूष्ठ	सख्या
१७५	सदन या सदनों को सम्बोधन कर	ते और संदेश भेज	ने का राज्यपा	छ /	
	का अधिकार	•••	•••	•••	९४
१७६	प्रत्येक सत्तारम्भ में राज्यपाल का	विशेष अभिभाषण	•••	•••	९४
.१७७	सदनों विषयक मंत्रियों और महाधि	ववक्ता के अधिकार		•••	९५
	राज्य के विधा	न-मंडल के पदा	धिकारी		
१७८	विधान-सभा का अध्यक्ष और उपा	ाघ्यक्ष	•••	•••	९५
१७९	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रि	वतता, पदत्याग तः	या पद से हटा	या	
	जाना	•••	•••	•••	९५
१८०	अध्यक्ष-पद के कर्तव्य पालन की	अथवा अध्यक्ष के रू	प में कार्य करन	ने	
	की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति	की शक्ति	•••	•••	९६
.४८४	जब उस के पद से हटाने का संव	हल्प विचाराधीन हं	ो तब अध्यक्ष य	या	
	उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पी	ोठासीन न होगा	•••	•••	९६
१८२	विधान-परिषद् के सभापति और	उपसभापति	•••	•••	९७
\$23	सभापति और उपसभापति की प	द-रिक्तता, पदत्या	गतथा पद र	से	
	हटाया जाना •••	•••	•••	•••	९७
१८४				न	
	करने की अथवा सभापति के			•••	96
१८५	जब उस के पद से हटाने का संक		तब सभापति	या	
	उपसभापति पीठासीन न होगा		•••	•••	९८
१८६	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभाव	ाति और उपसभाप	ति के वेतन औ	र	
	भत्ते	•••	•••	•••	90
१८७	राज्य क विधान-मंडल का सचिवा	लय	•••	•••	९९
	٠ क	ार्य-संचालन			
366	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	•••	•••	•••	९९
१८९	सदनों में मतदान, रिक्तताओं के	होते हुए भी सद	नों के कार्य कर	.ने	
	की शक्ति तथा गणपूर्ति	•••	•••	•••	१००
	सदस्य	गों की अनर्हताएं			
१९०	स्थानों की रिक्तता	•••	•••	***	१००
	सदस्यता के लिये अनर्हताएं	•••	•••	•••	१०२
385	सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्र	श्नों पर विनिश्चय	•••	•••	१०२

अनुच्छे	i a		ą	ष्ठ संख्या
१९३	अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान कर न होते हुए अयवा अनर्ह किये जाने पर बठन			
	लिये दंड	•••	···	१०३
राज्य	के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों		विशाषा	ाधकार :
	और उन्मुक्तियां			,
१९४	विधान-मंडलों क सदनों की तथा उन के सदस	यों और समितिये	Ť	
	की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि	•••	•••	१०३
१९५	सदस्यों के वतन और भत्त	* • •	•••	१०४
	विधान-प्रकिया			
१९६	विधयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपब		•••	१०४
१९७	धन-विधयकों से अन्य विधेयकों के बारे में विधान	-परिषद् की शक्ति	यों	
	का निर्बन्धन	•••	•••	१०५
१९८	धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया	•••	•••	१०६
888	धन-विधेयकों की परिभाषा	•••	•••	१०७
२००	विधेयकों पर अनुमति	•••	•••	१०९
२०१	विचारार्थ रक्षित विधेयक	•••	•••	११०
	वित्तीय विषयों में प्रकि	या	•	
२०२	वार्षिक-वित्त -विवरण	•••	•••	११०
२०३	विधान-मंडल में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया	•••	•••	११२
208	विनियोग विधेयक	•••	•••	११२
२०५	अनुपूरक, अपर या अतिरिक्त अनुदान	•••	•••	११३
२०६	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान	•••	•••	११४
२०७	वित-विशेयकों के लिये विशेष उपबन्ध	•••	•••	११५
	सावारणतया प्रक्रिया			
२०८	प्रिकया के नियम	•••	•••	११५
२०९	राज्य के वियान-मंडल में वित्तीय कार्य सम्बन्ध	ो प्रक्रिया का वि	घे	,
	द्वारा विनियमन	•••	•••	११६
२१०	विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा	•••	•••	११६
२११	विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बन्धन	•••	•••	880
२१२	न्यायालय विवात-मंडल की कार्यवाहियों की जांच	ान करेंगे	***	११७
	अध्याय ४.––राज्यपाल की वि	धायिनी शक्तिय	Ť	
२१३	विवान-मंड़ल के विश्रान्ति-काल में राज्यपाल की	अध्यादेश-प्रग्व्यापन	· -	
	शक्ति	· 144.	•••	ن و وث ^ن
	a *		•	

अनु च्छे	द	`	१०० सख्या
	अध्याय ५.—-राज्यों के उच्चन्यायालय		
२१४	राज्यों के लिये उच्चन्यायालय	•••	११९
284	उच्चत्यायालय अभिलेख-न्यायालय होंगे	•••	१२०
२१६	उच्चन्यायालयों का गठन	•••	१२०
२१७	उच्चन्यायालय के न्यायाघीश की नियुक्ति तथा उस के पद की शर्ते	•••	१२०
२१८	उच्चतमन्यायालय सम्बन्धी कुछ उपबन्धों का उच्चन्यायालयों को		
•	लागु होना	•••	१२२
२१९	उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	•••	१२२
२२०	न्यायाधीशों द्वारा न्यायालयों में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष		
	विधि-वृत्ति करने का प्रतिषेध •••	•••	१२२
२२१	न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि •••	•••	१२२
२२२	एक उच्चन्यायालय से दूसरे को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण	•••	१२३
२२३	कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति	•••	१२३
२२४	सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की उच्चन्यायालयों की बैठकों में उपस्थिति	•••	१२३
२२५	वर्तमान उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार	•••	१२४
२२६	कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्चन्यायालयों की शक्ति	•••	१२४
२२७	सब न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति	•••	१२५
२२८	विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तान्तरण	•••	१२५
२२९	उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय	•••	१२६
२३०	उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार ग्रौर अपवर्जन	•••	१२७
२३१	राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्चन्यायालय		
	के क्षेत्राधिकार के बारे में, राज्यों के विधान-मंडलों की विधि		
	बनाने की शक्तियों पर निर्बन्धन	•••	१२७
२३२	निर्वचन	•••	१२८
	अध्याय ६.—अधीन न्यायालय		
२३३	जिला न्यायाघीशों की नियुक्ति	•••	१२९
२३४	न्यायिक सेवा में जिला-न्यायाघीशों से अन्य व्यक्तियों की भर्ती	0 • •	१२९
२३५	अधीन न्यायालयों पर नियंत्रण	•••	१२९
२३६	निर्वचन ••	•••	१३०
२३७	कुछ प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारयों पर इस अध्याय के उपबन्धे	ों का	
	लागू होना	•••	१३०
	भाग ७		
	प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य		
२३८	प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों को भाग ६ के		
	ज्ञानकों का काम केवा		0.7.0

अनुच्छे	द		पृष्ठ संख्या
	भाग =		
	प्रथम अनुसूची के भाग (ग)्रुमें के राज्य		
२३९	प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्यों का प्रशासन	•••	१३५
२४०	स्थानीय विधान-मंडलों अथवा मंत्रणा-दाताओं या मंत्रियों की		
	परिषद् का सृजन करना या बनाये रखना	•••	१३५
२४१	प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्यों के लिये उच्चन्यायालय	•••	१३६
585	कोड्गू।	•••	१३७
	भाग ६		
प्रश	यम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य राज्य	न्य-क्षे	त्र जो
	उस अनुसूची में उिल्लिखित नहीं हैं		
२४३	प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का और		
	उस में अनुल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन	•••	१३८
	भाग १०		
	अनुसूचित और आदमजाति-क्षेत्र		
२४४	अनुसूचित और आदिमजाति-क्षेत्रों का प्रशासन	•••	१३९
	भाग ११		
	संघ ग्रौर राज्यों के सम्बन्ध		
	•		•
	अध्याय १.—विधायी सम्बन्ध		
	विधायिनी शक्तियों का वितरण		
२४५	संसद् तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्ता	₹	१४०
२४६	संसद् द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों के ।	विषय	१४०
२४७	किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद्		
	की शक्ति	•••	586
२४८	अवशिष्ट विधान-शक्तियां	•••	888
२४९	राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची में के विषय के बारे में विधि बनाने की		-
	संसद् की शक्ति	•••	१४१
२५०	यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य-सूची में के विषय	Ť	
	के बारे में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	•••	१४२
२५१	अनुच्छेद २४९ और २५० के अधीन संसद् द्वारा निर्मित विधियों		
	तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति	•••	१४२
२५२	दो या अधिक राज्यों के लिये उन की सम्मिति से विधि वनाने की संसद्		
	की शक्ति तथा ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अंगीकार		
21.2	किया जाना अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ विधान	•••	१४३
२५३	जन्तराष्ट्राय करारा क पालनाय ।वधान		१४३

[88]

अनुच्छे	c		पुष्ठ संख्या
२५४	संसद् द्वारा निर्मित विधियों और राज्यों के विधान-मृंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति •••		१४४
२५५	सिपारिशों और पूर्व मंजूरी की अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय		
	मानना	•••	888.
	अध्याय २.—प्रशासन-सम्बन्ध		
-	साधारण	• '	
२५६	संघ और राज्यों के आभार	•••	१४५
२५७	किन्हीं अवस्थाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्ररा	•••	१४५
२५८	कतिपय अवस्थाओं में राज्यों को शक्ति आदि देने की संघ की शक्ति	•••	१४६
२५९	प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों में के सशस्त्र-बल	•••	१४७
२६०	भारत के बाहर के राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में संघ का क्षेत्राधिकार	•••	१४७
२६१	सार्वजनिक किया, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां	•••	१४७
. ' ;"	. जल सम्बन्धी विवाद		
२६२	अन्तर्राज्यिक निर्द्यों या नदी-दूनों के जल सम्बन्धी वादों का न्याय- निर्णयन ••• ••• ••• राज्यों के बीच समन्वय	•••	१४ 年
२६३	अन्तर्राज्यिक परिषद् विषयक उपबन्ध	•••	१४८
-	भाग १२		•
	वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद		
	अध्याय १.—वित्त		
	. साधारण	•	1
२६४	निर्वचन	•••	१५०
२६५	विधि-प्राधिकार के सिवाय करों का आरोपण न करना…	•••	१५0
२६६	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक-लेखे	•••	१५०
२६७	आकस्मिकता-निधि	•••	848
	संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण		
२६८	संघ द्वारा आरोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत		
	तथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क	•••	१५२

[{4]

अनुच	बेद [े]		पृष्ठ संस्था
२६९ २७०	संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंपे जाने वाले । संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बी		१५२
(0)	वितरित कर		ं १५३
२७१	संघ के प्रयोजनों के लिये शुल्क और करों पर अधिभार		१५४
२७२	करजो संघद्वारा उद्गृहीत और संगृहीत हैं तथा जो संघ और राज्यों के	बीच	
	वितरित किये जा सकेंगे।		१५४
२७३	पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के स्थान	में	•
	अनुदान	***	844
२७४	राज्यों के हितों से सम्बन्ध करों पर प्रभाव डालने वाले विधेयव	ों	
	के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सिपारिश की अपेक्षा		१५५
२७५	कतिपय राज्यों को गंघ से अनुदान	•••	१५६
२७६	वित्तयों, व्यापारों, आजीविकाओं ग्रौर नौकरियों पर कर	•••	१५७
२७७	व्यावृत्तिः	•••	१५८
२७८	कितपय वित्तीय विषयों के बारे में प्रथम अनुसूची के भाग (ख)	के	
	राज्यों से करार	•••	१५८
२७९	शुद्ध आगम की गणना	•••	ै १५ ९
२८०	वित्त-आयोग	•••	१६०
२८१	वित्त-आयोग की सिपारिशें	•••	₹ ₹
·**	प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध		
२८२	संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय	•••	१६१
२८३	संचित निधियों की आकस्मिकता-निधियों की तथा लोक-लेखों में	-	•
	जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि	•••	१६१
२८४	लोक-सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और अ	न्य	
	धन की अभिरक्षा	•••	१६२
२८५	संघ की सम्पत्ति की राज्य के करों से विमुक्ति	•••	१६२
२८६	वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण के बारे में निर्बन्धन	•••	१६३
२८७	विद्युत पर करों से विमुक्ति	•••	१६४
२८८	पानी या विद्युत के विषय में राज्य द्वारा लिये जाने वाले करों से कुट	ड	
	अवस्थाओं में विमुक्ति	•••	१६
२८९	संघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति श्रौर आय की विमुक्ति		१६५
२९०	कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन	•••	१६६
२९१	शासकों की निजि थैली की राशि	•••	१६७
707	अध्याय २.—उधार लेना		
२९२	भारत सरकार द्वारा उधार लेना	•••	१६७-
२९३	राज्यों द्वारा उधार लेना		286

अनुच्छे	द	Ą	ष्ठ संख्याः
अध्य	ाय ३.—सम्पत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, आभार औ	र व्यवहा	ार-वाद
२९४	कतिपय अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों	और	
	आभारों का उत्तराधिकार	•••	१६९.
२९५	अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और अ	गभारों	
	का उत्तराधिकार	•••	१७०
२९६	राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से प्रोद्भूत सम्पत्ति	•••	१७१
२९७	जलप्रांगण में स्थित मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी	•••	१७१
२९८	सम्पत्तिके अर्जन की शक्ति		१७१
२९९	संविदाएं	•••	१७२
३००	व्यवहार-वाद और कार्यवाहियां	•••	१७२:
	भाग १३		
	भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और स	मागम	
३०१	व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता	•••	१७४
३०२	व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्वन्धन लगाने की संसद्		
	की शक्ति	•••	१७४
३०३		ो	
	शक्तियों पर निर्बन्धन	***	\$08.
₹08		ī	१७५
३०५	वर्तमान विधियों पर अनुच्छेद ३०१ और ३०३ का प्रभाव	•••	<i>१७५</i> .
३०६	प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कतिपय राज्यों की व्यापा	र	
	और वाणिज्य पर निर्बन्धनों के आरोपण की शक्ति	•••	१७५
२०७	अनुच्छेद ३०१ और ३०४ तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के वि	लय े	
	प्राधिकारी की नियुक्ति	•••	१७६
	भाग १४		
	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं		
	अध्याय १. से वाएं		
३०८	निवर्चन।		<i>१७७</i> .
३०९	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की	†	,00
	शर्ते		१७७
३१०	संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदाविध		१७७·
३११	संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियं	Ť	,
	की पदच्युति. पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना	***	१७८
३१२	अखिल भारतीय सेवायें	••	१७९.

[१७]

अन ु च् छेर	τ				पृष्ठ :	संख्या
383	अन्तर्कालीन उपबन्ध	•••	•••	•••		१८०
३१४	कतिपय सेवाओं के वर्तमान पदाधि	कारियों के संरक्ष	ग के लिये उपबन्ध	•••		१८०
	अध्याय २	लोकसेवा-आ	योग			
३१५	संघ और राज्यों के लिये लोकसे	ग-आयोग	•••	•••		१८१
३१६	सदस्यों की नियुक्ति तथा पदान	त्रधि	•••	•••		१८२
३१७	लोकसेवा-आयोग के किसी सदस्य	म का हटाया जान	ा या निलम्बित			
	किया जाना	•••	•••	•••		१८३
३१८	आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-	वृन्द की सेवाओं क	ो शर्तों के बारे में			
	विनियम बनाने की शक्ति	•••	•••	•••		१८४
३१९	आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सद	स्य न रहने पर प	दों के घारण के			
	सम्बन्ध में प्रा	•••	•••	•••	:	१८४
३२०	लोकसेवा-आयोग 🖟 कृत्य	•••	•••	•••	:	१८५
३२१	लोकसेवा-आयोग 🕠 कृत्यों के वि	स्तार की शक्ति	•••	•••	;	१८७
३२२	लोकसेवा-आयो . के व्यय	•••	•••	•••	:	१८८
३२३	लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन	•••	•••	•••	:	१८८
		भाग १५				
		निर्वाचन				
•		गित्राप्त				
३२४	निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन	और नियंत्रण नि	र्वाचन-आयोग में			
	निहित होंगे	• ,•	•••	• • •	;	१८९
३२५	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आ	वारपर कोई व्य	क्ति निर्वाचक-			
	नामावलि में सम्मिलित किये	जाने के लिये अप	ात्र न होगा तथा			
	किसी विशेष निर्वाचक-नामाव	बिल में सम्मिलित	ा किये जाने का			
	दावा न करेगा	•••	•••	•••	;	१९०
३२६	लोक-सभा और राज्यों की विध	ान-सभाओं के लि	ये निर्वाचन का			
	वयस्क-मताधिकार के आधार	पर होना	•••	•••	:	१९१
३२७	विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों	के सम्बन्ध में उ	पबन्ध करने की			
	संसद् की शक्ति	•••	•••	•••	;	१९१
३२८	किसी राज्य के विधान-मंडल की प	रेसे विधान-मंडल व	हे लिये निर्वाचनों			
	के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने व	-	•••	•••		१९१
३२९	निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के	हस्तक्षेप पर रोव	Б	•••		१९१

अर्नुच्छद	r - '			त्रह	ठ संख्या
		भाग १६			ن د
	कतिपय वर्गी के स	तम्बन्ध में	विशेष उपबन्ध	,	•
३३०	अनुसूचित जातियों और अनुसू सभा में स्थानों का रक्षण		तेयों के लिये लोक •••		१९३
३३१	लोक-सभा में भ्रांग्ल-भारतीय	समुदाय का प्र	तिनिधित्व	•••	१९३
३३२	राज्यों की विधान-सभाओं में आदिमजातियों के लिये स्थ	0 "	तेयों और अनुस् 	्चित •••	१९३
३३३	राज्यों की विधान-सभा में आं	ग्ल-भारतीय सग	पुदाय का प्रतिनि धि	घत्व	१९४
३३४	स्थानों का रक्षण और विशेष दस वर्ष के पश्चात् न रहेग		विधान के प्रारम्भ 	से	१९५
३३५	सेवाओं और पदों के लिये अनुस् जातियों के दावे		ौर अनुसूचित आवि	देम-	१९५
३३६	कतिपय सेवाओं में आंग्ल भारती	ग्य समदाय के लि	ज्ये विशेष उपबन् ध	•••	१९५
३३७	आंग्ल-भारतीय समुदाय के फा	•		लये विशेष	,
	उपबन्ध	•••	•••	•••	१९६
३३८	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित विशेष पदाधिकारी	त आदिमजातिय •••	ों इत्यादि के वि 	त्रये •••	१९७
३३९	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर	तया अनुसूचितः	आदिमजातियों के व	ह त्याणार्थ	
	संघ का नियंत्रण	•••		•••	۽ تي ي
३४०	पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं है नियुक्ति	के अनुसधान के	लिय आयाग का	•••	१९८
३४१	अनुसूचित जातियां	•••	•••	•••	१९८
३४२	अनुसूचित आदिमजातियां	•••	•••	•••	१९९
		भाग १७	•		,

अध्याय १ — संघ की २१पा ३४३ संघ की राजभाषा ३४४ राजभाषा के लिये संसद्का बायोग और समिति

२०० २००

अनुच्छे	द ′	पृष्ठ	संख्या
	अध्याय२.—प्रादेशिक भाषाएं		
376	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं		२०२
	एक राज्य और दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच मे	ř	(- (
454	संचार के लिये राजभाषा		२०२
३४७	किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली	•••	(- (
400	भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	•••	२०२
			(- (
	अध्याय ३.—उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायालय आदि की भ	ाषा	
385	उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों,		
	विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा	•••	२०३
३४९	भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष	•	
	प्रक्रिया	• • •	२०४
	अध्याय ४विशेष निदेश		
34 o	व्यथा के निवारण के लिये अभिवेदन में प्रयोक्तव्य भाषा	•••	२०४
	हिन्दी भाषा के विकास के लिये निदेश	•••	२०५
	भाग १८		•
	आपात-उपबन्ध		
३५२	आपात की उद्घोषणा	•••	२०६
३५३	आपात की उद्घोषणा का प्रभाव	•••	२०७
३५,४	आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्तन में न हो तब राजस्वों के वितरण		
	सम्बन्धी उपबन्धों की प्रयुक्ति,	•••	२०७
३५५	वाह्य आक्रमण और आभ्यन्तरिक अशान्ति से राज्य का संरक्षण		
	करने का संघ का कर्तव्य	•••	२०८
३५६	राज्यों में संविधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की अवस्था मे उपबन्ध	• • •	२०८
३५७	अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के अधीन विधायिनी		
	शक्तियों का प्रयोग	• • •	२१०
३५८	आपातों में अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का निलम्बन	•••	२१२
	प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन	•••	२१२
३६०	वित्तीय आपात के बारे में उपबन्ध	•••	२१२
	भाग १६		
	प्रकीर्ए		
३६१	राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखो का संरक्षण	•••	२१४

अनुच्छेद	ŧ			
३६२	देशी राज्यों के शासकों के अधिव	कार और वि	त्रशेषाधिकार .	
३६३	कतिपय संधियों, करारों इत्यादि	से उद्भूत वि	ववादों में न्यायालयों द्वारा	
	हस्तक्षेप का वर्जन	•••	•••	
३६४	महा-पत्तनों और विमान-क्षेत्रों	के लिये विश	ोष उपबन्ध	•••
३६५	संघ द्वारा दिये गये निदेशों का			
	करने में असफलता का प्रभ	ाव	•••	•••
३६६	परिभाषाएं	•••	•••	•••
३६७	निर्वचन	•••	•••	•••
		भाग २	•	
	संविध	गनका स		
३६८	संविधान के संशोधन के लिये प्र	किया	•••	•••
		भाग र	8 8	
	अस्थायी त	ाथा अन्तव	र्हालीन उपबन्ध	
३६९	राज्य-सूची में के कुछ विषयों	के वारे में ि	विधि बनाने की संसद् की	
	इस प्रकार अस्थायी शक्ति म	ानो कि वे वि	षय समवर्ती सूची के हैं	•••
३७०	जम्मू और काश्मीर राज्य के स	ाम्बन्ध में अ	स्थायी उपबन्ध	•••
३७१	प्रथम अनुसूची के भाग (ख)	में के राज	यों के विषय में अस्थायी	
	उपवन्ध	•••	•••	•••
३७२	वर्तमान विधियों का प्रवृत्त बर्	-	0 41	•••
३७३	निवारक-निरोध में रखे गये व्य		•	
	में आदेश देने की राष्ट्रपति			•••
३७४	फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशो			
	सपरिषद् सम्राट् के, समक्ष ल			•••
३७५	संविधान के उपबन्धों के अर्ध	-	· ·	
	और पदाधिकारियों का कृत	-		•••
३७६	उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों			•••
३७७	भारत के नियंत्रक-महालेखापरी		ारे में उपबन्ध	• • •
३७८			•••	•••
३७९	•	के अध्यक्ष	और उपाध्यक्ष के बारे में	
_	उपबन्ध	***	•••	•••
३८०	•	•••	•••	•••
३८१	राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्		•••	

अनु च्छ	₹				qe	ठ संस्या
३८२			में के राज्यों के अ	ान्तर्कालीन वि	धान-	
		बारे में उपबन्ध		•••	•••	२३५
३८३		पालों के बारे में		•••	•••	२३६
३८४		मंत्रि-परिषद्		•••		२३७
३८५		•) में के राज्यों के	अन्तर्कालीन	विधान- •	
	मंडलों के	बारे में उपबन्ध	य	•••	•••	२३७
३८६	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, ,	में के राज्यों की म	•	•••	२३७
३८७			िलिये जनसंख्या	के निर्घारण के	बारे में	
	विशेष उप	बन्ध	•••	•••	•••	२३८
३८८	अन्तर्कालीन स	तथा राज	न्यों के अन्तर्काली	न विधान-मंडर	हों में	
	आकस्मिक	रिक्तताओं की	पूर्ति के बारे में	उपबन्ध	• • •	२३८
३८९	डोमीनियन वि	घान-मंडल तथ	ा प्रांतों और देशी	राज्यों के व	धान-	
	मंडलों में र	ल्रम्बित विधेयक	ों के बारे में उपब	न्घ	•••	२४०
३९०	इस संविधान व	ने प्रारम्भ और	१९५० की ३१ मा	र्च के बीच प्रा	न्त या	
	उत्थापित र	या व्यय किया ह	इआ धन	•••	•••	२४०
३९१			- और चतुर्थ अनुसूर्च	ो को संशोधन		
		राष्ट्रपति की श			•••	२४१
३९२		••	ट्रपति की शक्ति	•••	***	२४१
	**		•			
			भाग २२			
		संक्षिप्त न	नाम, प्रारम्भ औ	रि निरसन		
३९३	संक्षिप्त नाम	•••	•••	•••	•••	२४३
३९४	प्रारम्भ	•••	•••	•••	•••	२४३
३९५	निरसन	•••	•••	•••	•••	२४३
			•			
			अनुसूचियां			
प्रथम	अनुसूची-भार	त के राज्य औ	र राज्य-क्षेत्र	•••	•••	२४५
_	र अनुसूची—					•
	0 41			=\ ਜੋ - ਿਜ	daa	
याप			ानुसूची के भाग (के लिये उपबन्ध	भ) म उल्ला	अत	244
277777				v (-		२४८
साग			ाूची के भाग (क) के सम्बन्ध में उपब		a) + 1	71/0
**************************************					•••	२४९
साग	- •		भौर उपाध्यक्ष के सम्बद्धाः		•	~
			पसभापति के तथ	•	•	
	भाग	(क) म क र	ाज्य की विधान-स	मा क अध्यक्ष	अरि	

[२२]

अनुसूचियां

			, ,	गुष्ठ संख्या
उपाध्यक्ष के तथा । सभापति और उपस	-		प्रद्के	२४९
भाग (घ)—उच्चतमन्यायालय तर राज्यों के उच्चन्या				
उपबन्ध	•••	•••	•••	३५०
भाग (ङ)-भारत के नियंत्रक-महा	लेखापरीक्षक वे	सम्बन्ध में उपबन्ध	1	२५३
तृतीय अनुसूची-शपथ और प्रतिज्ञान	ृंके प्रपत्र	•••	•••	२५४
चतुर्थं अनुसूची-राज्य-परिषद् में के	स्थानों का बंट	वारा	•••	२५७
पंचम अनुसूची-अनुसूचित क्षेत्रों औ	र अनुसूचित अ	ादिम जातियों के	प्रशासन	
और नियंत्रण के स				
. ,	•••	•••	•••	२५९
भाग (ख)-अनुसूचित क्षेत्रों और	अनुसूचित न्आ	देमजातियों का प्रव	ासन	
और नियंत्रण	•••	•••	• • •	२५९
भाग (ग)-अनुसूचित क्षेत्र	•••	•••	•••	२६ १
भाग (घ)-अनुसूची का संशोधन	•••	•••	•••	२६२
षष्ठ अनुसूची-आसाम में के आदिमज	ाति-क्षेत्रों के प्रव	ासन के बारे में उप	बन्ध	२६३
सप्तम अनुसूची-				
सूची १संघ सूची	•••	•••	•••	२८१
सूची २.–राज्य [.] सची	•••	•••	• • •	२८९
सूची ३समवर्ती सूची	•••	•••	•••	२९४
अष्टम अनुसूची-भाषाएं	•••	•••	•••	२९९
-		·		
भारत के संविधान का पारिभाषिक-व	ग्रब्दावलि-कोष	•••	•••	१—५१

१—५१

भारत का संविधान

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उस के समस्त नागरिकों को :

प्रस्तावना.

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा श्रौर अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिये,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की

एकता सुनिश्चित करने वाली **बन्धुता**

बढ़ाने के लिये

दृढ़संकल्प हो कर अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छ विक्रमी) को एतद्द्रारा इस संविधान को अङ्गीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भाग १

संघ और उसका राज्य-इंत्र

संव का नाम और राज्य-क्षेत्र.

- १. (१) भारत, अर्थात् इण्डिया, राज्यों का संघ होगा।
- (२) उसके राज्य और राज्य-क्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य और उन के राज्य-क्षेत्र होंगे
 - (३) भारत के राज्य-क्षंत्र में--
 - (क) राज्यों के राज्य-क्षेत्र;
 - (ख) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) मं उल्लिखित राज्य-क्षेत्र; तथ:
- (ग) ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र जो अर्जित किये जायें, समाविष्ट होंगे !

नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना. २ संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों भौर शर्तों के साथ जिन्हों वह उचित समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी।

नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना.

- ३ संसद् विधि द्वारा-
 - (क) किसी राज्य से उस का प्रदेश अलग कर के अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर नया राज्य बना सकेगी;
 - (स) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
 - (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
 - (घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी;
 - (ङ) हिकसी राज्य के नाम को बदल सकेगी

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिपा-रिश विना, तथा जहां विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव ई

भाग १--संघ और उसका राज्य-क्षेत्र--अनु० ३-४

प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (क) में उल्लिखित राज्य या राज्यों की सीमाओं पर अथवा किसी ऐसे राज्य या राज्यों के नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जब तक कि विधेयक की पुरः स्थापना की प्रस्थापना के तथा उस के उपबन्ध, इन दोनों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल अथवा राज्यों में से प्रत्येक के विधान-मंडल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से न जान लिये हों तब तक, किसी सदन में पुरःस्थापित न किया जायेगा।

- ४. (१) अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध अन्तिवष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध (जिन के अन्तर्गंत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के, संसद् या विधान-मंडल या विधान मंडलों में, प्रतिनिधित्व के बारे में उप-बन्ध भी हैं) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद् आवश्यक समझे।
- (२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायगी।

7 . 77 20 f a 30 103 + 115

प्रथम और चतुर्थं अनु-स्चियों के संशोधन तथा अनुपूरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक विषयों के लिये अनुच्छेद २ और ३ के अधीन निर्मित

भाग २

नागरिकता

इस संविधान क प्रारम्भ पर सामरिकता. ५. इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस का भारत राज्य-क्षेत्र में अधिवास है, तथा--]

- (क) जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा
- (ख) जिस के जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा
- (ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष तक भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है;

भारत का नागरिक होगा।

पाकिस्तान से मारत को प्रव्रजन कर वाये कुछ व्यक्तियों के नायरिकता के अधिकार. ६. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 'बी पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर आया है इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जायेगा—

- (क) यदि वह अथवा उस के जनकों में से कोई अथवा उस के महाजनकों में से कोई भारत-शासन-अधि-नियम १९३५ (यथा मूळतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा थाः तथा
- (स)(१)जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन् १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन से पूर्व प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है; अथवा
 - (२) जब कि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन् १९४८ की जुलाई के उन्नीसवें दिन या उस के पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन कर आया है तब यदि वह भारत डोमी-नीयन की सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति

भाग २--नागरिकता--अनु० ६-=

से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहिले ऐसे पदाधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया है, दिये जाने पर उस पदाधिकारी द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र की तारीख से ठीक पहिले कम से कम छ महीन भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो तो वह इस प्रकार पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा।

७. अनुच्छेद ५ और ६ में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति १९४७ के मार्च के पहिले दिन के पर्व्चात् भारत राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायंगा:

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन के पश्चात् भारत राज्य-क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने के लिये किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गई है, तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद ६ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये भारत राज्य-क्षेत्र को १९४८ की जुलाई के १९ वें दिन के पश्चात् प्रव्रजन करने वाला समझा जायेगा।

८. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिस के जनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई भारत-शासन-अधिनियम १९३५ (यथा मूलतः अधिनियिमत) में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यतया है इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, भारत का नागरिक समझा जायेगा, यदि वह भारत डोमीनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनियक या वाणिज्यिक

पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों में से कुछ के नागरिकता के अधिकार,

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नाग-रिकता के अधिकार.

भाग २--नागरिकता--अनु० ८-११

प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या बाद, दिये जाने पर ऐसे राजनियक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया है।

विदेशी
राज्य की
नागरिकता
स्वेच्छा से
अजित
करने वाछे
व्यक्ति
नागरिक न
होंगे.

९. यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अजित कर ली है तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर भारत का नागरिक न होगा और न अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ के आधार पर भारत का नागरिक समझा जायेगा।

नागरिकता के अधि-कारों का बना रहना. १०. प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा निर्मित की जाये, भारत का वैसा नागरिक बना रहेगा।

संसद् विधि
द्वारा नागरिकता के
अधिकार
का विनिन्
यसन करेगी

११. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद् की शक्ति का अल्पी-करण नहीं करेगी।

भाग ३

मूल अधिकार

साधारण

१२ यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद्, तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान-मंडल, तथा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, भी हैं।

परिभाषा.

- १३. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने । से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत हैं।
- (२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्धारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

मूल अघि-कारों से असंगत अयवा उनका अस्पीकरण करने वाली विधियां.

- (३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस अनुच्छेद में—
 - (क) भारत राज्य-क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि अथवा प्रथा "विधि" के अन्तर्गत होगी;
 - (ख) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य [क्षमताशाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित अथवा निर्मित विधि, जो पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई विधि या उस का कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशेष क्षेत्रों में प्रवर्तन में न भी हो, "प्रवृत्त विधियों" के अन्तर्गत होगी।

भाग ३--मूल अधिकार-अनु० १४-१६

समता-अधिकार

विधि के समक्ष समता. १४. भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचितः नहीं किया जायेगा ।

धर्म, 'मूलवंग, जाति, छिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध -

- १५. (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
- (२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक——
 - (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; अथवा
 - (ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के

बारे में किसी भी नियोंग्यता, दायित्व, निर्बन्ध अथवा शर्त के अधीन न होगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसीबात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी।

राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता

- १६. (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।
- (२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के। लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा।

भाग ३-मूल अधिकार-अनु० १६-१८

- (३) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के अथवा उस के राज्य-क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में वैसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के अन्दर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो।
- (४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिन का प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधान होगी।
- (५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करती हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ही हो।
- १७. "अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी नियोंग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अस्पृश्यता

का अन्त.

१८. (१) सेना या विद्या सम्बन्धी उपाधि के सिवाय और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा।

खिताबों का अन्त.

- (२) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा !
- (३) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब राष्ट्रपति की सम्मति के विना स्वीकार न करेगा।

भाग ३---मूल अधिकार--अनु० १८-१९

(४) राज्य के अधीन लाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के विनक्त स्वीकार न करेगा।

स्वातन्त्र्य-अधिकार

वाक्-स्वा-तन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

- १९. (१) सब नागरिकों को---
 - (क) वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का;
 - (ख) शान्ति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन का;
 - (ग) सन्था या संघ बनाने का;
 - (घ) भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का ;
 - (ङ) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का:
 - (च) सम्पत्ति के अर्जन, घारण और व्ययन का; तथा
 - (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का,

अधिकार होगा।

- (२) खंड (१) के उपखंड (क) की काइ बात अपमानलेख, अपमान-वचन, मानहानि, न्यायालय-अवमान से अथवा
 शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले, अथवा राज्य की
 सुरक्षा को दुर्बल अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी
 विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक
 उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि
 को बनाने में राज्य के लिये एकावट, न डालेगी।
- (३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती

भाग ३--मूल ग्रधिकार--अनु० १९

हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्वन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।

- (४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उप-खंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजिनिक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।
- (५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिमजाति के हितों का संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी।
- (६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त खंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये क्कावट न डालेगी; तथा विशेषतः उक्त उपखंड की कोई बात, कोई वृत्ति, उपजीविका व्यापार या कारबार करने के लिये आवश्यक वृत्तिक या शिल्पिक अईताओं को जहां तक कोई वर्तमान विधि विहित करती है अथवा किसी प्राधिकारी को विहित करने की शक्ति देती है वहां तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा विहित करने, या विहित करने की शक्ति किसी प्राधिकारी को देने, वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये क्कावट, न डालेगी।

भाग ३--म्ल अधिकार--अनु० २०-२२

अपराधों के लिये दोष-सिद्धि के विषय में संरक्षण.

- २०. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, और न वह उस से अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था।
- (२) कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित न किया जायेगा।
- (३) किसी अपराश में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य न किया जायेगा।

पाण और दैहिक स्वा-घीनता का

संरक्षण.

- २१. किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि दारा स्थापित प्रक्रिया को छोड कर अन्य प्रकार वंचित न किया जायेगा।
- २२. (१) कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये विना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से बंचित रखा जायेगा।
- (२) प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध किया गया है, बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़ कर ऐसे बन्दीकरण से २४ घंटे की कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि से आगे दंडाधिकारी के प्राधिकार के विना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा।
 - (३) खंड (१) और (२) में की कोई बात-
 - (क) जो व्यक्ति तत्समय रात्रु अन्यदेशीय है उसको, अथवा

कुछ अवस्थाओं बन्दीक रण और निरोध से संरक्षण.

भाग ३--मूल अधिकार--अनु० २२

(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया है उसको,

लागू न होगी।

- (४) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालाविध के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि—
 - (क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा नियुक्त होने की अहेंता रखते हैं, मिल कर बनी मंत्रणा-मंडली ने तीन महीने की उक्त कालाविध की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध कें लिये उस की राय में पर्याप्त कारण हैं:

परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम कालाविध से आगे, निरोध को प्राधिकृत न करेगी जो खंड (७) के उपखंड (ख) के अधीन संसद्-निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई है; अथवा

- (ख) ऐसा व्यक्ति खंड (७) के उपखंड (क) और (ख) के अधीन संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं है।
- (५) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीझ उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया है उन को बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे शीझातिशीझ अवसर देगा।
- (६) खंड (५) की किसी बात से आद्देश इदेने वाले प्राधिकारी के लिये ऐसे तथ्य को प्रकट करना आकृत्यक नहीं

भाग ३--मूल अधिकार--अनु० २२-२३

होगा जिन का कि प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है।

- (७) संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि--
 - (क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालाविध के लिये खंड (४) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा-मंडली की राय प्राप्त किये विना निरुद्ध किया जा सकेगा;
 - (ख) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम कालाविध के लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपवन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; तथा
 - (ग) खंड (४) के उपखंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्या होगी।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

मानव के पण्य श्रीर बलात्श्रम का अतिषेध.

- २३. (१) मानव का पण्य और बेट बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्देस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
- (२) इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये बाध्य सेवा लागू करने में रुकावट न होगी। ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इन में से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं करेगा.

भाग ३—मूल अधिकार—अनु० २४-२५

२४ चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाया जायेगा।

कारखानें अवि में जन्मों को नौकर रखने का रूपतिषेध.

धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार

- २५. (१) सार्वजिनक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को, अन्तः करण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा।
- (२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट, न डालेगी जो—
 - (क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक कियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो:
 - (स) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हो, अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म-संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के के लिये खोलती हो।

व्याख्या १.—कृपाण घारण करना तथा लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग समझा जायेगा।

व्याख्या २.—खंड (२) के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तिओं का भी निर्देश अन्तर्गत है तथा हिन्दू धर्म-संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी तदनुक्ल ही किया जायेगा।

अन्तः करण की तथा घमं के अबाध मानने, आचरण और इचार करने की स्वतंत्रता.

भाग ३--मूल अधिकार--अनु**० २**६-२८

वामिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता. २६. सार्कजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उस के किसी विभाग को—

- (क) धार्मिक और पूर्त-प्रयोजनों के लिये संस्थाओं की स्थापना और पोषण का;
- (ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने काः
 - (ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का; तथा
- (घ) ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का; अधिकार होगा।

किसी विशेष यमं की उन्नति के लिये करों के देने के बारे में स्वतंत्रता.

स्वतंत्रता.
कुछ शिक्षाधंस्थाओं में
वार्मिक शिक्षा
अथवा धार्मिक
उपासना में
उपस्थित होने
के विषय में

२७. कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा जिन के आगम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये हों।

- २८. (१) राज्य-निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा-संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जायेगी ।
- (२) खंड (१) की कोई बात ऐसी शिक्षा-संस्था पर लागू न होगी जिस का प्रशासन राज्य करता हो किन्तु जो किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिस के अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।
- (३) राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली, शिक्षा-संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसा संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उस से संलग्न स्थान में की

भाग ३--मूल अधिकार--अनु० २८-३१

जाने वाली धार्मिक उप।सना में उपस्थित होने के लिये बाध्य न किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह जावयस्क हो तो उस के संरक्षक ने, इस के लिये अपनी सम्मति न दे दी हो।

संस्कृति ग्रौर शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

२९. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिस की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण.

- (२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इन में से किसी के आवार पर वंचित न रखा जायेगा।
- ३०. (१) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यकः वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- (२) शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह चर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबन्ध में है।

शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्प-संस्यकों का अधिकार.

्सम्पत्ति का अधिकार

- ३१. (१) कोईं व्यक्ति विधि के प्राधिकार के विना अपनी सम्मत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।
- सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन.
- (२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिस के अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उस की स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्जा या अर्जन करने का प्राधिकार देती है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये कब्जाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायेगी जब

भाग ३--मूल अधिकार--अनु० ३१

तक कि वह विधि कब्जाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत न कर दे या उन सिद्धांतों और रीति का उल्लेख न कर दे जिन से प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है।

- (३) राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि, जैसी कि खंड (२) में निर्दिष्ट है, तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात्, उस की अनुमति न मिल गई हो।
- (४) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के विधान-मंडल के सामने किसी लिम्बत विधेयक को, ऐसे विधान-मंडल द्वारा पार किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार के लिये रिक्षत किया जाता है तथा उस की अनुमित मिल जाती है तो उस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार अनुमत विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपित नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है।
 - (५) खंड (२) की किसी बात से---
 - (क) ऐसी किसी विधि को छोड़ कर जिस पर कि खंड (६) के उपबन्ध लागू होते हैं किसी अन्य वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, अथवा
 - (ख) एतत्पश्चात् राज्य जो कोई विधि--
 - (१) किसी कर या अर्थ-दण्ड के आरोपण या उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिये बनाये उस के उपबन्धों पर्र; अथवा
 - (२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा प्राण या सम्पत्ति के संकट-निवारण के लिये बनाये उस के उपबन्धों पर, अथवा

भाग ३--मूल अधिकार--अनु० ३१-३२

(३) भारत डोमीनियन की अथवा भारत की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच किये गये करार के अनुसरण में, अथवा अन्यथा, जो सम्पत्ति विधि द्वारा निष्काम्य सम्पत्ति घोषित की गई है उस सम्पत्ति के लिये बनाये उस के उपबन्धों पर,

प्रभाव नहीं होगा।

(६) राज्य की कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से अठारह महीने से अनिधक पहिले अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्भ से तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपित के समक्ष उस के प्रमाणन के लिये रखी जा सकेगी, तथा ऐसा होने पर यदि लोक-अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपित ऐसा प्रमाणन देता है तो किसी न्यायालय में उस पर इस आधार पर आपित्त नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है अथवा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९९ की उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन कर चुकी है।

संविधानिक उपचारों के अधिकार

- ३२. (१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को समुचित कार्य-वाहियों द्वारा प्रचालित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।
- (२) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को प्रवितित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या लेख, जिन के अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।
- (३) उच्चतमन्यायालय को खंड (१) और (२) द्वारा दी गई शक्तियों पर विना प्रतिकल प्रभाव डाले, संसद्

इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपचार. भाग ३--मूल अधिकार--अनु० ३२-३४

विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतमन्यायालय द्वारा खंड (२) के अधीन प्रयोग की जाने वाली सब अथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी।

(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को ू छोड़ कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलम्बित न किया जायेगा।

इस भाग द्वारा प्र दत्त अधिकारों का बलों के लिये प्रयुक्ति की अवस्था में. रूपभेद करने की संसद् की शक्ति. जब किसी क्षेत्र में सेना-विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वार। दिये अधिकारों पर निर्वन्धन.

३३. संसद् विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों के सदस्यों के लिये प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निर्वेन्धित या निराकृत किया जाये ताकि उन के कर्तव्यों का उचित पालन तथा उन में अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

३४. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा में के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी हे ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी जो उस ने भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र मे, जहां सेना-विधि प्रवृत्ता थी, व्यवस्था के बनाये रखने या पुनःस्थापन के सम्बन्ध में किया है अथवा ऐसे क्षेत्र में सेना-विधि के अधीन किसी दिये गये दंडादेश, किये गये दंड, आदेश की हुई जब्ती, अथवा किये गये अन्य कार्य को मान्य कर सकेगी।

इस भाग के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिये विधान. ३५. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-

(क) संसद् को शक्ति होगी तथा किसी **राज्य** के विधान-मंडल को शक्ति न होगी कि वह—

(१) जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३), अनुच्छेद ३२ के खंड (३), अनुच्छेद ३३ भाग ३--मूल अधिकार--अनु० ३५

और अनुच्छेद ३४ के अधीन संसद् विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी, उन में से किसी के लिये, तथा

(२) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के दंड विहित करने के लिये,

विधि बनाये तथा संसद् इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशी घ्र ऐसे कार्यों के लिये जो उपखंड (२) में निर्दिष्ट हैं दंड विहित करने के लिये विधि बनायेगी।

(ख) खंड (क) के उपखंड (१) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से सम्बन्ध रखने वाली, अथवा उस खंड के उपखंड (२) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिये दंड का उपबन्ध करने वाली, कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत राज्य-क्षेत्र में इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहिले लागू थी, उस में दिये हुए निबन्धनों के तथा अनुच्छेद ३७२ के अधीन उस में किये गये किन्हीं अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि वह संसद् द्वारा परिवर्तित या निरसित या संशोधित न की जाये।

व्याख्या.—"प्रवृत्त विधि" पदाविल का जो अर्थ इस संविधान के अनुच्छेद ३७२ में है वही इस अनुच्छेद में भी होगा।

भाग ४

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व

परिभाषा.

३६. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है।

इस भाग में वर्णित तत्वों क्री प्रयुक्ति. ३७. इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुए तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।

लोक-कल्याण के उन्नित के हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगाः राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति- ३८. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिस में सामाजिक, आधिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर के लोक-कल्याण की उन्नित का प्रयास करेगा।

३९. राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा सचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

- (क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;
- (ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिस से सामुहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;
- (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से घन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण नहो;
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो;
- (ङ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहों तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में नजाना पड़े जो उन की आयुया शक्ति के अनुकूळ नहों;

भाग ४--राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व--अनु० ३१-४४

(च) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।

४०. राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन करने के लिये अग्रसर होंगा, तथा उन को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों।

ग्राम-पंचायतीं का संघटन.

४१. राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।

कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक-सहायता पाने का अधिकार.

४२. राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिक्चित करने के लिये तथा प्रसूति-सहायता के लिये उपबन्ध करेगा।

काम की
न्याय्य तथा
मानवोचित
दशाओं का
तथा प्रसूतिसहायता का
उपबन्ध

४३. उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा, अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रीमकों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

श्रमिकों के लिये निर्वाह--मजुरी आदि.

४४. भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिये राज्य । एक समान व्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

नागरिकों के लिये एक समान व्यव-हार-संहिता.

भाग ४--राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व--अनु० ४५-४९

बालकों के
लिये निःशुलक
और अनिवायं
शिक्षा का
उपबन्धः
अनुसूचित
जातियों,
आदिमजातियों
तथा अन्य
दुर्वक विमागों
के शिक्षा
और अर्थ
सम्बन्धी हितों

४५. राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालाविध के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

४६. राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से उन का संरक्षण करेगा।

आहारपुष्टि-तल श्रीर जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वे-जनिक स्वास्थ्य के सुघार करने का राज्य का कर्तेव्य. ४७. राज्य अपने लोगों के आहारपृष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया, स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

कृषि ग्रौर पशुपालन का संघटन. ४८. राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उन के वध का प्रतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा।

राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों का संरक्षण. ४९. संसद् से, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्त्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिकृष्टि वाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या चीज का यथास्थिति लुंठन, विरूपन, विनाश, अपनयन, व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा।

भाग ४--राज्य की नींति के निदेशक तत्त्व--अनु १०-५१

५०. राज्य की लोक-सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिये राज्य अग्रसरं होगा। कार्यपालिका से न्याय-पालिका का पृथक्करण.

५१. राज्य--

- (क) अन्तरिष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का;
- (ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का;
- (ग) संघटित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का; तथा
- (घ)अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये प्रोत्साहन देने का,

प्रयास करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ग्रौर सुरक्षा की उन्नति.

ं भाग ५

संघ

अध्याय १--कार्यपालिका

राष्ट्रपति अौर उपराष्ट्रपति

ंभारत का ⁻राष्ट्रपति. ५२ भारत का एक राष्ट्रपति होगाः।

संघ की कार्य-पालिका शक्ति.

- ५३. (१) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या ती स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।
- (२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर विना प्रतिकुल प्रभाव डाले संघ के रक्षा-बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपित में निहित होगा और उस का प्रयोग विधि से विनियमित होगा।
 - (३) इस अनुच्छेद की किसी बात से=
 - (क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी राज्य की

 सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे

 कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न
 समझे जायेंगे; अथवा
 - (ख) राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य देने में संसद को बाधा न होगी।

-राष्ट्रपति -का 'निर्वाचन ५४<u>राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-गण के सदस्य</u> करेंगे जिस में—

- (क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा
- (ख) <u>राज्यों</u> की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य,

भाग ५--संघ--ग्रनु० ५५

५५. (१) जहां तक व्यवहायं हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक से मापमान से होगा।

राष्ट्रपति को निर्वाचन की रीति

- (२) राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिये संसद् तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का हक्कदार है उन की संख्या नीचे लिखे प्रकार ऐसे निर्धारित की जायेगी—
 - (क) किसी राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित, उस भाग फल में हों जो राज्य की जन-संख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से, भाग देने से आये;
 - (ख) एक हजार के उक्त गुणितों को छेने के बाद यदि शेष पांच सौ से कम न हो तो उपखंड (क) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड दिया जायेगा;
 - (ग) संसद् के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होगी जो उपखंड (क) तथा (ख) के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों के लिये नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद् के दोनों सदनों। के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आये, जिस में आधे से अधिक भिन्न की एक गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी।
- (३) राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गढ़ शलाका द्वारा होगा।

.भाग ५--संघ--अनु० ५५-५८

व्याख्या <u>इस अन</u>्च्छेद में "जनसंख्या" से, ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिस के तत्सम्बन्धी <u>आंकडे प्रकाशित हो चुके हैं</u>।

राष्ट्रपति की पदाविध. ५६ (१) राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्षं की अविध तक पद धारण करेगा:

परन्तु-

- (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;
- (ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपित् अनुच्छेद ६१ में उपबन्धित रीति से किये गये महाभियोग द्वारा पद से इटाया जा सकेगा;
- (ग) राष्ट्रपति अपने पद की अविध समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा।
- [(२) खंड (१) के परन्तुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्र-पति को सम्बोधित किसी त्यागपत्र की सूचना उस के द्वारा लोक-सभा के अध्यक्ष को अविलम्ब दी जायेगी।

पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता. ५७ कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा है अथवा कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस पद के लिये पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अहंतायें.

- ५८. (१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह—
 - (क) भारत का नागरिक न हो
 - (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा

भाग ५--संघ--अनु० ५८-५६

- (ग) <u>लोक सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अह</u>ता न रखता हो ।
- (२) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

व्याख्या .— इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ् का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख है अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

५९. (१) राष्ट्रपति न तो संसद् के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

राष्ट्रपति के पद के लिये शर्ते.

- (२) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा।
- (३) राष्ट्रपति को, विना किराय दिये, अगने पदावासों के उपयोग का हक्क होगा तथा उस को उन उपलब्धियों, भत्तों और विश्रेषाधिकारों का भी, जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विश्रेषाधिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, इक्क होगा।
- (४) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उस के पद की अविधि में घटाये नहीं जायेंग्रेश.

भागा । ५ -- संघ -- अनु० ६०-६१

राष्ट्रपति द्वाराः शपथ या प्रतिज्ञान. ६०. प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन करता है अपने पद-प्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस की अनुपस्थित में उच्चतमन्यायाद्य के प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्

"मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं स्त्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्य गालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, सरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहुंगा।

राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया.

- ६१. (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद् का कोई सदन दोषारोप करेगा
- . (२) ऐसा कोई दोषारोप तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि—
 - (क) ऐसे दोषारोप के करने की प्रस्थापना, किसी संकल्प में न हो, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिये जाने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया के है, जिस पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर कर के, उस संकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रगट किया है, तथा
 - (ख) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित न किया गया हो।

भाग ५--संघ--अनु० ६१-६४

- (३) जब दोषारोप संसद् के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया जा चुके तब दूसरा सदन उस दोषारोप का अनुसंधान करेगा या करायेगा तथा इस अनुसंधान में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।
- (४) यदि अनुसंधान के फलस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प दोषारोप के अनुसंधान करने या कराने वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उस की पारण तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद से इटाया जाना होगा।
- . ६२. (१) राष्ट्रपति की पदाविध की समाप्ति, से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अविध-समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायेगा ।
- (२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन, रिक्तता होने की तारी के पश्चात् यथासम्भव शीझ और हर अवस्था में छ मास बीतने के पहिले किया जायेगा, तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की [तारी ख से पांच वर्ष की पूरी अविध के लिये पद धारण करने का हक्कदार होगा।

६३. भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।

६४. उपराष्ट्रपति, पदेन, राज्य-परिषद् का सभापति होगा तथा अन्य किसी लाभ का पद धारण न करेगा:

परन्तु जिस किसी कालाविध में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्ये करता है अथवा अनुच्छेद ६५ के अधीन राष्ट्रपति के कुत्यों का निर्वहन करता है तब वह राज्य-परिषद् के सभापति-पद राष्ट्रपतिपद की
रिक्ततापूर्ति के
लिये निर्वाचन करने
का समय तथा
आकस्मिक
रिक्तता-पूर्ति
के लिये
निर्वाचित
व्यक्ति की
पदावधि.

भारत का उपराष्ट्र-पति.

उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य-परिषद् का सभा-पति होना,

भाग ५--संघ--अनु० ६४-६६

के कर्तव्यों को न करेगा तथा उसे अनुच्छेद ९७ के **अधीन** राज्य-परिषद के सभापति को दिये जाने वाले विसी वेतन अथवा भत्ते का हक्क न होगा।

राष्ट्रपति
के पद की
आकस्मिक
रिकतता
अथवा
उसकी
अनुपस्थिति
में उपराष्ट्रपः का
राष्ट्रपति
के रूप में
कार्य करना
अथवा उस
के कृत्यों
का निर्वहन

- ६५. (१) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाये जाने अथवा अन्य कीरण से उस के पद में हुई रिक्तता की अवस्था में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को कि इस अध्याय के ऐसी रिवतता-पूर्ति सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित नया प्राप्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है।
- (२) अनुपास्थात, बामारा अथवा अन्य ।कसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्रपित उस के कृत्यों का निर्वहन उस तारीख तक करेगा जिस तारीख, को कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभासे।
- (३) उपराष्ट्रपति को उस कालाविध में और उस काला-विध के सम्बन्ध में, जब कि वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कर्म्य करता है अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्र-पति की सब शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा उसे ऐसी उप-लिख्यों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जिन्हें संसद् विध द्वारा निश्चित करे, तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो द्वितीय अनुसची में उल्लिखित है हक्क होगा।
- ६६. (१) संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों रके सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गृढ़ शलाका द्वारा होगा।
 - (२) उपराष्ट्रपति न तो संसद् के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का, अथवा किसी राष्ट्रय के विधान-मंडल के सर्दन का, सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाये तो यह

उपराष्ट्र-पति का निर्वाचन.

भाग ५--संघ--अनु० ६६-६७

समझा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

- (३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का प्रात्र न होगा जब तक कि वह—
 - (क) भारत का नागरिक न हो;
 - (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो; तथा
 - (ग) राज्य-परिषद् के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अईता न रखता हो।
- (४) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अभीन कोई लाभ का पढ धारण किये हुए है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा। Massel

व्याख्या.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपित या उपराष्ट्रपित अथवा किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

६७. उपराष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अविध तक पद धारण करेगा:

उपराष्ट्रपति की पदावधि.

परन्तु--

- (क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ता-क्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा;
- (ख) उपराष्ट्रपति, राज्य-परिषद् के ऐसे संकल्प द्वारा, अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे परिषद् के तत्कों- लीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो तथा जिसे लोक-सभा ने स्वीकृत किया हो;

भाग ५--संघ--अनु० ६७-६९

किन्तु इस खंड के प्रयोजन के छिये कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उसे प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम चौदह दिन पूर्व न दे दी गई हो

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि-समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा।

उपराष्ट्रपति
के पद की
रिक्तता-पूर्ति
के लिये
निर्वाचन करने
का समय तथा
आक स्मिक
रिक्त नः पूर्ति
के लिये
निर्वाचित
क्यक्ति की
पदावधि

६८. (१) उपराष्ट्रपति की पदाविध की समाप्ति से हुईं रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अविध समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

(२) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन रिक्तता होने की तारीख के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किया जायेगा तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद ६७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अविध के लिये पद धारण करने का हक्कदार होगा।

६९ प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्र-पति अथवा उसके द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्न रूप में रापथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्—

''मैं, ''अमुक, '' ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उस के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।''

डपराष्ट्रपति डारा शपथ या प्रतिज्ञान.

भाग ५--संघ--अनु० ७० ७२

७०. इस अध्याय में उपविन्धित न की हुई किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिये संसद् जैसा उचित समझे वैसा उपवन्ध बना सकेगी।

- ७१. (१) राष्ट्रपित या उपराष्ट्रपित के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सब शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतमन्यायालय करेगा और उस का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (२) यदि उच्वतमन्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उस के द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्वतमन्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या से पूर्व किये गये कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य न हो जायेंगे।
- (३) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्र-पति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी।
- ७२. (१) किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलम्बन, परिहार या लघूकरण की राष्ट्र-पति को—
 - (क) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय ने दिया हो;
 - (ख) उन सव अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है;
 - (ग) उन सब अवस्थाओं में जिनमें कि दंडादेश मृत्यु का हो,

अन्य आकस्मिकताओं में
राष्ट्रपति के
कृत्यों का
निवंहन.
राष्ट्रपति
या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बनिधत या
संसक्त विषयः

क्षमा, आदि
की तथा कुछ
अभियोगों में
दंडादेश के
निलम्बन,
परिहार या
लघूकरण
करने की
राष्ट्रपति की

शक्ति होगी।

भाग ५--संघ--अनु० ७२-७३

- (२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के । सशस्त्र बलों के किसी पदाधिकारी की सेना-न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की विधि द्वारा दी गई शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।
- (३) खंड (१) के उपखंड (ग) की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रयोग की जाने वाली मृत्यु-दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार.

- ७२. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार—
 - (क) जिन विषयों के सम्बन्ध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उन तक; तथा
 - (ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सर-कार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक,

होगा :

परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में, स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड (क) में उल्लिखित कार्यपालिका शक्ति का विस्तार प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में ऐसे विषयों तक न होगा जिन के बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

(२) जब तक संसद् अन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनु-च्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिन के सम्बन्ध में संसद् को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है ऐसी कार्यपालिकां शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग करता रि रह सकता है जैसे कि वह राज्य या उस का पदाधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कर सकता था।

भाग ५--संघ--अनु० ७४-७६

मन्त्रि-परिषद्

- ७४. (१) राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिस का प्रधान-प्रधान-मंत्री होगा।
- राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद्.
- (२) क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाचन की जायेगी।
- ७५. (१) प्रधान-मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा पर करेगा।

मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्धः

- (२) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे।
- (३) मंत्रि-परिषद् लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- (४) किसी मंत्री के अपने पद-ग्रहण करने से पिहले राष्ट्रपित उस से तृतीय अनुसूची में इस के लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार पद की तथा गोपनीयता की शपथें करायेगा।
- (५) कोई मंत्री जो निरन्तर छ मास की किसी कालाविध तक संसद् के किसी सदन का सदस्य न रहे उस कालाविध की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा।
- (६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे, समय समय पर, संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक संसद् इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।

भारत का महान्यायवादी

७६. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा।

भारत का महान्यायवादी.

भाग ५--संघ--अनु० ७६-७८

- (२) महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर भेजे या सौंपे, तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों।
- (३) अपने कर्तव्यों के पालन के लिये महान्यायवादी को भारत राज्य-क्षेत्र में के सब न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।
- (४) महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा ऐसा पारिश्रमिक पायेगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे।

सरकारी कार्य का संचालन

भारत सरकार के कार्य का संचालन

- ७७. (१) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जायेगी।
- (२) राष्ट्रपति के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उस रीति से किया जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा वनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता पर आपित्त इस आधार पर न की जायेगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।
- (३) भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने के लिये तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के बंटवारे के लिये राष्ट्रपति नियम बनायेगा।

राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि विषयक प्रधान-मंत्री के कर्तव्य.

७८. प्रधान-मंत्री का--

(क) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के समस्त विनिश्चयों तथा विधान के लिये प्रस्थापनायें राष्ट्रपति को पहुंचाने का;

भाग ५--संघ--अनु० ७८-८०

- (ख) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मंगावे उस को देने का; तथा
- (ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपित की अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का,

कर्तव्य होगा।

अध्याय २.--संसद

साधारण

७९. संघ के लिये एक संसद् होगी जो राप्ट्रपित और दो सदनों से मिल कर बनेगी जिन के नाम क्रमशः राज्य-परिषद् और लोक-सभा होंगे।

संसद् का गटन.

८०. (१) राज्य-परिषद्—}

राज्य-परिषद् की रचना.

- (क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (३) के उपबन्धों के अनुसार नामनिर्देशित किये जाने वाले बारह सदस्यों; तथा
- (ख) राज्यों के दो सौ अड़तीस से अनिधक प्रतिनिधियों से, मिल कर बनेगी।
- (२) राज्य-परिपद् में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने बाले स्थानों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तिविष्ट तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार होगा ।
- (३) खंड १ के उपखंड (क) के अधीन राष्ट्रपित द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्—

साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा ।

भाग ५--संघ--अनु० ८०-८१

- (४) राज्य-परिषद् के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धित के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
- (५) राज्य-परिषद् के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जैसी कि संसद् विधि द्वारा विहित करे।

छोक-सभा की रचना.

- ८१. (१) (क) खंड (२) के तथा अनुच्छेद ८२ और ३३१ के जगबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यों में के मतदाताओं द्वारा प्रत्यं रीति से निर्वाचित पांच सौ से अनिधक सदस्यों से मिल कर लीक सभा बनेगी।
- (ख) उपखंड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्वारित की जायेगी जिस से कि यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न होगा।
- (ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये गये सदस्यों की संख्या का, उस निर्वाचन-क्षेत्र की ऐसी अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से, अनुपात भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र यथासाध्य एक ही होगा।

भाग ५--संघ--अनु० ८१-८३

- (२) भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक-सभा में वैसा होगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे।
- (३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में विभिन्न प्र:देशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे:

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का विघटन न हो जाये।

८२. अनुच्छेद ८१ के खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी संसद, विधि द्वारा, लोक-सभा में प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उत्लिखित किसी राज्य के, अथवा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले किन्हीं राज्य-क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस खंड में उपबन्धित आधार या रीति से भिन्न उपबन्ध कर सकेगी।

भाग (ग) प्रें के राज्यों तथा राज्यों से अन्य राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपवन्ध

- ८३. (१) राज्य-परिषद् का विघटन न होगा, किन्तु उस के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई, संसद्-निर्मित विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे।
- (२) लो क-सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालाविध की समाप्ति का परिणाम लोक-सभा का विघटन होगा:

संसद् के सदनों की अवधि.

भाग ५--संघ--अनु० ८३-८५

परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद्, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छ मास की कालाविध से अधिक विस्तृत न होगी।

संसद् की सदस्यता के लिये अहंता. ८४. कोई व्यक्ति संसद् में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि—

- (क) वह भारत का नागरिक न हो;
- (ख) राज्य-परिषद् के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का, तथा लोक-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का,

न हो; तथा

(ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें।

संसद् के सत्तु, सत्तावसाव और विघटन.

- ८५. (१) संसद् के सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायेगा तथा उन के एक सत्त्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्त्र की प्रथम बैठक के लिये नियुवत तारीख के बीच छ मास का अन्तर न होगा।
- (२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति समय समय पर—
 - (क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा;
 - (ख) सदनों का सत्त्रावसान कर सकेगा;
 - (ग) छोक-सभाका विघटन कर सकेगा।

भाग ५--संघ--अनु० ८६-८९

- ८६. (१) संसद् के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।
- (२) राष्ट्रपति संसद् में उस समय लिम्बत किसी विश्रेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश संसद् के किसी सदन को भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार मेजा गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीझता से विचार करेगा।
- .८७. (१) प्रत्येक सत्त्र के आरम्भ में साथ समवेत संसड् के दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद् को उस के आह्वान का कारण बतायेगा।
- (२) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निष्टिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिये, तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने के लिये, उपबन्ध किया जायेगा।
- ८८. भारत के प्रत्येक मंत्रो और महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त वैटक में, तथा संसद् की किसी समिति में, जिस में उस का नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उस को मत देने का हक्क न होगा।

संसद् के पदाधिकारी

- ८९. (१) भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद् का सभापति होगा।
- (२) राज्य-परिषद् यशासम्भव शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त हो तब तब किसी अन्य सदस्य को अपना उप-सभापति चुनेगी ;

सदनों को सम्बोधन करने श्रौर संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार.

संसद् के
प्रत्येक सत्तारम्म में
राष्ट्रपति का
विशेष
अभिभाषण

सदनों विषयक मंत्रियों और महान्याय-वादी के अधिकार.

राज्य-परिषद् के सभापति और उप-सभापति

भाग ५--संघ--अनु० ९०-९१

उपसभापति की पद-रिक्तता, पद-त्याग तथा पद से हटाया जाना.

- ५०. राज्य-परिषद् के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य---
 - (क्) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपना अद रिक्त कर देगा;
 - (ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो सभापित को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा; तथा
 - (ग) परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद् के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

उपसभापति या अन्य व्यक्ति की, सभापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करंने की,

- ९१. (१) जब कि सभापित का पद रिक्त हा, अथवा किसी कालाविध में जब कि उपराष्ट्रपित राष्ट्रपित के रूप में कार्य कर रहा हो अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब उपसभा-पित अथवा, यदि उपसभापित का पद भी रिक्त हो तो, राज्य-पिरिषद् का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपित उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (२) राज्य-परिषद् की किसी बैठक में, सभापित की अनुपस्थित में उपसभापित, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निर्धारित करे, सभापित के रूप में कार्य करेगा।

भाग ५--संघ--अनु ० ९२-९४

९२. (१) राज्य-परिषद् की किसी बैठक मं, जब उपराष्ट्र-पित को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापित, अथवा जब उपसभा ित को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापित, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९१ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिस में कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थित सभापित या उपसभापित अनुपस्थित है। जब उस के
पद से हटाने
का संकल्प
विचाराधीन
हो तब सभापति या उपसभापति
पीठासीन न
होगा.

(२) जब कि उपराष्ट्रपित को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प राज्य-परिषद् में विचाराधीन हो तब सभापित को परिषद् में बोळने तथा दूसरी प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, मत देने का बिल्कुल हक्क न होगा।

९३. लोक सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को कमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

लोक-सभा का अध्यक्ष ग्रौर उपाध्यक्ष.

- ९४. लोक-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य--
 - (क) यदि लोक-सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा;
 - (ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा; तथा

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिक्तता, पदत्यागृतथा पद से हटाया जानाः

भाग ५--संघ--अनु ० ९४-९६

(ग) लोक-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित ने किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो:

परन्तु यह और भी कि जब कभी लोक-सभा का विघटन किया जाये तो विघटन के पश्चात् होने वाले लोक-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पिहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्स न करेगा।

- ९५. (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो, लोक-सभाका ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्राति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (२) लोक-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थित में उपाध्यक्ष, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- ९६. (१) लोक-सभा की किस्मी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९५ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिस में कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।

अध्यक्ष-पद के ्रेंडिय-प्रस्मा छो, अथवा खध्यक्ष के रूप में कार्य करने की, उपाध्यक्ष या अन्य ख्यक्ति की शक्ति

जब उस के पद
से हटाने का
संकल्प
विचाराधीन
हो तब अध्यक्ष
या उपाध्यक्ष
खोक-सभा को
बैठकों में
पीठासीन न

भाग ५--संघ--अनु ० ९६-९८

- (२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प लोक-सभा में विचाराधीन हो तब उस को लोक-सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु मतसाम्य होने की दशा में न होगा।
- ९७. राज्य-परिषद् के सभापित और उपसभापित को, तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे क्रमशः संसद् विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उहिलखित हैं, दिये जायेंगे।

९८. (१) संसद् के प्रत्येक सदन का अपना पृथक् साचिवक कर्मचारी वृन्द होगा: सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्त और उपाध्यक के वेतन और

संसद् काः सचिवालयः

परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह संसद् के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सुजन को रोकती है।

- (२) संसद्, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन के साचिवक कर्मचारी वृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्ती का, विनियमन कर सकेगी ।
- (३) खंड (२) के अधीन जब तक संसद् उपवन्ध नहीं करती तब तक राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक-सभा के अध्यक्ष से, या राज्य-परिषद् के सभापति से परामर्श कर के लोक-सभा के या राज्य-परिषद् के साचिवक कर्मचारी वृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन वनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

भाग ५--संघ--अनु० ९९-१००

कार्य संचालन

सदस्यों द्वारा श्वपथ या प्रतिज्ञान ९९. संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान
ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपित के अथवा राष्ट्रपित द्वारा उस लिये
नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये
दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस
पर हस्ताक्षर करेगा।

सदनों में मत-दान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणप्रति. १००. (१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर किसी सदन की किसी बैठक में अथवा सदनों की संयुक्त बैठक में सब प्रदनों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापित अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर उपस्थित तथा मित देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

सभापित या अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, किन्तु मतसाम्य की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उस का प्रयोग करेगा।

- (२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी संसद् के किसी सदन को कार्य करने की शिक्त होगी, तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति, जिसे ऐसा करने का हाक न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी संसद् में की कोई कार्यवाही मान्य होगी।
- (३) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपविन्धित न करे तब तक संसद् के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश होगी।
- (४) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो सभापित या अध्यक्ष अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थिगित कर देया अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर देजब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।

भाग ५--संघ--अनु० १०१ सदस्यों की अनर्हतायें

१०१. (१) कोई व्यवित संसद् के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यवित दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिवत करने के लिये संसद् विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगी। स्थानों की रिक्तता.

- (२) कोई व्यक्ति संसद् तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने राज्य के विधान-मंडल में के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो।
 - (३) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य---
 - (क) अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में विणित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है; अथवा
 - (ख) यथास्थिति सभापित या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,
- ं तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिवत हो जायेगा।
 - (४) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के विना उस के सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा:

परन्तु साठ दिन की उक्त कालाविध की संगणना में किसी ऐसी कालाविध को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्ताविसत अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहा है।

भाग ५--संघ--अनु० १०२ १०३

सदस्यता के लिये अनर्हतायें.

- १०२. (१) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनई होगा--
 - (क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनई न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है;
 - (ख) यदि वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
 - (ग) यदि वह अनुनमुक्त दिवालिया है;
 - (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषवित को अभिस्वीकार किये हुए है;
 - (ङ) यदि वह संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वाराया अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है।
- (२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन,

- १०३. (१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उस का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

भाग ५--संघ--अनु० १०४-१०५

१०४. यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में अनुच्छेद ९९ की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि मैं उस की सदस्यता के लिये अर्ह नहीं हूं अथवा अर्ह कर दिया गया हूं अथवा संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के उपवन्धों से ऐसा करने से प्रतिपिद्ध कर दिया गया हूं, बैठता या सतदान करता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिये, जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है पांच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा।

अनु च्छेद ९९ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करनें से पूर्व अथवा अर्हे न होते हुए अथवा अनर्हे किये जाने पर बैठने, और मत देने के लिये दंड.

संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार श्रौर उन्मुक्तियां

- १०५. (१) इस संविधान के उपवन्धों के तथा संसद् की प्रक्रिया के विनियासक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद् में वांक्-स्वातन्त्र्य होगा।
- (२) संसद् या उस की किसी सिमिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संसद् के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी।
- (३) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी संसद्. समय समय पर, विधि हारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगीं जो इस सविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पालियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उस के सदस्यों और समितियों की हैं।

संसद् क सदनों की तथा उस के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधि-कार आदि.

भाग ५--संघ--अनु० १०५-१०७

(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधाः पर संसद् के किसी सदन अथवा उस की किसी समिति में बोलने का, अधवा अन्य प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उन के सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं।

सदस्यों के वेतन और भत्ते. १०६. संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें संसद्, विधि द्वारा, समय समय पर, निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता तब तक ऐसे भत्तों को, ऐसी दरों से और ऐसी शतों पर, जैसी कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले लागू थीं, पाने का हक्क होगा।

विधान प्रक्रिया

विधेयकों के प्रःस्थापन और पारण विषयक उपवन्ध.

- १०७. (१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय-विधेयकों के विषय में अनुच्छेद १०९ और ११७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद् के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा।
- (२) अनुच्छेद १०८ और १०९ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद् के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा अब तक कि, या तो विना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो।
- (३) संसद् में लम्बित विधेयक [सदनों के सत्तावसान के कारण व्यपगत न होगा।
- (४) राज्य-परिषद् में लिम्बत्र विधेयक, जिस को लोक-सभा ने पारित नहीं किया है, लोक-सभा के विघटन पर व्यपगत न होगा।

भाग ५--संघ--अनु० १०७-१०८

- (५) कोई विधेयक, जो लोक-सभा में लम्बित है, अथवा, जो लोक-सभा से पारित हो कर राज्य-परिषद् में लम्बित है, अनुच्छेद १०८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक-सभा के विघटन पर व्यपगत हो जायेगा।
- १०८. (१) यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने तथा दूसरे सदन को पहुंचाये जाने के पश्चात्--
 - (क) दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है; अथवा
 - (ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो चुके हैं; अथवा
 - (ग) विधेयक-प्राप्ति की तारीख से, विना इस को पारित किये, दूसरे सदन को छ मास से अधिक बीत चुके हैं,

तो लोक-सभा के विघटन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर पर्यालोचन करने और मत देने के प्रयोजन के लिये संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत करने के अभिप्राय की अधिसूचना सदनों को, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा, अथवा यदि बैठक में नहीं हैं तो लोक-अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति देगा:

परन्तु इस खंड में की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू न होगी।

- (२) ऐसी किसी छ मास की कालाविध की संगणना में, जो कि खंड (१) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी कालाविध को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में उक्त खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन सत्ताविसत अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहता है।
- (३) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशनं के लिये आहूत करने के अभिप्राय को जब राष्ट्रपति खंड (१) के अधीन अधिसूचित कर चुका हो, तो कोई सदन विधेयक पर आगे

किन्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैटक.

भाग ५--संघ--अनु० १०८

कार्यवाही न करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अधिसूचना की तारीख के पश्चात् किसी समय सदनों को अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिये संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत कर सकेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार अधिवेशित होंगे।

(४) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिन को संयुक्त बैठक में स्वीकार कर लिया गया है, दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से, पारित हो जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये वह दोनों सदनों से पारित समझा जायेगा:

परन्तु संयुक्त बैठक में---

- (क) यदि विधेयक एक सदन से पारित हो कर दूसरे सदन द्वारा संकोधनों सहित परित नहीं किया गया है तथा उस सदन को, जिस में वह आरम्भित हुआ था, लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों के सिवाय (यदि कोई हों), जो कि विधेयक के पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, विधेयक पर कोई और संशोधन प्रस्थापित न किया जायेगा:
- (ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लौटाया जा चुका है तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन, जैसे कि ऊपर कथित हैं, तथा ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन पर सदनों में सहमित नहीं हुई है, प्रस्थापित किये जायेंगे;

और पीठासीन व्यवित का विनिश्चय, कि इस खंड के अधीन कौन से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा।

(५) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिये आहूत करने के अभिप्राय की राष्ट्रपति की अधिसूचना

भाग ५--संघ--अनु० १०८-१०९

के पश्चात्, यद्यपि लोक-सभा का विघटन बीच में हो चुका है तो भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी तथा उस में विधेयक पारित हो सकेगा।

- १०९. (१) राज्य-परिषद् में धन-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा।
- (२) लोक-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, धन-विधेयक, राज्य-परिषद् को, उस की सिपारिशों के लिये पहुंचाया जायेगा तथा राज्य-परिषद्, विधेयक की अपनी प्राप्ति की तारीख़ से चौदह दिन की कालाविध के भीतर, विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित लोक-सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर लोक-सभा राज्य-परिषद् की सिपारिशों में से सब को या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।
- (३) यदि राज्य-परिषद् की सिपारिशों में से किसी को लोक-सभा स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक राज्य-परिषद् द्वारा सिपारिश किये गये तथा लोक-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा।
- (४) यदि राज्य-परिषद् की सिपारिशों में से किसी को भी लोक-सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, राज्य-परिषद् द्वारा सिपारिश किये गये संशोधनों में से किसी के विना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस में कि वह लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था।
- (५) यदि लोक-सभा द्वारा पारित तथा राज्य-परिषद् को उस की सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धन-विधेयक उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर लोक-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर यह दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में लोक-सभा ने उस की पारित किया था।

धन-विधेयको विषयक विशेद प्रक्रियाः

भाग ५--संघ--अन्० ११०

धन-विधेयकों की परिभाषा.

- ११०. (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट ही हैं, अर्थान्—
 - (क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियमन:
 - (ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत सरकार द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, विनियमन;
 - (ग) भारत की संचित-निधि अथवा आकरिमकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उस में से धन निकालना ;
 - (घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;
 - (ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना;
 - (च) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक-लेखे के मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षाया निकासी करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओं का लेखा-परीक्षण; अथवा
 - (छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।
- (२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञष्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के

भाग ५--संघ--अनु० ११०-१११

लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

- (३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर लोक-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा :
- (४) अनुच्छेद १०९ के अधीन जब धन-विधेयक राज्य-परिषद् को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद १११ के अधीन अनुमति के लिये राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर लोक-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन-विधेयक है।
- १११. जब संसद् के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है:

विषेयकों पक अनुमति

परन्तु राष्ट्रवित अनुमित के लिये अपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, सदनों को संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे उस विधेयक पर अथवा उस के किसी उल्लिखित उपवन्त्रों पर पुनर्विचार करें तथा विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरः-स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उस ने अपने संदेश में सिपारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष अनुमित के लिये रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमित न रोकेगा।

भाग ५--संघ--अनु ० ११२

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

वाषिक-वित्त-विवरण.

- ११२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपित भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्राक्किलत प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक-वित्त-विवरण" नाम से निर्दिष्ट किया गया है।
- (२) वार्षिक-वित्त-विवरण में दिये हुए व्यय की प्राक्कलनों में—
 - (क) जो व्यय इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित है उस की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां; तथा
- (ख) भारत की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां, पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी तथा राजस्व-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा।
- (३) निम्नवर्ती व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा—
 - (क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय ;
 - (ख) राज्य-परिषद् के सभापित और उपसभापित तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;
 - (ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व भारत सरकार पर है, जिन के अन्तर्गत व्याज, निक्षेप-निधि-भार और मोचन-भार तथा उधार लेने और ऋण-सेवा और ऋण-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं;

भाग ५--संघ--अनु० ११२-११३

- (घ) (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतनृ;
- (२) फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों को, या के वारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन ;
- (३) जो उच्चन्यायालय भारत राज्य-क्षेत्र में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी प्रांत में के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था उस के न्यायाधीशों को, या के बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन;
- (ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के, या के बारे-में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन;
- (च) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई राशियां;
- (छ) इस संविधान द्वारा, अथवा संसद् से विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।
- ११३. (१) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलनें संसद् में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह संसद् के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा को रोकती है।
- (२) उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे लोक-सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखी जायेंगी तथा लोक-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार

संसद् में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया.

भाग ५--संघ --अनु० ११३-११५

या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उिल्लिखित राशि को कम कर के, स्वीकार करे।

(३) राष्ट्रपति की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी।

विनियोग-विषेयक.

- ११४. (१) लोक-सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीझ भारत की संचित निधि में से——
 - (क) लोक-सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की; तथा
 - (ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किन्तु संसद् के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राजि से किसी भी अवस्था में अनिधिक, व्यय की,

पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जायेगा।

- (२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेर-फार करने, अथवा अनुदान के लक्ष्य की बदलने, अथवा भारत की संखित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक पर, संसद् के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (३) अनुच्छेद ११५ और ११६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।

अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान.

- ११५. (१) यदि---
 - (क) अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित वि.सी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष

माग ५--संघ--अनु० ११५-११६

के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक-वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है; अथवा

(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये, अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्किलत की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा लोक-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

- (२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में, तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग के बारे में, अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद ११२, ११३ और ११४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण तथा उस में विणित व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।
- ११६. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उगबन्धों में किसी बात के होते हुए भी लोक-सभा को—
 - (क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, ऐसे अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद ११३

लेखानुदान, १ त्ययानुदान श्रीर अपवा-दानुदान.

भाग ५--संघ--अनु० ११६-११७

में विहित प्रिक्तिया की पूर्ति के लिम्बित रहने तक, तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लिम्बत रंहने तक, पेशगी देने की;

- [(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित
 हम के कारण मांग वैसे व्योरे के साथ वर्णित क्र
 नहीं की जा सकती जैसा कि वार्षिक-वित्तविवरण में साधारणतया दिया जाता है तब
 भारत के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की
 पूर्ति के लिये अनुदान करने की;
 - (ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा कोई अपदाद नुदान करने की,

शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उन के लिये भारत की सचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति संसद् को होगी।

(२) खंड (१) के अवीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद ११३ और ११४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बना जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

वित्त -विषेयकों के लिये विशेष उपबन्ध. ११७. (१) अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (च) तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिपारिश के विना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक राज्य-परिषद् में पुरःस्थापित न किया जायेगाः

भाग ५--संघ--अनु० ११७-११८

परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिये उपवन्ध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी।

- (२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनु- ज्ञाप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।
- (३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद् के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिपारिश न की हो।

साधारणतया प्रक्रिया

११८. (१) इस संविधान के उन्बन्धों के अधीन रहते हुए संसद् का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने कार्य-संचालन के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगा। प्रक्रिया के नियम.

- (२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के विधान-मंडल के बारे में जो प्रिक्तिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों और अनुकूलनों के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य-परिषद् का सभापित या लोक-सभा का अध्यक्ष करे, संसद के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे।
- (३) राज्य-परिषद् के सभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष के परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त

भाग ५--संघ--अनु० ११८-१२०

बैठकों सम्बन्धी, तथा उन में परस्पूर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

(४) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा उस की अनुपस्थित में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिस का खंड (३) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार निर्धारण हो ।

संसद् में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन. ११९ वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से संसद, विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से, अथवा भारत को संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से, सम्बन्धित संसद् के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगी, तथा यदि, और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का उपबन्ध अनुच्छेद ११८ के खंड (१) के अधीन संसद् के किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन संसद् के संबंड (२) के अधीन संसद् के संबंड (२) के अधीन संसद् के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम [या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा।

संसद् में प्रयोग होने वाली भाषा. १२०. (१) भाग (१७) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा :

परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद् का सभापित या लोक-सभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालाविध की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उस में से लुप्त कर दिये गये हैं।

भाग ५ --संघ--श्रनु० १२१-१२३.

१२१. उच्चतमन्यायालय या उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश्च को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद् में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में न होगी।

संसद् में चर्चा पर निबंन्धन.

१२२. (१) प्रिक्रिया में किसी कथित अनियमिता के आधार पर संसद् की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी।

न्यायालय संसद् की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे.

(२) संसद् का कोई पराधिकारी या सदस्य, जिस में इस संविधान के द्वारा या अधीन संसद् में प्रक्रिया को, या कार्य-संचालन को, विनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की, शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा '

अध्याय ३.--राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां

१२३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद् के दोनों सदन सत्त्र में हैं यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाबित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।

संसद् के विश्वान्तिकाल में राष्ट्रपति की अध्यादेश _
प्रस्थापनशक्ति.

- (२) इस अनुच्छेद के अशीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश——
 - (क) संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा, तथा संसद् के पुनः समवेत होने से छ सप्ताह

भाग ५ --संघ--अनु ० १२३-१२४

की समाप्ति पर, अथवा, यदिन उस कालाविध की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उस के निरनु-मोदन के संकल्प पार कर देते हैं तो, इन में दूसरे से संकल्प के पारण होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा; तथा

- (ख) राष्ट्रपित द्वारा किसी समय लौटा लिया जा सकेगा।

 व्याख्या.—जब संसद् के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः
 समवेत, होने के लिये आहूत किये जाते हैं तो इस खंड के
 प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की कालाविध की गणना उन तारीखों
 में से पिछली तारीख से की जायेगी।
- (३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपवन्ध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिये संसद् इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो वह शून्य होगा।

अध्याय ४ -- संघ की न्यायपालिका

उच्च तम + न्यायालय की स्थापना और गठन •

- १२४. (१) भारत का एक उच्चतमन्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा, जब तक संसद् विधि द्वारा और अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती तब तक, अन्य सात से अनिधक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।
- (२) उच्चतमन्यायालय के, तथा राज्यों के उच्चन्याया-लयों के, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिन से कि इस श्रयोजन के लियं परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्र-पति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम-न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले:

परन्तु मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से सर्वेदा परामर्शे किया जायेगा:

भाग ५-- संघ-- अनु० १२४

परन्तु यह और भी कि-

- (क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा:
- (ख) खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्याया-धीश अपने पद से हटाया जा सकेगा।
- (३) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तत्र तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा—
 - (क) किसी उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश न रह चुका हो; अथवा
 - (ख) किसी उच्चन्यायालय का, अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का, लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो; अथवा
 - (ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता न हो । पारता ९ — इस खाइ में "उच्चन्यायाल्य" से वह उच्च-

व्याख्या १.— इस खण्ड में "उच्चन्यायालय" से वह उच्चन्यायालय अभिप्रेत है जो भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय भी, प्रयोग करता था।

व्याख्या २.— इस खंड के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति के अधिववता रहने की कालाविध की संगणना में वह काला-विध भी अन्तर्गत होगी जिस में कि उस व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ऐसे न्यायिक पद को जो जिला-न्यायाधीश के पद से छोटा नहीं है, धारण किया हो।

(४) उच्चतमन्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक हटाया न जायेगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा भाग ५--संघ--अनु० १२४-१२५

असमर्थता के लिये ऐसे हटाये जाने के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सन् में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो।

न्यायाधीशों के वेतन आदि.

- १२५. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे नेतन दिये जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिख़ित हैं।
- (२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेपाधिकारों और भत्तों का, तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधि-कारों का, जैसे कि संतद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधि-

भाग ५--संघ--अनु० १२५-१२७

कारों ना, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उित्लिखित हैं, हक्क होगा:

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो विशेषाधिकारों में और न भनों में और न अनुपस्थिति-छृट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चान् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।

- १२७. (१) यदि किसी समय उच्चतमन्द्रायालय के मन् की करने या चालू रखने के लिये उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्य न हो तो राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से तथा सम्बद्ध उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श कर के भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी उच्चन्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश में, जो उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये एथारीति धर्ह है तथा जिसे भारत का मुख्य यायाधिकि के लिये न्यायाधिक करे, न्यायालय की बैठकों में इतनी कालाविध के लिये, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ-न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिये लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेगा।
- (२) इस प्रकार नामोद्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्ववर्तिता देकर उच्चतमन्यायालय की बैठकों में, उस समय, तथा उस कालावधि के लिये, जिस के लिये उस की उपस्थित अपेक्षित है, उपस्थित हो, तथा जब वह इस प्रकार उपस्थित हो तब उस को उच्चतमन्यायालय के न्याया-धीश के, सब अत्राधिकार, शक्तियां और विशेपाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

तदयं न्यायाधीशों की नियुक्तिः

भाग ५--संघ--अनु० १२८-१३१

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम-न्यायालयों की बैठकों में उपस्थिति. १२८. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतमन्यायालय के, या फेडरलन्यायालय के, न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतमन्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्राधित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शिक्तियों और विशेषाधिकारों का, हक्क होगा किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा:

परन्तु जब तक पूर्वोवत कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी।

उच्चतमन्या-यालय अभि-लेख न्याया-लय होगा.

उच्चत्तमन्या-यालय का स्थान

उच्चतमन्या-यालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार. १२९. उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियां होंगी।

१३०. उच्चतमन्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे, बैठेगा।

१३१. इस संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते हुए--

- (क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के; अथवा
- (ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के वीच के; अथवा
- (ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के, किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस

भाग ५--सघ--अनु० १३१-१३२

पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है वहां तक, अन्य न्यायालयों का अपवर्जन कर के उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा:

परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जिस में:---

- (१) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, संविदा, वचन-वंध, सनद या अन्य तत्सम लिखत के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की गई या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है या रख ली गई है, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ है।
- (२) कोई राज्य एक पक्ष है, यि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बंध, सनद या अन्य तत्सम लिखत के, जो उपबन्ध करती है कि वैसा क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ है।
- १३२. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक चाहे दांडिक चाहे अन्य कार्यवाही में दिये निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में हो सकेगी यदि वह उच्चन्य।यालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रंस्त है।
- (२) जहां कि उच्चन्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर दिया हो वहां, यदि उच्चतमन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है तो, वह ऐसे निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा।

किन्हीं मामलों में उच्च-न्यःयालयों से अपील में उच्चतम-न्यःयालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार.

भाग ५--संघ--अनु० १२८-१३१

सेवानिवत्त न्यायाधीशों की उच्चतम-न्यायालयों की बैठकों में उपस्थिति.

१२८. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतमन्यायालय के, या फेडरलन्यायालय के, न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतमन्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को. इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्घारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियों और विशेषाधिकारों का, हक्क होगा किन्तु वह अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश न समझा जायेगा :

परन्तु जब तक पूर्वीवत कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी।

उच्चतमन्या-यालय अभि-लेख न्याया-

लय होगा.

उच्चत्तमन्या-यालय का स्थान.

उच्चतमन्या-यालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार.

१२९. उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियां होंगी।

१३०. उच्चतमन्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे, बैठेगा।

१३१ इस संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते हए--

- (क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के: अथवा
- (ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के; अथवा
- (ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के, किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस

भाग ५--सघ--अनु० १३१-१३२

पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है वहां तक, अन्य न्यायालयों का अपवर्जन कर के उच्चतमन्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राविकार होगा:

परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जिस में :---

- (१) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, संविदा, वचन-वंध, सनद या अन्य तत्सम लिखत के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की गई या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है या रख ली गई है, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ है।
- (२) कोई राज्य एक पक्ष है, यि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-वंध, सनद या अन्य तत्सम लिखत के, जो उपवन्ध करती है कि वैसा क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, किसी उपवन्ध से पैदा हुआ है।
- १३२. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक चाहे दांडिक चाहे अन्य कार्यवाही में दिये निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में हो सकेगी यदि वह उच्चन्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।
- (२) जहां कि उच्चन्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना अस्वीकार कर दिया हो वहां, यदि उच्चतमन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन का सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है तो, वह ऐसे निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा।

किन्हीं मामलों में उच्च-न्यायालयों से अपील में उच्चतम-न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार.

भाग ५--संघ--अनु० १३२-१३३

(३) जहां ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा ऐसी इजाजत दे दी गई हो वहां मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी पूर्वोक्त प्रश्न के अशुद्ध निर्णय हो जाने के आधार पर, तथा उच्चतम-न्यायालय की इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उच्चतम-न्यायालय में अपील कर सकेगा।

व्याख्या,—इस अन्च्छेद के प्रयोजनार्थं "अन्तिम आदेश" पदावली के अन्तर्गत ऐसे वाद-पद कः विनिश्चयात्मक आदेश भी है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित हो तो, उस मामले के अन्तिम निबटारे के लिये पर्याप्त होगा।

उच्वन्यायालयों
से व्यवहार
विषयों के बारे
की अपीलों में
उच्चतमन्यायालय का
अपीलीय
सेताधिकार.

१३३. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के उच्चन्यायालय की व्यवहार-कार्यवाही में के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में होगी यदि उच्च-न्यायालय प्रमाणित करे—

- (क) कि विवाद-विषय की राशिया मूल्य प्रथम बार के न्यायालय में बीस हजार रुग्ये सेया ऐसी अन्य राशि से, जो इस बारे में संसद् से विधि द्वारा उल्लिजित की जाये, कम न थी और अपील-गत विवाद में भी उस से कम नहीं है; अथवा
- (ख) कि निर्णय, आज्ञिष्ति या अन्तिम आदेश में उतनी राशि या मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई दावा या प्रश्न प्रत्यक्ष या परोत्त रूप मे अन्तर्ग्रस्त हैं; अथवा
- (ग) कि म:मला उच्चतमन्यायालय में अपील के लायक है,

तथा, जहां कि अपीलकृत निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश उपखंड (ग) में निर्दिष्ट मामले से भिन्न किसी मामले में विनान्तर नीचे के न्यायालय के वििनश्चय की पुष्टि करता है

भाग ५---संघ--अनु० १३३-१३४

वहां, यदि उच्चन्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि अपील में कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

- (२) अनुच्छेद १३२ में किसी बात के होते हुए भी खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय में अपील करने वाला कोई पक्ष ऐसी अपील के कारणों में यह कारण भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के सारवान विधि-प्रक्रन का अशुद्ध विनिश्चय किया गया है।
 - (३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में न होगी जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे।
 - १३४. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, किसी दंड-कार्यवाही में दिये हुए निर्णय, अन्तिम आदेश या दंडादेश की उच्चतमन्यायालय में अपील होगी यदि—
 - (क) उस उच्चन्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त है व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उस को मृत्यु-दंडादेश दिया है; अथवा
 - (ख) उस उच्चन्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से किसी मामले को परीक्षण करने के हेतु अपने पास मंगा लिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहरायया है और मृत्यु-दंडादेश दिया है; अथवा
 - (ग) उच्चन्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतमन्यायालय में अपील किये जाने लायक है:

परन्तु उपखंड (ग) के अधीन होने वाली अपील ऐसे उप-बन्धों के अधीन रह कर, जो अनुच्छेद १४५ के खंड (१) के दंड विषयों में उच्चतमन्या-यालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार.

भाग ५--संघ--अनु० १३४-१३६

अधीन उस लिये बनाये जायें तथा ऐसी कार्तों के अधीन रह कर जो उच्चन्यायालय द्वारा स्थापित या अपेक्षित की जायें, ही होगी।

(२) संसद् विधि द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन, जो ऐसी विधि में उिल्लिखित की जायें, उच्चतमन्याया-लय को भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के दंड-कार्यवाही में दिये गये किसी निर्णय, अन्तिम आदेश अथवा दंडा-देश की अपील लेने और सुनने की और भी शक्ति दे सकेगी।

वर्तमान विधि
के अधीन
फेडरलन्यायालय का
क्षेत्राधिकार
श्रीर शक्तियों
का उच्चतमन्यायालय
द्वारा प्रयोक्तब्य होना

१३५. जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धन करे तब तक उच्चतमन्यायालय को भी किसी विषय के बारे में जिस पर अनुच्छेद १३३ या अनुच्छेद १३४ के उपबन्ध लागू नहीं होते, क्षेत्राधि-कार और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के सम्बन्ध में इस संवि-धान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी वर्तमान विधि के अधीन क्षेत्राधिकार और शक्तियां फेडरलन्यायालय द्वारा प्रयोवतव्य थीं।

अपील के लिये उच्चतमन्या-यालय की विशेष इजा-जत.

- १३६. (१) इस अध्याय में किसी वात के होते हुए भी उच्चतम-न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय में दिये हुए किसी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिये विशेष इजाजत दे सकेगा।
- (२) सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या दत्त किसी निर्णय, निर्धारण, दंडादेश या आदेश को खंड (१) की कोई बात लागून होगी।

भाग ५--संघ--अनु० १३७-१४०

१३७. संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपवन्धों के, अथवा अनुच्छेद १४५ के अधीन बनाये गये किसी नियम के, अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय या दिये गये आदेश पर पुनिवलोकन करने का अधिकार होगा।

निर्णयों या आदेशों पर उच्चतम-न्यायालय द्वारा पुनर्वि-लोकन.

१३८. (१) संघ-सृची के विषयों में से किसी के बारे में उच्च-तमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी जैसे संसद् विधि द्वारा प्रदान करे।

उच्चतम-न्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धिः

(२) यदि संसद् न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और शिक्तयों के प्रयोग का विधि द्वारा उपबन्ध करे तो किसी विषय के , बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शिक्तयां होंगी जिन्हें भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे।

१३९: अनुच्छेद ३२ के खंड (२) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश, आदेश या लेख जिन के अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा इन में से किसी को, निकालने की शक्ति संसद् विधि द्वारा उच्चतमन्यायालय को प्रदान कर सकेगी

कुछ लेखों के निकालने की शक्ति का उच्चतम-न्यायालय को प्रदान.

१४०. ऐसी अनुपूरक शक्तियों को, जो इस संविधान के उप-बन्धों में से किसी से असंगत न हों, संसद् विधि द्वारा उच्च-तमन्यायालय को प्रदान करने के लिये उपवन्ध कर सकेगी, जैसी कि उस न्यायालय को इस संविधान के द्वारा या अधीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक कार्य-साधक रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों!

उच्चतम न्या-यालय की सहायक शक्तियां.

भाग ५--संघ--अनु० १४१-१४३

उच्चतमन्यायालय द्वारा
घोषित विधि
सबन्यायालयों
को बन्धनकारी होगी.

१४१. उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी।

उच्चतमन्यायालय की आक्राप्तियों और
आदेशों का
प्रवृत्त कराना
तथा प्रकटन
आदि
के आदेश.

- १४२. (१) अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्चतमन्यायालय ऐसी आजिप्त या ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि उस के समक्ष लिम्बित किसी बाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक हो तथा इस प्रकार दी हुई आजिप्त या आदेश भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जैसी कि संयद् किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित करे, तथा, जब तक उस लिये उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक, ऐसी रीति से, जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा।
- (२) संसद् द्वारा इस बारे में बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के, अथवा अपने किसी अवमान का अनुसंधान कराने या दंड देने के, प्रयोजन के लिये कोई आदेश देने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी।

उच्चतमन्यायालय से
परामर्श करने
की राष्ट्रपति
की शक्ति.

- १४३. (१) यदि किसी समय राष्ट्रपित को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है. अथवा उस के उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो इन प्रकार का और ऐसे सार्वजिनक महत्त्व का है कि उस पर उच्चतमन्यायालय की राय प्राप्त करना इष्टकर है, तो वह उस प्रश्न को उस न्यायालय को विचारार्थ सौंप सकेगा तथा वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपित को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।
- (२) राष्ट्रपति, अनुच्छेद १३१ के परन्तुक के खंड (१) में , किसी बात के होते हुए भी, उक्त खंड में वर्णित प्रकार के विवाद

भाग ५--संघ--अनु० १४३-१४५

को उच्चतमन्यायालय को राय देने के लिये सौंप सकेगा तथा उच्चतमन्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपि। राय प्रतिवेदित करेगा।

१४४. भारत राज्य-क्षेत्र के सभी असैनिक और न्यायिक प्राधि-कारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।

असैनिक तथा
न्यायिक
प्राधिकारी
उच्चतमन्यायालय की
सहायता में
कार्य करेगे.
न्यायालय के
नियम आदि.

- १४५. (१) संसद् द्वारा वनाई हुई किसी विधि के उपवन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय, समय समय पर, राष्ट्रपित के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के साधारण विनियमन के लिये नियम बना सकेगा तथा जिन के अन्तर्गत—
 - (क) उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम;
 - (ख) अपीलें सुनने के लिये प्रिक्तिया के बारे में, तथा अपीलों सम्बन्धी अन्य विषयों के, जिन के अन्दर्गत वह समय भी है जिस के भीतर अपीलें न्यायालय में दाखिल की जानी हैं, बारे में नियम ;
 - (ग) भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी की पूर्ति कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम ;
 - (घ) अनुच्छेद १३४ के खंड (१) के उखंपड (ग) के अधीन अपीलों के लिये जाने के बारे में नियम;
 - (ङ) उस न्यायालय द्वारा मुनाया गया कोई निर्णय अथवा दिया गया आदेश जिन शर्तो के अधीन रह कर पुनर्विलोकित किया जा सकेगा उन के बारे में. तथा

भाग ५--संघ--अनु० १४५

ऐसे पुनर्विलोकन के लिये प्रिक्तिया के बारे में, जिस के अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिये आवेदन-पत्र न्यायालय में दाखिल किये जाने हैं, नियम;

1

- (च) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों में के और तत्प्रासंगिक खर्चें के बारे में, तथा उसमें कार्यवाहियों के विषय में ली जाने वाली फीसों के बारे में, नियम;
- (छ) । मिन की मंजूरी के बारे में नियम;
- ' (ज) कार्यवाहियों के रोकने के बारे में नियम;
 - (झ) ऐसी अपील जो उस न्यायालय को तुच्छ या तंग करने वाली अथवा विलम्ब करने के प्रयोजन से की हुई प्रतीत्रहोती है उस के संक्षेपतः निर्धारण के लिये उपबन्धन करने वाले नियम;
 - (अ) धनुच्छेद ३१७ के खंड हू (१) में निर्दिष्ट जांचों के लिये प्रक्रिया के बारे में नियम:

भी हैं।

- (२) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अनुच्छेद के अधीन बने नियम, उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिये बैठेंगे तथा, अकेले न्यायाधीशों और खंड-न्यायालयों की शक्ति के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।
- (३) इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न जिस मामले के अन्तर्ग्रस्त है उस का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये, अथवा इस संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन सौंपे गये प्रश्न सुनने के प्रयोजन के लिये, बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होगी:

परन्तु जहां इस अध्याय में के अनुच्छेद १३२ से भिन्न उपबन्धों के अधीन अपील सुनने वाला न्यायालय पांच न्याया-

भाग५--संघ--अनु० १४५-१४६

धीशों से कम से मिल कर बना है तथा अपील सुनने के दौरान में उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में संविधान के निर्वचन का ऐसा सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्गस्त है जिस का निर्धारण अपील के निवटारे के लिये आवश्यक है, वहां वह न्यायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को, जो ऐसे प्रश्न को अन्तर्गस्त रखने वाले किसी मामलें के विनिश्चय के लिये इस खंड द्वारा अपेक्षित रूप में गठित किया जाये, उस की राय के लिये सौंपेगा तथा राय की प्राप्ति पर उस अपील को वैसी? राय के अनुसार निबटायेगा।

- (४) उच्चतमन्यायालय कोई निर्णय खुले न्यायालय में के सिवाय नहीं सुनायेगा तथा अनुच्छेद १४३ के अधीन कोई प्रतिवेदन खुले न्यायालय में ही सुनाई गई राय से अन्यथा न दिया जायेगा।
- (५) कोई निर्णय और ऐसी कोई रायं उच्चतमन्यायालय द्वारा, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों में के बहु-संख्यक की सहमति से अन्यथा, न दी जायेगी किन्तु इस खंड की कोई बात सहमत न होने वाले किसी न्यायाधीश को अपने विमत-निर्णय या राय देने से न रोकेगी।
- १४६ (१) उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा निदेशित उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा:

उच्चतमन्यायालय के
पदाधिकारी
और सेवक
तथा व्यय-

परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से संसक्त किसी पद पर, संघलोकसेवा-आयोग से परामर्श किये विना, नियुक्त न किया जायेगा।

भाग ५--संघ--अनु० १४६-१४७

(२) संसद् द्वारा निर्मित विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शतें ऐसी होंगी जैसी कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विहित करे:

परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, जहां तक कि वे वेतनों, भक्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से सम्बद्ध हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(३) उच्चतमन्यायालय के प्रशासन-व्यय, जिन के अन्तर्गत उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि का भाग होंगी।

१४७. इस अध्याय में तथा भाग ६ के अध्याय ५ में इस सविवान के निर्वचन के सारवान विधि-प्रश्न के बारे में जो निर्देश हैं उन का अर्थ ऐमा किया जायेगा कि मानो उन के अन्तर्गत भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के (जिस के अन्तर्गत उस अधिनियम को संशोधित या अनुपूरित करने वाली कोई अधिनियमिति भी है) अथवा उस के अधीन बनाये गये किसी परिषदादेश या आदेश के, अथवा भारतीय-स्वतंत्रता-अधिनियम १९४७ के अथवा उस के अधीन बनाये गये किसी आदेश के, निर्वचन के सारवान विधि-प्रश्न के निर्देश भी हैं।

भाग ५--संघ--अनु० १४८

अध्याय ४.--भारत दा नियंत्रक-मह लेखा परीचक

१४८. (१) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिस को राष्ट्रपति अपने हम्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति और उन्हीं कारणों से हटाया जायेगा जिस रीति और जिन कारणों से उच्चतमन्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है।

भारत का नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक.

- (२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है, अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- (३) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक संसद् इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसी होंगी जैसी कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं:

परन्तु न तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और न उस की अनुपस्थिति-छुट्टी, निवृत्ति वेतन या निवृत्ति-वयस् सम्बन्धी अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।

- (४) अपने पद पर न रह जाने के पश्चात् नियंत्रक्त-महालेखापरीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन और पद का पात्र न होगा।
- (५) इस संविधान के तथा संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा-विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा-शर्ते तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनीय शक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे।

भाग ५--संघ--अनु ० १४८-१५१

(६) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासन-व्यय, जिन के अन्तर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को, या के बारे में, देय सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक के कर्तव्य ग्रीर शक्तियां. १४९. नियत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के, लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित किये जायें तथा, जब तक उस बारे में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कमशः भारत डोमीनियन के और प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत के महालेखा-परीक्षक को प्रदत्त थीं या के द्वारा प्रयोक्तव्य थीं।

लेखे के विषय में निदेश देने की नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की शक्ति. १५०. संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में रखा जायेगा जैसा कि भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे।

लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन.

- १५१. (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ-लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उन को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।
- (२) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राजप्रमुख के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उन को उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा।

भाग ६

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य

श्रध्याय १.--साधारण

१५२. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस परिभाषा. भाग में "राज्य" पद का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य है।

अध्याय २.--कार्यपालिका

राज्यपाल

१५३. प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा।

राज्यों के राज्यपाल.

१५४. (१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति.

- (२) इस अनुच्छेद की किसी बात से-
 - (क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कृत्य राज्य-पाल को हस्तान्तरित किये हुये न समझे जायेंगे; अथवा
 - (ख) राज्यपाल के अवीनस्य किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य देने में संसद् अथवा राज्य के विधान-मंडल को बाधा न होगी।

१५५. राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।

राज्यपाल की नियुक्ति.

राज्यपाल की पदावधि.

१५६. (१) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण करेगा ।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १५६-१५८

- (२) राज्यपाल राष्ट्रपित को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।
- (३) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपवन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा:

परन्तु अपने पद की अविध की समाप्ति हो जाने पर भी राज्य-पाल अपने उत्तराधिकारी के पद ब्रह्म तक पद धारण किये रहेगा।

राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अर्हुताएं. १५७. (१) कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र न होगा जब तक कि वह भण्त का नागरिक न हो तथा पैतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो ।

राज्यपाल-पद के लिये शर्ते.

- १५८० (१) राज्यपाल न तो संसद् के किसी सदन का, और न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद् के किसी सदन का, अथवा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का, सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उस ने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के पद प्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
 - (२) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा।
- (३) राज्यपाल को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का हक्क होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा।
- (४) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद की अविध में घटाये नहीं जायेंगे।

भाग ६.--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १५६-१६१

१५९. प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वेहन करता है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के, अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के प्राप्य अगतम न्यायाधीश के, समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उम पर अपने हस्ताक्षर करेगा अर्थात्—

राज्यपाल द्वारा शपथ यः प्रतिज्ञान.

१६०. इस अध्याय में उपबन्धन की हुई किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिये राष्ट्रपति, जैसा उचित समझे, वैसा उपबन्ध बना सकेगा।

4 ;

१६१. जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका शिक्त् का विस्तार है उस विषय सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा, प्रविलम्बन, विराम, या पिरहार करने की, अथवा दंडादेश का निलम्बन, पिरहार या लघूकरण करने की, उस राज्य के राज्यपाल को शिक्त होगी।

कुछ आक< स्मिकताओं में राज्यपाळ के कृत्यों का निर्वहन.

क्षमा आदि
की तथा कुछ
अभियोगों
में दंडादेश के
निलम्बन,
परिहार या
लघुकरण
करने की
राज्यपाल की
शक्ति.

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १६२-१६३

राज्य कीं कार्यपालिका शक्ति का विस्तार. १६२ इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों (तक होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है:

परन्तु जिस विषय के बारे में राज्य के विधान-मंडल और संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उस में राज्य की कोई कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, अथवा संसद् निर्मित किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को स्पष्टता पूर्वेक प्रदत्त शक्ति के अधीन रह कर, और से परिसी-मित हो कर, ही होवेगी।

मंत्रि-परिषद्

राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मंत्रि-परिषद.

- १६३. (१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उन में से किसी को स्विविवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिस का प्रधान मुख्य मंत्री होगा।
- (२) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिस के सम्बन्ध में, इस संविधान के द्वारा या अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह स्वविवेक से कार्य करें तो राज्यपाल का स्वविवेक से किया हुआ विनिश्चय अन्तिम होगा तथा राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण से कोई आपित्त न की जायेगी कि उसे स्वविवेक से कार्य करना, या न करना, चाहिये था।
- (३) क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच ुन की जायेगी

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- अनु० १६४-१६५

१६४. (१) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे:

मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपवन्ध.

परन्तु उड़ीसा, विहार और मध्यप्रदेश राज्यों में आदिमजातियों के कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुये वर्गों के कल्याण का, अथवा किसी अन्य कार्य का भी, भार-साधक हो सकेगा।

- (२) मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- (३) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पिहले राज्यपाल उस से, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्रों के अनुसार, पद की और गोपनीयता की शपथें करायेगा।
- (४) कोई मंत्री, जो निरन्तर छ मासों की किसी कालाविध तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस कालाविध की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा।
- (५) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय समय पर उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निर्धारित करे तथा, जब तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक, ऐसे होंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है।

राज्य का महाधिवक्ता

१६५ (१) उच्चन्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा ।

राज्य का महाधिवनता.

(२) महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- अनु० १६५-१६७

विधि-रूप दूसरे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसे, समय समय पर, भेजे या सौंपे तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसे इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन दिये गये हों।

(३) महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पायेगा।

सरकारी कार्य का संचालन

राज्य की सरकार के कार्य का संचालन

- '१६६. (१) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी।
- (२) राज्यपाल के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उसी रीति से किया जायेगा जो राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी कि वह राज्यपाल द्वारा दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।
- (३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये जाने के लिये तथा जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिस के विषय में इस संविधान के द्वारा या अधीन अपेक्षित है कि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करे वहां तक उन्त कार्य के बंटवारे के लिये राज्यपाल नियम बनायेगा।

राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कर्तव्य. १६७. प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री का--

- (क) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के समस्त विनिश्चय तथा विधान के लिये प्रस्था-पनायें राज्यपाल को पहुंचाने का;
- (ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के
 िलंगे प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी
 को राज्यपाल मंगावें, उस को देने का; तथा

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १६७-१६९

(ग) किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखने का,

कर्तव्य होगा।

अध्याय ३ --- राज्य का विधान-मंडल

साधारण

[१६८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा जो राज्यपाल तथा—— राज्यों के विधान-मंडलीं का गठन.

- (क) पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मुम्बई, और संयुक्त प्रान्त के राज्यों में दो सदनों से;
- (ख) अन्य राज्यों में एक सदन से, मिल कर बनेगा।
 - (२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हों वहां एक विधान-परिषद् और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा और जहां केवल एक सदन हो वहां वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा।
 - १६९. (१) अनुच्छेद १६८ में किसी वात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा किसी विधान-पिष्वद् वाले राज्य में विधान-पिष्यद् के उत्सादन के लिये अथवा वैसी पिरपद् से रहित राज्य में वैसी पिर्षद् के सृजन के लिये उपवन्ध कर सकेगी यदि राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर दिया हो।

राज्यों में वि-धान-परिषद् का उत्सादन या सृजन.

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १६९-१७०

- (२) खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विधि में इस सविधान के संशोधन के लिये ऐसे उपवन्ध भी अन्तर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपवन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे।
- (३) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

विधान-सभा-

- १७०. (१) अनुच्छेर ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधान-सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनेगी।
- (२) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर होगा, तथा आसाम के स्वायत्त जिलों को, तथा शिलोंग के नगर-क्षेत्र व कटक से मिलकर बने निर्वाचन-क्षेत्र को, छोड़ कर जनसंख्या के प्रत्येक पचहत्तर हजार के लिये एक से अनिधक प्रतिनिधि के अनुपात से होगा:

परन्तु किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त संख्या किसी अवस्था में पांच सौ से अधिक अथवा साठ से कम न होगी।

(३) राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने वाले सदस्यों की संख्या का उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से अनुपात सारे राज्य में सर्वत्र यथा-साध्य एक ही होगा।

भाग ६--प्रथम ग्रनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १७०-१७१

(४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद् विधि द्वारा निर्धारित करे:

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से विधान-सभा में के प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब तक कि उस समय वर्तमान विधान-सभा का विघटन न हो जाये।

१७१. (१) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या की एक चौथाई से अधिक न होगी: विधान-परिषदों की, । रचना,

परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या चालीस से कम न होगी।

- (२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तब तक किसी राज्य की विधान-परिषद् की रचना खंड (३) में उपवैन्धित रीति से होगी।
- (३) किसी राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या का----
 - (क) यथाशक्य तृतीयांश उस राज्य में की नगरपालिकाओं, जिला-मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिका-रियों के, जैसे कि संसद् विधि द्वारा उल्लिखित करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा;
 - (ख) यथाशवय द्वादशांश उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यवितयों से मिल कर बने हुए निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी विश्व-विद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से

- भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १७१
 - ऐसी अर्हताओं को धारण किये हुए हैं जो संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन वैसे किसी विश्व-विद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के तुल्य विहित की गई हो ;
 - (ग) यथाशक्य द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम से कमतीन वर्ष से लगे हुए हैं जैसी कि संसद् निर्मित विधि केद्वारा या अधीन विहित की जायें:
 - (घ) यथानक्य तृतीयांग राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं हैं;
 - (ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उस रीति से नाम-निर्देशित होंगे जो कि इस अनुच्छेद के खंड (५) में उपबन्धित हैं।
- (४) खंड (३) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जायेंगे, जैसे कि संसद्-निर्मित किसी विधि के अधीन या द्वारा विहित किये जायें तथा उक्त उपखंडों के, और उपखंड (घ) के, अधीन होने वाले निर्वाचन अनुपाती-प्रतिनिधित्व पद्धित के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।
- (५) खंड (३) के उपखंड (ङ) के अधीन राज्यपाल द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्त प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है,

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा

भाग ६--प्रथम स्रनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १७२-१७३

१७२. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पाँच दर्ष तक चालू रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त कालाविध की समाप्ति का परिणाम विधान-सभा का विघटन होगा: राज्यों ू्रेक ान-मंडलों की अवधि.

परन्तु उदत कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद् विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेशी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा विसी अवस्था में भी उद्घेषणा वे प्रवर्तन का अन्त हो जाने के परचात् छ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।

(२) राज्य की विधान-परिषद् का विधान न होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई संसद् निर्मित विधि द्वारा बनाये गये तद्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समान्ति पर यथ सम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे।

१७३ कोई व्यक्ति विसी राज्य के विधान-मंडल में के किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि—

राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अर्हता

- (क) वह भारत का नागरिक न हो;
- (ख) विधान-सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का, तथा विधान-परिषद् के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का, न हो; तथा
- (ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे
 में निर्मित किसी विधि के द्व.रा या अधीन
 विहित की जायें।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १७४-१७६

राज्य के
विद्यान-मंडल
के सत्त्र,
सत्त्रावसान
और विघटन,

- १७४. (१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूत किया जायेगा तथा उनके एक सत्त्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्त्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छ मास का अन्तर न होगा।
- (२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते [हुए राज्य-
 - (क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा;
 - (ख) सदन या सदनों का सत्त्रावसान कर सकेगा;
 - (ग) विधान-सभा का विघटन कर सकेगा।

सदन या
सदनों को
सम्बोधन
करने और
संदेश भेजने
का राज्यपाल
का स्रिकार.

- १७५ (१) विधान-सभा को, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधित कि कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।
- (२) राज्यपाल राज्य के विधान-मंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश उस राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों को भेज सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीझता से विचार करेगा।

प्रत्येक सत्ता-रम्भ में राज्यपाल का विश्लेष अभि-माषण- १७६ (१) प्रत्येक सत्तृ के आरम्भ में विधान-सभा का, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा आह्वान का कारण विधान-मंडल को बतायेगा।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--श्रनु० १७६-१७९

(२) सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया के विनिया-मक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिये तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववित्ता देने के लिये उपबन्ध किया जायेगा।

१७७. राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में दोनों सदनों में, बोले तथा दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग ले तथा विधान-मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु इस अनुच्लेद के आधार पर उसको मत देने का हक्क न होगा।

सदनों विषयक मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार.

राज्य के विधान-मंडल के पदाधिकारी

१७८. राज्य की प्रत्येक विद्यान-सभौ यथासम्भैव बीघ्र भपने दो सदस्यों को ऋमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेभी ध्या जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा कैसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

विधान-समा का अध्यक्ष भ्रोर उपाध्यक्ष.

- १७९. विघान-सभा के अध्यक्ष या उपाघ्यक्ष के रूप में द घारण करने वाला सदस्य—
 - (क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा;
 - (ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि दह सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा; तथा
 - (ग) विधान-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदिस्किता, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना.

भाग ६--प्रथम ग्रनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १७९-१८१

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो:

परन्तु यह और भी कि जब कभी विधान-सभा का विघटन किया जाये तो विघटन के पश्चात् होने वाले विधान-सभा के प्रथम अश्विवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त न करेगा।

अध्यक्ष-पद के
कर्तव्य-पालन
की अथवा
अध्यक्ष के रूप
में कायं करने
की, उपाध्यक्ष
या अन्य
ध्यक्ति की
ध्यक्ति

- १८०० (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिवत हो तब उपाध्यक्ष अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिवत हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (२) विधान-सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुप-स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- १८१ (१) विधान-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से कोई हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा, तथा अनुच्छेद १८० के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिस से कि यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।
- (२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-सभा में विचाराधीन हो तब उसको सभा में बोलने

जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचा-राधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा. भाग_६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १८१-१८३

तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधि-कार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु मत साम्य होने की दशा में न होगा।

१८२. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्, जहां ऐसी परिषद् हो, यथासम्भव शीघ्र, अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना सभा-पति और उपसभापित चुनेगी तथा जब जब सभापित या उप-सभापित का पद रिक्त हो तब तब परिषद् किसी अन्य सदस्य को यथास्थित सभापित या उपसभापित, चुनेगी। विधान-परिषद्
के सभापति
और उपसभापति.

१८३. विधान-परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य—

- (क) यदि परिषद् का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा;
- (ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपसभापित को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापित है तथा सभापित को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभापित है, अपना पद त्याग सकेगा; तथा
- (ग) परिषद् के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित परिषद् के संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दें दी गई हो।

सभापति और
उपसभापति
की पदरिक्तता,
पदत्याग तथा
पद से हटाया
जाना.

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अन्० १८४-१८६

डपसभापति अन्य या व्यक्ति की समापति-पद के कर्तव्यों के पालन करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की

जब उस के पद से हटाने का

संकल्प विचा-

राधीन हो तब

होगा.

- १८४. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो तब उप-सभापति अथवा, यदि उपसभापति का भी पद रिक्त हो तो, विधान-परिषद् का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।
- (२) विधान-परिषद् की किसी बैठक से सभापति अनुपस्थिति में उपसभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद् की प्रक्रिया के नियमों से निर्घारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद् निर्घारित करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा।
- १८५. (१) विधान-परिषद् की किसी बैठक में, सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद १८४ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में प्रत्येक ऐसी बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लाग होते हैं जिस से कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है।
- (२) जब कि सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान-परिषद् में विचाराधीन हो तब उस को परिषद् में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हए भी, ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक्क होगा किन्तु, मत साम्य की दशा में न होगा।

सभापति या उपसभापति पीठासीन न

अध्यक्ष और उपाघ्यक्ष तथा सभापति और चपसभापति

१८६. विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तथा विधान-परिषद् के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे क्रमशः राज्य का विधान-मंडल द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार भाग ६ -- प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-अनु० १८६-१८८

न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे।

१८७. (१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् साचविक कर्मचारी-वृन्द होगा :

परन्तु विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के बारे में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है।

- (२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के साचिवक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगा।
- (३) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान-मंडल उपबन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधान-सभा के अध्यक्ष से, या विधान-परिषद् के सभापित से, परामर्श कर के सभा या परिषद् के साचिवक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

कार्य संचालन

१८८. राज्य की विधान-संभा अथवा विधान-परिषद् का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शप्य लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

के वेतन और मत्ते.

राज्य के विधान-संडल का सचिवा-लय

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रति-ज्ञान. भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १८९-१९०

सदनों में मत-दान, रिक्त-ताम्रों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति. १८९. (१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की किसी बैठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापित या उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर, उपस्थित तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

अध्यक्ष अथवा सभापित या उस के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत न देगा, पर मत साम्य की श्विवस्था मिं उसका निर्णायक मत होगा और वह उस का प्रयोग करेगा।

- (२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन को कार्य करने की दािक्त होगी, तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का हक्क न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भी राज्य के विधान-मंडल में की कार्यवाही मान्य होगी।
- (३) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे तब तक राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश, इस में से जो भी अधिक हो, होगी।
- (४) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद् के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न रहे तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस के रूप में कार्यं करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।

सदस्यों की अनर्हताएं .

स्थानों की रिक्तता, १९०. (१) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य---अनु० १९०

हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगा।

- (२) कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालाविध की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, ऐसे सब राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में के विधान-मंडलों के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो।
- (३) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सेदस्य—
 - (क) अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनर्हताओं में से किसी का भागी हो जाता है; अथवा
 - (ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापित को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के विना उस के सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा:

परन्तु, साठ दिन की उक्त कालाविध की संगणना में किसी ऐसी कालाविध को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्ताविसत अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लियें स्थगित रहा है। भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १९१-१९२

सदस्यता ने लिये अनहैं-तायें.

- १९१. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अन्हें होगा—
 - (क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है;
 - (ख) यदि वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
 - (ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है ;
 - (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अजित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किये हुए है;
 - (ङ) यदि वह संसद् निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनहें कर दिया गया है।
- (२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

सदस्यों की अनहैंताओं विषयक प्रश्नों पर विनि-श्वय. १९२ (१) यदि कोई प्रश्न उठता है कि राज्य के विधान-मंडल का सदस्य अनुच्छेंद १९१ के खंड (१) में वर्णित अनहंताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग ६-- प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १९२-१९४

(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

१९३ यदि राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में, अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं की पूर्ति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि में उस की सदस्यता के लिये अई नहीं हूं अथवा अनई कर दिया गया हूं अथवा संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्य के दिन के लिये, जब कि वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पांच सौ रुपये के दण्ड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल होगा।

पराज्य के विधान-मंडलों और उन के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

१९४. (१) इस संविधान, के उपबन्धों के तथा विधान-मंडल की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्-स्वातन्त्र्य होगा।

(२) राज्य के विधान-मंडल में या उस की किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कायवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाही चल सकेगी।

अनुष्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अहं न होते हुए अथवा अनहं किये जाने पर बैटने और मत देने के लिये दण्ड,

विधान-मंडछों के सदनों की तथा उन के सदस्यों और समितियों की श्वितयां, विशेषाधिकार आदि. भाग ६-- प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य -- अनु ०, १९४-१९६

- (३) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान-मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और सिमितियों की, शिक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पालियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उस के सदस्यों और सिमितियों की हैं।
- (४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन अथवा उस की किसी समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उस की कार्य-वाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उन के सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू हैं।

सदस्यों के वेतन और भत्ते. १९५. राज्य की विधान-सभा और विधान-परिषद् के सदस्यों को ऐसे वेतनों और भत्तों के, जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन, और भत्तों के, ऐसी दरों से और ऐसी शतीं पर, जैसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थीं, पाने का हक्क होगा।

विधान प्रक्रिया

विषेयकों के पुरस्थापन और पारण विषयक उपवन्य.

१९६. (१) घन-विधेयकों तथा अन्य वित्त-विधेयकों के विषय में अनुच्छेद १९८ और २०७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा।

भाग ६--प्रथम अनुस्ची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १९६-१९७

- (२) अनुच्छेद १९७ और १९८ के उपबन्धों के अधीन रहते, [हुए कोई विधेयक, विधान-परिषद् वाले, राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा जब तक कि या, तो विना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो।
- (३) किसी राज्य के विधान-मंडल में लम्बित-विधेयक उस के सदन या सदनों के सत्तृवसान के कारण व्यपगत न होगा।
 - (४) किसी राज्य] की विधान-परिषद् में लिम्बत-विधेयक, जिस को विधान-सभा ने पारित नहीं किया है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत न होगा।
 - (५) कोई विधयक जो किसी राज्य की विधान-सभा में लिम्बत है, अथवा, जो विधान-सभा से पारित हो कर विधान-परिषद् में लिम्बत है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत हो जायेगा।
 - १९७. (१) यदि विधान-परिषद् वाले राज्यकी विधान-सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित हो जाने तथा विधान-परिषद् को पहुंचाये जाने के पश्चात्,——
 - (क) परिषद् द्वारा विघेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा
 - (ख) परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उस से विधेयक पारित हुए विना तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा
 - (ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिन से सभा सहमत नहीं होती,

घन-विधेयकों से अन्य विधे-यकों के बारे में विधान-परिषद् की शक्तियों का निबंन्धन. भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० १९७-१९८

तो विधान-सभा विधेयक को, अपनी प्रिक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रह कर, उसी या किसी आगे आने वाले सत्तू में ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित या विना, यदि कोई हों, जो विधान-परिषद् ने किये हैं, सुझाये हैं या स्वीकार किये हैं, पुनः पारित कर सकेगी तथा तब इस प्रकार पारित विधेयक को विधान-परिषद् को पहुंचा सकेगी।

- (२) यदि विधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दो-बारा पारित हो जाने तथा विधान-परिषद् को पहुंचाये जाने के पश्चात्—
 - (क) परिषद् द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है; अथवा
 - (ख) परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख सें, उस से विधेयक पारित हुए विना एक मास से, अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा
 - (ग) परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारितः होता है जिन्हें सभा स्वीकार नहीं करती,

तो विधेयक राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेंगा जिस में कि वह विधान-सभा द्वारा ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जो कि विधान-परिषद् द्वारा किये या सुझाये गये हों तथा विधान-सभा ने स्वीकार कर लिये हों, दूसरी बार पारित किया गया था।

(३) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागु नहीं होगी ।

घन-विघेयकों विषयक विश्वेष प्रक्रिया. १९८. (१) विधान-परिषद् में धन-विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा ।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य---अनु० १९८-१९९

- (२) विधान-परिषद् वाले राज्य की विधान-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्, धन-विधेयक विधान-परिषद् को, उस की सिपारिशों के लिये, पहुंचाया जायेगा तथा विधान-परिषद् विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालाविध के भीतर विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित विधान-सभा को लौटा देगी 'तथा ऐसा होने पर विधान-सभा, विधान-परिषद् की सिपारिशों में से सब को, या किसी को, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी।
 - (३) यदि विधान-परिषद् की सिपारिशों में से किसी को विधान-सभा स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक विधान-परिषद् द्वारा सिपारिश किये गये तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा।
 - (४) यदि विधान-परिषद् की सिपारिशों में से किसी को भी विधान-सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, विधान-परिषद् द्वारा सिपारिश किये गये किसी संशोधन के विना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस में कि वह विधान-सभा द्वारा पारित किया गया था।
- (५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित तथा विधान-परिषद् को उसकी सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धन-विधेयक उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधान-सभा को लौटाया नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में विधान-सभा ने उस की पारित किया था।
- १९९. (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तर्विष्ट हैं, अर्थात्—

'धन-विधेयकों की परिभाषा,

(क) किसी कर का आरोग्ण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियम : भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-अनु० १९९

- (ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, विनियमन ;
 - (ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उस में से धन निकालना;
- (घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग;
- (ङ) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना;
- (च) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक लेखें मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभि-रक्षा या निकासी करना; अथवा
- (छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय।
- (२) कोई विधेयक केवल इस कारण स धन-विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दंडों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञिप्तयों के लिये फीसों की, या की हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है अथवा, इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य---अनु ० १९९-२००

- (३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मंडल में पुर: स्थापित कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (४) अनुच्छेद १९८ के अधीन जब धन-विधेयक विधान-परिषद् को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद २०० के अधीन अनुमति के लिये राज्य के राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर विधान-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन-विधेयक है।

२०० ्जब राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमित देता है या अनुमित रोक लेता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपित के विचारार्थ रिक्षत कर लेता है:

परन्तु राज्यपाल अनुमित के लिये अपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पश्चात् यथाशीझ उस विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं हैं तो, सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर अथवा उस के किन्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर पुनर्विचार करें तथा विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उसने अपने संदेश में सिपारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया गया हो तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे तथा यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राज्यपाल के समक्ष अनुमित के लिये रखा जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमित न रोकेगा:

विषेयकों पर अनुमति. भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-अनु० २००-२०२

परन्तु यह और भी कि जिस विधेयक से, यदि वह विधि हो गया तो, राज्यपाल की राय में उच्चन्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिस की पूर्ति के लिये वह न्यायालय इस संविधान द्वारा बनाया गया है, संकटापन्न हो जायेगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति न देगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखेगा।

विचारार्थं रक्षित विधेयकः २०१. राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थे रिक्षित कर लिया जाये तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो सम्मित देता है या सम्मित रोक लेता है:

परन्तु, जहां विधेयक धन-विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन को या सदनों को ऐसे संदेश सहित, जैसा कि अनुच्छेद २०० के पिहले परन्तुक में विणित है, लौटा दे, तथा जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाये तब ऐसे संदेश के मिलने की तारीख से छ महीने की कालावधि के अन्दर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार फिर से विचार किया जायेगा तथा, यदि वह संशोधन के सहित या विना सदन या सदनों द्वारा फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्र-पित के समक्ष उस के विचार के लिये पुनः उपस्थित किया जायेगा।

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

वार्षिक-वित्त-विवरण. २०२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष, राज्यपाल उस राज्य की उस वर्ष के लिये प्राक्किलत प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में "वार्षिक-वित्त-विवरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है।

⁽२) वार्षिक-वित्त-विवरण में व्यय के प्राक्कलन में दिये हुए---

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २०२

- (क) जो व्यय इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित है उसकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशिया; तथा
- (ख) राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां,

पृथक् पृथक् दिखाई जायेंगी, तथा राजस्व-लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा।

- (३) निम्नवर्ती व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा—
 - (क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उस के पद से सम्बद्ध अन्य व्यय;
 - (ख) विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तथा किसी राज्य में विधान-परिषद् होने की अवस्था में विधान-परिषद् के सभापित और उपसभा-पित के भी, वेतन और भत्ते;
 - (ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व राज्य पर है जिन के अन्तर्गत व्याज, निक्षेप-निधि-भार, और मोचन भार, उधार लेने और ऋण-सेवा और ऋणमोचन सम्बन्धी अन्य व्यय, भी हैं;
 - (घ) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों विषयक व्यय;
 - (ङ) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई राशियां;
 - (च) इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल से विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

भाग ६—-प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-अनु० २०३-२०४

विधान-मंडल में प्राक्कलनों के विषय में इक्तिया.

- २०३. (१) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलनें विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा को रोकती है।
- (२) उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे विधान-सभा के समक्ष अनुदान-मांग के रूप में रखी जायेंगी तथा विधान-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उल्लिखित राशि को कम कर के, स्वीकार करे।
- (३) राज्यपाल की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान की मांग न की जायेगी।

वि नियोग-विधेयक.

- २०४० (१) विधान-सभा द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से—
 - (क) सभा द्वारा इस प्रकार किये अनुदानों की; तथा
 - (ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनिधक व्यय की,

पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुर:स्थापित किया जायेगा।

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेंगा तथा कोई मंशोधन इस खंड के अीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-अनु० २०४-२०५

- (३) अनुच्छेद २०५ और २०६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से, इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा।
 - २०५ (१) यदि---
 - (क) अनुच्छेद २०४० के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक-वित्त-विवरण में अवेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा
 - (ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवापर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्किलत की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में, तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, अनुच्छेद २०२, २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वार्षिक-विल्त-विवरण तथा उस में विणत व्यय अथवा अनुदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे किसी व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिये धनों

अनुपूरक, अपर या अतिरिक्त अनुदान. भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २०५-२०६

का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपकादा नुदान

- २०६ (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान-सभा को—
 - (क) किसी वित्तीय वर्षं के भाग के लिये प्राक्किलत व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में विहित प्रिक्तिया की पूर्ति लिम्बत रहने तक तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लिम्बत रहने तक, पेशगी देन की;
 - (ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे व्योरे के साथ विणित नहीं की जा सकती जैसा कि वार्षिक-वित्त-विवरण में साधारणतया दिया जाता है, तब राज्य के सम्पत्ति-स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की;
 - (ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान करने की,

शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उन के लिये राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधान-मंडल को होगी।

(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वे वार्षिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने के तथा राज्य की संचित निधि में से

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २०६-२०८

ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये घनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

२०७. (१) अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिपारिश के विना पुर:स्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाला विधेयक विधान-परिषद् में पुर:स्थापित न किया जायेगा:

वित्त -विषेयकें. लिये उपबन्ध •

परन्तु किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपबन्ध बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी।

- (२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थ-दंड के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के लिये फीस की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है।
- (३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल ने सिपारिश न की हो।

ं साघारणतयां प्रक्रिया 🗼 💈

२०८. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के

प्रक्रिया के व

भाग ६-प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-अनु० २०८-२१०

तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगा।

- (२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, तत्स्थानी राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे, ऐसे रूपभेदों और अनुकूलनों के साथ जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापति करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगें।
- (३) विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-सभा के अध्यक्ष तथा विधान-परिषद् के सभापित से परामर्श करने के प्रश्चात् राज्यपाल, उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

राज्य के
विधान-मंडल
में वित्तीय
कार्य सम्बन्धी
प्रिक्रिया का
विधि द्वारा
विनियमन

२०९. वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से अथवा राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, और जहां तक, इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का कोई उपबन्ध अनुच्छेद २०८ के खंड (१) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, और वहां तक, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा।

विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली माबा. २१०. (१) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा:

भाग ६—प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य—— अनु० २१०-२१३

परन्तु यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान-परिषद् का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

- (२) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालाविध की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उस में से लुप्त कर दिये गये हैं।
- २११. उच्चतमन्यायालय या किसी उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा न होगी।
- २१२ (१) प्रिक्रिया में, किसी कथित अनियमिता के आधार पर राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी।
- (२) राज्य के विधान-मंडल का कोई पदाधिकारो या सदस्य, जिस में इस संविधान के द्वारा या अधीन उस विधान-मंडल में प्रिक्रिया को या कार्य-संचालन को विनियमन करने की अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हैं उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा।

श्रध्याय ४ -- रॉज्यपॉल की विधायिनी शक्तियाँ

२१३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान-सभा, तथा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदन, सत्त्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों। विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंन्धन.

न्यायालय विद्यान मंडल की कार्यवा-हियों की जांच न करेंगे•

विभान-मंडल के विश्वान्ति-काल में राज्य-पाल की अध्यादेश प्रस्थापन-शक्ति. भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-अनु० २१३

परन्तु राष्ट्रपति के अनुदेशों के विना राज्यपाल कोई ऐसा अध्यादेश प्रस्थापित न करेगा यदि—

- (क) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले विधेयक को विधान-मंडल में पुरःस्थापित किये जाने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती; अथवा
- (ख) वैसे ही द्रिपबन्ध अर्न्तिवष्ट रखने वाले विधेयक को राष्ट्रपित के विचारार्थरिक्षत करना वह आवश्यक समझता; अथवा
- (ग) वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखने वाले राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अमान्य होता जब तक कि राष्ट्रपति के विचारार्थं रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमृति प्राप्त न हो चुकी होती।
- (२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वहीं बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—
 - (क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, तथा जहां राज्य में विधान-परिषद् है वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छ सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उस कालाविध की समाप्ति से पूर्व उस के निरनुमोदन का संकल्प विधान-सभा से प्रारित, और यदि विधान-परिषद् है तो उस से स्वीकृत, हो जाता है तो यथास्थित संकल्प पारण होने पर, अथवा परिषद् द्वारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा; तथा
 - (ख) राज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा लिया जा सकेगा।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २१३-२१४

व्याख्या.—जब विधान-परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिये आहूत किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की कालाविध की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायेगी।

(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जो विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत अधिनियम के रूप में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा:

परन्तु राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो सम-वर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद् के किसी अधिनियम अथवा किसी वर्तमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव को दिखाने वाले इस संविधान के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये कोई अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया गया है, राज्य के विधान-मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया था तथा उस के द्वारा अनुमत हो चुका है।

श्रध्याय ५ -- राज्यों के उचन्यायालय

- २१४. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्चन्यायालय होगा।
- (२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय को इस संविधान के प्रयोजन के लिये, तत्स्थानी राज्य के लिये होने वाला उच्चन्यायालय समझा जायेगा।
- (३) इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय पर इस अध्याय के उपबन्ध लागू होंगे।

राज्यों के लिये उच्च-न्यायालय• भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २१५-२१७

उच्चन्याया-रुय अभिलेख-न्यायालय

२१५. प्रत्येक उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होगा तथा उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तियां होंगी।

उच्चन्याया-लयों का गठन.

२१६. प्रत्येक उच्चन्यायालय मुख्य न्यायाधिपति तया ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे :

परन्तु इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश उस अधिकतम संख्या से अधिक न होंगे जिसे राष्ट्रपति, समय समय पर, उस न्यायालय के सम्बन्ध में आदेश द्वारा नियत करे।

उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उस के पद की शर्ते.

२१७. (१) भारत के म्ख्य न्यायाधियति से उस राज्य के राज्यपाल से तथा, मुख्य न्यायाधिपति को छोड़ अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्याया-घिपति से परामर्श कर के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को निय्क्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले:

परन्तु---

- (क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सिहत लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा;
- (ख) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के हेत् इस संविधान के अनुच्छेद १२४ के खंड (४) में उपवन्धित रीति से कोई न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा;
- (ग) किसी न्यायाघीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतंमन्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत राज्य-

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २१७

> क्षेत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने पर, रिक्त कर दिया जायेगा।

- (२) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, तथा—
 - (क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर चुका हो; अथवा
 - (ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में के उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो।

व्याख्या,--इस खंड के प्रयोजनों के लिये--

- (क) किसी उच्चन्यायालय के अधिवक्ता रहने की कालाविध की संगणना के अन्तर्गत वह कोई काला-विध भी होगी जिस में किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया हो;
- (ख) उस कालाविष्य की संगणना के अन्तर्गत, जिस में कि कोई व्यक्ति भारत राज्य-क्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुका है अथवा किसी उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व की वह कोई कालाविध भी होगी जिस में उस ने किसी क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ से पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम १९३५ में परिभाषित भारत में समाविष्ट था, यथास्थित न्यायिक पद धारण किया हो अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- अनु० २१८-२२१

उच्चतमन्यायालय
सम्बन्धी कृष्ठ
उपबन्धों का
उच्चन्यायालय
को लागू होना.
उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा
शपथ या प्रति-

२१८. अनुच्छेद १२४ के खंड (४) और (५) के उपबन्ध, जहां जहां उन में उच्चतमन्यायालय के निर्देश हैं वहां वहां उच्चन्यायालय के निर्देश रंब कर, उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उच्चतमन्यायालय के सम्बन्ध में लागू हैं।

२१९. किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के राज्यपाल के, अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी व्यक्ति के, समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

२२० कोई व्यक्ति, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का पद इस संविधान के प्रारम्भ के बाद धारण कर चुका है, भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य न करेगा।

न्यायाधीशों द्वारा न्याया-रूयों में अथवा किसी प्राधि-कारी के समक्ष विधि-वृत्ति करने का प्रति-मेध. न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि.

- २२१. (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं।
- (२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों का, जैसे कि संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जैसे द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा:

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उस की अनु-पस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति -वेतन विषयक उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा। भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २२२-२२४

२२२. (१) राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामशं कर के भारत राज्य-क्षेत्र में के एक उच्चन्यायालय से किसी दूसरे उच्चन्यायालय को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर सकेगा।

(२) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार स्थानान्तरित किया जाये तब उस. कालाविष में, जिस में कि वह दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, उस को अपने वेतन के अति-रिक्त, ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जैसा संसद्, विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जाये तब तक ऐसे प्रतिकुरात्मक भत्ते के जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, पाने का हक्क होगा।

२२३ (१) जब किसी उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्र-पति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा।

२२४. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, किसी व्यक्ति से, जो उस न्यायालय के या किसी अन्य उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार प्रार्थित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और विशेषाधिकारों का हक्क होगा, किन्त् वह अन्यथा उस न्यायाधिश न समझा जायेगा:

परन्तु जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्या-याधीश के रूप में बैठने तथा कार्य करने की सम्मित न दे तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली न समझी जायेगी। एक उच्चत्याः यालय से दूसरे की किसी न्यायाघीश का स्थानान्तरण्

कायंकारी मुख्य न्याया-विपति की नियुक्ति.

सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों) की उच्च-न्यायालयों की बैठकों उपस्थिति.

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २२५-२२६

वर्तमान उच्च-न्यायालयों के क्षेत्राधिकार २२५. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तथा इस संविधान द्वारा विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वर्तमान उच्चन्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, तथा उस न्यायालय में न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उस के न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिन के अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उस के सदस्यों के अकेले या खंड-न्यायालयों में बैठने के विनियमन करने की शक्ति भी है, वैसी ही रहेंगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थीं:

परन्तु राजस्व सम्बन्धी, अथवा उस के सगृीत करने में आदेशित अथवा किये हुए किसी कार्य सम्बन्धी विषय में उच्चन्यायालयों में से किसी के आरिम्भक क्षेत्राधिकार का प्रयोग, जिस किसी निर्बन्धन के अधीन इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले था, वह निर्बन्धन ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर आगे लागून होगा।

कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्च-न्यायालयों की शक्ति

- २२६ (१) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्चन्यायालय को, उन क्षेत्रों में सर्वत्र जिन के सम्बन्ध में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग (३) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उन राज्य-क्षेत्रों में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश या लेख जिन के अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं अथवा उन में से किसी को निकालने की शक्ति होगी।
- (२) खंड (१) द्वारा उच्चन्यायालय को प्रदत्त शक्ति से इस संविधान के अनुच्छेद ३२ के खंड (२) द्वारा उच्चतम-न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का बल्पीकरण न होगा।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--

- २२७: (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय उन राज्य-क्षेत्रों में सर्वत्र, जिन्हिके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्याया-लयों और न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करेगा।
- (२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर विना प्रतिकूल प्रभाव हुए उच्चन्यायालय—
 - (क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा;
 - (ख). ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रणाली और कार्यवाहियों के विनियमन के हेतु साधारण नियम बना और निकाल सकेगा तथा प्रपन्नों को विहित कर सकेगा; तथा
 - (ग) किन्हीं ऐसे न्यायालयों के पदािकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रपन्नों को विहित कर सकेगा।
- (३) उच्चन्यायालय उन फीसों की सारिणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शेरीफ को तथा समस्त लिपिकों को और पदाधिकारियों को तथा इन में वृत्ति करने वाले न्याय-वादियों, अधिवक्ताओं और वकीलों को मिल सकेंगी:
- परन्तु खंड (२) या खंड (३) के अधीन बनाये हुए कोई नियम अथवा विहित कोई प्रपत्र अथवा स्थिरीभूत कोई सारिणी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों से असंगत न होगी, तथा इन के लिये राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।
- (४) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्चन्यायालय को सशस्त्र बलों सम्बन्धी किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर अधीक्षण की शिवतयां देने वाली न समझी जायेगी।
- २२८. यदि उच्चन्यायालय का समाधान हो जाये कि उस के अधीन न्यायालय में लम्बित किसी मामले में इस संविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है जिस का

सब न्याया-लयों के अधीक्षण की उच्चन्याया-लय की शक्ति.

विशेष मामलों का उच्च-न्यायालय को हस्तान्तरण. भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २२८-२२९

निर्घारित होना मामले को निबटाने के लिये आवश्यक है तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा तथा—

- (क) या तो मामले को स्वयं निबटा सकेगा; या
- (ख) उक्त विधि-प्रश्न का निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे प्रश्न पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस मामले को उस न्यायालय को, जिस से मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा तथा उस के प्राप्त होने पर उक्त न्यायालय ऐसे निर्णय का अनुसरण करते हुए उस मामले को निबटाने के लिये आगे कार्यवाही करेगा।

उच्चत्याया-लयों के पदा-धिकारी और सेवक और २२९. (१) उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा निदिष्ट उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी करेगा:

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिस में न्यायालय का मुख्य स्थान है, नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उिल्लेखित हों, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायालय में लगा हुआ नहीं है, न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर राज्य-लोकसेवा-आयोग से परामर्श किये विना नियुक्त न किया जायेगा।

(२) राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के उप- बन्धों के अधीन रहते हुए उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विहित करे:

परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से सम्बद्ध भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २२९-२३१

हैं, उस राज्य के राज्यपाल के जिस में उच्चन्यायालय का मुख्य स्थान है, अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(३) उच्चन्यायालय के प्रशासनीय व्यय जिन के अन्तर्गत _ उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्याया-लय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि का भाग होंगी।

२३०. संसद् विधि द्वारा-

- (क) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार, जिस राज्य में उस का मुख्य स्थान है, उस से भिन्न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में, अथवा उस के भीतर न होने वाले किसी क्षेत्र में; अथवा
- (स) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन, जिस राज्य में उस का मुख्य स्थान है, उस से मिन्न प्रथम अनुसूची में उत्लिखित किसी राज्य से, अथवा उस के भीतर नहोने वाले किसी क्षेत्र से,

कर सकेगी।

२३१ जहां कोई उच्चन्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर, जिस में उस का मुख्य स्थान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्रा- धिकार का प्रयोग करता है, वहां इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह—

- (क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिस में उस न्याया-लय का मुख्य स्थान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, निर्वन्धन या उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है;
- (ख) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखत राज्य के विधान-मंडल को, जिस में ऐसा कोई क्षेत्र अवस्थित है, उस क्षेत्राधिकार के उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है; अथवा

उच्चत्याया-लयों के क्षेत्रा-घिकार का विस्तार और अपवर्जन.

राज्य के
बाहर क्षेत्राविकार प्राप्त
किसी राज्य
के उच्चन्यायालय के
क्षेत्राधिकार
के बारे में,
राज्यों के
विधान-मंडलों
की विधि
बनाने की

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २३१-२३२

शक्तियों पर् निर्बन्धन (ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये, तद्विषयक विधि बनाने की शिक्त रखने वाले विधान-मंडल को, उस न्याया- लय को उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार विषयक, खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए, ऐसी विधियां पारित करने से रोकती है, जैसी कि वह, यदि उस न्यायालय का मुख्य स्थान उस क्षेत्र में होता तो, पारित करने के लिये सक्षम होता।

निर्वचन.

२३२ जहां कोई ्उच्चन्यायालय प्रथम अनुसूची में उिल्लिखित एक से अधिक राज्यों के सम्बन्ध में, अथवा किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, वहां—

- (क) इस अध्याय में उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में राज्यपाल के प्रति जो निर्देश हैं उन से अभिप्रेत उस राज्य के राज्यपाल से होगा जिस में उस न्यायालय का मृख्य स्थान है;
- (ख) अधीन न्यायालय के लिये नियमों, प्रपत्रों और सारिणियों के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के प्रति जो निर्देश है वह उन का उस राज्य के, जिस में अधीन न्यायालय अवस्थित है, राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा अनुमोदन के प्रति अथवा यदि वह प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग .(ख) में उल्लिखित किसी राज्य का भाग न होने वाले क्षेत्र में अवस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के प्रति माना जायेगा, तथा
- (ग) राज्य की संचित निधि के प्रति जो निर्देश हैं, वे उस राज्य की संचित निधि के प्रति माने जायेंगे जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान है।

भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २३३-२३५

अध्याय ६ -- अधीन न्यायालय

२३३. (१) किसी राज्य में जिला-न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उन की पद-स्थापना और पदोन्नित ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय से परामर्श कर के राज्य का राज्यपाल करेगा।

जिला-न्याया-घीशों की नियुक्ति.

(२) कोईं व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहिले से ही नहीं लगा हुआ है, जिला-न्यायाधीश होने के लिये केवल तभी पात्र होगा जब कि वह हू सात से अन्यून वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका है तथा उस की नियुक्ति के लिये उच्चन्यायालय ने सिपारिश की है।

२३४. जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों को राज्य की क् न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य-लोकसेवा-आयोग तथा ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायालय से परामर्श के पश्चात् उस के द्वारा इस लिये बनाये गये नियमों के अनुसार की जायेगी। न्यायिक सवा
में जिलान्यायाघीशों
से अन्य
व्यक्तियों की
भर्ती-

२३५. जिला-न्यायाधीश के पद से निचले किसी पद को । घारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यवितयों की पद-स्थापना, पदोन्नित और उन को छुट्टी देने के सिहत जिला-न्यायालयों तथा उन के अधीन न्यायालयों का नियंत्रण उच्च-न्यायालयों में निहित होगा, किन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात । का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि मानो वह ऐसे किसी व्यक्ति से उस अपील के अधिकार को छीनती है जो कि उस की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे प्राप्त है अथवा उच्चन्यायालय को अधिकार देती है कि वह उस की । सेवा की ऐसी विधि के अधीन विहित शर्तों के अनुसरण से अन्यथा उस से व्यवहार करे। अधीन न्या-यालयों पर नियंत्रण. भाग ६ --प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--अनु० २३६-२३७

निव्चन.

- २३६ (१) इस अध्याय में---
 - (क) "जिला-न्यायाधीश" पदाविल के अन्तर्गत नगर-व्यवहार-न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला-न्यायाधीश, संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सहायक जिला-न्यायाधीश, लघुवाद-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, सत्त्र-न्यायाधीश, अपर सत्त्र-न्यायाधीश और सहायक सत्त्र-न्यायाधीश भी हैं।
 - (ख) "न्यायिक सेवा" पदाविल से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनी है, जो जिला-न्यायाधीश के पद तथा जिला-न्यायाधीश-पद से निचले अन्य व्यवहार न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्दिष्ट है।

कुछ प्रकार

या प्रकारों

के दंडाधिकारियों पर
इस अध्याय

के उपबन्धों

का लागू
होना

२३७. राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपवन्ध तथा उन के अधीन बनाये गये कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह उस बारे में नियत करे, राज्य के किसी प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों के सम्बन्ध में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे कि अधिसूचना में उल्लिखित हों, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

प्रथम अनुस्ची के भाग (ख) में के राज्य

२३८ भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूपभेदों और लुप्तियों के अधीन रह कर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उस अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, अर्थात्—

- (१) "राज्यपाल" पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड (ख) में जहां वह दूसरी बार आता है वहां को छोड़ कर, जहां भी वह उसक भाग में आता है, "राजप्रमुख" शब्द रख दिया जायेगा।
- (२) अनुच्छेद १५२ में "भाग (क)" शब्द और अक्षर के लिये "भाग (ख)" शब्द और अक्षर रख दिये जायेंगे।
- (३) अनुच्छेद १५५,१५६ और १५७ लुप्त कर दिये जायेंगे।
- (४) अनुच्छेद १५८ में—
 - (१) खंड (१) में "नियुक्त होने" शब्दों के लिये "होता है" शब्द रख दिये जायेंगे।
 - (२) खंड (३) के स्थान में निम्नलिखित खंड रखदिया जायेगा, अर्थात्—
 - "(३) राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उस का अपना निवासगृह न हो, तब विना किराया दिये पदावास के उपयोग का हक्क होगा तथा उस को ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसे कि राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।"
 - (३) खंड (४) में से "और उपलब्धियां" जब्द ल्प्त कर दिये जायेंगे।

प्रथम अनुसूची के भाग
(ख) में
उिल्लिखित
राज्यों को
भाग ६ के
उपवन्धों का
लागू होन

भाग ६ ---प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-∸ अनु० २३६-२३७

निर्वचन.

२३६ (१) इस अध्याय में---

- (क) "जिला-न्यायाधीश" पदाविल के अन्तर्गत नगर-व्यवहार-न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला-न्यायाधीश, संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सहायक जिला-न्यायाधीश, लघुवाद-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, अपर मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, सत्त्र-न्यायाधीश, अपर सत्त्र-न्यायाधीश और सहायक सत्त्र-न्यायाधीश भी हैं।
- (ख) "न्यायिक सेवा" पदाविल से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनी है, जो जिला-न्यायाधीश के पद तथा जिला-न्यायाधीश-पद से निचले अन्य व्यवहार न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्दिष्ट है।

कुछ प्रकार

या प्रकारों

के दंडाधिकारियों पर

इ.स अध्याय

के उपबन्धों

का लागू

होना

२३७ राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपवन्ध तथा उन के अधीन बनाये गये कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह उस बारे में नियत करे, राज्य के किसी प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों के सम्बन्ध में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे कि अधिसूचना में उल्लिखित हों, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य

२३८ भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उिल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में निम्निलिखित रूपभेदों और लुप्तियों के अधीन रह कर वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उस अनुसूची के भाग (क) में उिल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, अर्थात्—

- (१) "राज्यपाल" पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड (ख) में जहां वह दूसरी बार आता है वहां को छोड़ कर, जहां भी वह उस। भाग में आता है, "राजप्रमुख" शब्द रख दिया जायेगा।
- .(२) अनुच्छेद १५२ में "भाग (क)" शब्द और अक्षर के लिये "भाग (ख)" शब्द और अक्षर रख दिये जायेंगे।
- (३) अनुच्छेद १५५, १५६ और १५७ लु^रत कर दिये जायेंगे।
- (४) अनुच्छेद १५८ में—
 - (१) खंड (१) में "नियुक्त होने" शब्दों के लिये "होता है" शब्द रख दिये जायेंगे।
 - (२) खंड (३) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—
 - "(३) राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उस का अपना निवासगृह न हो, तब विना किराया दिये पदावास के उपयोग का हक्क होगा तथा उस को ऐसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसे कि राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।"
 - (३) खंड (४) में से "और उपलब्धियां" जब्द ल्प्त कर दिये जायेंगे।

प्रथम अनुसूची के भाग
(ख) में
उल्लिखित
राज्यों को
भाग ६ के
उपवन्धों का
लागू होन .

- भाग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य-अनु० २३८
 - (५) अनुच्छेद १५० में "न्यायालय का प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश" शब्दों के स्थान में "अथवा ऐसी अन्य रीति से जैसी कि राष्ट्रपति द्वारा उस बारे में निर्घारित की जाये" शब्द जोड़ दिये जायेंगे।
 - (६) अनुच्छेद १६४ में खंड (१) के परन्तुक के स्थान
 में निम्नलिखित परन्तुक रख्द्विया जायेगा:
 "परन्तु मध्यभारत राज्य में आदिमजातियों के
 कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री
 होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों
 और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का
 अथवा किसी अन्य कार्य का भार-साधक
 भी हो सकेगा।"
 - (७) अनुच्छेद १६८ में खंड (१) के स्थान में निम्न-लिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—— "१. प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा जो राजप्रमुख तथा
 - (क) मैसूर राज्य में दो सदनों से;
 - (ख) अन्य राज्यों में एक सदन से; मिल कर बनेगा।"
 - (८) अनुच्छेद १८६ में "जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है" शब्दों के स्थान में "जो राजप्रमुख निर्धारित करें" शब्द रख दिये जायेंगे।
 - (९) अनुच्छेद १९५ में "जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानीय प्रान्त की विधान-सभा के सदस्यों के विषय में लागू थे" शब्दों के स्थान में "जैसे कि राजप्रमुख निर्धारित करे" शब्द विये जायेंगे।
 - (१०) अनुच्छेद २०२ के खंड (३) में —
 (१) उपखंड (क) के स्थान में निम्नलिखित उपखंड
 रख दिया जायेगा, अर्थात—

- भाग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य---अनु० २३८
 - "(क) राजप्रमुख के भत्ते तथा उस के पद सम्बन्धी अन्य व्यय जो राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे;"
 - (२) उपखंड (च) के स्थान में निम्नलिखित उप-खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात् —
 - "(च) तिरुवांकुर-कोचीन-राज्य के बारे में ५१ लाख की राशि जिस का तिरुवांकुर और कोचीन के देशी राज्यों के शासकों द्वारा तिरुवांकुर और कोचीन संयुक्त-राज्य के निर्माण के लिये, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की गई प्रसंविदा के अबीन प्रति वर्ष देवस्वम् निधि को दिया जाना अपेक्षित है;
 - (छ) इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल से विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।"
 - (११) अनुच्छेद २०८ में खंड (२) के स्थान में निम्न-लिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—
 - "(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में जो, प्रिक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे अथवा जहां राज्य में विधान-मंडल का कोई सदन न था वहां ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे प्रान्त की, जिस को कि उस लिये उस राज्य का राजप्रमुख उल्लिखित करे, विधान-सभा के बारे में जो प्रिक्रया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों

भाग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य--अनु० २३८

> और अनुकूलनों के अधीन रह कर, जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद् का सभापित करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे।"

- (१२) अनुच्छेद २१४ के खंड (२) में "प्रान्त" शब्द के स्थान में "देशी राज्य" शब्द रख दिये जायेंगे।
- (१३) अनुच्छेद २२१ के स्थान में निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"न्यायाघीशों के वेतन इत्यादि.

- २२१. (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जैसे कि राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति निर्धारित करे।
- (२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों के, तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतनों के
 सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का जैसे संसद्निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय
 समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक
 इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे
 भत्तों और अधिकारों का, जैसे कि राजप्रमुख से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति
 निर्धारित करे, हक्क होगा:

परन्तु न तो न्यायाधीश के भत्ते और न उस के अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उस के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा।"

भाग =

प्रथम अनुद्वी के भाग (ग) में के राज्य

२३९. (१) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के अथवा पड़ौसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य करेगा:

प्रथम अनुसूची में के भाग (ग) में के राज्यों का प्रशासन.

परन्तु राष्ट्रपति--

- (क) सम्बन्धित सरकार से परामर्श किये विना, तथा
- (स) इस प्रकार प्रशासित किये जाने वाले राज्य की जनता के विचारों को उस रीति से, जिसे राष्ट्र-पित अत्यन्त समुचित समझता है, निश्चय पूर्वक जाने विना,

पड़ौसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य नहीं करेगा।

- (२) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत राज्य के भाग के निर्देश भी हैं।
- २४०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित तथा मुख्य आयुक्त या राज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिये संसद् विधि द्वारा—
 - (क) राज्य के विधान-मंडल के रूप में कृत्य करने के लिये नाम-निर्देशित या निर्वाचित अथवा अंशतः नाम-निर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय को, अथवा
 - (ख) मंत्रणा-दाताओं की, या मंत्रियों की, परिषद् को या दोनों को ऐसे गठन, शक्तियों तथा कृत्यों सिहत, जो कि प्रत्येक के बारे में विधि द्वारा उल्लिखित की जाये, सृजित कर सकेगी या बनाये रख सकेगी।

स्थानीय
विधानमंडलों अथवा
मंत्रणादाताओं या
मंत्रियों की
परिषद् का
स्जन करना
या बनाये
रखना.

भाग ८--प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य--अनु० २४०-२४१

(२) खंड (१) में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी चाहे फिर उस में कोई ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट क्यों न हो, जो इस संविधान का संशोधन करता है, या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।

धस अनुसूची के बाग (ग) में के राज्यों के छिने उच्च-

- २४१ (१) संसद् विधि द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के लिये उच्चन्यायालय गठित कर सकेगी अथवा ऐसे किसी राज्य में के किसी न्यायालय को इस संविधान के प्रयोजनों में से सब या किसी के लिय उच्चन्यायालय घोषित कर सकेगी।
- (२) खंड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में भाग (६) के अध्याय (५) के उपबन्ध, ऐसे रूपभेदों और अपवादों के अधीन रह कर, जैसे कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे इस संविधान के अनुच्छेद २१४ में निर्दिष्ट किसी उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
- (३) इस संविधान के उपबन्धों के, तथा इस संविधान के द्वारा या अधीन समुचित विधान-मंडल को दी गई शक्तियों के आधार पर उस विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के, अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्चन्यायालय, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित किसी राज्य के या उस के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था वह न्यायालय ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस राज्य या क्षेत्र के सम्बन्ध में वैसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा।
- (४) इस अनुच्छेद की कोई बात प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार को उस अनुसूची के भाग (ग)

कोइगु.

भाग द--प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य-ग्रनु० २४१-२४२

में उल्लिखित किसी राज्य पर अथवा उस राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र पर विस्तृत करने की, या उस से अपर्वाजत करने की, संसद् की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करती।

२४२. (१) जब। तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करती तब तक कोड़गू की विधान-परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य वैसे ही होंगे जैसे कि वे इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थे।

(२) कोड़गू में संगृहीत राजस्व के, तथा कोड़गू के सम्बन्ध में व्ययों के, विषय में प्रबन्ध तब तक अपरिवर्तित रहेंगे जब तक कि इस बारे में राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अन्य उपबन्ध नहीं करता।

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य राज्य-क्षेत्र जो उस ग्रनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का और उस में अनुल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन.

- २४३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र का तथा भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में अनुल्लिखित किसी अन्य राज्य-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपित करेगा तथा वह इस बारे में उस मात्रा तक, जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा।
- (२) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना हुआ कोई विनियम, संसद्-निर्मित किसी विधि का अथवा किसी वर्तमान विधि का, जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर उस का उस राज्य-क्षेत्र पर लागू संसद्-अधिनियम के जैसा ही बल और प्रभाव होगा।

अनुस्चित और आदिमजाति-चेत्र

२४४. (१) आसाम राज्य के अतिरिक्त प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में उिल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के द्वित्ये पंचम अनुसूची के उपवन्य लागू होंगे।

अनुसूचित और आदिम-जाति-क्षेत्रों का प्रशासन.

(२) आसाम राज्य में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।

संघ और राज्यों के सम्बन्ध

- 1,

अध्याय १.---वि' ायी सम्बन्ध

विधायिनी शक्तियों का वितरण

संसद् तथा राज्यों के विघान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों का विस्तार.

- २४५. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद् भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान-मंडल उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।
- (२) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, इस कारण से कि उस का राज्य-क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा, अमान्य नहीं समझी जायेगी।

संसद् द्वारा, तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा, निर्मित विधियों के विषय.

- २४६. (१) खंड (२) और (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो इस संविधान में "संघ-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।
- (२) खंड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को, तथा खंड (१) के अत्रीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (३) में (जो इस संविधान में "समवर्ती सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति है।
- (३) खंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विद्यान-मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (जो इस संविधान में "राज्य-सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे

भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध--अनु० २४६-२४९

राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(४) संसद् को भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के लिये, जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) के अन्तर्गत नहीं है, किसी भी विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति हैं चाहे फिर वह विषय "राज्य-सूची" में प्रगण्ति विषय क्यों नहो।

२४७ इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद्-निर्मित विधियों के, अथवा किसी वर्तमान विधि के, जो संघ-सूची में प्रगणित विषय के बारे में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिये संसद् किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी।

२४८. (१) संसद् को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो "समवर्ती सूची" अथवा "राज्य-सूची" में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(२) ऐसी शक्ति के अन्तर्गत ऐसे करों के, जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, आरोपण करने के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति भी है।

२४९. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य-परिषद् ने उपस्थित श्रौर मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समिथित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि संसद् राज्य-सूची में प्रगणित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के बारे में विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद् के लिये उस विषय के बारे में भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाना विधि-संगत होगा।

(२) खंड (१) के अघीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनिधक ऐसी कालावित्र के लिये प्रवृत्त रहेगा जैसी कि उस में उल्लिखित हो: किन्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना का उपवन्ध करने की संसद् की शक्ति.

अवशिष्ट विधान-शक्ति

राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची में के विषय के बारे में विघि बनाने की संसद् की शवित.

भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध--अनु० २४९-२५१

परन्तु यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त वनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (१) में उपबन्धित रीति से पारित हो जाये तो ऐसा संकल्प उस तारीख से आगे, जिस को कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त न रहता, एक वर्ष की और कालाविध तक प्रवृत्त रहेगा।

- (३) संसद् द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद् खंड (१) के अधीन संकल्प के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने से छ मास की कालाविध की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्त प्रभावी न होगी जो उक्त कालाविध की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई है।
- २५०. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी ससद् को, जब तक आपात की उद्घोपणा प्रवर्तन में है, भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उस के किसी भाग के लिये राज्य-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी।
- (२) संसद् द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद् शापात की उद्बोषणा के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन की समाप्ति के पश्चात् छ मास की कालाविध की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन सब बातों के अतिरिक्त प्रवर्तनहीन होगी जो उस कालाविध की समाप्ति से पूर्व की गई दा की जाने से छोड़ दी गई है।

अनुच्छेद २४९ और २५० के अधीन संसद् द्वारा निर्मित विधियों तथा राज्यों के विधान-मंडलों २५१. इस संविधान के अनुच्छेद २४९ और २५० की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल की कोई विधि बनाने की शिक्तत को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शिवत उसे हैं, निर्वेन्धित न करेगी किन्तु यदि किसी राज्य के विधान-मडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपबन्ध, संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् उवत दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन

यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य-मूची में के विषयों के वारे में विधि वनाने की संसद् की

भाग ११--संघ स्रौर राज्यों के सम्बन्ध--अनु० २५१-२५३

बनाने की शक्ति रखती है, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो, संसद् द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित हुई हो तथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक प्रवर्तन-शून्य होगी किन्तु तभी तक जब तक कि संसद् द्वारा निर्मित विधि प्रभावी रहे।

द्वारा निर्मित् विधियों में असंगतिः

२५२. (१) यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिन के बारे में संसद् को, अनुच्छेद २४९ और २५० में उपविध्यत रीति के अतिरिवत, उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सब सदनों ने उस लिये संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि-संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी अन्य राज्य को, जो तत्पश्चात् अपने विधान-मंडल के सदन अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक से उस लिये पारित संकल्प द्वारा उस को अंगीकार करे, लागू होगा।

दो या अधिक राज्यों के लिये उन की सम्मति से विधि वंनाने की संसद् की शक्ति तथा ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना.

(२) संसद् द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद् के अधिनियम से संशोधित या निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के सम्बन्ध में, जहां कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम से संशोधित या निरसित न किया जायेगा।

२५३ इस अध्याय के पूर्वगामी उपवन्धों में किसी बात के होते हुए भी, ससर् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सन्या या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिञ्चय के परिपालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उस के किसी भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है।

अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ विधान-

भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध-अनु० २५४-२५५

संसद् द्वारा निर्मित विधियों श्रौर राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति.

- १५४. (१) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई उपबन्ध संसद् द्वारा निर्मित विधि के, जिसे संसद् अधिनियमित करने के लिये सक्षम हैं, किसी उपबन्ध, अथवा समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान विधि के, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थित संसद् द्वारा निर्मित विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के पहिले या पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि अभिभावी होगी, तथा उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि की मात्रा तक शून्य होगी।
- (२) जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में है, कोई ऐसा उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो जो संसद् द्वारा पहिले निर्मित की गई विधि के, अथवा उस विषय के बारे में किसी वर्तमान विधि के, विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि उस राज्य में अभिभावी होगी यदि उस को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया गया है और उस पर उस की अनुमित मिल चुकी है:

परन्तु इस खंड की कोई बात संसद् को, किसी समय उसी विषय के सम्बन्ध में कोई विधि, जिस के अन्तर्गत ऐसी विधि भी है जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, अधिनियमित करने से न रोकेगी।

सिपारिशों भौर पूर्वं मंजूरी की अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय माननाः

- २५५. यदि संसद् के, अथवा पहिली अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम को—
 - (क) जहां राज्यपाल की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने ;

भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध--अनु० २५५-२५७

- (ख) जहां राजप्रमुख की सिपारिश अपेक्षित थी वहां राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने ;
- (ग) जहां राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने,

अनुमित दी है तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम का कोई उपबन्ध केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिपारिश न की गई या पूर्व मंजूरी न दी गई थी।

अध्याय २.--प्रशासन-सम्बन्ध

साधारण

२५६. प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होगा, कि जिस से संसद् द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, पालन सुनिश्चित रहे तथा संब की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे।

संघ और राज्यों के आभार.

- २५७. (१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिस से संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे।
- अवस्थाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण.

किन्हीं

(२) संघ की कार्यपालिका गक्ति का विस्तार राज्य को किसी ऐसे संचार-सायनों के निर्माण करने और बनाये रखने के लिये निदेश देने तक भी विस्तृत होगा जिन का राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो:

परन्तु इस खंड की कोई बात राज-पथों या जल-पथों को राष्ट्रीय राज -पथ या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करने की संसद् की शक्तियों, अथवा इस प्रकार घोषित राज-पथ या जल-पथ के

भाग ११--संघ श्रौर राज्यों के सम्बन्ध--अनु० २५७-२५८

बारे में संघ की शक्ति को, अथवा नौ-बल, स्थल-बल, और विमान-बल कर्मशालाओं विषयक अपने कृत्यों का भाग मान कर संचार-साधनों के निर्माण और बनाये रखने की संघ की शक्ति को निर्वन्धित करने वाली न मानी जायेगी।

- (३) किसी राज्य में की रेलों की रक्षा के लियें किये का जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निदेश देने तक भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा।
- (४) जहां खड (२) के अधीन संचार-साधनों के निर्माण अथवा उन को बनाये रखने के बारे में, अथवा खंड (३) के अधीन किसी रेल की रक्षा के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निदेश के पालन में उस से अधिक खर्च होता है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया होता तो, राज्य के माम्ली कर्तव्यों के पालन में खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा करार के अभाव मे, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।

कतिपय अवस्थाओं में राज्यों को शक्ति आदि देने की संघ की शक्ति.

- २५८. (१) इस सविधान में किसी वात के होते हुए भी किसी राज्य की सरकार की सम्मित से राष्ट्रपति, उस सरकार को या उस के पदाधिकारियों को ऐसे किसी विषय सम्बन्धी कृत्य, जिन पर सब की कार्यपालिका बिस्त का विस्तार है, बार्ती के साथ या विना बार्त सौंप सकेगा।
- (२) ऐसे विषय से, जिस के बारे में राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शिवत नहीं है, सम्बद्ध होने पर भी संसद्-निर्मित विधि, जो किसी राज्य में लागू है, उस राज्य अथवा उस के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शिंदत दे सकेगी और कर्तव्य आरोपित कर सकेगी अथवा शिवतयां दिया जाना और कर्तव्य आरोपित किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी।

भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बंन्ध--अनु० २५८-२६१

- '(३) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा उस के पदाधिकारियों या प्राधिकारियों को शिवतयां दी गई हैं, अथवा कर्तव्य आरोपित कर दिये गये हैं वहां उन शिवतयों और कर्तव्यों के प्रयोग के बारे में राज्य द्वारा प्रशासन में किये गये अति-रिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा करार के अभाव में जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे।
- २५९. (१) इस संविधान में किसी वात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य, जो कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पिहले सज्ञस्त्र बलों को रखता था, उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रह कर, जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर इस बारे में निकाले, तब तक बनाये रख सकेगा जब तक कि संसद् विविद्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे।
- (२) कोई ऐसे सशस्त्र वल, जंसे कि खंड (१) में निर्दिष्ट हैं, संघ के सशस्त्र बलों का भाग होंगे।
- २६०. भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, जो भारत राज्य-क्षेत्र का भाग नहीं है, करार कर के ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों को ग्रहण कर सकेगी किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी क्षेत्रा-धिकार के प्रयोग से सम्बद्ध दिसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रहेगा और उस से शासित होगा।
- २६१. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र, संघ की और प्रत्येक राज्य की, सार्वजिनक कियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास ग्रौर पूरी मान्यता दी जायेगी।
- (२) खंड (१) में निर्दिष्ट क्रियाओं, अभिलेखों और कार्यवाहियों की सिद्धि की रीति और शर्तें तथा उन के प्रभाव

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों में के सशस्त्र बल.

भारत के
वाहर के
राज्य-क्षेत्रों के
सम्बन्ध में
मंघ का
क्षेत्राधिकार

सार्वजनिक किया, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां.

भाग ११---संघ और राज्यों के सम्बन्ध-अनु० २६१-२६३

का निर्धारण संसद्-निर्मित विधि द्वारा उपबन्धित रीति के अनुसार होगा।

(३) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में के व्यवहार न्यायालयों द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय या आदेश उस राज्य-क्षेत्र के अन्दर कहीं भी विधि अनुसार निष्पादन-योग्य होंगे।

जल सम्बन्धी विवाद

अन्तर्राज्यिक निंदरों या नदी-दूनों के जल सम्बन्धी वादों का न्याय-निर्णयन-

- २६२ (१) संसद् विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी या नदी-दून के, या में, जलों के प्रयोग, वितरण, या नियंत्रण के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय-निर्णयन के लिये उपवन्ध कर सकेगी।
- (२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी कि न तो उच्चतम-न्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

राज्यों के बीच समन्वय

अन्तर्राज्य-परिषद् विषयक उपबन्ध. २६३ यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक-हितों की सिद्धि होगी, जिस पर —

- (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उन की जांच करने और उन पर मन्त्रणा देने;
- (ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के, पारस्परिक हित से सम्बद्घ विषयों के अनुसन्नान और चर्चाः करने; अथवा

भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध--अनु०२६३

(ग) ऐसे किसी विषय पर सिपारिश करने, और विशेषतः उस विषय के बारे में नीति और कार्यवाही के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु सिपारिश करने,

का भार हो तो राष्ट्रपित के लिये यह विधि-संगत होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे तथा उस परिषद् के द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को और उस के संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे।

भाग १२

वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं श्रीर व्यवहार-वाद श्रध्याय १ -- वित्त साधारण

निर्वचन.

२६४ इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "वित्त-आयोग" से इस संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त-आयोग अभिप्रेत है;
- (ख) ''राज्य'' के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित कोई राज्य नहीं है;
- (ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के निर्देशों के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी राज्य-क्षेत्र के, तथा किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के जो भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट तो हो किन्तु उस अनुसूची में उल्लिखित न हो, निदेश भी होंगे।

विधि-प्राधि-कार के सि-वाय करों का आरोपण न करना. २६५. विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित और न संगृहीत किया जायेगा ।

भारत और राज्यों की संचित निधि-यां और लोक-लेंसे. २६६० (१) अनुच्छेद २६७ के उपबन्धों के, तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के राज्यों को पूर्णतः या अंशतः सौंपे जान के बारे में इस अध्याय के उपबन्धों के, अधीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राजहंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो

भाग १२—-वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—-अनु० २६६-२६७

"भारत की संचित निधि" के नाम से जात होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल कर, जिंधार द्वारा और अर्थोपाय पेशिंगयों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी।

- (२) भारत की सरकार या राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर से, प्राप्त अन्य सब सार्वजिनिक धन यथास्थिति भारत के या राज्य के लोक-लेखे में जमा किये जायेंगे।
- (३) भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन विधि की अनुकूलता से, तथा इस संविधान में उपविन्धित प्रयोजनों और रीति से, अन्यथा विनियुक्त नहीं किये जायेंगे।
- २६७. (१) संसद्, विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में 'भारत की आकस्मिकता-निधि' के नाम से ज्ञात आकस्मिकता-निधि की स्थापना कर सकेगी जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राज्ञियां, समय-समय, पर डाली जायेंगी, तथा अनवे-क्षित व्यय का अनुच्छेद ११५ या अनुच्छेद ११६ के अधीन संसद् द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये राष्ट्रपति को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी जायेगी।
- (२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में "राज्य की आकस्मिकता-निधि" के नाम से ज्ञात आकस्मिकता-निधि की स्थापना कर सकेगा जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्धा-रित राशियां समय समय पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद २०५ या अनुच्छेद २०६ के अधीन राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लिम्बत रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्रिम धन देने के लिये उस को योग्य बनाने के हेतु ऐसी निधि राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के हाथ में रखी जायेगी।

आकस्मिकता-निधि. भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-अनु० २६८-२६९

संघतथा राज्यों में राजस्वों का वितरण

संघ द्वारा आरोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क.

- २६८ (१) ऐसे मुद्रांक-शुल्क तथा औषधीय और प्रसा-धनीय सामग्री पर ऐसे उत्पादन-शुल्क जो संघ-सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा आरोपित किय जायेंगे, किन्तु—
 - (क) उस अवस्था में जिस में कि ये शुल्क प्रथम अनुसूची
 के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य के भीतर
 उद्गृहीत किये जाने वाले हों, भारत सरकार
 द्वारा, तथा
 - (ख) अन्य अवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्गृहीत किये जाने वाले हों, उन उन राज्यों द्वारा,

संगृहीत किये जायेंगे।

(२) जो शुल्क किसी राज्य के भीतर उद्गृहीत किये जाने वाले हैं उन में से किसी के, किसी वित्तीय वर्ष के आगम, भारत की संचित निधि के भाग न होंगे किन्तु उस राज्य को सौंप दिये जायेंगे।

संघ द्वारा बारोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंपे जाने नाले कर.

- २६९. (१) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात्—
 - (क) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क;
 - (ख) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क;
 - (ग) रेल, समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर:
 - (घ) रेल भाड़ों और वस्तु-भाड़ों पर कर;
 - (ङ) श्रेष्ठि-चत्वरों और वायदा बाजारों के सौदों पर मुद्रांक-शुल्क से अन्य कर;

भाग १२——वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—— अनु० २६९-२७०

- (च) समाचार-पत्रों के ऋय-विऋय तथा उन में प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।
- (२) किसी वित्तीय वर्ष में के ऐसे किसी शुल्क या वर के शुद्ध आगम, वहां तक भारत की संचित निधि के भाग न होंगे, जहां तक कि वे आगम प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों से मिलने वाले माने जायें, किन्तु उन राज्यों को सौंप दिये जायेंगे जिन में वह शुल्क या कर उस वर्ष में उद्गृहीत होना है तथा उन राज्यों में ऐसे वितरण-सिद्धान्तों के अनुकूल वितरित किये जायेंगे जैसे कि संसद् विधि द्वारा सूत्रित करे।
- ! २७० (१) कृषि-आय से अतिरिक्त अन्य आय पर करों को भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा तथा खंड (२) में उपबन्धित रीति के अनुसार संघ और राज्यों के बीच में वितरित किया जायेगा।
- (२) किसी वित्तीय वर्ष, में के किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम का, जहां तक वह आगम प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उिल्लिखित राज्यों में से अथवा संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों से मिला हुआ आगम माना जाये वहां तक के सिवाय, एसा प्रतिशत भाग, जैसा विहित किया जाये, भारत की संचित निधि का भाग न होगा किन्तु उन राज्यों को सौंपा जायेगा जिन के भीतर वह कर उद्गृहीत होना है तथा वह उन राज्यों को उस रीति और उस समय से, जो विहित किया जाये, वितरित होगा।
 - (३) खंड (२) के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय पर करों के उतने शुद्ध आगम का, जितना कि संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों का शुद्ध आगम नहीं है, वह प्रतिशत भाग, जो विहित किया जाये, प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों में से मिला हुआ आगम समझा जायेगा ।

संघ द्वारा उद्ग्रृहीत मौर संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरितः कर. भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु० २७०-२७२

- (४) इस अनुच्छेद में-
 - (क) "आय पर करो" के अन्तर्गत निगम-कर नहीं हैं;
 - (ख) "विहित" का अर्थ है कि--
 - (१) जब तक वित्त-आयोग गठित न हो जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित; तथा
 - (२) वित्त-आयोग के गठित हो जाने के पश्चात् वित्त-आयोग की सिपारिशों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित;
 - (ग) "संघ-उपलब्धियों" के अन्तर्गत भारत संचित निधि

 में से दी जाने वाली सब उपलब्धियां और

 निवृत्ति-वेतन, जिन के सम्बन्ध में आय-कर

 आरोपित किया जा सकता है, भी हैं।

२७१ अनुच्छेद २६९ और २७० में किसी बात के होते हुए भी संसद् उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिये अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अधिभार के समस्त आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे।

संघ के
प्रयोजनों के
लिये शुल्क
और करों पर
अधिभार.

कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत श्रीर संगृहीत हैं तथा जो संघ श्रीर राज्यों के बीच वितरित किये जा सकेंगे. २७२ संघ सूची में विणित औषधीय तथा प्रसाधन-सामग्री पर उत्पादन-शुल्क से अन्य संघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु यदि संसद् विधि द्वारा यह उपबन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली विधि जिन राज्यों को लागू होती हो उन राज्यों को भारत की संचित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध आगमों के पूर्ण अथवा किसी भाग के बराबर राशि दी जायेगी और वे राशियां उन राज्यों के बीच विधि द्वारा सूत्र-बद्ध वितरण-सिद्धान्तों के अनुसार वितरित की जायेंगी।

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद— अनु० २७३-२७४

२७३ (१) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम के किसी भाग को आसाम, उड़ीसा, पिंचमी बंगाल और बिहार राज्यों को सौंपने के स्थान में उन राज्यों के राजस्व में सहायक अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जायेंगी जैसी कि विहित की जायें।

पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के स्थान में अनुदान

- (२) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यात-शुल्क उद्गृहीत करती रहे अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहिले हो उस के होने तक, इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी।
- (३) इस अनुच्छेद में "विहित" पद का वही अर्थ है जो इस संविधान के अनुच्छेद २७० में है।
- २७४ (१) कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है, उस को आरोपित या परिवर्तित करता है, अथवा जो भारत आय-कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित "कृषि-आय" पदावलि के अर्थ को परिवर्तित करता है, अथवा जो उन सिद्धान्तों को प्रभावित करता है जिन से कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को घन वितरणीय हैं या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के लिये ऐसा कोई अधिभार आरोपित करता है जैसा कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में विणत है, राष्ट्रपित की सिपारिश के विना संसद् के किसी सदन में न तो पुरःस्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा।
- (२) इस अनुच्छेद में ''जिस कर या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध है'' पदाविल से अभिप्रेत हैं --

राज्यों के हितों से सम्बद्ध करों पर प्रभाव डालने वालें विधेयकों के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सिपारिश की अपेक्षा

भाग १२——वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार -वाद—— २७४-२७५

- (क) कोई कर या शुल्क जिस का शुद्ध आगम पूर्णतः या अंशतः किसी राज्य को सौंप दिया जाता है, अथवा
- (ख) कोई कर या शुल्क जिस के शुद्ध आगम के निर्देश से भारत संचित निधि में से तत्समय किसी राज्य को राशियां दी जानी हैं।

कतिपय राज्यों को संघ से अनुदान २७५ ऐसी राशियां, जो संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद् यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तथा भिन्न भिन्न राज्यों के लिये भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी:

परन्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से वैसी मृल तथा आव-तैंक राशियां दी जायेंगी जैसी कि उस राज्य को उन विकास-योजनाओं के खर्चों के उठाने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों, जो उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिये अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिये उस राज्य ने भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली हों:

परन्तु यह और भी कि आसाम राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से वैसी मूल तथा आवर्तक राशियां दी जायेंगी—

(क) जो षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न सारिणी के भाग (क) में उल्लिखित आदिम-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं भौर व्यवहार-वाद-अनु० २७५-२७६

> के प्रारम्भ से ठीक पहिले दो वर्ष में राजस्वों से औसतन अधिक व्यय के बराबर हों; तथा

- (ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिये उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली गई योजनाओं के खर्चों के बराबर हों।
- (२) जब तक खंड (१) के अघीन संसद् द्वारा उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक उस खंड के अघीन संसद् को प्रदत्त शक्तियां राष्ट्रपति से आदेश द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी तथा इस खंड के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिया कोई आदेश संसद् द्वारा इस प्रकार निर्मित किसी उपबन्ध के अधीन रह कर ही प्रभावी होगा:

परन्तु वित्त-आयोग गठित हो जाने के पश्चात् वित्त-आयोग की सिपारिशों पर विचार किये विना इस खंड के अधीन कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया जायेगा।

- २७६. (१) अनुच्छेद २४६ में किसी बात के होतें हुए भी किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई विधि, जो उस राज्य या किसी नगर-पालिका, जिला-मंडली, स्थानीय मंडली अथवा उस में अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हित साधन के लिये वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नौकरियों के बारे में लागू होती है, इस आधार पर अमान्य न होगी कि वह आय पर कर है।
- (२) राज्य को अथवा उस में की किसी एक नगर-पालिका, जिला-मंडली, स्थानीय मंडली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर करों द्वारा देय समस्त राशि दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी:

वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर **डर**. भाग १२—वित्त,सम्पत्ति, संविदाएं ग्रौर व्यवहार-वाद— अनु० २७६-२७८

परन्तु यदि इस सिवधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में अथवा किसी ऐसी नगर पालिका, मंडली या प्राधिकारी में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नौकरियों पर ऐसा कर लागू था जिस की दर या जिस की अधिकतम दर दो सौ पचास रुपये प्रति, वर्ष से अधिक थी तो ऐसा कर उस समय तक उद्गृहीत होता रहेगा जब तक कि संमद् विधि द्वारा इम के प्रतिकूल उपबन्ध न करे तथा संसद् द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतया या किन्हीं उल्लिखित राज्यों, नगर-पालिकाओं, मंडलियों या प्राधिकारियों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी।

(३) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर के विषय में उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का यह अर्थं न किया जायेगा कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोद्भूत या उत्पन्न आय पर करों के विषय में विधियां बनाने की संसद् की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई है।

व्यावृत्ति,

२७७ जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संविधान से ठीक पहिले किसी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा किसी नगर-पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिये विधिवत् उद्गृहीत किये जा रहे थे, वे कर, शुल्क, उपकर या फीस संव-सूची में वर्णित होने पर भी उद्गृहीत किये जाते रहेंगे तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाये जा सकेंगे जब तक कि संसद् विधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपबन्ध न करे।

२७८. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार, खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य की सरकार से——

(क) ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किये जाने वाले किसी कर या शुल्क के उद्ग्रहण और

कतिपय वि-त्तीय विषयों के बारे में प्रथम अनु-सूची के भाग (ख) के राज्यों से करार, भाग १२—–वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—– अनु० २७८-२७९

> संग्रह करने तथा उस के आगम के, इस अध्याय के उपबन्धों से अन्यथा, वितरण करने के;

- (ख) भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन उद्गृहीत किये जाने वाले किसी कर या शुल्क से अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से जो राजस्व वह राज्य पाता था उस की हानि के लिये ऐसे राज्य को भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान करने के;
- (ग) अनुच्छेद २९१ के खंड (१) के अधीन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले किसी देय घन के विषय में ऐसे राज्य द्वारा अंशदान करने के,

विषय में करार कर सकेगी, तथा जब ऐसा करार किया जाये तब इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे राज्य के सम्बन्ध में ऐसे करार के निबन्धनों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

(२) खंड (१) के अधीन किया गया कोई करार इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनिधक काल के लिये प्रवृत्त रहेगा:

परन्तु राष्ट्रपति ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय भी यदि वह वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा करना आवश्यक समझे तो, ऐसे किसी करार की समाप्ति या रूपभेद कर सकेगा।

२७९. (१) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में "शुद्ध आगम" से किसी कर या शुल्क के सम्बन्ध में उस आगम से अभिप्राय है जो उस के संग्रह के खर्चों को घटाने के पश्चात् बचे, तथा उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये किसी क्षेत्र के भीतर, अथवा उस से, मिले हुए माने जाने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा, किसी कर या शुल्क के किसी भाग का, शुद्ध आगम, भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित तथा प्रमाणित किया जायेगा, जिस का प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा।

शुद्ध आगम की गराना

(२) किसी अवस्था में जहां इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को विनियोजित किया जाता है या किया जाये वहां उपरोक्त उपबन्ध के तथा इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुए संसद्-निर्मित कोई विधि अथवा राष्ट्रपति का कोई आदेश, उस रीति का जिस से कि आगम की गणना की जानी है, उस समय का जिस से या जिस में तथा उस रीति का जिस से कोई शोधन किये जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का तथा अन्य किसी प्रासंगिक और सहायक बातों का उपबन्ध कर सकेगा।

विस-आयोग.

- २८०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर, अथवा उस से पहिले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग गठित करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सभापति और चार अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा।
- (२) संसद् विधि द्वारा उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिस के अनुसार उन का संवरण किया जायेगा, निर्धारण कर सकेगी।
 - (३) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह--
 - (क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगम का, जो इस अध्याय के अधीन उन में विभाजित होता है या होवे, वितरण के बारे में, तथा राज्यों के बीच ऐसे आगम के तत्सम्बन्धी अंशों के बंटवारे के बारे में;
 - (स) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान देने में पालनीय सिद्धान्तों के बारे में;

Ļ,

भाग १२—-वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-अनु० २८०-२८३

- (ग) अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन या अनुच्छेद ३०६ के अधीन भारत सरकार और प्रथम अनु-सूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के बीच किये गये किसी करार के उपबन्धों के चालू रखने अथवा रूपभेद करने के बारे में; तथा
- (घ) सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में ; राष्ट्रपति को सिपारिश करे।
- (४) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद् विधि द्वारा उसे प्रदान करे।

२८१ राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त-आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिपारिश को, उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन के सिहत, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

प्रकीणं वित्तीय उपबन्ध

२८२ संघ या राज्य किसी सार्वजिनक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान दे सकेगा, चाहे फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिस के विषय में यथास्थिति संसद् या उस राज्य का विधान-मंडल, विधि वना सकता है।

२८३. (१) भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धन का डालना उन से धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये जाने वाले धन से अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, उन का भारत के लोक-लेखों में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सब विषयों का विनियमन संसद् द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध इस प्रकार न किया जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों से होगा।

वित्त-आयोग की सिंधारिशें.

संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय

संचित निधियों की, आकस्मिकता-निधियों की तथा लोक-लेखों में जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि, भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद— अनु० २८३-२८५

(२) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकि स्विता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में घन का डालना, उन से धन का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये वन से अतिरिक्त राज्य की सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा, उन का राज्य के लोक-लेखे में दिया जाना तथा ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपर्युक्त विषयों से मंसवन या महायक अन्य सब विषयों का विनियमन राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से होगा तथा जब तक उस लिये उपवन्ध उस प्रकार नहीं किया जाये तब तक राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा निर्मित नियमों से होगा।

लोक-सेवकों श्रीर त्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों क निक्षेप और अन्य वन की अभिरक्षा. २८४. यथास्थिति भारत के लोक-लेखे में या राज्य के लोक-लेखे में---

- (क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा वसूल किये गये या प्राप्त राजस्व या लोक-धन को छोड़ कर, संघ या राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नौकरी में लगे हुए किसी पदाधिकारी को उस की उस हैसियतें में; अथवा
- (ख) किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में जमा किये गये भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्दर किसी न्यायालय को

प्राप्त या निक्षिप्त सब धन डाले जायेंगे।

संघकी सम्पत्ति की राज्य के करों से विमुक्ति.

- २८५ (१) जहां तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक किसी राज्य द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित सब करों से संघ की सम्पत्ति विमुक्त होगी।
- (२) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक खंड (१) की कोई बात किसी राज्य के अन्तर्गेत किसी प्राधिकारी को संघ की किसी सम्पत्ति पर कोई ऐसा कर उद्गृहीत करने में बाधा नहीं डालेगी जिस का

भाग१२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद— अनु० २८५-२८६

दायित्व, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, ऐसी सम्पत्ति पर था या समझा जाता था जब तक कि वह कर उस राज्य में लगा रहे।

२८६ (१) राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के ऋय और विऋय पर, जहां ऐसा ऋय या विऋय—

- (क) राज्य के बाहर, अथवा
- (ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उस के बाहर निर्यात के दौरान में, होता है वहां कोई करारोपण, न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी।

व्याख्या,—उपखंड (१) के प्रयोजनों के लिये कोई क्रय या विकय उस राज्य में हुआ समझा जायेगा जिस में ऐसे क्रय या विकय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया गया है चाहे फिर वस्तु-विकय सम्बन्धी साधारण विधि के अधीन उन वस्तुओं का, स्वर्व हस्तान्तरण ऐसे क्रय या विकय के कारण किसी दूसरे राज्य में क्यों न हो चुका हो।

(२) जहां तक मंसद् विधि द्वारा अन्यथा उपविन्धित करे उस के अतिरिक्त राज्य की कोई विधि किन्हीं वस्तुओं के कथ या विक्रय पर वहां कोई करारोगण न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगो जहां ऐसा कथ-विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान में होता है:

परन्तु राष्ट्रपित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कोई कर, जो किसी राज्य की सरकार द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले विधि-वत् उद्गृहीत किया जा रहा था, इस बात के होते हुए भी कि ऐसे कर का आरोपण इस खंड के उपबन्धों के प्रतिकूल है, १९५१ के मार्च के ३१वें दिन तक उद्गृहोत किया जाना रहेगा। वस्तुओं के
कय या विक्रय
पर करारोपण
के बारे में
निर्वन्धन

भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं ग्रौर व्यवहार-वाद— अनु० २८६-२८७

(३) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि, ऐसी वस्तुओं के, जो संसद् द्वारा समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक घोषित की गई हैं, क्रय या विक्रय पर करारोपण करती या करना प्राधिकृन करती है, तब तक प्रभावी न होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने पर उसे उस की अनुमित प्राप्त न हो गई हो।

'विद्युत पर करों से विमुक्ति, २८७. जहां तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे उस को छोड़ कर (सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्युत के उपभोग या ऋय पर, जो—

- (क) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त है अथवा भारत सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये उस सरकार को बेची गई है; अथवा
- (ख) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में भारत सरकार या रेलवे कम्पनी द्वारा जो उस रेलवे को चलानी है उपभुक्त है, अथवा किसी रेल के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये उस सरकार अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को बेची गई है,

राज्य की कोई विधि कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरो-पित करना प्राधिकृत करेगी; तथा विद्युत के ऋय पर कर-आरोपण करने, या कर आरोपित करना प्राधिकृत करने, वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उस सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये, अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय को, जैसा कि उपर्युक्त है, किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग के लिये, बेची गई विद्युत का मूल्य उस मूल्य से, जो कि विद्युत की प्रचुर-मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं से लिया जाता है, इतना कम होगा, जितनी कि कर की राशि है। भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु० २८८-२८९

२८८. (१) जहां तक कि राष्ट्रपित आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे, उस को छोड़ कर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि, किसी पानी या विद्युत के बारे में जो अन्तर्राज्यिक निदयों या नदी-दूनों के विनियमन या विकास के लिये किसी वर्तमान विधि से, अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि से, स्थापित किसी प्राविकारी द्वारा जमा की गई, पैदा की गई, उपभुक्त, वितरित या बेची गई है, कोई कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी।

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में "राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि' के अन्तर्गत राज्य की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित या निर्मित हो तथा पहिले ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब पूर्णतः, अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हों।

- (२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा खंड (१) में वर्णित कोई कर आरोपित, या आरोपित करना प्राधिकृत, कर सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपित के विचार के लिये रक्षित रखे जाने के पश्चात् उस की अनुमित न मिल गई हो, तथा यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रासंगिक बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाये जाने वाले नियमों या आदेशों के द्वारा, नियत करने का उपबन्ध करती है, तो विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के बनाने के लिये राष्ट्रपित की पूर्व सम्मित लिये जाने का उपबन्ध करेगी।
- २८९. (१) राज्य की सम्पत्ति और आय संघ के कराधान से विमुक्त होंगी ।
- (२) खंड (१) की किसी बात से संघंको राज्य की सरकार द्वारा, या की ओर से किये जाने वाले, किसी प्रकार के व्यापार या कारबार के बारे में, अथवा उन से सम्बन्धित

पानी या विद्युत के विषय में राज्य द्वारा लिये जाने वाले करों से कुछ् अवस्था-ओं में वि-मुक्ति.

संघ के
कराधान से
राज्यों की
सम्पत्ति और
आय की
विमुक्ति.

भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं ग्रौर व्यवहार-वाद-अनु० २८९-२९०

किन्हीं कियाओं के बारे में, अथवा उन के प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई, किसी सम्पत्ति के बारे में, अथवा उन से प्रोद्भूत या उत्पन्न किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक, यदि कोई हो, जिसे कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, आरोपित करने या आरोपित करना प्राधिकृत करने में रुकावट नहीं होगी।

(३) खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारवार अथवा व्यापार या कारबार के किसी ऐसे प्रकार को लागू न होगी जिसे कि संसद् विधि द्वारा घोषित करे कि वह सरकार के मामूली कृत्यों से प्रामंगिक है।

कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन. २९० जहां इस मंविधान के उपबन्धों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के प्रारम्भ में पूर्व भारत में सम्राट् के अधीन, अथवा ऐसे प्रारम्भ के पदचात् संघ के या किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा की है उस को या उस के बारे में देय निवृत्ति-वेतन भारत की सचित निधि अथवा राज्यों की संचित निधि पर भारित हैं, वहां यदि—

- (क) भारत की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था में, वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की किन्हीं पृथक् आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता हो, अथवा उम व्यक्ति ने राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या अंशतः सेवा की हो; अथवा
- (ख) राज्य की संचित निधि पर भारित होने की अवस्था में न्यायालय या आयोग संघ की या अन्य राज्य की पृथक् आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता हो अथवा उस व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या अंशतः सेवा की

भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु० २९०-२९२

हो,

तो उस राज्य की संचित निधि पर अथवा यथास्थिति भारत की , संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि पर व्यय विषयक या निवृत्ति-वेतन विषयक उतना अंशदान भारित होगा और उस निधि से दिया जायेगा जितना कि करार हो, अथवा करार के अभाव में उतना अंशदान जितना कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्घारित करे।

२९१. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई कि ती प्रसंविदा या करार के अवीन ऐसे राज्य के शासक को निजी थैली के रूप में किन्हीं राशियों की कर मक्त देनगी भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित की गई है वहां—

- (क) सी राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी तथा उस में से दी जायेंगी; तथा
- (ख) किसी शासक को दी गई वैसी राशियां, सभी , अाय पर करों से विमुक्त होंगी ।
- (२) उपर्युक्त जैसे किसी देशी राज्य के राज्य-क्षेत्र जहां प्रथम अनसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में समाविष्ट हैं वहां खंड (१) के अधीन भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली देनगियों के विषय में ऐसा अंशदान, यदि कोई हो, उस राज्य की संचित निधि पर भारित होगा और उस से दिया जायेगा और ऐसी कालावधि के लिये जैसी कि अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन उस बारे में किये गये किसी करार के अधीन रह कर राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।

अध्याय २.--उधार लेना

२९२ भारत की संचित निधि की प्रतिभृति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद् समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक तथा ऐसी निजी यैली की राशि.

शासकों की

भारत सरकार द्वारा उधार लेनाः भाग १२—वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—
अनु० २९२-२९३

सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक, संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है।

राज्यों द्वारा उधार लेना.

- २९३ (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक तथा एसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाये, प्रत्याभूति देने तक विस्तृत है ।
- (२) भारत सरकार ऐसी शतों के साथ, जैसी कि संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन रखी जायें, किसी राज्य को उधार दे सकेगी, अथवा जहां तक इस संविधान के अनुच्छेद २९२ के अनुसार नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंधन न होता हो वहां तक ऐसे किसी राज्य के द्वारा लिये गरं उधारों के बारे में प्रत्याभूति दे सकेगी तथा, जो राशियां ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, वे भारत की संचित निधि पर भारित होंगी।
- (३) यदि किसी ऐसे उधार का, जिसे भारत सरकार ने या उसकी पूर्विधिकारी सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके विषय में भारत सरकार ने अथवा उसकी पूर्विधिकारी सरकार ने प्रत्याभूति । थी, कोई भाग देना शेष है तो वह राज्य भारत सरकार की सम्मति के बिना कोई उधार न ले सकेगा ।
- (४) खंड (३) के अनुसार सम्मति उन शर्ती के अधीन, यदि कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार आरोपित करना उँचित समझे।

भाग १२—-वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु० २९४

श्रध्याय ३. --प्तम्पत्ति, संत्रिदा, श्रधिकार, दायित्व श्राभार श्रीर व्यवहार-वाद

२९४. इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर--

- (क) जो सम्गत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट् में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं तथा जो सम्पत्ति और आस्तियां प्रत्येक राज्यपाल-प्रान्त की सरकार के प्रयोजनों के लिये सम्राट् में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रान्तों के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर कमशा. संव और तत्स्थानी राज्य में निहित होंगी; तथा
- (ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार भारत डोमीनियन की सरकार के तथा प्रत्येक राज्यपाल-प्रान्त की सरकार के थे, चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पृहिले पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा पिरचमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पिर्वमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के प्रान्तों के सृजन के कारण किये गये या किये जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रह कर क्रमशः भारत सरकार तथा प्रत्येक तत्स्थानी राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे।

कतिपय अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अभिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तरा-धिकार. भाग १२—-वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु०२९५

अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति,
शास्तियों,
अधिकारों,
दायित्वों और
आभारों का
उत्तराधिकार.

- २९५. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर-
 - (क) जो सम्पत्तियां और आस्तियां प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं वे सब, ऐसे करार के अधीन रह कर जैसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करे, संघ में निहित होंगी यदि जिन प्रयोजनों के लिये ऐसी सम्पत्तियां और आस्तियां ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले संघृत थीं, वे तत्पश्चात् संघ-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध संघ के प्रयोजन हों, तथा
 - (ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थे चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब ऐसे करार के अवीन रह कर जैसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे यदि जिन प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे अधिकार अजित किये गये थे अथवा दायित्व या आभार लिये गये थे, वे संघ-सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध भारत सरकार के प्रयोजन हों।
- (२) उपरोक्त के अधीन रह कर, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सब सम्पत्ति और आस्तियों, तथा संविदा से या अन्यथा उद्भूत सब अधिकारों, दायित्वों और आभारों के बारे में, जो खंड (१) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं, तत्स्थानी देशी राज्य की इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर उत्तराधिकारिणी होगी।

भाग १२--वित्त, सम्पत्ति संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु० २९६-२९८

२९६. एतत्परचात् उपबन्धित के अधीन रह कर यदि द्व यह संविधान प्रवर्तन में न आया होता तो जो कोई सम्पत्ति भारत राज्य-क्षेत्र में राजगामी या व्यपगत होने से, या अधिकारयुक्त स्वामी के अभाव में स्वामिहीनत्व-रिक्थ के रूप में यथास्थिति सम्राट् को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, वह सम्पत्ति यदि राज्य में स्थित हो तो ऐसे राज्य में और किसी अन्य अवस्था में, संघ में निहित होगी:

परन्तु कोई सम्पत्ति, जो उस तारीख को, जब कि वह इस प्रकार सम्राट् को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोट्भूत हुई होती भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के कब्जे या वियंत्रण में थी, तब यदि उस का जिन प्रयोजनों के लिये उस समय उपयोग या घारण था, वे प्रयोजन संघ के थे. तो वह संघ में और यदि वे प्रयोजन किसी राज्य के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी।

व्याख्या.—इस अनुच्छेद में "शासकं अौर "देशी राज्य" पदों का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद ३६३ में है।

२९७. भारत के जल-प्रांगण में, समुद्र के नीचे की सब भूमियां, खिनंज तथा अन्य मूल्यवान चीजें संघ में विहिन्न होंगी तथा संघ के प्रयोजनों के लिये घारण की जायेंगी।

- २९८. (१) संघ की, और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शिक्त, समुचित विधान-मंडल की किसी विधि के अधीन रहते हुए, यथास्थिति संघ के अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनों के लिये धारण की हुई किसी सम्पत्ति के अनुदान, विकय, व्ययन या बंधक तक विस्तृत होगी, तथा क्रमशः उन प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के क्रय या अर्जन तक, तथा संविदाकरण तक, विस्तृत होगीं।
- (२) संघ के, अथवा राज्य के प्रयोजनों के लिये अर्जित मव सम्पत्ति, यथास्थिति, संघ में या ऐसे किसी राज्य में निहित होगी।

राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से प्रोद्भूत सम्पत्ति.

जल-प्रांगरा में स्थित मृत्य-वान चीजें संघ में निहित होंगी

सम्पत्ति के अर्जन की शक्ति. भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--अनु० २९९-३००

संविदाएं.

- २९९. (१) संघ की, अथवा राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई सब संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट्र-पित द्वारा अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की गई कही जायेंगी तथा वे सब संविदाएं और सम्पत्ति-सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र, जो उस शक्ति के पालन में किये जायें राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख की ओर से उस के द्वारा निदेशित या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा और रीति के अनुसार लिखे जायेंगे।
- (२) न तो राष्ट्रपित और न किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख इस संविधान के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत सरकार विषयक इस से पूर्व प्रवर्तित किसी अधिनियमिति के प्रयोजनों के हेतु, की गई अथवा लिखी गई किसी संविदा या हस्तान्तरण-पत्र के बारे में वैयविदक रूप से उत्तरदायी होगा, और न वैसा कोई व्यक्ति ही इस के बारे में वैयवितक रूप से उत्तरदायी होगा, जिस ने उन में से किसी की ओर से ऐसी संविद्र का हिस्तान्तरण-पत्र किया या लिखा हो।

व्यवहार-वाद ग्रौर कार्यवा-हियां. ३००. (१) भारत संघ के नाम से, भारत संरकार व्यवहार-वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा तथा किसी राज्य के नाम से, उस राज्य की सरकार व्यवहार-वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा, तथा इस संविधान से दी हुई शिवतयों के आधार पर, संसद् द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, जो अधिनियम बनाया जाये, उस के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे अपने अपने कार्यों के बारे में उसी प्रकार व्यवहार-वाद ला सकेंगे, अथवा उन के विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार-वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत डोमीनियन और तत्स्थानी प्रान्त अथवा तत्स्यानी देशी राज्य-व्यवहार-वाद ला सकते अथवा उन के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकता, यदि इस संविधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता ।

भाग १२——वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद—— अनु ० ३००

- (२) यदि इस संविवान के प्रारम्भ भूपर-
 - (क) कोई , ऐसी विधि-कार्यवाहियां लिम्बत ह जिस में भारत डोमीनियन एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त डोमीनियन के स्थान में भारत संघ समझा जायेगा, तथा
 - (ख) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लिम्बित हैं जिन में कोई प्रान्त या कोई देशी राज्य एक पक्ष है, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त या देशी राज्य के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझा जायेगा।

भाग १३

भागत के राज्य चीत्र के भीतर व्यासर, वाणिज्य और समागम

ब्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता. ३०१ इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा ।

व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्वेन्धन लगाने की संसद् की शक्ति. ३०२ संसद् विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के वीच अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रना पर ऐसे निर्बन्धन आरोपित कर सकेगी जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों।

व्याषार ग्रौर वाणिज्य के विषय में संघ और राज्यों की विधायिनी शक्तियों पर निबंन्धन.

- ३०३. (१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुए भी सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी किसी प्रविष्टि के आधार पर न तो संसद् को, और न राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है।
- (२) खंड (१) में की कोई बात संसद् को ऐसी कोई विधि बनाने से न रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है. यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुर्लभता से उत्नन किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

भाग १३--भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम--श्रनु० ३०४-३०६

३०४. अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के होते हुए भी राज्य का विधान-मंडल विशि द्वारा—

- (क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर आरोपित कर सकेगा जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु इस प्रकार कि उस से इस तरह आयात की गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो; तथा
- (ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों:

परन्तु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या.संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विना राज्य के विधान-मंडल में पुर:स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

३०५ अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, जिस मात्रा तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे, उस के अतिरिक्त, कोई प्रभाव न डालेगी ।

३०६. इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में, अथवा इस संविधान के अन्य उपबन्धों में, किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उिल्लेखित कोई राज्य, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले दूसरे राज्यों से उस राज्य में वस्तुओं के आयात पर अथवा उस राज्य से दूसरे राज्यों

राज्यों के
पारस्परिक
व्यापार,
वाणिज्य और
समागम पर
निर्बन्धन.

वर्तमान विधियों पर अनुच्छेद ३०१ और ३०३ का ६भाव.

प्रथम अनुमूची के भाग (ख) में उल्लिखित कतिपय राज्यों की भाग १३--भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य औरसमागम--अनु० ३०६-३०७

व्यापार और बाणिज्य पर निबंन्धनों के आरोपण की जानित को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या शुक्क उद्गृहीत करता था, ऐसे कर या शुक्क को, यदि भारत सरकार और उस राज्य की सरकार में उस लिये करार हो जाये तो, ऐसे करार के निर्वन्धनों के अधीन रहते हुए तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनिधक ऐसी कालाविध के लिये, जैसी कि करार में उल्लिखित हो, उद्गृहीत और संगृहीत करता रहेगा:

परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय भी यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद २८० के अधीन गठित वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे किसी करार का अन्त या रूपभेद करना आवश्यक समझे तो वह ऐसा कर सकेगा।

अनुच्छैद १०१ से २०४ तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकारी की नियुक्ति. ३०७ संसद् विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि वह अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ और ३०४ के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समुचित समझे तथा इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे।

भाग १४

संव श्रीर राज्यों के श्रधीन सेवाएं अध्याय १ — सेवाएं

३०८. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेजित न हो, "राज्य" पद से प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य अभिप्रेत है।

३०९. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेंगे:

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद्र के अधीन समुचित विश्वान-मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपवन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति संघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपित को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के अबीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होंगे।

३१०. (१) इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या असैनिक सेवा का या अबिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी पद को अथवा किसी असैनिक पद को धारण करता है,

निर्वचन.

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की **शर्ते**.

संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदाविध.

भाग १४--संघ श्रौर राज्यों के अधीन सेवाएं--अनु ३१०-३११

राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यवित, जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता है, यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।

- (२) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद को घारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पर्यन्त पद घारण करता है कोई संविदा, जिस के अधीन कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा-सेवा या अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के अधीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथा-स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक समझता है तो, यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता है अथवा उस के द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बद्ध कारणों के लिये उस से पद रिवत करने की अपेक्षा की जाती है तो, उसे प्रतिकर दिया जायेगा।
- ३११ (१) जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जायेगा।
- (२) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत ज़हीं किया जायेगा, अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा, अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस के बारे में

संघ या राज्य के अधीन असै-निक हैसियत से नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की पदच्युति,पद से हटाया जाना या पंक्तिच्युत किया जाना.

भाग १४-- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं--अनु० ३११-३१२

प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो:

परन्तु यह खड वहां लागू न होगा—

- (क) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्ति-च्युत किया गया है जिस के लिये दंड-दोषारोप पर वह सिद्ध-दोष हुआ है;
- (ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाये; अ गवा
- (ग) जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख का समाधान हो जाता है कि राज्य कीः सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये।
- (३) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खंड (२) के अवीन किसी व्यक्ति को करण दिखाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति पदच्युन करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

३१२. (१) भाग ११ में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य-परिषद् ने उपस्थित और मन देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समिथित संकल्प द्वारा घोषित कर दिया है कि राष्ट्र-हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो संसद् विधि द्वारा संघ और राज्यों के

अखिल भारतीय सेवाएं.

भाग १४—–संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं—– अनु० ३१२-३१४

लिये सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी तथा इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तीं का, विनियमन कर सकेगी।

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत प्रशासन सेवा और भारत आरक्षी सेवा नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेदं के अधीन संसद् द्वारा सृजित सेवाएं समझी जायेंगी।

अन्तर्वतीं उपबन्ध. ३१३. जब तक इस संविधान के अधीन इस लिये अन्य उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पिहले सब प्रवृत्त विधियां, जो किसी ऐसी लोक-सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते हैं, लागू हो, वहां तक प्रवृत्त बनी रहेगी जहां तक कि वे इस संविधान के उपबन्धों से संगत हों।

कतिपय सेवाश्रों के वर्तमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिये उपबन्ध ३१४. इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वंक उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति को, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में सम्राट् की किनी असैनिक सेवा में नियुक्त होने के पश्चात् इस संविधान के प्रारम्भ पर और पश्चात् भारत की या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा में बना रहता है, भारत सरकार या राज्य की सरकार से, जिस की सेवा वह समय समय पर करता रहता है, पारिश्रमिक, छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में उन्हीं सेवा-शर्तों का, तथा अनुशासनीय विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उन के तुल्य ऐसे अधिकारों का, जैसे कि परिवर्तित परिस्थितियों में सम्भव हो, हक्क होगा जिन का कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले हक्क था।

भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं--अनु० ३१५

अध्याय २ -- लोक्सेवा-आयोग

- ३१५. (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ के लिये एक लोकसेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोकसेवा-आयोग होगा।
- (२) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिये एक ही लोकसेवा आयोग होगा तथा, यदि उस उद्देश्य का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक के विधान-मंडल के सदन द्वारा अथवा जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो, संसद् उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विधि द्वारा संयुद्द लोकसेवा आयोग (जो इस अध्याय में 'संयुद्द आयोग' के नाम से निर्दिष्ट है) की नियुक्ति का उपबन्ध कर सकेगी।
- (३) उपरोवत विधि में ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषिगक उपबन्ध भी अन्तिविष्ट हो सकेंगे जैसे कि उस विधि के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये आवस्यक या वांछनीय हों।
- (४) यदि किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, संघ के लोकसेवा-आयोग से ऐसा करने की प्रार्थना करे तो, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, वह उस राज्य की सब या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्य करना स्वीकार कर सकेगा।
- (५) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इस संविधान में संघ के लोकसेवा-आयोग अथवा किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के प्रति निर्देशों को ऐसे आयोग के प्रति निर्देश समझा जायेगा जो प्रश्नास्पद किसी विशेष विषय के बारे में यथास्थिति संघ की अथवा राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।

संघ और राज्यों के लिये लोक-सेवा-आयोग.

भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं--अनु० ३१६

सदस्यों की नियुक्ति तथा पदाविष. ३१६. (१) लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की जायेगी:

परन्तु प्रत्येक लोकसेवा-आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्तियों की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद घारण कर चुके हैं, तथा उक्त दस वर्ष की कालावधि की संगमना में ऐसी कालाविध भी सिम्मिलित होगी, जिस में इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी व्यक्ति ने भारत के सम्राट् के अधीन या देशी राज्य के अधीन पद घारण किया है।

(२) लोकसेवा-आयोग का सदस्य, अपने पद-म्रहण की तारीख से छ वर्ष की अविघ तक, अथवा यदि वह संघ-आयोग है तो, पैंसठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, तथा यदि वह राज्य-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, साठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, जो भी इन में से पहिले हो, अपना पद धारण करेगा:

परन्तु--

- (क) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति को, तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को, सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा;
- (ख) लोकसेवा-आयोग का कोई सदंस्य अपने पद से अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) या खंड (३) में उपबन्धित रीति से हटाया जा सकेगा।
- (३) कोई व्यक्ति, जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुर्नीनयुक्ति के लिये अपात्र होगा।

भाग १४,--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं--अनु० ३१७

- ३१७. (१) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक-सेवा-आयोग का सभापित या अन्य कोई सदस्य अपने पद से कैवल राष्ट्रपित द्वारा कदाचार के आधार पर दिये गये उसक्क आदेश पर ही हटाया जायेगा, जो कि उच्चतमन्यायालय से राष्ट्रपित द्वारा पृच्छा किये जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद १४५ के अधीन उस लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गये इस प्रतिवेदन के पश्चात्, कि यथास्थित सभापित या ऐसे किसी सदस्य को, ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाये, दिया गया है।
- (२) आयोग के सभापित या अन्य किसी सदस्य को, जिस के सम्बन्ध में खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय से पृच्छा की गई है, राष्ट्रपित यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है, तथा राज्यपाल या राजप्रमुख, यदि वह राज्य-आयोग है, उस को पद से तब तक के लिये निलम्बित कर सकेगा जब तक कि ऐसी पृच्छा की गई बात पर उच्चतमन्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपित अपना आदेश न दे।
- (३) खंड -(१) में किसी बात के होते हुए भी यदि यथा-स्थिति लोकसेवा-आयोग का सभापित या कोई दूसरा सदस्य—
 - (क) दिवालिया न्यायनिणीत हो जाता है; अथवा
 - (ख) अपनी पदाविध में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर कोई वैतनिक नौकरी करता है; अथवा
 - (ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दौर्बल्य के कारण अपने पद पर रहे आने के लिये अयोग्य है,

तो सभापति या ऐसे अन्य सदस्य को राष्ट्रपति आदेश द्वाराः अपने पद से हटा सकेगा। लोकसेवाआयोग के
किसी सदस्यः
का इटाया
जाना या
निलम्बित
किया जानाः

भाग १४--संघ श्रौर राज्यों के अधीन सेवाएं--अनु० ३१७-३१९

(४) यदि लोकसेवा-आयोग का सभापित या अन्य कोई सदस्य भारत सरकार के या राज्य की सरकार के द्वारा, या ओर से, की गई किसी संविदा या करार में, निगमित समवाय के सदस्य के नाते तथा उस के अन्य सदस्यों के साथ साथ के सिवाय, किसी प्रकार से भी संपृक्त या हित-सम्बद्ध है या हो जाता है अथवा किसी प्रकार से उस के लाभ में अथवा तदुत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है, तो वह खंड (१) के प्रयोजनों के लिये कदाचार का अपराधी समझा जायेगा।

आयोग के
सदस्यों तथा
कर्मचारी-वृन्द
की सेवाओं
की शतों के
बारे में
विनियम
बनाने की
शक्ति.

३१८ संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल या राज-प्रमुख विनियमों द्वारा—-

- (क) आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उन की सेवाओं की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा; तथा
- (ख) आयोग के कर्मचारी-वृन्द के सदस्यों की संख्या के तथा उन की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उप-बन्ध कर सकेगा:

परन्तु ़लोकसेवा-आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उस की नियुक्ति के पश्चात् उस को अलाभकारी परिवर्तन न किया जायेगा।

३१९ पद पर न रहने पर--

- (क) संघ-लोकसेवा-आयोग का सभापित भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नौकरी के लिये अपात्र होगा;
- (ख) राज्य के लोकसेवा-आयोग का सभापित संघ-लोक-सेवा-आयोग के सभापित या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापित के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा;

श्रायोग के
सदस्यों द्वारा
ऐसे सदस्य
न रहने पर
पदों के
धारएा के
सम्बन्ध
में प्रतिषेष

भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं--अनु० ३१९-३२०

- (ग) संघ-लोकसेवा-ग्रायोग के सभापित से अतिरिवत कोई अन्य सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापित के रूप में अथवा राज्य-लोकसेवा-आयोग के सभापित के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के, अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा;
- (घ) किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापित से अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापित या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी, या किसी अन्य, राज्य-लोकसेवा-आयोग के सभापित के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा।

३२०. (१) संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोगों का कर्तव्य होगा कि ऋमणः संघ की सेवाओं ग्रौर राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे। लोकसेवा-आयोगों क कृत्य.

- (२) यदि संघ-लोकसेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उस का यह भी कर्तव्य होगा कि ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिये, जिन के लिये विशेष अईता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, मिली जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तन में लाने के लिये उन राज्यों की सहायता करें।
- (३) यथास्थिति संघ-लोकसेवा-आयोग या गज्य-लोक सेवा-आयोग से——
 - (क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिये भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर;
 - (ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुदित करने के, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नित और बदली करने के, तथा अभ्यर्थियों की ऐसी

भाग १२--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं--अन्० ३२०

नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वदली की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों पर;

- (ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी.

 राज्य की सरकार की असैनिक हैसियत

 से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन-विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं
 सम्बद्ध हैं उन के सिहत समस्त ऐसे अनुशासनविषयों पर;
- (घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या किसी राज्य की मरकार के अधीन या भारत- सम्राट् के अधीन या देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा ह या कर चुका है, अखवा वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत, जो कोई दावा है कि अपने कर्तव्य पालन में किये गये, या कर्तुमिभप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध में उस के विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि-कार्य- वाहियों में जो खर्चा उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है वह यथास्थिति भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर;
- (ङ) भारत सरकार यां किसी राज्य की सरकार या सम्राट् के अधीन अभवा किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई श्रित के बारे में निवृक्ति-वेतन दिये जाने के लिये किसी दावे पर तथा ऐसी दी जाने वाली राशि क्या हो. इस प्रश्न पर,

परामर्श किया जायेगा, तथा इस प्रकार उन से पृच्छा किये हुए किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथा- भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवायें-अनु० ३२०-३२१

स्थिति राष्ट्रपति अथवा उम राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, उन से पृच्छा करे, पराभर्श देने का लोकसेवा- आयोग का कर्तव्य होगा:

परन्तु अखिल भारतीय मेवाओं के बारे में तथा संघ-कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों से संमक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख, उन विषयों का उल्लेख करने वाले विनियम बना सकेगा, जिन में साधारण्या अथवा किसी विशेष वर्ग के मामले में, अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, लोकसेवा-आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।

- (४) खंड (३) की किसी वात से यह अपेक्षा न होगी कि लोकसेवा-अयोग से उस रीति के बारे में परामर्श किया जाये जिस से कि अनुच्छेद १६ के खंड (४) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद २३५ के उपबन्धों को प्रभाव दिया जाना है।
- (५) खंड (३) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपित अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा बनाये गये सब विनियम उन के बनाये जाने के पश्चान् यथामम्भव ग्रीष्ट्र यथा-स्थिति संसद् के प्रत्येक सदन, अथवा राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के ममक्ष चौदह दिन से अन्यून समय के लिये रखे जायेंगे, नथा निरमन या संगोधन द्वारा किये गये ऐसे रूपभेदों के अधीन होंगे जैसे कि संसद् के दोनों सदन अथवा उस राज्य के विधान-मंडल का मदन या दोनों सदन उस मन् में करें जिस में कि वे इस प्रकार रखे गये हों।

३२१. यथास्थिति संसद् द्वारा निर्मित अथवा राज्य के विधान-मडल द्वारा निर्मित, कोई अधिनियम संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोकसेवा-आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के वारे में, तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा

लोकसेवा आयोगों के कृत्यों के विस्तार की णक्टि. भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवायें--अनु० ३२१-३२३

विधि द्वारा गठित अन्य निगम-निकाय अथवा किसी सार्व-जिनक संस्था की सेवाओं के बारे में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिये उपबन्ध कर सकेगा।

लोकसेवा-आयोगों के व्यय. ३२२ संघ के, या राज्य के, लोकसेवा-आयोग के व्यय, जिन के अन्तर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी-वृन्द को, या के विषय में, दिये जाने वाले कोई वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन भी यथास्थिति भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।

लोकसेवा-आयोगों के प्रतिबेदन

- ३२३० (१) संघ-आयोग का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किथे गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रति-वेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किथा गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।
- (२) राज्य-आयोग का कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिन की आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राजप्रमुख को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा इन में से प्रत्येक अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा ।

भाग १५

निर्वाचन

- ३२४. (१) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामाविल तैयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, जिस के अन्तर्गत संसद् के तथा राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त सन्देहों और विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की नियुवित भी है, एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान में "निर्वाचन-आयोग" के नाम से निर्दिष्ट है)।
- (२) निर्वावन-आयोग मुख्य निर्वावन-आयुक्त तथा, यदि कोई हों तो, अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्तों से, जितने कि राष्ट्रपित समय समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन-आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा उस लिये बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपित द्वारा की जायेगी।
- (३) जब कोई अन्य-निर्वाचन-आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन-आयुक्त निर्वाचन-आयोग के सभा-पित के रूप में कार्य करेगा।
- (४) लोक-सभा, तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व, तथा विधान-परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् के लिये पहिले साधारण निर्वाचन तथा तत्पश्चात् प्रत्येक द्विवाणिक निर्वाचन से पूर्व, राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग से परामर्श कर के खंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिये ऐसे प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे।

निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और

निर्वाचन आयोग में निहित होंगे.

भाग १५---निर्वाचन--अनु० ३२४-३२५

(५) संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्वाचन-आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्ते और पदाविध ऐसी होंगी जैसी कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे:

परन्तु मुख्य निर्वाचन-आयुवत अपने पद से वैसे कारणों और वैसी रीति के विना न हटाया जायेगा जैसे कारणों और रीति से उच्चतम-न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है तथा मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस की सेवा की शर्तों में उस को अलाभकारी कोई परिवर्तन न किया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि किसी अन्य निर्वाचन-आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की सिपारिश के विना पद से हटाया न जायेगा।

- (६) जब निर्वाचन-आयोग ऐसी प्रार्थना करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख निर्वाचन-आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को ऐसे कर्मचारी-नृन्द प्राप्य करायेगा जैसे कि खंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये कृत्यों के निर्वेहन के लिये आवश्यक हो।
- ३२५. (क) मंसद् के प्रत्येक सदन अथवा किनी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचन के हेतु प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये एक माधारण निर्वाचक-नामाविल होगी तथा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इन में से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किमी नामाविल में सम्मिलत किये जाने के लिये अपात्र न होगा अथवा, ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी विशेष निर्वाचक-नामाविल में सम्मिलत किये जाने का दावा न करेगा।

धर्म, मुलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में सम्मिलित किये जाने का दावा न करेगा.

भाग १५--निर्वाचन--अनु० ३२६-३२९

३२६. लोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विद्यान-सभा के लिये निर्वाचन वयस्क-मताबिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी कि समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस लिये नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चिन-विकृति, अपराव अथवा भ्रष्ट या अत्रैय आचार के आधार पर अनहें नहीं कर दिया गया है. ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाना के हम में पंजीबद्ध होने का हक्कदार होगा।

३२७. इस मंविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संमद्, समय समय पर, विधि द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या संमक्त सब विध्यों के सम्बन्ध में जिन के अन्तर्गत निर्वाचक-नामाविलयों का तैयार कराना तथा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी है, उपबन्ध कर सकेगी।

३२८. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा जहां तक संसद् इस लिये उपबन्ध नहीं बनानी वहां नक. किसी राज्य का विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त सब विपयों के सम्बन्ध में, जिन के अन्तर्गत निर्वाचक-नामा-विलयों का तैयार कराना तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्बन्ध गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी है, उपबन्ध कर सकेगा।

३२९, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी--

(क) अनुच्छद ३२७ या अनुच्छेद ३२८ के अधीन निर्मित या निर्मातुमभिप्रेत किसी विधि की, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को लोक-सभा और राज्यों की विधान-सभाओं के लिये निर्वा-चन का वपस्क-मना-धिकार के आधार पर होना.

विधान-मंडकों के लिये निर्वा-चनों के विषय में उपबन्ध बनाने की संसद् की शक्ति.

किसी राज्य के विवान-मंडल की ऐसे विवान-मंडल के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध बमाने की शक्ति.

निर्वाचन-विषयों म् न्यायालयों क हम्नक्षेप पर रोकें.

भाग १५---निर्वाचन--अनु० ३२९

स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, मान्यतापर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी ;

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के किसी निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन-याचिका के विना कोई आपत्ति न की जायेगी जो ऐसे प्राविकारी को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गई है जो समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि के द्वारा या अधीन उपबन्धित हैं!

भाग १६

कतिपय दगीं से सम्बद्ध िशेष उपबन्ध

- २३०. (१) लोक-सभा में---
 - (क) अनुसूचित जातियों के लिये,
 - (ख) आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर आदिमजानियों के लिये,
 - (ग) आसाम के स्वायत्तशासी जिल्हों में की अनुसूचित आदिमजातियों के लिये,

स्थान रक्षित रहेंगे।

- (२) खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये किसी. राज्य में रिक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का अनुपात लीक-सभा में उस राज्य को बांट में दिये गये स्थानों की समस्त संर्या से यथाशवय वहीं होगा जो यथा-स्थित उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिम-जातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रिक्षत हैं, जन-संख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से हैं।
- ३३१. अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक-सभा में उस समुदाय के दो से अनिधक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा।
- ३३२. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उित्लिखित प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों के लिये तथा आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम-जातियों को छोड़ कर अन्य आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे।
 - (२) आसाम राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों लिये भी स्थान रक्षित रहेंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये नोक सभा में स्थानों का रक्षण.

> लोक-सभा में भांग्ल-भार-तीय समुदाय का प्रतिनि-घित्व.

> राज्यों की
> विधान-समास्रों में अनुसूचित जातियों और
> अनुसूचित
> आदिमजातियों के लियेस्थानों काः
> रक्षण-

भाग १६—कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध—— अनु० ३३२-३३३

- (३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रिक्षत स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रिक्षत हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से हैं।
- (४) आसाम राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों की समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य की समस्त जनसंख्या से हैं।
- (५) शिलोंग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिल कर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्त-शासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा।
- (६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले में की अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान-सभा के लिये शिलौंग के कटक और नगर-क्षेत्र से मिल कर वने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र न होगा।

राज्यों की विधान-समाओं, में अमल-मारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.

३३३. अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यसुत्र की राय हो कि उस राज्य की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित समझे नाम-निर्देशित कर सकेगा।

भाग १६-कतिपय वर्गो से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध -अनु० ३३४-३३६

३३४ इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—

- (क) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये स्थानों के रक्षण सम्बन्धी; तथा
- (ख) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं में नाम-निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी,

इस संविधान के उपबन्ध, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालाविध की समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे:

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक-सभा के या राज्य की विधान-सभा के किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि यथास्थिति उस समय विद्यमान लोक-सभा या विधान-सभा का विधटन न हो जाये।

े ३३५ संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपट्टता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।

३३६ (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम दो वर्षों में संघ की रेल, बिहःशुल्क, डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाओं के पदों के लिये आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुवितयां १५ अगस्त १९४७ ई० के तुरन्त पूर्व वाले आधार पर की जायेंगी।

स्थानों का रक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के पश्चात न रहेगा.

सेवाओं और
पदों के लिये
अनुसूचित
जातियों भीर
अनुसूचित
अपदिमजातियों के
दावे.

कतिपय सेवाओं में आंग्लमारतीय समुदाय के लिये विशेष उपबन्ध

भाग १६ कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध — अनु० ३३६-३३७

प्रत्येक अनुवर्ती दो वर्षों की कालाविध में उक्त समुदाय के जनों के लिये, उक्त सेवाओं में, रक्षित पदों की संख्या, निकट पूर्ववर्ती दो वर्षों की कालाविध में इस प्रकार रक्षित संख्या से यथासम्भव दस प्रतिशत कम होगी:

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में ऐसे सब रक्षणों का अन्त हो जायेगा।

(२) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के जन अन्य समुदायों के जनों की तुलना में कुशलता के कारण नियुक्ति के लिये आई पाये जायें तो खंड (१) के अधीन उस समुदाय के लिये रिक्षित पदों से अन्य, अथवा उन से अधिक, पदों पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्ति में उस खंड की किसी बात से रुकावट न होगी।

आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के जिलवे जिल्लाए-व्यनुदान के जिलवे विश्वेष व्यवन्य- ३३७. इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चाल् पहिले तीन वित्तीय वर्षों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई अनुदान रहे हों तो वही अनुदान संघ तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक पराज्य द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १९४८ ई० को अन्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिये गये थे।

प्रत्येक अनुवर्ती तीन वर्ष की कालाविध में, अनुदान निकट पूर्ववर्ती तीन वर्ष की कालाविध की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये जा सकेंगे:

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष रियायत हैं, उस मात्रा तक अन्त हो जायेंगे:

परन्तु यह और भी कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी शिक्षा-संस्था को अनुदान पाने का तब तक हक्क न होगा जब तक कि उस के वार्षिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आंग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य न किये गये हों।

भाग १६--कितपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध--अनु ० ३३८-३३९

- ३३८ (१) अनुसूचित जातियों और अनसचित] आदिम-जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रयति नियुक्त करेगा
- (२) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से
 सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंघान करना तथा उन परित्राणों पर
 कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति
 निदिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का
 कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद् के
 प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।
- (३) इस अनुच्छेर में अनुसूचित जातियों और अनुसू-चित आदिमजातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिन को कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेर ३४० के खंड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राष्ट्रि पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्ल-भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी हैं।
- ३३९ (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) में उिल्लिखित राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर सकेगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

आयोग की रचना, शक्तियों और प्रक्रिया की परिभाषा आदेश में की जा सकेगी तथा उस में वे प्रासंगिक और सहायक उपबन्ध भी हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे किसी राज्य को उस प्रकार के निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित अदिमजातियों के कल्याण के लिये निदेश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखते हों। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी.

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तथा अनुसू-चित आदिम-जातियों के कल्याणार्थ संघ का नियंत्रण.

भाग १६--कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध-अनु० ३४०-३४१

पिछड़े हुए वर्गों की दशा-ओं के अनुसं-धान के लिये आयोग की नियुक्ति.

- ३४०० (१) भारत राज्य-क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुये वर्गों की दशाओं के तथा जिन कितनाइयों को वे झेल रहे हैं उन के अनुसंधान के लिये तथा संघ या किसी राज्य द्वारा उन कितनाइयों को दूर करने और उन की दशा को सुधारने के लिये करने योग्य उपायों के बारे में, तथा उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिये जाने चाहियें तथा जिन शतीं के अधीन वे अनुदान दिये जाने चाहियें उन के बारे में, सिपारिश करने के लिये राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को मिला कर, जैसे वह उचित समझे, आयोग बना सकेगा तथा आयोग नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी।
- (२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए विषयों का अनुसन्धान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिस में पाये गये तथ्यों का समावेश होगा तथा जिस में ऐसी सिपारिशें की जायेंगी जिन्हें आयोग उचित समझे।
- (३) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिये गये प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सिहत, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

श्रनुसूचित जातियां.

- ३४१. (१) राष्ट्रपित, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परा-मर्श करने के पश्चात्, लोक-अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी।
- (२) संसद् विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति के भाग या उस में के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत या से अपर्वाजत कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा

भाग १६--कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध -अनु० ३४१-३४२

उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

- ३४२. (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख से परामर्श करने के पश्चात् लोक-अधिसूचना द्वारा उन आदिमजाितयों या आदिमजाित-समुदायों अथवा आदिमजाितयों या आदिमजाित-समुदायों के भागों या उन में के यथों का उल्लेख कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिमजाितयां समझी जायेंगी।
- (२) संसद् विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय को, अथवा आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय के भाग या उस में के यूथ को, खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उिल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित, कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

अनुसूचित आदिम-जातियां.

भाग १७

राजभाषा

अध्याय १.-- संघ की भाषां

संघ की राज-भाषा. ,३४३. (१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(२) खंड (१) सें किसी बान के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालाविध के लिये संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी:

परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालाविध में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय ग्रंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

- (३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रह साल की कालाविध के पश्चात् विधि द्वारा—
 - (क) अंग्रेजी भाषा का; अथवा
 - (ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों।

राजभाषा के लिये संसद् का आयोग धौर समिति. ३४४. (१) राष्ट्रपित, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापित और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रति-निधित्व करने वाले ऐसे अन्य सुदस्यों से मिल कर बनेगा भाग १७-- राजभाषा--अनु० ३४४

जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश परिशाषित करेगा।

- (२) राष्ट्रपंति को-
 - ं (क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के ;
 - (ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सबया किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रक्रोग पर निर्बेन्धनों के;
 - (ग) अनुच्छेद ३४८ में विश्वत प्रयोजनों में से सब या किसी के स्थिय प्रयोग की जाने वाली भाषा के;
 - (घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों 'के लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों के रूप के;
 - (ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच क्षथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच चार की भाषा तथा उन के प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किये द्वुए किसी अन्य विश्वय के,

बारे में सिपास्सि करने का आयोग का कर्तव्य होगा ।

- (३) खंड (२) के अधीन अपनी सिपारिसें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक-सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ब्यान ख्लेगा।
- (४) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जिन में से बीस छोक-सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य-परिषद् के सदस्य होंगे जो कि कमकः छोक-सभा के सदस्यों तथा राज्य-परिषद् के सदस्यों द्वारा अनु गाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वोचित होंगे

भाग १७--राजभाषा--अनु० ३४४-३४७

- (५) खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपित को करना सिमित का कर्तंव्य होगा।
- (६) अनुच्छेद ३४३ में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड (५) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चार्त उस सारे प्रतिवेदन के या उस के किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

अध्याय २.--प्रादेशिक भाषाएं

राज्य की राजभाषा या राजभाषायें. ३४५. अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा:

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा इस से अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी।

एक राज्य श्रीर दूसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राज-भाषा. ३४६. संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के लिये तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा होगी:

परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली ३४७. तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समा-धान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उस के द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी

१७--राजभाषा--अनु० ३४७-३४८

भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उस के किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये।

अध्याय ३.-- उचतमन्यायालय, उचन्यायालयों आदि की भाषा

- ३४८. (१) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक—
 - (क) उच्चतमन्यायालय में तया प्रत्येक उच्चन्यायालय में सब कार्यवाहियां;
 - (ख) जो---
 - (१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन, संसद् के प्रत्येक सदन में पुर:-स्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ.
 - (२) अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रस्थापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा
 - (३) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन, अयवा संसद् या राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जायें उन सबके प्राधिकृत पाठ,

अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

(२) खंड (१) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हिन्दी भाग का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजन के लिये प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्चन्यायालय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर सकेगा:

जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

उच्चतमन्याः यालय श्रौर उच्चन्यायाः लयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषाः भाग १७--राजभाषा--म्रन्० ३४८-३५०

परन्तु इस खंड की कोई बात वैसे उच्चन्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी।

(३) खंड (१) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते? हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुर:स्थापित विधेयकों या उस के द्वारा पारित अधि-नियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका (३) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उस का अनुवाद उस खंड के अभिप्रायों के लिये उस का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा!

माषा सम्बन्धों कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष प्रक्रिया. ३४९. इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की काला-विधा तक अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) में विणित प्रयोजनों में से किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विनान तो पुरःस्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुरःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किये जाने की मंजूरी अनुच्छेद ३४४ के खंड (१) के अशीन गठित आयोग की सिपारिशों पर, तथा उस अनुच्छेद के खंड (४) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर, विचार करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति देगा।

- अध्याय ४ -- विशेष निदेश

क्यथा के विश्वे संघ या राज्य निवारण के के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में

[२०५

भाग १७--राजभाषा--अनु० ३५०-३५१

या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक्क होगा।

लिये अभिके दन में प्रयोक्तव्यः भाषाः

३५१. हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उस का विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उस की आत्मीयता में हस्तक्षेप किये विना हिन्दुस्थानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाग्रों के रूप, शैली और पदाविल को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उस के शब्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उस की समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

हिन्दी माषा के विकास के लिये निदेश.

भाग १८

श्रापात-उपबन्ध

वापात की उद्घोषणा.

- ३५२. (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिस से कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति से भारत या उस के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।
 - (२) खंड (१) के अधीन की गई उद्घोषणा-
 - (क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी;
 - (ख) संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी;
 - (ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह उस कालावधि की समाप्ति से पहिले अनुमोदित न कर दी जाये:

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई है जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन इस खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की कालाविश्व के भीतर हो जाता है, तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालाविध की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गंठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि उक्त लीस दिन की कालाविध की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता।

भाग १८--आपात-उपबन्ध--अनु० ३५२-३५४

(३) यदि राष्ट्रपति का समायान हो जाये कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति का संकट सन्निकट है तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा ऐसा कोई आक्रमण या अशान्ति नहीं हुई हो तो भी भारत की अथवा भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा इस प्रकार से संकट में है ऐसा घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी।

३५३ जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब-

- (क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी : राज्य को इस विषय में निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति में प्रयोग करे;
- (ख) किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति के अन्तर्गत ऐसी विधियां बनाने की शक्ति भी होगी जो उस विषय के बारे में संघ अथवा संघ के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां देती तथा कर्तव्य सौंपती हो अथवा शक्तियों का दिया जाना और कर्तव्यों का सौंपा जाना प्राधिकृत करती हो चाहे फिर वह विषय ऐसा हो जो संघ-सूची में प्रगणित नहीं है।
- ३५४. (१) जब कि आपात की उद्घोपणा प्रवर्तन में है, तब राष्ट्रपित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद २६८ से २७९ तक के सब या कोई उपबन्ध ऐसी किसी कालाविध में, जैसी कि उस आदेश में उल्लिखित की जाये और जो किसी अवस्था में भी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे विस्तृत न होगी, जिस में कि उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती, ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन प्रभावी होंगे जैसे कि वह उचित समझे।

आपात की उद्घोषणा को भाव.

आपात की
उद्घोषणा
जब प्रवर्तन
में है तब
राजस्वों के
वितरण
सम्बन्धी
उपबन्धीं की
प्रयुक्ति.

भाग १८--आपात-उपबन्ध-- अनु० ३५४-३५६ '

ं (२) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दिये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

वाह्य आक्रमण बीर बाम्यन्तरिक बाग्नान्ति से राज्य का संरक्षण करने कां संघ का कतंब्य. ३५५. वाह्य आक्रमण और आम्यन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण करना, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जा में, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

राज्यों में साविधानिक तांत्र के विफल तांत्र को विफल तांत्र को की अवस्था में राज्यबन्ध

- ३५६. (१) यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समायान हो जायें कि ऐसी। स्थिति पैदा हो गई है जिस में कि उस राज्य का शबसन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—
 - (क) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य, तथा यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख में, अथवा राज्य के विधान-मंडल को छोड़ कर राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में, निहित, या तस्तद्द्वारा प्रथीक्तव्य सब या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा;
 - (ख) वाषित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार के द्वारा या . अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ;
 - (ग) राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बद्ध इस संविधान के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बत करने के लिये उपबन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपवन्ध बना सकेगा जैसे कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या बांछनीय दिखाई दें:

भाग १८--आपात-उपबन्ध--अनु० ३५६

परन्तु इस खंड की किसी बात से राष्ट्रपति को यह प्राधिकार न हागा कि वह उच्चन्यायालय में निहित या तद्द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले अथवा इस संविधान के उच्चन्यायालयों से सम्बद्ध किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित कर दे।

- (२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंहत या परिवर्तित की जा सकेगी।
- (३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी, तथा जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को प्रतिसंहत करने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह दोच महीने की समाप्ति पर, यदि उस कालाविष की समाप्ति से पूर्व संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह अनुमोदित नहीं हो जाती तो, प्रवर्तन में नहीं रहेगी:
- परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पहिले की उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली नहीं है) उस समय निकाली गई है जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की कालाविष के भीतर हो जाता है तथा यदि उद्घोषणा कम अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालाविष की समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीक से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालाविष की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता।
- (४) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि प्रतिसंहत नहीं हो गई हो तो, इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों मं से दुसरे के पारित हो जाने की

भाग १८—-आपात-उपबन्ध—-अनु० ३५६-३५७ तारीख से छ महीने की कालाविध की समाप्ति पर वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी:

परन्तु ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त रखने के लियें अनु-मोदन करने वाला संकल्प, यदि और जितनी बार, संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो, और उतनी बार, वह उद्घोषणा, जब तक कि प्रतिसंहत न हो जाये, उस तारीख से जिस से कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, छ महीने की और कालाविष तक प्रवृत्त बनी रहिंगी, किन्तु कोई ऐसी उद्-घोषणा किसी अवस्था में भी तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी:

परन्तु यह और भी कि यदि लोक-सभा का विघटन छ मास की किसी ऐसी कालाविध के भीतर हो जाता है तथा ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद् द्वारा पारित हो चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने के बारे में कोई संकल्प लोक-सभा द्वारा उक्त कालाविध में पारित नहीं हुआ है तो उद्घोषणा उस तारीख से जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गटन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा जब तक कि उक्त तीस दिन की कालाविध की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को प्रवर्तन में बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता।

अनुच्छेद ३५६ के अधीन निका-छी गई उद्घोषणा के अधीन विघायिनी.

- ३५७ (१) जहां अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के अधीन निकाली गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी वहां—
 - (क) राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने के लिये तथा

भाग १८--आपात-उपबन्ध--अनु० ३५७

ऐसी दी हुई शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति उस लिये उल्लिखित करे, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रत्यायोजन करने के लिये राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद् की;

शक्तियों का प्रयोग.

- (ख) सघ अथवा उस के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति ेने या कर्तव्य आरोपित करने के लिये, अथवा शक्तियों का दिया जाना या कर्तव्यों का आरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिये, विधि बनाने की संसद् की अथवा राष्ट्रपति की या ऐसी विधि बनाने की शक्ति जन्य प्राधिकारी में उपखंड (क) के अधीन निहित है उस की;
- (ग) जब लोक-सभा सत्त्र में न हो तब व्यय के लिये संसद् की मंजूरी लिम्बित रहने तक राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की,

क्षमता होगी।

(२) राज्य के विवान-मंडल की शक्ति के प्रयोग में संसद् द्वारा अथवा राष्ट्रपति अथवा खड (१) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे अनुच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव में संसद् या राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के लिये सक्षम न होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के परचात् एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक सिवाय उन बातों के प्रभाव में न रहेगी जो उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ दी गई थीं जब तक कि वे उपबन्ध, जो इस प्रकार प्रभावी न रहेंगे, समुचित विशान-मंडल के अधिनियम द्वारा उस से पहिले ही या तो निरसित और या रूपभेदों के सहित या विना पुनः अधिनियमित न कर दिये गये हों।

भाग १८--आयात-उपबन्ध--अनु० ३५८-३६०

आपातों में अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का निलम्बन ३५८. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद १९ की किसी बात से राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की अथवा कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही करने की भाग ३ में परिभाषित शक्ति, जिसे वह राज्य उस भाग में अन्तिविष्टं उपबन्धों के अभाव में बनाने अथवा करने के लिये सक्षम होता, निर्वन्धित नहीं होगी, किन्तु इस प्रकार निर्मित कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता की मात्रा तक तुरन्त प्रभावशून्य हो जायेगी सिवाय उन बातों के जो विधि के इस प्रकार प्रभावशून्य होने से पहिले की गई या की जाने से छोड़ दो गई थीं।

आपात में भाग ३ द्वारा १ दत्त अधिकारों के १ वर्तन का निलम्बन.

- ३५९. (१) जहां कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से ऐसों को प्रवर्तित कराने के लिये जैसे कि इस आदेश में विणत हों, किसी न्यायालय के प्रचालन का अधिकार तथा इस प्रकार विणत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लियें किसी न्यायालय में लिम्बत सब कार्यवाहियां उस कालावधि के लियें जिस में कि उद्घोषणा लागू रहती है अथवा उस से छोटी ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाये, निलम्बत रहेगी।
- (२) उपरोक्त प्रकार दिया हुआ आदेश, भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में अथवा उस के किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा।
- (३) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दिये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

वित्तीय आपात के बारे में उपबन्ध ३६०. (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस से भारत अथवा उस के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा उस बात की घोषणा कर सकेगा।

भाग १८--आपात-उपबन्ध--अनु० ३६०

- (२) अनुच्छेद ३५२ के खंड (२) के उपबन्ध इस अनुच्छंद के अधीन निकाली गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे अनुच्छेद ३५२ के अधीन निकाली गई आपात की उद्घोषणा के लिये लागू होते हैं।
- (३) उस कालाविध में जिस में कि खंड (१) में विणित कोई उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने के लिये निदेश देने तक, जैसे कि निदेशों में उल्लिखित हों तथा ऐसे अन्य निदेश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगी।
 - (४) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी--
 - (क) ऐसे किसी निदेश के अन्तर्गत-
 - (१) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किन्हीं वर्गों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाले उपबन्ध,
 - (२) धन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, जिन को अनुच्छेद २०७ के उपबन्ध लागू हैं, राज्य के विधान-मंडल के द्वारा उन के पारित किये जाने के पदचात् राष्ट्रपति के विचार के लिये रिक्षत करने के लिये उप-बन्ध, भी हो सकेंगे;
 - (ख) उस कालाविध में, जिस में कि इस अनुच्छेद के अधीन निकाली गई उद्घोषणा प्रवर्तन में है, उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित, संघ के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लिये निदेश निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा।

भाग १६

प्रकीर्गा

राष्ट्रपति और राज्यपाछों और राज-प्रमुखों का संरक्षण ३६१. (१) राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किये गये अथवा कर्तुमिभिप्रेत किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय को उत्तरदायी न होगा:

परन्तु अनुच्छेद ६१ के अधीन दोषारोप के अनुसंधान के लिये संसद् के किसी सदन द्वारा नियुक्त या नामोद्दिष्ट किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्वि-लोकन किया जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायेगा मानो कि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के खिलाफ समृचित कार्यवाहियों के चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्वन्धित करती है।

- (२) राष्ट्रपित के अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के खिलाफ उस की पदाविध में किसी भी प्रकार की दंड कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जायेगी और न चालू रखी जायगी।
- (३) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की पदाविध में उसे बन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्याया- लय से कोई आदेशिका नहीं निकलेगी।
- (४) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राज-प्रमुख के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात्, अपने वैयनितक रूप में किये गये अथवा कर्तुमिभप्रेत किसी कार्य के बारे में राष्ट्रपति अथवा ऐसे राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के खिलाफ अनुतोष की मांग करने वाली कोई व्यवहार-कार्यवाहियां...

भाग १९--प्रकीर्ण-- अनु ० ३६१-३६३

उसकी पदाविध में किसी न्यायालय में तब तक संस्थित न की जायेंगी, जब तक कि कार्यवाहियों के स्वरूप, उन के लिये वाद का कारण ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, निवासस्थान तथा उस से मांग किये जाने वाले अनुतोष का वर्णन करने वाली लिखित सूचना को यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख को दिये जाने अथवा उस के कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात् दो मास का समय व्यतीत न हो गया हो।

३६२. संसद् की या किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शवित के प्रयोग में, अथवा संघ या किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, देशी राज्य के शासक के वैयिवतक अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा के विषय में ऐसी प्रसंविदा या करार के अधीन, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है, दी गई प्रत्याभूति या आश्वासन का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

३६३. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद १४३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतमन्यायालय और न किसी अन्य न्यायालय को किसी सिन्ध, करार, प्रसंविदा वचन-बन्ध सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य लिखत से, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई या निष्पादित की गई थी तथा जिस में भारत डोमीनियन की सरकार या इस की पूर्वाधिकारी कोई भी सरकार एक पक्ष थी तथा जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है या बनी रही है, उद्भूत किसी विवाद में अथवा ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बन्ध, सनद अथवा ऐसी ही किसी अन्य लिखत से सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्धों में से किसी से प्रोद्भूत किसी अधिकार, या उद्भुत किसी दायित्व या आभार, के विषय में किसी विवाद में क्षेत्राधिकार होगा।

(२) इस अनुच्छेद में-

(क) "देशी राज्य" से अभिप्रेत है कोई राज्य-क्षेत्र जो सम्राट् या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले, ऐसा राज्य अभिज्ञात था; तथा देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार

कतिपय सन्धियों, करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन. भाग १९--प्रकीर्ण-- अनु० ३६३-३६४

(ख) ''शासक'' के अन्तर्गंत हैं, राजा, मुखिया या अन्य कोई व्यक्ति जो सम्राट्या भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा, ऐसे प्रारम्भ से पहिले किसी देशी राज्य का शासक अभिज्ञात था।

महापत्तनों और विमान-क्षेत्रों के लिये विशेष उपबन्ध. ३६४. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख से ले कर जैसी कि अधिसूचना में उल्लिखित हो—

- (क) संसद् वा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि किसी महापत्तन या विमान-क्षेत्र को लागू न होगी अववा ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसे कि लोक-अधिसूचना में उल्लिखित हों, लागू होगी; अथवा
- (ख) कोई वर्तमान विधि किसी महापत्तन या विमान-क्षेत्र में उक्त तारीख से पहिले की हुई या किये जाने से छोड़ दी गई बातों के सम्बन्ध से अतिरिक्त अन्य बातों के लिये प्रभावी न होगी, अथवा ऐसे पत्तन या विमान-क्षेत्र में ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन रह कर, जैसे कि लोक-अधिसूचना में उल्लिखित हों, प्रभावी होगी।

(२) इस अनुच्छेद में--

- (क) "महापत्तन" से अभिप्रेत है कोई पत्तन जो संसद्
 द्वारा निर्मित किसी विधि या किसी
 वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन
 महापत्तन घोषित किया गया है तथा उस
 के अन्तर्गत वे सब क्षेत्र हैं जो तत्समय
 ऐसे पत्तन की सीमाओं के अन्तर्गत हैं;
 - (स) "विमान-क्षेत्र" से अभिष्रेत है बायु-पथों, विमानों और विमान-परिव्रह्न से सम्बद्ध अधिनिय-मितियों के प्रयोजमों के लिये परिभाषित विमान-क्षेत्र।

भाग १९--प्रकीर्ण--अनु० ३६५-३६६

३६५. जहां इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिये गये किन्हीं निदेशों का अनुवर्तन करने में या उन को प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है वहां राष्ट्रपित के लिये यह मानना विधि-संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है जिस में राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता।

३६६. जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस सविधान में निम्नलिखित पदों के वे अर्थ हैं जो क्रमशः उन को यहां दिये गये हैं; अर्थात्—

- (१) "कृषि-आय" से अभिप्रेत है भारतीय आय-कर से सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित कृषि-आय;
- (२) "आंग्ल-भारतीय" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिस का पिता अथवा पितृ-परम्परा में कोई अन्य पुरुष-जनक योरोपीय उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत अधिवासी है और जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में ऐसे जनकों से जन्मा है जो वहां साधारणतया निवास करते रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हैं;
- (३) 'अनुच्छेद'' से अभिश्रेत हैं इस संविधान का अनुच्छेद ;
- (४) "उधार लेना" में अन्तर्गत है वार्षिकियों के अनुदान द्वारा धन लेना तथा "उधार" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा;
- (५) "खंड" से अभिप्रेत है उस अनुच्छेद का खंड जिस में कि वह पद आता है;
- (६) "निगम-कर" से अभिप्रेत है कोई आय पर कर, जहां तक कि वह कर समवायों द्वारा देय है, तथा ऐसा कर है जिस के सम्बन्ध में निम्न लिखितं शर्तें पूरी होती हैं—
 - (क) कि वह कृषि-आय के विषय में आदेय नहीं है;

संबद्घारा दियें गये निदेशों का अनुवर्तन करने या उन को प्रभावी करने में अस-फलता का प्रभाव.

परिमाषाएं

भाग १९--प्रकीण--अनु० ३६६

- (ख) कि उस कर पर लागू होने वाली किन्हीं अधिनियमितियों से समवायों द्वारा दिये जाने वाले कर के बारे में कोई कटौती उन लाभांशों में से जो समवायों द्वारा व्यक्तियों को देय हैं प्राधिकृत नहीं है;
- (ग) कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने वाले व्यक्तियों की पूर्ण आय की गणना में, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय अथवा उन को लौटाये जाने वाली भारतीय आय-कर की गणना में, इस प्रकार दिये गये कर को सम्मिलित करने का कोई उपवन्ध विद्यमान नहीं है;
- (७) "तत्स्थानी प्रान्त", "तत्स्थानी देशी राज्य" अथवा "तत्स्थानी राज्य" से संशयात्मक दशाओं में अभिप्रेत हैं ऐसा प्रांत, देशी राज्य, या राज्य जिसे प्रश्नास्पद विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्र-पति यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त, तत्स्थानी देशी राज्य अथवा तत्स्थानी राज्य निर्धारित करे;
- (८) "ऋण" के अन्तर्गत है वार्षिकियों के रूप में मूलधन राशियों के लौटाने के किसी आभार के विषय में कोई दायित्व, तथा किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व तथा "ऋणभारों" का तदनुसार अर्थ किया जायेगा;
- (९) "सम्पत्ति-शुल्क" से अभिप्रेत है कोई शुल्क जो मृत्यु पर रिक्थ हुई, अथवा संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस शुल्क के सम्बन्ध में निर्मित विधियों के उपबन्धों के अधीन वैसी रिक्थ हुई समझी जाने वाली, सारी सम्पत्ति के, उक्त विधियों के द्वारा या अधीन विहित नियमों के अनुसार अभिनिश्चित, मूल मूल्य पर या के निर्देश से परिगणित की जानी हो;

भाग १९--प्रकीर्ण--अनु० ३६६

- (१०) "वर्तमान विधि" से अभिप्रेत है कोई विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम को बनाने की शक्ति रखने वाले किसी विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित या निर्मित है;
- (११) "फेंडरलन्यायालय" से अभिप्रेत है भारत शासन-अधिनियम १९३५ के अधीन गठित फेंडरल-न्यायालय ;
- (१२) "वस्तुओं" के अन्तर्गत है सब सामग्री पण्य और पदार्थ ;
- (१३) "प्रत्याभूति" के अन्तर्गत है कोई ऐसा आभार जो इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी उपक्रम के लाभों के किसी उल्लिखित राशि से कम होने की अवस्था में देने के लिये उठाया गया हो;
- (१४) "उच्चन्यायालय" से अभिप्रेत है कोई न्यायालय जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये किसी राज्य के लिये उच्चन्यायालय समझा जाता है, तथा इस के अन्तर्गत है—
 - (क) इस संविधान के अधीन उच्चन्यायालय रूप में गठित या पुनर्गठित भारत राज्य-क्षेत्र में का कोई न्यायालय; तथा
 - (ख) भारत राज्य-क्षेत्र में का कोई अन्य न्यायालय
 जो इस संविधान के सब या किन्हीं
 प्रयोजनों के लिये संसद् से विधि द्वारा
 उच्चन्यायालय घोषित किया जाये;
- (१५) "देशी राज्य" से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य-क्षेत्र जिसे भारत डोमीनियन की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती थी;

भाग १९--प्रकीर्ण--अनु० ३६६

- (१६) "भाग" से अभिप्रेत है इस संविधान का भाग;
- (१७) "निवृत्ति-वेतन" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को, या के बारे में, देय किसी प्रकार का निवृत्ति-वेतन चाहे फिर वह अंशदायी हो या न हो तथा इस के अन्तर्गत है उस प्रकार देय सेवा-निवृत्ति-वेतन, उस प्रकार देय, उपदान तथा किसी भविष्य निधि के चन्दों को ब्याज़ सहित या रहित तथा उन के अन्य जोड़ सहित या रहित लौटाने के लिये देय कोई राशि या राशियां;
- (१८) "आपात की उद्घोषणा" से अभिप्रेत है वह
 . उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद ३५२ के खंड (१)
 को अधीन निकाली गई हो;
- (१९) "लोक-अधिसूचना" से अभिप्रेत है भारत के सूचना-पत्र में अथवा जैसी कि स्थित हो, राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में अधिसूचना;
- (२०) "रेल" में--
 - (क) किसी नगर-क्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामवे,
 - (ख) संचार की कोई अन्य (लीक [जो १ किसी एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे संसद् ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित किया हो;
- (२१) "राजप्रमुख" से अभिप्रेत है।
 - (क) हैदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के निजाम के रूप में तत्सगय अभिज्ञात है;
 - (ख) जम्मू और काश्मीर राज्य या मैसूर राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में तत्समय अभिज्ञात है; तथा

भाग १९--प्रकीण --अनु ० ३६६

- (ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी अन्य राज्य कें सज्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपित द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात है,
 - तथा उस में उक्त राज्यों में से किसी के सम्बन्ध में, वह कोई व्यक्ति मी अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सम्बन्ध में राजप्रमुख की शक्तियां प्रयोग करने के लिये सक्षम तत्समय अभिज्ञात है;
- (२२) "शासक" से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत हैं कोई राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिस ने ऐसी कोई प्रसंविदा या करार, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है, किया था तथा जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्समय अभिज्ञात है तथा उस के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति द्वारा उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है;
- (२३) "अनुसूची" से. अभिप्रेत है इस संविधान की अनुसूची;
- (२४) "अनुसूचित जातियां" से अभिप्रेत हैं ऐसी जातियां, मूलवंश या आदिमजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भाग या उन में के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं;
- (२५) "अनुसूचित आदिमजातियां" से अभिप्रेत हैं ऐसी आदिम जातियां या आदिमजाति-समुदाय

१९--प्रकीर्ण--अनु० ३६६-३६७

अथवा ऐसी आदिम-जातियों या आदिमजाति-समुदायों के भाग या उन में के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसू-चित आदिमजातियां समझी जाती हैं;

- (२६) "प्रतिभूतियों" के अन्तर्गत निधि पत्र भी है;
- (২৬) "उपखंड" से अभिप्रेत है उस खंड का उपखंड जिस में कि यह पद आता है;
- (२८) "कराधान" के अन्तर्गत है किसी कर या लाभ-कर का लगाना चाहे फिर वह साधारण या स्थानीय या विशेष हो, और "कर" का तदनु-सार अर्थ किया जायेगा;
- (২९) ''आय पर कर'' के अन्तर्गत है अतिरिवत लाभ-कर के प्रकार का कर।
- (३०) "उपराजप्रमुख" से प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उिल्लेखित किसी राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात है।

निर्वचन.

- ३६७ (१) जब तक कि प्रमंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस संविधान के निर्वचन के हेतु साधारण परिभाषा-अधिनियम १८९७, किन्हीं ऐसे अनुकूलनों और रूपभेदों के साथ जैसे कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन उस में किये जायें वैसे ही लागू होगा जैसे कि वह भारत डोमीनियन के विधान-मंडल के अधिनियम के निर्वचन के लिये लागू है।
- (२) इस संविधान में संसद् के या द्वारा निर्मित अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश में अथवा प्रथम अनुसूची के भाग

भाग १९--प्रकीणं--अनु० ३६७

- (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के या द्वारा निर्मितं अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश के अन्तर्गत यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा अध्यादेश का निर्देश भी समझा जायेगा।
- (३) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये "विदेशी राज्य" से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई राज्य :

परन्तु संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसे कि आदेश में उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा।

भाग २०

संविधान का संशोधन

संविधात के संशोधन के लिये प्रत्रिया.

३६८ इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक को संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित कर के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक-सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उप-स्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से बहु विधेयक पःरित हो जाता है तब बहु राष्ट्रपति के समक्ष उस की अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात् विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा ३

परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन-

- (क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनु-च्छेद १६२, या अनुच्छेद २४१ में; अथवा
- (ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ या भाग ११ के अध्याय १ में; अथवा
- (ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में; अथवा
- (घ) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; अथवा
- (ङ) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में,

कोई परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमित को लिये उपस्थित किये जाने के पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मंडलों से पारित संकल्यों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

भाग २१

अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध

३६९ इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालाबिध में निम्नलिखित विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् को इस प्रकार शक्ति होगी मानो कि ये समवर्ती सची में प्रगणित हैं; अर्थात्—

- (क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची रुई (जिस के अन्तर्गत धुनी हुई रुई और विना धुनी रुई या कपास है), बिनौले, कागज (जिस के अन्तर्गत समाचार-पत्र का कागज है), खाद्य पदार्थ (जिस के अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं), ढोरों के चारे (जिस के अन्तर्गत खली और पथर अन्य सारकृत चारे हैं), कोयले (जिस के अन्तर्गत कोक और पथर-कोयला जन्य पदार्थ हैं), लोहे, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर ब्यापार और वाणिज्य तथा उन का उत्पा-दन सम्भरण और वितरण;
- (ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चतम-न्यायालय से भिन्न सब न्यायालयों का उस विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तथा उन विषयों से किसी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसों से अन्य फीसें.

किन्तु संसद् द्वारी निर्मित कोई विधि, जिसे इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अभाव में बनाने के लिये संसद् सक्षम म होती, उक्त कालाविध की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उस की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से छोड़ी गई बातों से अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रभाव हीन हो जायेगी।

राज्य-सूची में के कुछ विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो कि वे विषय समवर्ती सूची के हैं. भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७०

३७०. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,--

- (क) अनुच्छेद २३८ के उपबन्ध जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू न होंगे;
- (ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति——
 - (१) संघ-सूची और समवर्ती सूची में के जिन विषयों
 को राज्य की सरकार से परामर्श कर के
 राष्ट्रपित उन विषयों का तत्स्थानी विषय
 घोषित कर दे जो भारत डोमीनियन में उस
 राज्य के प्रवेश को शासित करने वाली
 प्रवेश-लिखत में उल्लिखित ऐसे विषय हैं जिन
 के बारे में डोमीनियन विधान-मंडल विधि
 बना सकता है उन विषयों तक; तथा
 - (२) उक्त सूचियों में के जिन अन्य विषयों को उस राज्य की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक; सीमित होगी।

व्याख्या — इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति १९४८ की मार्च के पांचवें दिन निकाली गई महाराजा की उद्घोषणा के अधीन तत्समय पदस्थ मंत्रि-परिषद् की मंत्रणा के अनुसार कार्य करने वाला जम्मू और काश्मीर का महाराजा तत्समय अभिज्ञात करता है;

- (ग) अनुच्छेद १ के और इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस राज्य के सम्बन्ध में लागू होंगे ;
- (घ) इस संविधान के उपबन्धों में से ऐसे अन्य उपबन्ध ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ उस राज्य के बारे में लागू होंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे;

जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उप-बन्ध.

भाग २१—-अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध —-अनु० ३७०-३७१

परन्तु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) की कंडिका (१) में निर्दिष्ट राज्य के प्रवेश- लिखत में उल्लिखित विषयों से सम्बद्ध हो राज्य की सरकार से परामर्श किये विना न निकाला जायेगा:

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई आदेश, जे अन्तिम पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से सम्बद्ध हो, उस सरकार की सहमति के विना न निकाला जायेगा।

- (२) यदि उस राज्य की सरकार द्वारा खंड (१) के उपखंड (ख) की कंडिका (२) में अथवा उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट सहमित, उस राज्य के लिये संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के बुलाये जाने से पहिले, दी जाये तो उसे ऐसी सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिये रखा जायेगा जैसा कि वह उस पर ले।
- (३) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा कि यह अनुच्छेद ऐसी ताीख से प्रवर्तनहीन, अथवा ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित ही प्रवर्तन में, होगा जैसे कि वह उल्लिखित करे:

परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपित द्वारा निकाले जाने से पिहले खंड (२) में निर्दिष्ट उस राज्य की मंविधान-सभा की सिपारिश आवश्यक होगी।

३७१ इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालाविध के भीतर अथवा किसी ऐसी दीर्घतर या अल्पतर कालाविध के भीतर, जिसे किसी राज्य के बारे में संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखत प्रत्येक राज्य की सरकार राष्ट्रपित के साधारण नियंत्रण के अधीन होगी तथा ऐसे विशिष्ट निदेशों का, यदि कोई हों, अनुवर्तन करेगी जैसे कि राष्ट्रपित समय समय पर दे:

परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद

प्रथम अनु-सूची के भाग (ख) में के राज्यों के विषय में अस्थायी उप-बन्ध. भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७१-३७२

के उपबन्ध उस आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को लागू न होंगे।

वर्तमान वि-धियों का प्रवृत्त बने रहना तथा उन का अनुकूलन.

- ३७२. (१) अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधि उस में तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित न की जाये।
 - (२) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबन्धों को इस संविधान के उपबन्धों से संगत करने के प्रयोजन से राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे अनुकूलन और रूपभेंद चाहे निरसन या चाहे संशोधन द्वारा, कर सकेगा जैसे कि आवश्यक या इष्टकर हों तथा उपबन्ध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से ले कर जैसी कि आदेश में उल्लिखित हो, ऐसे किये गये अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही प्रभावी होगी तथा ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी।
 - (३) खंड (२) की कोई बात-
 - (क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विधि का कोई अनुकूलन या रूपभेद करने की शक्ति देने वाली; अथवा
 - (ख) किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी ो राष्ट्रपित द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलन या रूपभेद की गई किसी विधि को निरसित या संशोधित करने से रोकने वाली,

न समझी जायेगी।

व्याख्या १ — इस अनुच्छेद में "प्रवृत्त विधि" पदाविल के अन्तर्गत है कोई विधि जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७२-३७३

राज्य-क्षेत्र में किसी विघान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित हुई हो तथा पहिले ही निरिसत न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब पूर्णतः अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हों।

व्याख्या २.—भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित किसी ऐसी विधि का, जिस का इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव तथा भारत राज्य-क्षेत्र में भी प्रभाव था, उपरोक्त किन्हीं अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा।

्रव्याख्या ३.—इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को, उस की समाप्ति के लिये नियत तारीख से, अथवा उस तारीख से, जिस को कि, यदि यह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता, तो वह समाप्त हो जाती, आगे प्रवृत्त बनाये रखती है।

व्याख्या ४.—िकसी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा ८८ के अबीन प्रख्यापित तथा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवृत्त अध्यादेश, यदि तत्स्थानी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहिले ही वापिस न ले लिया गया हो तो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अनुच्छेद ३८२ के खंड (१) के अधीन कृत्यकारिणी उस राज्य की विधान-सभा के प्रथम अधि-वेशन से छ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तनहीन होगा, तथा इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह ऐसे किसी अध्यादेश को उक्त कालाविध से आगे प्रवृत्त बनाये रखती है।

३७३. जब तक अनुच्छेद २२ के खंड ७ के अधीन संसद् उपबन्ध न करे, अथवा जब तक इस सविधान के प्रारम्भ के पश्चात् एक वर्ष समाप्त न हो, जो भी इन में से पहिले हो, तब तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि उस के खंड (४) और (७) में संसद् के प्रति किसी निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति के

निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुळ अवस्थाओं

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध— अनु० ३७३-३७४

में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति. प्रति निर्देश, तथा उन उपखंडों में संसद् द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रति निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये आदेश का निर्देश, रख दिया गया हो।

फेडरलन्याया-छय के न्याया-धीशों के तथा फेडरलन्याया-छय में अथवा सपरिषद् सम्राट् के, समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के बारे में जपबन्ध.

- ३७४. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरल-न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेंगे जैसे कि उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों के वारे में अनुच्छेद १२५ के अधीन उपबन्धित हैं।
- (२) इस संविधान के प्रारम्भ पर फेडरलन्यायालय में लिम्बत सभी व्यवहार-वाद, अपीलें और कार्यवाहियां, चाहे व्यवहार सम्बन्धी चाहे दाण्डिक, उच्चतमन्यायालय को चली गईं रहेंगी, तथा उच्चतमन्यायालय को उन के सुनने तथा निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा तथा फेडरलन्यायालय के, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले सुनाये या दिये गये निर्णयों और आदेशों का, ऐसा बल और प्रभाव होगा मानो कि वे उच्चतमन्यायालय द्वारा सुनाये या दिये गये हों।
- (३) इस संविधान की कोई बात भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की, या के विषय में, अपीलों या याचिकाओं को निबटाने क लिये सपरिषद् सम्राट् के क्षेत्राधिकार के प्रयोग को वहां तक अमान्य न करेगी जहां तक कि ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है तथा ऐसी किसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारम् के पश्चात् दिया गया सपरिषद् सम्राट् का कोई आदेश सब प्रयोज्ञनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानो कि वह उच्चतमन्यायालय द्वारा उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान द्वारा दिया गया है, दिया गया कोई आदेश या आज्ञप्ति हो।
 - (४) इस संविधान के प्रारम्भ पर, और से, प्रथम अनुसूची

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७४-३७६

क भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में अन्तःपरिषद् के रूप में कृत्यकारी प्राधिकारी का उस राज्य में के किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञिप्त या आदेश की अपील या याचिका को ग्रहण या निबटाने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारम्भ पर लिम्बत सब अपीलें और अन्य कार्यवाहियां उच्चतमन्यायालय को भेज दी जायेंगी और उस के द्वारा निबटाई जायेंगी।

(५) इस अनुच्छेद के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये संसद् विधि द्वारा और उपबन्ध बना सकेगी।

३७५. भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यवहार, दंड और राजस्व क्षेत्राधिकार वाले सब न्यायालय तथा न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और पदाधिकारी इस संविधान के उप-बन्धों के अधीन रहते हुए अपने अपने कृत्यों को करते रहेंगे। संविधान के उपबन्धों के अधीन रह कर न्यायालयों, प्राधिकारियों और पदा-धिकारियों का कृदय करते रहना

३७६. (१) अनुच्छेद २१७ के खंड (२) में किसी बात के होते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेंगे जैसे कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अनुच्छेद २२१ के अधीन उपबन्धित हैं।

उच्च न्या-यालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबन्ध.

(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७६-३७८

राज्य में के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर वैसे उल्लिखित राज्य में के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा अनुच्छेद २१७ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (१) के परन्तुक के अधीन रहते हुए ऐसी काला-विध तक पदस्थ बने रहेंगे जैसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।

(३) इस अनुच्छेद में "न्यायाधीश" पद के अन्तर्गत कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नहीं है।

भारत के नियंत्रकमहालेखापरीक्षक के बारे में उप-

३७७. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पदस्थ भारत का महालेखा-परीक्षक, यदि वह अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, ऐसे प्रारम्भ पर भारत का नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक हो जायेगा तथा तत्पश्चात् ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हक्क रखेगा जैसे भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद १४८ के खंड (३) के अधीन उपबन्धित हैं, तथा अपनी उस पदाविध की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे लागू होने वाले उपबन्धों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक, पदस्थ बने रहने का हक्क रखेगा।

लोकसेवा-आयोग के बारे में उपबन्ध.

- ३७८. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर संघ-लोकसेवा-आयोग के सदस्य हो जायोंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदाविध की, जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू होने वाले नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे।
- (२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त के लोकसेवा-आयोग के अथवा प्रान्तों के समह की आवश्यकता

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७८-३७९

के लिये सेवा करने वाले किसी लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, यथास्थिति तत्स्थानी राज्य के लोकसेवा-आयोग के सदस्य अथवा तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं के लिये सेवा करने वाले संयुक्त राज्य-लोकसेवा-आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के खंड (२) के परन्तुक के अवीन रहते हुए अपनी उस पदाविध की जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे।

३७९. (१) जब तक कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन संसद् के दोनों सदन सम्यक् रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्त्र में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक वह निकाय, जो भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कृत्यकारी था, अन्तर्कालीन संसद् होगा तथा इस संविधान के उपबन्धों द्वारा संसद् को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

व्याख्या.—इस खंड के प्रयोजनों के लिये भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के अन्तर्गत—

- (१) किसी राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र का, जिन के प्रति-निधित्व के लिये खंड (२) के अधीन उपबन्ध है, प्रतिनिधित्व करने के लिये चुने गये सदस्य, तथा
- (२) उक्त सभा में आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति के लिये चुने गये सदस्य,

भी होंगे ।

- (२) राष्ट्रपति नियमों द्वारा--
- (क) खंड (१) के अघीन कृत्यकारणी अन्तर्कालीन संसद् में किसी ऐसे राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र के, जिस का प्रतिनिधित्व इस संविधान के प्रारम्भ

अन्तर्कालीन संसद् तथा उस के अध्यक्ष और उपाच्यक्ष के बारे में उपबन्ध.

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७९

से ठीक पहिले भारत डोमीनियन की संविधान-सभा में न था, प्रतिनिधित्व के लिये,

- (ख) अन्तर्कालीन संसद् में ऐंसे राज्यों या अन्य राज्य-क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिस रीति से चुने जायेंगे उस के लिये, तथा
- (ग) ऐसे प्रतिनिधियों की जो अहंताएं चाहियें उन के लिये,

उपबन्ध कर सकेगा।

- (३) यदि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा का कोई सदस्य १९४९ के अक्टूबर के छठे दिन अथवा तत्पश्चात् इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय किसी राज्यपाल-प्रान्त अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य था अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री था तो इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर संविधान-सभा में ऐसे सदस्य का स्थान, यदि उस का उस सभा का सदस्य होना इस से पहिले ही समाप्त न हो गया हो, रिक्त हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकरिमक रिक्तता समझी जायेगी।
- (४) इस बात के होते हुए भी कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा में ऐसी कोई रिक्तता, जैसी कि खंड (३) में विणित है, उस खंड के अधीन नहीं हुई है, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिये पग उठाया जा सकेगा किन्तु ऐसे प्रारम्भ से पहिले उस रिक्तता की पूर्ति के लिये पृति के लिये चुने हुए किसी व्यक्ति को उक्त सभा में अपना स्थान ग्रहण करने का हक्क तब तक न होगा जब तक कि रिक्तता इस प्रकार न हो जाये।
- (५) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत शासन-अधिनियम १९३५ के अधीन डोमीनियन विधान-मंडल के रूप में कृत्यकारिणी संविधान-सभा के अध्यक्ष

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३७९-३८२

ुया उपाध्यक्ष के रूप में पदस्य था, वह ऐसे प्रारम्भ पर खंड
(१) के अधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद् का यथास्थिति
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा।

- ३८०० (१) ऐसा व्यक्ति, जिसे उस बारे में भारत डोमीनियन की संविधान-सभा ने निर्वाचित कर लिया हो, भारत का तब तक राष्ट्रपति होगा जब तक कि भाग ५ अध्याय १ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाये तथा अपने पद को ग्रहण न कर ले।
- (२) भारत डोमीनियन की संविधान-सभा द्वारा इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपित के पद में, उस की मृत्यु, पदत्याग या हटाये जाने के कारण या अन्यथा, कोई रिक्तता होने पर उस की पूर्ति अनुच्छेद ३७९ के अधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद् द्वारा उस लिये निर्वाचित व्यक्ति से की जायेगी तथा जब तक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित न हो तब तक भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपित के रूप में कार्य करेगा।
- ३८१. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राष्ट्रपति उस लिये नियुक्त करे, इस संविद्यान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् के सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें, तब तक इस संविद्यान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत डोमीनियन के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्य सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविद्यान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।
- ३८२. (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लि-खित प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्त्र में अविवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्यानी प्रान्त के कृत्यकारी विधान-मंडल का सदन, या के सदन, इस संविधान के उपबन्धों द्वारा ऐसे राज्य के विधान-मंडल के सदन या

राष्ट्रपति के वारे में उपवन्ध.

राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्.

प्रथम अनुसूची के भाग
(क) में के
राज्यों के
अन्तर्कालीन
विधान-मंडलों
के बारे में
उपवन्ध.

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध— अनु० ३८२-३८३

सदनों को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा या करेंगे।

- (२) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पिहले किसी प्रान्त की विधान-सभा के पुनर्गठन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया है वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् निर्वाचन इस प्रकार पूरा किया जा सकेगा मानो कि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं आया है तथा ऐसी पुनर्गठित सभा उस खंड के प्रयोजनों के लिये उस प्रान्त की विधान-सभा समझी जायेगी।
- (३) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अथवा विधान-परिषद् के सभापित या उपसभापित के रूप में पदस्थ था, ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित तत्स्थानी राज्य की विधान-सभा का यथास्थित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा, विधान-परिषद् का यथास्थिति सभापित या उपसभापित होगा, जब तक कि वह सभा या परिषद् खंड (१) के अधीन कृत्य करती है:

परन्तु जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के पुनर्गंठन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया है तथा ऐसी पुनर्गंठित सभा का प्रथम अधिवेशन ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् होता है वहां इस खंड के उपबन्ध लागू न होंगे तथा ऐसी पुनर्गंठित सभा अपने दो सदस्यों को क्रमशः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के लिये निर्वाचित करेगी।

प्रान्तों के राज्यपालों के बारे में उपबन्ध. ३८३. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले जो व्यक्ति किसी प्रान्त में राज्यपाल के रूप में पदस्थ हैं वह ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिख्त तत्स्थानी राज्य का राज्यपाल तब तक होगा जब तक

भाग २१—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध— अनु० ३८३-३८६

कि भाग ६ के अध्याय २ के उपबन्धों के अनुसार नया राज्य-पाल नियुक्त न हो गया हो और उस ने अपना पद ग्रहण न कर लिया हो।

३८४. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य का राज्यपाल उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन राज्यपाल की मंत्रि-परिषद् के सदस्य होंगे तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्य सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन उस राज्य के राज्यपाल की मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।

राज्यपालों की मंत्रि-परिषद्.

३८५. जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लि-खित राज्य के विधान-मंडल का सदन या के सदन इस संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से गठित न हो जायें तथा प्रथम सत्त् में अधिवेशित होने के लिये आहूत न हो जायें तब तक वह निकाय या प्राधिकारी, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के विधान-मंडल के रूप में कृत्यकारी था, उस प्रकार उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को इस संविधान उपबन्धों द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के अन्तकालीन विधान-मंडलों बारे में उपबन्ध.

३८६. ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य का राजप्रमुख उस लिये नियुक्त करे, इस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख की मंत्रि-पारषद् के सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख की मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे।

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों की मंत्रि-परिषद्.

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३८७-३८८

कुछ निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये जन-संस्था के निर्धारण बारे में विशेष पबन्ध. ३८७. इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की काला-विध में इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन किये गये निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये भारत या उस के किसी भाग की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे तथा ऐसे आदेश द्वारा विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये विभिन्न उपवन्ध बनाये जा सकेंगे।

अन्तर्कालीन संसद् तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के बारे में

- ३८८. (१) अनुच्छेद ३७९ के खंड (१) के अधीन कृत्य-कारिणी अन्तर्कालीन संसद् के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, जिस के अन्तर्गत उस अनुच्छेद के खंड (३) और (४) में निर्दिष्ट रिक्ततायें भी हैं तथा ऐसी रिक्त-ताओं की पूर्ति से सम्बद्ध सब विपयों का (जिन के अत्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय करना भी है) विनियमन——
 - (क) राष्ट्रपति उस बारे में जो नियम बनायें, उन के अनुसार, तथा
 - (ख) जब तक इस प्रकार नियम न बनें तब तक यथास्थिति भारत डोमीनियन की संविधान-सभा में
 की आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के समय,
 अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले
 वैसी रिक्तताओं की पूर्ति से तथा तत्संसक्त विषयों
 से सम्बद्ध प्रवृत्त नियमों में, वैसे प्रारम्भ
 से पहिले उस सभा का सभापति तथा
 तत्पश्चात् भारत का राष्ट्रपति जो अपवाद
 और रूपभेद करे उन के अधीन रह कर उन
 नियमों कें अनुसार,

होगा:

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३८८

परन्तु जहां ऐसा कोई स्थान, जैसा कि इस खंड में विणित है रिक्त होने से ठीक पहिले ऐसे व्यक्ति द्वारा घारित था जो अनुसूचित जातियों का अथवा मुस्लिम या सिक्ख समुदाय का है तथा यथास्थिति किसी प्रान्त का अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता रहा है वहां जब तक कि यथास्थिति संविधान-सभा का सभापित अथवा भारत का राष्ट्रपित अन्यथा उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय न समझे तब तक ऐसे स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसी समुदाय का होगा:

परन्तु यह और भी कि किसी प्रान्त या प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के स्थान में ऐसी किसी रिक्तता की पूर्ति करने के लिये निर्वाचन में यथास्थिति उस प्रान्त की या तत्स्थानी राज्य की या उस राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक सदस्य को भाग लेने और मत देने का हक्क होगा।

व्याख्या.--इस खंड के प्रयोजनों के लिये--

(क) जो सब जातियों, मूलवंश या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के जो भाग या में के जो यूथ भारत-शासन (अनुसूचित जाति) आदेश १९३६ में किसी प्रान्त के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के नाम से उिल्लेखित हैं वे तब तक उस प्रान्त अथवा तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी जब तक कि उस तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३४१ के खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों को उिल्लेखित करने वाली अधिसूचना राष्ट्रपित द्वारा निकाल दी गई हो;

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु ० ३८८-३६०

- (ल) किसी प्रान्त या राज्य में की सब अनुसूचित जातियां एक ही समुदाय समझी जायेंगी।
- (२) अनुच्छेद ३८२ या अनुच्छेद ३८५ के अधीन कृत्यकारी राज्य के विधान-मंडल के सदन में के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से संसक्त सब विषयों का (जिन के अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त शंकाओं और विवादों का विनिश्चय भी है) विनियमन, ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति को शासित तथा ऐसे वि यों का विनियमन करने वाले ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवृत्त थे, ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे, होगा।

होमीनियन विधान-मंडल तथा प्रांतों और देशी राज्यों के विधान-मंडलों में लम्बित विधेयकों के बारे में उपबन्ध. ३८९. कोई विधेयक, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पिहले भारत डोमीनियन के विधान-मंडल में अथवा किसी प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में लिम्बत था, किसी ऐसे प्रतिकूल उपबन्ध के अधीन रह कर जो यथास्थिति संसद् अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस संविधान के अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाये, यथास्थित संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में इस प्रकार चालू रखा जा सकेगा, मानो कि भारत डोमीनियन के विधान-मंडल में अथवा उस प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में उस विधान-मंडल के बारे में की गई कार्यवाहियां संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में जस विधान-मंडल में उस विधान-मंडल के विधान-मंडल में उस विधान-मंडल में की गई कार्यवाहियां संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में की गई कार्यवाहियां संसद् में अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल में की गई थीं।

इस संविधान के प्रारम्भ और १९५० की ३१ मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापित या व्यय किया इसा धन. ३९०. भारत की संचित निधि से, अथवा किसी राज्य की संचित निधि से, तथा इन निधियों में से किसी से धनों के विनियोग से, सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्ध उन धनों के सम्बन्ध में लागू न होंगे जो धन कि इस संविधान के प्रारम्भ के दिन तथा १९५० की मार्च के ३१वें दिन के बीच, इन दोनों दिनों को सम्मिलित कर के, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त या उत्थापित या व्यय किये गये

भाग २१--अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३९०-३९२

हों तथा अपित उस कालाविष में किया गया कोई व्यय, प्राधिकृत व्यय की किसी ऐसी अनुसूची में उल्लिखित हैं जो भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल या तत्स्थानी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अनुसार प्रमाणीकृत है अयवा राज्य के राजप्रमुख द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के राजस्वों में से व्यय को प्राधिकृत करने के लिये लागू थे, प्राधिकृत कर दिया गया है तो वह व्यय सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया समका जायेगा।

- ३९१. (१) यदि इस संविधान के पारित होने तया इस के प्रारम्भ के बीच में किसी समय भारत शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अधीन कोई किया की जाती है जिस के लिये राष्ट्रपति की राय में प्रथम अनुसूची और चतुर्य अनुसूची में कोई संशोधन अपेक्षित है तो राष्ट्रपति, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उक्त अनुसूचियों में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे कि इस प्रकार की गई किया को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे अनुपरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी अन्तविष्ट हो सकेंगे जैसे कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे।
 - (२) जब प्रथम अनुसूची या चतुर्थं अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये तब इस संविधान में उस अनुसूची के प्रति निदेश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह इस प्रकार संशोधित वैसी अनुसूची के प्रति निदेश है।
 - ३९२. (१) राष्ट्रपति किन्हीं किठनाइयों को विशेषतः भारत शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों से इस संविधान के उप-बन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में किठनाइयों को दूर करने के प्रयो-जन से आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश

कुछ आकस्मिकताओं
में प्रथम
और चतुर्थ
अनुसूची के
संशोधन करने
की राष्ट्रपति की
शक्ति.

कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति.

भाग २१-- अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध--अनु० ३९२

में उल्लिखित कालाविध में, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूप-भेद या जोड़ या लोप के रूप में हों, रह कर जैसे कि वह आवश्यक या इष्टकर समझे प्रभावी होगा:

परन्तु भाग ५ के अध्याय ३ के अधीन सम्यक् रूप से गठित संसद् के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् ऐसा कोई आदेश न निकाला जायेगा ।

- (२) खंड (१) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश संसद् के समक्ष रखा जायेगा ।
- (३) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद ३२४, अनुच्छेद ३६७ के खंड (३) और अनुच्छेद ३९१ द्वारा राष्ट्रपित को दी गई शक्तियां इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्तब्य होंगी।

भाग २२

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन

३९३. यह संविधान भारत का संविधान के नाम से कात हो संक्षिप्त नाम. सकेगा।

३९४ यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५,६,७,८,९,६०,३२४, शरम्भ. ३६६,३६७,३७९,३८०,३८८,३९१,३९२,और ३९३ तुरन्त प्रवृत्त होंगे, तथा इस संविधान के अविशष्ट उपवन्ध १९५० की २६ जनवरी के दिन प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

३९५. भारत स्वाधीनता-अधिनियम १९४७ और भारत- निरसन. शासन-अधिनियम १९३५ पश्चादुक्त अधिनियम के प्रिवी कौन्सिल क्षेत्राधिकार अधिनियम १९४९ को छोड़ कर संशोधन या अनुपूरण करने वाली सब अधिनियमितियों के साथ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

	·
-	
	·

प्रथम अनुसूची

(अनुच्छेद १, ४ और ३९१)

भारत के राज्य श्रीर राज्य-क्षेत्र

भाग (क)

राज्यों के नाम	तत्स्थानी प्रान्तों के नाम

१ आसाम
 २ उड़ीसा
 ३ पंजाब
 ४ पश्चिमी बंगाल
 आसाम
 उड़ीमा
 पृवीं पंजाब
 पश्चिमी बंगाल

५ बिहार . बिहार ६ मद्रास मद्रास

७ मध्यप्रदेश मध्य प्रान्त और बरार

८. मुम्बई बम्बई९ युक्त प्रदेश युक्त प्रान्त

राज्यों के राज्य-क्षेत्र

आसाम राज्य के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले आसाम प्रान्त खासी राज्य और आसाम आदिमजाति-क्षेत्र के राज्य-क्षेत्रों में समाविष्ट थे।

पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पश्चिमी बंगाल प्रान्त के राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट था।

इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 'पहिले तत्स्थानी प्रान्त के राज्य-क्षेत्र में तथा ऐसे राज्य-क्षेत्रों में समाविष्ट थे जो कि भारत-शासन-अधि-नियम १९३५ की धारा २९० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों।

प्रथम अनुसूची भाग (ख)

राज्यों के नाम

- १. जम्मू और काश्मीर
- र. तिरुवांकुर-कोचीन
- ३. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ
- ४. मध्य भारत
- ५ मैसूर
- ६. राजस्थान
- ७. विन्ध्य प्रदेश
- ८. सौराष्ट्र
- ९. हैदराबाद

राज्यों के राज्य-क्षेत्र

इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य में समाविष्ट था तथा—

- (क) राजस्थान और सौराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य की सर= कार द्वारा प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम १९४७ के उपवन्धों के अधीन या अन्यथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रशासित थे; तथा
- (ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट होगा जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले पन्थ पिपलोदा के मुख्य आधुक्त प्रान्त मे समाविष्ट था।

प्रथम अनुसूची भाग(ग)

राज्यों के नाम

- १. अजमेर
- २: कच्छ
- ३. कोच बिहार
- ४: कोड़ग
- ५. त्रिपुरा
- ६: दिल्ली
- ७. विलासपुर
- ८: भोपाल
- ९ः मनीपुर
- १०. हिमाचल प्रदेश

राज्यों के राज्य-क्षेत्र

अजमेर, कोड़गू और दिल्ली राज्यों में से प्रत्येंक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले ककशः अजमेर-मेरवाड़ा, कोडगु और दिल्ली के मुख्य आयुक्तों के प्रान्त में समा-विष्ट था।

इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जो भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पिहले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उसी नाम के मुख्यायुक्त प्रान्त रहे हों।

भाग (घ)

अन्दमान और निकोबर-द्वीप।

ः[ब्रानुच्छेद ५९ (३), ६५ (३), ७५ (६), ९७, १२५, १४८ (३), १५८ (३), १६४ (५), १८६ श्रीर २२१]

भाग (क)

राष्ट्रपति तथा । थम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के राज्य-पालों के लिये उपवन्ध,

१ राष्ट्रपति तथा प्रयम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित उग्लिब्ध्यां प्रतिमास दी जायेंगी अर्थात्—

राज्य के राज्यपाल को ५०,००० रुपया

- २. राष्ट्रपति तथा इस प्रकार उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्ते भी दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल को तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवर्नरों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे।
- ३ राष्ट्रपति तया ऐसे राज्यों के राज्यपालों को अपनी अपनी सम्पूर्ण पदाविध में ऐसे विशेषाधिकारों का हक्क होगा जैसे कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः गवर्नर जनरल तथा तत्स्थानी प्रान्तों के गवर्नरों को था।
- ४. जब कि उपराष्ट्रपित अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपित के कृत्यों का निर्वहन अथवा उस के रूप में कार्य कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उसको वैसी ही उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्का होगा जैसा कि यथास्थिति राष्ट्रपित या राज्यपाल को है जिस के कृत्यों का वह निर्वहन करता है अथवा यथास्थिति जिस के रूप में वह कार्य करता है।

भाग (ख)

संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) श्रीर (ख) में के राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध में उपबन्ध,

५ संघ के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को ऐसे वेतन और भक्ते दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे।

६ प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त या तत्स्थानी देशी राज्य के ऐसे मंत्रियों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे।

भाग (ग)

लोक-सभा के अध्यत्त और उपाध्यत्त के तथा राज्य-परिषद् के सभापित और उपसभापित के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य की विधान-सभा के अध्यत्त और उपाध्यत्त के तथा ऐसे किसी राज्य की विधान-परिषद् के सभापित और उपसभापित के सम्बन्ध में उपवन्ध.

७. लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-परिषद् के सभापित को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के अध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे तथा लोक-सभा के उपा-ध्यक्ष को और राज्य-परिषद् के उपसभापित को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के उपाध्यक्ष को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे।

८. प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ऐसे राज्य की विधान-परिषद् के सभापित और उपसभापित को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि क्रमशः तत्स्थानी प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद् के सभापित और उपसभापित को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे, तथा जहां तत्स्थानी प्रान्त की ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कोई विधान-परिषद् न थी वहां उस राज्य की विधान-परिषद् के सभापित और उपसभापित को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि उस राज्य का राज्य-पाल निर्धारित करे।

भारत का संविधान द्वितीय अनुसूची

भाग (घ)

उच्चतमन्यायालय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध.

र् ९. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेव में बिताये समय के बारे में निम्नलिखितादूदर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा अर्थात्—

मुख्य न्यायाधिपति ५,००० रुपया कोई अन्य न्यायाधीश्रा

परन्तु यदि उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उस की पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहिले की गई सिवा के बारे में (नियोंग्यता या क्षत-पेन्शन से अतिरिक्त) कोई निवृत्ति-वेतन मिलता हो तो उच्चतमन्यायालय में सेवा के बारे में उस के वेतन में से निवृत्ति-वेतन की राशि घटा दी जायेगी।

- (२) उच्चतमन्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को, विना किराया दिये, पदावास के उपयोग का हक्क होगा।
- (३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) में की कोई बात उस न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले—
 - (क) फेडरलन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण किये था, तथा जो ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७४ के खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बन गया है; अथवा
 - (ख) फेडरलन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के अधीन उच्चतमन्यायालय का (मुख्य न्यायाध्रिपति से अन्य) कोई न्यायाधीश बन गया है,

उस कालाविघ में, जिस में कि वह ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में पद घारण करता है, लागू न होगी, तथा प्रत्येक न्यायाधीश को, जो इस प्रकार उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति

या अन्य न्यायाधीश हो जाता है, या स्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तिविक सेवा म बिताये समय के बारे में इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन से अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

- (४) उच्चतमन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षत्र के भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे युक्तियुक्त भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे।
- (५) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति-छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी सम्बन्धी भत्ते भी हैं) तथा निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे।
- १०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य में के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा, अर्थातु—

मुख्य न्यायाधिपति ४,००० रुपये कोई अन्य न्यायाधीश ३,५०० रुपये

- (२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले-
 - (क) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय क मुख्य न्यायाधिपित के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७६ के खंड (१) के अधीन तत्स्थानी राज्य के उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपित बन गया है, अथवा
 - (ख) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद्धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के अधीन तत्स्थानी राज्य में के उच्चन्यायालय का (मुख्य न्यायाधिपति से अन्य) कोई न्यायाधीश बन ग्रया है,

उसको यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित दर से अधिक वेतन पाता था तो, यथास्थिति ऐसे मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में उक्त उपकंडिका में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।

- (३) उच्चन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूर्ति के लिये ऐसे युवितयुवत भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी जैसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे।
- (४) किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति-छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी-भत्ते भी हैं) और निवृत्ति-वेतन के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे।
 - ११. इस भाग में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो---
 - (क) "मुख्य न्यायाधिपति" पदाविल के अन्तर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति है तथा "न्यायाधीश" पद के अन्तर्गत तदर्थ न्यायाधीश है।
 - (ख) "वास्तविक सेवा" के अन्तर्गत :---
 - (१) न्यायाधीश के रूप में क व्य करते हुए अथवा ऐसे अन्य कृत्यों के पालन में, जिन का कि राष्ट्रपति की आकांक्षा पर उस ने निर्वहन करने का भार लिया हो, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत समय;
 - (२) उस समय को न गिन कर जिस में कि वह न्यायाधीश छुट्टी ले कर अनुपस्थित है, विश्रामावकाश ; तथा
 - (३) उच्चन्यायालय से उच्चतमन्यायालय को अथवा एक उच्च-न्यायालय से दूसरे को बदले जाने पर योगकाल।

भाग (ङ)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरी चक के सम्बन्ध में उपबन्ध.

- १२· (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चार सहस्र रुपये प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायेगा।
- (२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महा-लेखा-परीक्षक के रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७७ के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है उस को इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर है।
- (३) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से यथास्थिति शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखा-परीक्षक को लागू थे तथा उन उपबन्धों में गवर्नर जनरल के प्रति सब निर्देशों का ऐसा अर्थ किया जायेगा मानो कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं।

तृतीय अनुस्चो

[अनुच्छेद ७५(४), ९९, १२४ (६), १४८(२), १६४(३), १८८ भ्रौर २१९] शपथ श्रौर प्रतिज्ञान के प्रपत्र

ξ

संघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र:---

"मैं, अमुक, अमुक, कि मैं स्विधान के प्रतिज्ञान करत! हूं कि मैं सित्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करत! हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के विना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

२

संघ के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र:---

"मैं,...अमुक,... ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ-मंत्री सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ-मंत्री कें रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अउस अवस्था को छोड़ कर जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

3

तृतीय अनुसूची

तथा जिस पद को म ग्रहण करने वाला हूं उस क कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा।"

8

उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :---

"मैं,...अमुक,...जो भारत के उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपित (या न्यायाधीश) (या भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) नियुक्त हुं ईश्वर की शपथ लेता हुं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना पालन करूंगा, तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखूंगा।"

у

राज्य के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :---

"में, . . अमुक, . . . ईश्वर की शपय लेता हूं कि में विधि द्वारा स्थापित । सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा में राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अन्तः करण से निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना में सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

ξ

राज्य के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र:---

"मैं, अमुक, क्रिक्ट की शपथ लेता हूं कि जो विषय ... सत्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़ कर जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उँचित निर्वहन के लिये ऐसा करना

तृतीय अनुसूची

अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

9

राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र:—

"मैं, . . . अमुक, . . जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्) के लिये सदस्य निर्वाचित (या नाम-निर्देशित) हुआ हूं, र्व्यविष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं सत्यिनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उस के कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा।"

ح

उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथया प्रतिज्ञान का

"मैं, . अमुक, . . . जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या न्यायाधीश) नियुक्त हुआ र्इश्वर की शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना पालन करूंगा, तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये रखुंगा।"

चतुर्थ अनुसूची

[अनुच्छेद ४ (१) ८० (२) ग्रौर ३९१]

राज्य-परिषद् में के स्थानों का बंटवारा

्रइस अनुसूची से संलग्न स्थान-सरिणी के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित प्रत्येक राज्य या राज्य-समूह को यथास्थिति उतने स्थान बांट में दिये जायेंगे जितने कि उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस राज्य या राज्य-समूह के सामने उल्लिखित हैं।

स्थान-सारिगो

राज्य-परिषद्

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि

8	२
राज्य	कुल स्थान
े१. आसाम	Ę
२. उड़ीसा	9
३. पंजाब	۷
४. पश्चिमी बंगाल	88
५. बिहार	२१
६. मद्रास	२७
७. मध्य प्रदेश	१२
८. मुम्बई	१७
९. युक्त प्रदेश	38

भारत का संविधान

चतुर्थं अनुसूची

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में डिल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि

8	२
राज्य	कुल स्थान
१. जम्मू और काश्मीर	٧
२. तिरुवांकुर-कोचीन	Ę
३. पटियाला ग्रौर पूर्वी पंजाब राज्य	TA .
४. मध्य भारत	€ .
५. मैसूर	Ę
६. राज स ्थान	9
७. विन्घ्य प्रदेश	8
८. सौराष्ट्र	8
९. हैदराबाद	११
	कुल ५३
प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लि	त्तखित राज्यों के प्रतिनिधि
8	२
राज्य और राज्यसमूह	कुल स्थान
१. अजमेर े	
१. अजमेर	8
१. अजमेर े २. कोड़गु ∫ ३. कच्छ	१
२. कोड़गु ∫ ३. कच्छ ४. कोच-बिहार	१ १ १
 श्रजमेर \ कोड़गु ∫ कच्छ कोच-बिहार दिल्ली 	१
 श्र अजमेर \ २. कोड़गु ∫ ३. कच्छ ४. कोच-बिहार ५. दिल्ली ६. बिलासपुर	१ १ १
 श्र अजमेर \ त कोड़गु ∫ क कच्छ कोच-बिहार दिल्ली बिलासपुर \ हिमाचल प्रदेश ∫ भोपाल 	१ १ १ १
 श. अजमेर \ २. कोड़गु ∫ ३. कच्छ ४. कोच-बिहार ५. दिल्ली ६. बिलासपुर ७. हिमाचल प्रदेश ∫ 	? ? ?

कुल स्थानों का जोड़...२०५

[अनुच्छेद २४४ (१)]

अनुसूचित चेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में उपबन्ध

भाग (क)

साधारण

- १. निर्वचन इस अनुसूची में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो "राज्य" पद से अभिप्रेत है प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य किन्तु इसके अन्तर्गत आसाम राज्य नहीं है।
- २ अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति .--इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उत में के अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा।
- ३. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपित को राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रतिवेदन प्रत्येक राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख जिस में अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष, अथवा जब भी राष्ट्रपित इस प्रकार की अपेक्षा करे, उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपित को प्रतिवेदन करेगा तथा संघ की कार्यगालिका शक्ति राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में निदेश देने तक विस्तृत होगी।

भाग (ख)

अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

४. आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् — (१) प्रत्येक राज्य में, जिस में अनुसूचित क्षेत्र है, तथा, यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिस में अनुसूचित आदिमजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् स्थापित की जायेगी जिसके बीस से अधिक सदस्य न होंगे जिन में कि यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान-सभा में के अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधि होंगे :

परन्तु यदि उस राज्य की विधान-सभा में के अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन आदिमजातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे।

- (२) आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य में की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बद्ध ऐसे विषयों पर मंत्रणा दे जो उन को यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा सौंपे जायें।
 - (३) राज्यपाल या राजप्रमुख---
 - (क) परिषद् के सदस्यों की संख्या, उन की नियुवित की तथा परिषद् के सभापति तथा उस के पदाधिकारियों और सेवकों की नियुवित की रीति के;
 - (ख) उस के अधिवेशनों के संचालन तथा उस की साधारण प्रक्रिया के; तथा
 - (ग) अन्य सब प्रासंगिक विषयों के,

यथास्थिति विहित करने या विनियमन करने के लिये नियभ बना सकेगा।

- ५. अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि .—(१) इस संविधान में किसी बात के होतें हुए भी यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दें सकेगा कि संसद् का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में लागू न होगा अथवा राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ लागू होगा जैसा कि वह अधिसूचना में उल्लिखित करे और इस उपकंडिका के अधीन दिया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उस का भूतलक्षी प्रभाव हो।
- (२) यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख राज्य में के किसी ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा जो कि तत्समर्य अनुसूचित क्षेत्र है।

विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर विना विपरीन प्रभावः डाले ऐसे विनियम—

- (क) ऐसे क्षेत्र में की अनुसूचित आदिमजानियों के सदस्यों द्वारा या में भूमि के हस्तान्तरण का प्रतिषेध या निर्बन्धन कर सकेंगे;
- (ख) ऐसे क्षेत्र में की आदिमजातियों के सदस्यों को भूमि बांटने का विनियमन कर सकेंगे;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों को घन उघार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे।
- (३) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जैसा कि इस कंटिका की उपकंटिका (२) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल या राजप्रमुख संसद् के या उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम को अथवा विसी वर्तमान विधि को जो प्रश्नास्पद क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसित या संशोधित कर सकेगा।
- (४) इस कंडिका के अधीन बनाये गये सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपिन को प्रेषित किये जायेंगे और जब तक वह उन को अनुमित न दे दे तब तक उन का कोई प्रभाव न होगा।
- (५) इस कंडिका के अधीन कोई विनियम तब तक न बनाया जायेगा जब तक कि विनियम बनाने वाले राज्यपाल या राजप्रमुख ने उस राज्य के लिये आदिमजानि-मंत्रणा-परिषद् होने की अवस्था में ऐसी परिषद् से परामर्श न कर लिया हो।

भाग (ग)

अनुसूचित क्षेत्र

६. अनुसूचित क्षेत्र.--(१) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्रों" पदाविल से अभिप्रेत हैं ऐसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपित आदेश द्वारा अनु-सचित क्षेत्र होना घोषित करे।

- ं (२) राष्ट्रपति किसी समय भी आदेश द्वारा---
 - (क) निदेश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उस का कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग न रहेगा;
 - (ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को बदल सकेगा, किन्तु केवल सीमाओं का शोधन कर के ही बदल सकेगा;
 - (ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर अथवा संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर अथवा नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या उस का भाग घोषित कर सकेगा जो पहिले से किसी राज्य में समाविष्ट नहीं है;

तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध हो सकेंगे जैसे कि राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु उपर्युवत रीति से अन्यथा इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन किकाला गया आदेश किसी अनुगामी आदेश से परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

भाग (घ) अनुसूची का संशोधन

- . ७. अनुसूची का संशोधनः—(१) संसद्, समय समय पर विधि द्वारा जोड़, फेरफार या निरसन कर के, इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन कर सकेगी तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित हो जाये तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह निर्देश इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति है।
- (२) ऐसी कोई विधि जैसी कि इस कंडिका की उपकंडिका (१) में विणित है इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

[अनुच्छेद २४४ (२) और २७५ (१)]

; · 1

श्रासाम में के श्रादिमजाति-चेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध

- १. स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी क्षेत्र.—(१) इस कडिका के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अनुसूची की कंडिका (२०) से संलग्न सारिणी के भाग (क) के प्रत्येक पद में के आदिमजाति-क्षेत्रों का एक स्वायत्तशासी जिला होगा।
- (२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित आदिम- जातियां हैं तो राज्यपाल, लोक-अधिसूचना द्वारा, इन से बसे हुए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्तशासी प्रदेशों में बांट सकेगा।
 - (३) राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा---
 - (क) उक्त सारिणी के भाग (क) में किसी क्षेत्र को डाल सकेगा:
 - (ख) उक्त सारिणी के भाग (क) में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगा;
 - (ग) नया स्वायत्तशासी जिला वना मकेगा;
 - (घ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा;
 - (ङ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा;
 - (च) दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों या उन के भागों को मिला कर एक स्वायतशासी जिला वना सकेगा;
 - (छ) किसी स्वायत्तशासी जिले की सीमाएं परिभाषित कर सकेगा:

परन्तु राज्यपाल इस उपकंडिका के खंड (ग), (घ), (ङ) और (च) के अधीन कोई अधिक इस अनुसूची की कंडिका १४ की उपकंडिका (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद ही निकालेगा।

- २. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन.—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये चौबीस से अनिधक सदस्यों की एक जिला-परिषद् होगी जिन में से तीन चौथाई से अन्यून सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे।
- (२) इस अनुसूची की कंडिका (१) की उपकंडिका (२) के अधीन स्वायत्तशासी प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक पृथक् प्रादेशिक परिषद् होगी।
- (३) प्रःयेक जिला-परिषद् और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमशः (जिला का नाम) की "जिला-परिषद्" और (प्रदेश का नाम) की "प्रादेशिक परिषद्" के नाम से निगम-निकाय होगी, उस का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उस की एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा उक्त नाम से वह व्यवहार-वाद चलायेगी अथवा उस पर व्यवहार-वाद चलाया जायेगा।
 - (४) इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन ऐसे जिले की जिला-परिषद् में वहां तक निहित होगा जहां तक कि वह ऐसे जिले में की किसी प्रादेशिक परिषद् में इस अनुसूची के अधीन निहित नहीं है, तथा स्वायत्तशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् में निहित होगा।
 - (५) प्रादेशिक परिषद् वाले स्वायत्तशासी जिले में प्रादेशिक परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के बारे में जिला-परिषद् की इस अनुसूची द्वारा ऐसे क्षेत्रों के बारे में दी गई शिवतयों के अतिरिक्त केवल ऐसी शक्तियां और होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद् प्रत्यायोजित करे।
 - (६) राज्यपाल, सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों या प्रदेशों के अन्तर्गत वर्तमान आदिमजाति-परिषदों अथवा प्रतिनियान रखने वाले अन्य आदिम-जाति संघटनों से परामर्श कर के, जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिये नियम बनायेगा तथा ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिये उपबन्ध होंगे—
 - (क) जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की रचना तथा उन में स्थानों का बंटवारा;

- (ख) उन परिषदों के लिये निर्वाचनों के प्रयोजनार्व प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन;
- (ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान के लिये अईताएं तथा उन कें लिये निर्वाचक नामावलियों का तैयार कराना;
- (घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसे परिजदों के सदस्य चुने जाने के लिये अहेताएं;
- (ङ) ऐसो परिषदों के सदस्यों की पदाविध;
- (च) ऐसे परिषदों के लिये निर्वाचन या नाम-निर्देशन से सम्बद्ध या संसक्त कोई अन्य विषय;
- (छ) जिला और प्रादेशिक परिवदों में प्रक्रिया और कार्य-संचालन;
- (ज) जिला और प्रादेशिक परिषदों के पदाधिकारियों और कर्मचारी-वृन्द की नियुक्ति।
- (७) अपने प्रथम गठन के पश्चात् जिला या प्रादेशिक परिषद् इस कंडिका की उपकंडिका (६) में उल्लिखित विषयों के बारे म नियम बना सकेगी, तथा—
 - (क) निचली स्थानीय परिषदों या मंडलियों की रचना तथा उन की प्रक्रिया और उन के कार्य-संचालन का; तथा
- (ख) यथास्थिति जिलेया प्रदेश के प्रशासन विषयक कार्य-सम्पादन से सम्बद्ध समस्त साघारण विषयों का, विनियमन करने वाले नियम भी लना सकेगी:

परन्तु जब तक जिला अथवा प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस उप-कंडिका के अधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद् के लिये निर्वाचनों के, उस के पदाधिकारियों और कर्मचारी-वृन्द के तथा प्रक्रिया और कार्य-संचालन के बारे में इस कडिका की उप-कंडिका (६) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे:

परन्तु यह और भी कि इस अनुसूची की कंडिका (२०) से संलग्न सारिणी के भाग (क) में के क्रमशः पद ५ और ६ में के अन्तर्गत क्षेत्रों के बारे में उत्तर कछार और मिकिर पहाडियों का यथास्थिति मंडलायुक्त या उपविभागीय पदाधिकारी पदेन जिला-परिषद् का सभापित होगा, तथा जिला-परिषद् के प्रथम गठन के पदचात् छ वर्ष की कालाविध तक राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसे, जिला-परिषद् के किसी संकल्प या निर्णय को रद्द या रूपभेद करने की अथवा जिला-परिषद् को, जैसी वह उचित समझे, वैसी हिदायतें देने की शिवत होगी तथा जिला-परिषद् ऐसी दी हुई प्रत्येक हिदायत का अनुवर्तन करेगी।

- ः ३. जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि बनाने की शक्ति.—
- (१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के भीतर के सब क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर उस जिले के भीतर के अन्य सब क्षेत्रों के बारे में, निम्नलिखित विषयों के लिये विधियां बनाने की शक्ति होगी—
 - (क) किसी रक्षित वन की भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि को, कृषि या चराई के प्रयोजन के लिये अथवा निवास या कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिये जिस से किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की उन्नति सम्भावनीय हो, बंटन, दखल या उपयोग अथवा अलग रखना:

परन्तु ऐसी विधियों की किसी बात से अनिवार्य अर्जन
प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार
आसाम राज्य को, किसी भूमि के, चाहे वह दखल में हो या
न हो, लोक-प्रयोजनार्थ अनिवार्य अर्जन पर क्कावट न होगी;

- ख) रक्षित वन न होने वाले किसी वन का प्रबन्ध;
- ्ग) कृषि प्रयोजनार्थं किसी नहर या जलधारा का उपयोग;
- [घ] झूम की प्रथा का अथवा अन्य प्रकारों की स्थानान्तरणशील कृषि की प्रथा का विनियमन;

- (ङ) ग्राम अथवा नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियां;
- (च) ग्राम या नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिन क अन्तर्गत ग्राम या नगर आरक्षी और लोक-स्वास्थ्य और स्वच्छता भी है;
- (छ) प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार;
- (ज) सम्पत्ति का दायभाग;
- (झ) विवाह;
- (ञा) सामाजिक रूढ़ियां।
- (२) इस कंडिका में "रक्षित वन" से एसा क्षेत्र आभिप्रेत हैं जो आसाम-वन-विनियम १८९१ के अधीन, अथवा प्रश्नास्पद क्षेत्र में किसी दूसरी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, रक्षित वन है।
- (३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विधियां तुरन्त राज्यपाल के समक्ष रखी जायेंगी और जब तक वह उन को अनुमित न दे दे प्रभावी न होंगी।
- प्रशासन (१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकारात्रीन क्षेत्रों से उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के बारे में, ऐसे व्यवहार-वादों और मामलों के परीक्षण के लिये जिन के सभी पक्ष ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित आदिमजातियों के ही है तथा जो उन व्यवहार-वादों से भिन्न हैं जिन्हें इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध लागू होते हैं, उस राज्य के प्रत्येक न्यायालय का अपवर्जन कर के ग्राम-परिषदों के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी, तथा ऐसे पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी, जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के अधीन बनाई हुई विवियों के प्रशासन के लिये आवश्यक हों।

- (२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् अथवा उस प्रादेशिक परिषद् द्वारा उस लिये गठित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद् न हो तो ऐसे जिले की जिला-परिषद् अथवा उस जिला-परिषद् द्वारा उस लिये गठित कोई न्यायालय, इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध जिन व्यवहार-वादों और मामलों को लागू होते हों उन को छोड़ कर, इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन यथास्थित ऐसे प्रदेश अथवा क्षेत्र के अन्तर्गत गठित ग्राम-परिषद् अथवा न्यायालय द्वारा परीक्षीय समस्त व्यवहार-वादों और मामलों में अपीलीय न्यायालय की शक्तियां प्रयोग में लायेगा तथा उच्चन्यायालय और उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे व्यवहार-वादों अथवा मामलों में क्षेत्राधिकार न होगा।
- (३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के उपबन्ध जिन व्यवहार-वादों और मामलों पर लागू होते हैं उन पर आसाम का उच्चन्यायालय ऐसा क्षेत्राधिकार रखेगा और प्रयोग करेगा जैसा कि समय समय पर राज्यपाल आदेश द्वारा उल्लिखित करे।
- (४) यथास्थिति प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से—-
 - (क) ग्राम-परिषदों और न्यायालयों के गठन तथा इस कंडिका के अधीन प्रगोक्तव्य उन की शक्तियों के ;
 - (स) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन व्यवहार-वादों और मामलों के परीक्षण में परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के;
 - (ग) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला-परिषद् अथवा ऐसी परिषद् द्वारा संगठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के:
 - (व) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों के परिपालन के

(ङ) इस कंडिका की उपकंडिका (१) और (२) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये अन्य सब सहायक विषयों के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगी।

५ कूछ वादों, मामलों और अपराधों के परीक्षण के लिये प्रादेशिक और जिला-परिषदों को तथा किन्हीं न्यायालयों और पदाधिकारियों को व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता अधीन शक्तियों का प्रदान.—(१) राज्यपाल किसी स्वायत्तशासी जिले या प्रदेश में किसी ऐसी प्रवृत्त विधि से, जिस का उल्लेख राज्यपाल ने उस लिये किया है, पैदा हुए व्यवहार-वादों या मामलों के परीक्षण के लिये, अथवा भारतीय दण्ड-संहिता के अधीन अथवा ऐसे जिले या प्रदेश में तत्समय लागु किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन कालापानी या पांच वर्ष से अन्यन अवधि के लिये कारावास से दंडनीय अपराघों के परीक्षण के लिये ऐसे जिले अथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला-परिपद् या प्रादेशिक परिषद् को अथवा ऐसी जिला-परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा उस लिये नियुक्त किसी पदाधिकारी को यथास्थिति व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ के या दंड-प्रक्रिया-संहिता १८९८ के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जैसी कि वह समुचित समझे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्, न्यायालय या पदाधिकारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में व्यवहार-वादों, मामलों या अपराधों का परीक्षण करेगा।

- (२) राज्यपाल किसी जिला-परिषद्, प्रादेशिक परिषद्, न्यायालय या पदाधिकारी को इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों में से किसी को वापस ले सकेगा या रूपभेद कर सकेगा।
- (३) इस कंडिका में स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित दशा के अतिरिक्त व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ और दंड-प्रक्रिया-संहिता १८९८ किसी स्वायत्तशासी जिले में या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में, जिस को इस कंडिका के उपबन्ध लागू होते हैं, किन्हीं व्यवहार-वादों, मामलों या अपराधों के परीक्षण में लागू न होगी।

- ६ प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला-परिषद् की शक्ति स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, कांजीहौस, नौघाट, मीन-क्षेत्र, सड़कों और जल-पथों की स्थापना, निर्माण और प्रबन्ध कर सकेगी तथा विशेषतया जिले में के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में और जिस रीति से दी जाये, इसका निर्धारण कर सकेगी।
- ७ जिला और प्रादेशिक निधियां.—(१) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-निधि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक निधि गठित की जायेगी जिस में क्रमशः उस जिले की जिला-परिषद् द्वारा तथा उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् द्वारा यथास्थिति उस जिले या प्रदेश के इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन करने में प्राप्त सब धनों को जमा किया जायेगा।
 - (२) यथास्थिति जिला-निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबन्ध के लिये जिला-परिषद् और प्रादेशिक परिषद् राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बना सकेगी तथा इस प्रकार बने हुए नियम, उक्त निधि में धन के डालने के, उस में धन की अभिरक्षा के, तथा उपरोक्त विषयों से संसक्त या इन के सहायक किसी अन्य विषय के, सम्बन्ध में अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगे।
 - ८. भू-राजस्व निर्धारित करने तथा संग्रह करने और कर-आरोपण की शक्ति.—(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत सब भूमियों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हों तो उसके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ कर जिलान्तर्गत अन्य सब भूमियों के बारे में, स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को ऐसी भूमियों के बारे में, उन सिद्धान्तों के अनुसार भू-राजस्व निर्धारण करने और संग्रह करने की शक्ति होगी जो सामान्यतया आसाम राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजनार्थ भूमियों के परिगणन में आसाम सरकार द्वारा तत्समय अनुसरण किये जाते हैं।

- (२) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को, ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत किनों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हो तो उन के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर जिलों में के अन्य सब क्षेत्रों के बारे में स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को, भूमि और इमारतों पर करों को, तथा ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों पर पथ-कर को, उद्ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति होगी।
- ' (३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद् को ऐसे जिले के भीतर निम्न करों में से सब को या किसी को उद्ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति होगी, अर्थात्—
 - (क) वृत्तियों, ज्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर;
 - (ख) पशुओं, यानों ग्रौर नावों पर कर;
 - (ग) किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा नावों से जाने वाले व्यक्तियों और माल पर पथ-कर;
 - (घ) पाठशालाओं, औषधालाओं या सड़कों के बनाये रखने के लिये कर ।
- (४) इस कंडिका की उपकंडिका (२) और (३) में उिल्लिखत करों में से किसी के उद्ग्रहण और संग्रह को उपबन्धित करने के लिये यथास्थिति प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् विनियम बना सकेगी।
- ९. खनिजों के खोजने या निकालने के लिये अनुज्ञप्तियां या पट्टे.—
 (१) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में आसाम सरकार द्वारा खनिजों के अंशोजने या निकालने के लिये दी गई अनुज्ञप्तियों या पट्टों से प्रति वर्ष प्रोद्भूत होने वाले स्वामिस्व का ऐसा अंश उस जिला-परिषद् को दे दिया जायेगा जैसा कि आसाम सरकार और ऐसे जिले की जिला-परिषद् के बीच करार पाये।
- (२) जिला-परिषद् को दिये जाने वाले ऐसे स्वामिस्व के अंश के बारे में यदि कोई विवाद पैदा हो तो वह राज्यपाल को निर्धारण

के लिये सौंपा जायेगा तथा स्वविवेक से राज्यपाल द्वारा निर्धारित राशि इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन जिला-परिषद् को देय राशि समझी जायेगी तथा राज्यपाल का विनिश्चय अन्तिम होगा।

- १०. आदिमजातियों से भिन्न लो ों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिये जिला-परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति (१) स्वायत्त-शासी जिले की जिला-परिषद् उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उस में निवास करने वाली आदिमजातियों से भिन्न हैं, साहूकारी और व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लियें विनियम बना सकेगी।
- (२) विशेषतया तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर विना विपरीतः प्रभाव डाले ऐसे विनियम—
 - (क) विहित कर सकेंगे कि उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति रखने वाले के अतिरिक्त और कोई साहुकारी का कारबार न करेगा;
 - (ख) साहूकार द्वारा लगाई जाने या वसूल की जाने वाली व्याज की अधिकतम दर विहित कर सकेंगे;
 - (ग) साहूकारों द्वारा लेखा रखने का तथा जिला-परिषदों द्वारा उस लिये नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखे के निरीक्षण का उपबन्ध कर सकेंगे;
 - (घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवास करने वाली अनुसूचित आदिमजातियों में का नहीं है, जिला-परिषद् द्वारा उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति के विना किसी वस्तु में थोक या फुटकर कारबार न करेगा:

परन्तु इस कंडिका के अधीन ऐसे विनियम तब तक न बन सकेंगे जब तक कि वे जिला-परिषद् की समस्त सदस्य संख्या के तीन चौथाई से अन्यून बहुमत से पारित न किये जाये:

परन्तु यह और भी कि ऐसे [किन्हीं विनियमों के अधीन यह | क्षमता न होगी कि जो साहकार या व्यापारी ऐसे विनियमों के बनने के समय

से पूर्व जिले के अन्दर व्यापार करता रहा है, उस को अनुज्ञप्ति देना अस्वीकृत कर दिया जाये।

- (३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राज्यपाल के संमक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उन को अनुमित न दे दे प्रभावी न होंगे।
- ११: इस अनुसूची के अधीन बनी हुई विधियों, नियमों और विनियमों का प्रकाशन:— जिलां-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् हारा इस अनुसूची के अधीन बनाई हुई सब विधियां, नियम और विनियम राज्य के राजकीय सूचना-पक्र में तुरन्त प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन पर वे विधिसम प्रभावी होंगे ।
- १२ः स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों पर संसद् और राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना.—(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी--
 - (क) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों के बारे में है जिन को इस अनुसूची की कंडिका ३ में ऐसा विषय होना उल्लिखित किया गया है जिन के बारे में जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधि बना सकेगी तथा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो किसी अनासुत सौषविक पान के उपभोग का प्रतिषेध या निर्बन्धन करता है, किसी स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तशासी प्रदेश को तब तक लागू न होगा जब तक कि दोनों में से प्रत्येक स्थिति में ऐसे जिले की, अथवा ऐसे प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखने वाली, जिला-परिषद् लोक-अधिसूचना द्वारा उस प्रकार निदेश न दे तथा जिला-परिषद् किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश देने में यह निदेश भी दे सकेगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उस के किसी भाग पर लागू होने में अधिनियम ऐसे अपवादों या रूपभेदों के साथ प्रभावी होगा जैसे कि वह उचित समझे,
 - (ख) राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद् का अथवा राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम जिसे इस ु उपकंडिकां के खंड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होते, किसी

स्वायत्तशासी जिले या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को लागू न] होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश अथवा उस के किसी भाग को ऐसे अपवादों या रूपभेदों के साथ लागू होगा जैसे कि वह उस अधिसूचना में उल्लिखित करे।

- ्र (२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन दिया हुआ कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि इसका भूतलकी प्रभाव भी हो।
- १३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध प्राक्किलत प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक-वित्त-विवरण में पृथक् दिखाया जाना.—स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध प्राक्किलत प्राप्तियां और व्यय जो आसाम राज्य की संचित निधि में जमा होनी, या से की जानी, हैं पहिले जिला-परिषद् के सामने चर्चा के लिथे रखी जायेंगी तथा ऐसी चर्चा के पश्चात् इस संविधान के अनुच्छेद २०२ के अधीन राज्य के विधान-मंडल के समझ रखे जाने वाले वार्षिक-वित्त-विवरण में पृथक् दिखाई जायेंगी।
- १४. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति.—(१) राज्य-पाल, राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन से सम्बद्ध उस के द्वारा उल्लिखित किसी विषय की, जिस के अन्तर्गत इस अनुसूची की कंडिका (१) की उपकंडिका (३) के खंड (ग),(घ),(ङ) और (च) में उल्लिखित विषय भी हैं, जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये किसी समय भी आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के साधारणतया प्रशासन की और विशेषतया—
 - (क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं और संचार के उपबन्धों की ;
 - (खं) ऐसे जिलों और प्रदेशों के बारे में किसी नये या विशेष विधान की आवश्यकता की; तथा
 - (ग) जिला और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों के प्रशासन की, समय समय पर जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये आयोग नियुक्त कर सकेगा

तथा ब्रायोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया को परिभाषित कर सकेगा।

- (२) प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को राज्यपाल की तद्विषयक सिपारिकों के साथ, सम्बन्धित मंत्री उस पर आसाम सरकार द्वारा की जाने वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में व्याख्यात्मक जापन के साथ, राज्य के विधान-मंडल के सामने रखेगा।
- (३) शासन के कार्य को अपने मंत्रियों में बांटते समय आसाम का राज्यपाल अपने मंत्रियों में से विशेषतया एक को राज्य के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के कल्याण का भार-साधक बना सकेंगा।
- १५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों का रद्द या निलम्बन करना.— (१) यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाघान हो जाये कि जिला-परिषद् या प्रादेशिक परिषद् के किसी काम या संकल्प से भारत के क्षेम का संकट में पड़ना सम्भाव्य है तो वह ऐसे काम या संकल्प को रद्द या निलम्बित कर सकेगा तथा ऐसी कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत परिषद् का निलम्बन और परिषद् में निहित या उस से प्रयोवतब्य शिक्तयों में से सब या किन्हीं को अपने हाथ में ले लेना भी है) कर सकेगा जैसी वह ऐसे काम को किये जाने से या चालू रखे जाने से अथवा ऐसे संकल्प को प्रभावी किये जाने से रोकने के लिये आवश्यक समझे।
- (२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेश को, उस के कारणों सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष यथासम्भव शीघ्र रखा जायेगा तथा, यदि आदेश विधान-मंडल द्वारा प्रतिसंहत न कर दिया गया हो तो वह उस प्रकार दिये जाने की तारीख़ से १२ मास की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा:

परन्तु यदि, और जितनी बार, राज्य के विधान-मंडल द्वारा ऐसे आदेश के चालू रखने के लिये अनुमोदन का संकल्प पारित होता है तो आदेश, यदि राज्यपाल द्वारा प्रतिसंहत न कर दिया गया हो तो, उस तारीख से वारह मास की और कालाविध के लिये प्रवृत्त रहेगा जिस तारीख को कि इस कंडिका के अधीन वह अन्यथा प्रवर्तनशून्य होता ।

१६ जिला या प्रादेशिक परिषद् का विघटन.— इस अनुसूची की कंडिका १४ के अधीन नियुक्त आयोग की सिपारिश पर राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा किसी प्रादेशिक या जिला-परिषद् का विघटन कर सकेगा, तथा—

- (क) परिषद् के पुनर्गठन के लिये तुरन्त ही नया साधारण निर्वाचन करने के लिये निदेश दे सकेगा, अथवा
- (ख) राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद् के प्राधिकाराधीन क्षेत्र के प्रशासन को राज्यपाल अपने हाथ में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के ऐसे आयोग के, जो उक्त कंडिका के अधीन नियुक्त हुआ है, अथवा अन्य किसी निकाय के, जिसे वह समुपयुक्त समझता है, हाथ में १२ से अनिधक मास की कालाविध के लिये दे सकेगा:

परन्तु जब इस कंडिका के खंड (क) के अधीन कोई आदेश दे दिया गया हो तब राज्यपाल प्रश्नास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में साधारण निर्वाचन होने पर परिषद् के पुनर्गठन के प्रश्न के लिम्बत रहने तक इस कंडिका के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि यथास्थिति जिलाया प्रादेशिक परिषद् को, राज्य के विधान-मंडल के सामने अपने विचारों को रखने का अवसर दिये विना इस कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई कार्यवाही न की जायेगी।

१७. स्वायत्तशासी जिलों में निर्वाचन-क्षेत्रों के बनाने के हेतु ऐसे जिलों से क्षेत्रों का अपवर्जन — आसाम की विधान-सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिये राज्यपाल आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्दर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिये सभा में रक्षित स्थान या स्थानों के भरने के लिये किसी निर्वाचन-क्षेत्र का भाग न होगा, किन्तु इस प्रकार रक्षित न हुए सभा में के स्थान या स्थानों के भरने के लिये आदेश में उल्लिखत निर्वाचन-क्षेत्र का भाग होगा।

१८. कंडिका २० से संलग्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों

पर इस अनुसूची के उपन्बधों का लागू होना -- (१) राज्यपाल--

- (क) राष्ट्रपित के पूर्वानुमोदन से लोक-अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची के पूर्वगामी सब अथवा किन्हीं उपबन्त्रों को कंडिका २० से संलग्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिमजाति-क्षेत्र को, अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को, लागू कर सकेगा तथा ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र या भागका प्रशासन ऐसे उपबन्धों के अनुसार होगा, तथा
- (ख) ऐसे ही अनुमोदन से लोक-अधिसूचना द्वारा, उक्त सारिणी से उस सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिमजाति-क्षेत्र को अथवा उस के किसी भाग को अपवर्जित कर सकेगा ।
- (२) उक्त सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिमजाति-क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के बारे में जब तक इस कंडिका
 की उपकंडिका (१) के अधीन अधिसूचना नहीं निकाली जाती तब तक
 यथास्थिति ऐसे क्षेत्र अथवा उस के भाग का प्रसाशन राष्ट्रपित, आसाम
 के राज्यपाल द्वारा, जो उसके अभिकर्ता के रूप में होगा, करेगा तथा
 इस संविधान के भाग ९ के उपबन्ध उस में इस प्रकार लागू होंगे मानो
 कि ऐसा क्षेत्र या उसका भाग प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित
 राज्य-क्षेत्र हैं।
- (३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन राष्ट्रपित के अभिकर्ता के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन में राज्यपाल अपने स्विविक से कार्य करेगा।
- १९. अन्तर्कालीन उपबन्ध.—(१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र इस अनुसूची के अधीन राज्यपाल राज्य में के प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-परिषद् के गठन के लिये अग्रसर होगा तथा जब तक किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-परिषद् इस प्रकार गठित न हो तब तक ऐसे जिले का प्रशासन राज्यपाल में निहित होगा तथा ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इसे अनुसूची में दिये पूर्वगामी उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:—

- (क) संसद् का अथवा उस राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र में तब तक लागू न होगा जब तक कि राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा ऐसा होने का निदेश न दे, तथा किसी अधिनियम के बारे में राज्यपाल ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिनियम किसी क्षेत्र अथवा उस के किसी उल्लिखित भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित लागू होगा जिन को वह उचित समझे;
- (ख) ऐसे किसी क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये राज्यपाल विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बने विनियम ऐसे क्षेत्र में तत्समय लागू होने वाले संसद् के, अथवा उस राज्य के विधान-मंडल के, किसी अधिनियम को, या किसी वर्तमान विधि को, निरसित या संग्रोधित कर सकेंगे।
- (२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (क) के अधीन राज्यपाल द्वारा दिया हुआ कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि उस का भूतलक्षी प्रभाव भी हो।
- (३) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (ख) के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति के समक्ष रखे जायोंगे तथा जब तक वह उन को अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे।
- २०. आदिमजाति-क्षेत्र.—(१) निम्न सारिणी के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भीतर आदिमजाति-क्षेत्र होंगे।
- (२) शिलोंग, कटक और नगर-क्षेत्र के अन्तर्गत तत्समय समाविष्ट किन्हीं क्षेत्रों को अपवर्णित कर के, किन्तु शिलोंग के नगर-क्षेत्र के अन्दर समा-विष्ट इतने क्षेत्र को, जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग था, सम्मिलित कर के खासी राज्य तथा खासी और जयंतीया पहाड़ी जिले के नाम से इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ज्ञात क्षेत्रों से मिल कर संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिला बनेगा:

परन्तु इस अनुसूची की कंडिका ३ की उपकंडिका (१) के खंड (ङ) और (च), कंडिका ४, कंडिका ५, कंडिका ६, कंडिका ८

की उपकंडिका (२), उपकंडिका (३) के खंड (क), (ख) और (घ) और उपकंडिका (४) तथा कंडिका १० की उपकंडिका (२) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये शिलींग के नगर-क्षेत्र में ममाविष्ट कोई क्षेत्र उस जिले के अन्दर नहीं समझे जायेंगे।

(३) निम्न सारिणी में (संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले से अन्य) किसी जिले के या प्रशासी क्षेत्र के प्रति कोई निर्देश उस जिले या प्रदेश के प्रति इस संविधान के प्रारम्भ पर निर्देश समझा जायेगा:

परन्तु निम्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित आदिमजाति-क्षेत्रों के अन्तर्गत, मैदानों में के, कोई ऐसे क्षेत्र न होंगे जैसे कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से आसाम का राज्यपाल उस लिये अधिसूचित करे।

सारिणी

भाग (क)

- १ संयुक्त खासी-जयंतीया पहाड़ी जिला।
- २ गारो पहाड़ी जिला।
- ३ ल्साई पहाड़ी जिला।
- ४ नगा पहाड़ी जिला।
- ५ उत्तरी कछार पहाड़ियां।
- ६ मिकिर पहाड़ियां।

भाग (ख)

१. उत्तरी पूर्वीय सीमान्त इलाका जिस के अन्तर्गत वालिपारा सीमान्त इलाका, तिराप सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी जिला भी हैं।

२ नगा आदिमजाति-क्षेत्र।

२१, अनुसूची का संशोधन — (१) संसद् समय सयय पर विधि द्वारा जोड़, परिवर्तन, या निरसन कर के इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का संशोधन कर सकेगी, तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाये, तब

इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्देश इस प्रकार संशोधित अनुसूची के प्रति निर्देश समझा जायेगा ।

(२) कोई ऐसी विधि जो इस कंडिका की उपकंडिका (१) में विणित है इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लियें इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी।

सप्तम अनुसूची

(अनुच्छेद २४६)

सूची १. - संघ-सूची

- १. भारत की तथा उस के प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिस के अन्तर्गत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो युद्ध-काल में युद्ध को चलाने और उस की समाप्ति के पश्चात् सफलता पूर्वक सैन्य-वियोजन में सहायक हों।
 - २. नौ, स्थल और विमान बल; संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल।
- ३. कटक-क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तशासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राविकारियों का गठन और शक्तियां, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह-वासन का विनियमन (जिस के अन्तर्गत किराये का नियन्त्रण भी है)।
 - ४. नौ, स्थल और विमान-बल की कर्मशालायें।
 - ५. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, युद्धोपकरण और विस्फोटक।
 - ६. अणुशक्ति तथा उस के उत्पादन के लिथे आवश्यक खनिज सम्पत्।
- ७. संसद्-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा युद्ध चलाने के लिये आवश्यक घोषित किये गये उद्योग।
 - ८. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग।
- ९. भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवारक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति।
- १०. विदेशीय कार्य; सब विषय जिन के द्वारा संघ का किसी विदेश ' से सम्बन्ध होता है।
 - ११. राजनियक, वाणिज्य-दूतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व।
 - १२. संयुक्त राष्ट्र-संघटन।

सप्तम अनुसूची

- १३. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्याओं और अन्य निकायों में भाग लेना तथा उन में किये गये विनिश्चयों की अभिपूर्ति।
- १४. विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गईं संधियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति।
 - १५. युद्ध और शान्ति।
 - १६. विदेशीय क्षेत्राधिकार।
 - १७. नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्यदेशीय।
 - १८. प्रत्यर्पण ।
- १९. भारत में प्रवेश और उस में से उत्प्रवासन और निर्वासन; पार-पत्र और दृष्टांक।
 - २०. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं।
- २१. महा-समुद्र या वायु में की गई जलदस्युता और अपराधः; स्थल या महासमुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराधः

२२. रेल।

- २३. राज-पथ जिन्हें संसद्-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्य-पथ घोषित किया गया है।
- २४. यंत्र-चाल्ति जलयानों के विषय में ऐसे अन्तर्देशीय जल-पथों में नौ-वहन और नौ-परिवहन जो संसद्-निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जल-पथ घोषित किये गये हैं; तथा ऐसे जल-पथों के पथ नियम।
- २५. समृद्र-नौवहन और नौ-परिवहन जिस के अन्तर्गत ज्वार-जल नौवहन और नौ-परिवहन भी है; विणक्-पोतीय शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।
- २६. प्रकाशस्तम्म, जिन के अन्तर्गत प्रकाशगीत, आकाशदीप तथा नौवहन और विमानों की सुरक्षितता के लिये अन्य उपबन्ध भी है।

ंसप्तम अनुसूची

- ात्रिश्वः व पत्तन जिन को संसद्-िनिर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिस के अन्तर्गत उन का परिसीमन तथा उन में पत्तन-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां भी हैं।
- २८. पत्तन-निरोधा, जिस के अन्तर्गत उस से सम्बद्ध चिकित्सालय भी है; नाविक और समुद्रीय चिकित्सालय।
- २९. वायु-पथ; विमान और विमान-परिवहन, विमान-क्षेत्र के उपबन्ध; विमान-यातायात और विमान-क्षेत्रों का विनियमन और संघटन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा न्दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।
- ३०. रेल-पथ, समुद्र या वायु से अथवा यंत्रचालित यानों में राष्ट्रीय जल-पथों से यात्रियों और वस्तुओं का वहन ।
 - ३१. डाक और तार; दूरभाष, बेतार, प्रसारण और अन्य समरूप संचार।
- ३२. संघ की सम्पत्ति और उस से उत्थित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूची के भाग (क) या (ख) में उत्लिखित किसी राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के विषय में, जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए।
 - ३३ संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण।
 - ३४. देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण।
 - ३५. संघ का लोक-ऋण।
 - ३६ चलार्थ, टंकण और विधिमान्य; विदेशीय विनिमय।
 - ३७, विदेशीय ऋण।
 - ३८. भारत का रक्षित बैंक।
 - ३९ं. डाकघर बचत बैंक।
 - ४०. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित लाटरी।

सप्तम अनुसूची

४१. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; शुल्क-सीमान्तों की पार करने वाले आयात और निर्यात; शुल्क सीमान्तों की परिभाषा।

४२. अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।

४३. व्यापारिक निगमों का, जिन के अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय निगम भी हैं किन्तु सहकारी संस्थाएं नहीं हैं, निगमन, विनियमन और समापन।

४४. विश्वविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापारिक हों या नहीं, जिन के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन अोर समापन।

४५. महाजनी।

४६. विनिमय-पत्र, चेक, वचन-पत्र तथा ऐसी अन्य लिखतें।

४७. बोमा।

४८. श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार ।

४९. एकस्व; आविष्कार और रूपांकन; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार-चिन्ह और पण्य चिन्ह ।

५०. बाटों और मापों का मान स्थापन।

५१. भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन।

५२. वे उद्योग जिन के लिये संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोक-हित के लिये उन पर संघ का नियंत्रण इष्टकर है।

५३. तैल-क्षेत्रों और खनिज तैल सम्पत् का विनियमन और विकास; पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद; संसद् से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालाग्रही घोषित अन्य तरल और द्रव्य।

५४. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा छोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे।

सप्तम अनुसूची

- ५५. श्रम का विनियमन तथा खानों और तैल-क्षेत्रों में सुरक्षितता।
- ५६. उस सीमा तक अन्तर्राज्यिक निदयों और नदी-दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे।
 - ५७. जलप्रांगण से परे मछली पकडना और मीन -क्षेत्र ।
- ५८. संघ-अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, सम्भरण और वितरण का विनियमन और नियंत्रण।
 - ५९. अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिये विकय।
 - ६०. प्रदर्शन के लिये चल-चित्रों की मंजूरी।
 - ६१. संघ के नौकरों से संपृत्त औद्योगिक विवाद।
- ६२. इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, साम्राज्यिक युद्ध-संग्रहालय, विक्टोरिया-स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित ऐसी कोई अन्य तद्रप संस्था।
- ६३. इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित कोई अन्य संस्था।
- ६४. भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था घोषित वैज्ञानिक या शिल्पिक शिक्षा-संस्थाएं।
 - ६५. संघ-अभिकरण और संस्थाएं जो---
 - (क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिरिप-प्रशिक्षण, जिन के अन्तर्गत आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है, के लिये हैं; अथवा

भारत का संविधान

सप्तम अनुसूची

- · (ख) विशेष अध्ययनों या गनेषणा की उन्नति के लिय हैं; अथवा
 - (ग) अगराध के अनुपत्धान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पिक सहायता के लिये है।
- ६६. उन्चतर शिक्षा या गत्रेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और शिल्पिक-संस्थाओं में एकस्त्रता लाना और मानों का निर्धारण !
- ६७ संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेब तथा पुरातत्वीय स्थान और अवग्रेष
- ६८. भारतीय भूगरिमाप, भूतत्वीय, वानस्पतिक, नरतत्वीय, प्राणकीय परिमाप ; अन्तरिक्ष-शास्त्रीय संस्थाएं।

६९. जनगणना ।

- ७०. संव-लोकसेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संव-लोकसेवा-आयीग।
- ७१. संब-निवृत्ति-वेतन, अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संवित निधि में से दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन।
- ७२. संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन ; निर्वाचन-आयोग ।
- ७३. संसद् के सदस्यों, राज्य-परिषद् के सभा। ति और उपसभापति .तथा लोक-सभा के अव्यक्ष और उपाव्यक्ष के वेतन और भते।
- ७४. संसद् के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और सिमितियों की शिक्तयां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां; संसद् की सिमितियों अथवा संसद् द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थित बाध्य करना।
- ७५ राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विश्वषाधिकार तथा अनुपस्थिति-छुट्टी के बारे में अधिकार ; संघ के मंत्रियों के वेतन और .मंत्ते; नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति-छुट्टी के !बारे में अधिकार तथां अन्य सेवा-शर्ते ।

भारत का संविधान

सप्तम अनुसूची

७६ संघ के और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

- ७७ उच्चतमन्यायालय का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार और शिवतयां (जिस के अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान भी है) तथा उस में ली जाने वाली फीसें; उच्चतमन्याय।लय के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक्क रखने वाले व्यक्ति।
- ७८ उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और भृत्यों के बारे के उपवन्धों को छोड़ कर उच्चन्यायालयों का गठन और संघटन ; उच्चन्यायालयों के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक्क रखने वाले व्यक्ति ।
- ७९ किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र मे विस्तार तथा ऐसे किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अपवर्जन ।
- ८० किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शवितयां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र में विना उस राज्य की सरकार की सम्मित के जिस में कि ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियां और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके; किसो राज्य की आरक्षी बल के सदस्यों की शवितयां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर रेल-क्षेत्रों पर विस्तार।
 - ८१ अन्तर्राज्यीय प्रव्रजन ; अन्तर्राज्यीय निरोवा ।
 - ८२ किष आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर।
 - ८३ सीमा-शूरक जिस के अन्तर्गत निर्यात-शुरक भी है।
 - ८४ भारत में निर्मित या उत्पादित तमाकू तथा-
 - (क) मानव उपभोग के मद्य सारिक पानों ;
 - (ख) अफीम, भांग और अन्य पिनक लाने वाली ओषिघयों तथा स्वापकों,

को छोड़कर, किन्तु ऐसी औषघीय और प्रसाघनीय सामग्री को अन्तर्भत कर क कि जिन में मद्यसार अथवा उक्त प्रविष्टि की उपकंडिका(स्व) में का कोई पदार्थ अर्न्तावष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क।

सप्तम अनुसूची

८५ निगम-कर।

- ८६: व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से कृषि-भूमि को छोड़ कर उस क -मूलधन-मूल्य पर कर ; समवायों के मूल-धन पर कर ।
 - ८७. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क।
- ८८. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क।
- ८९. रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर, रेल के जन-भाड़े और वस्तु-भाड़े पर कर।
- ९०. मुद्रांक-शुल्क को छोड़ कर श्रेष्टि-चत्वर और वादा बाजार के सौदों पर कर ।
- ९१. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा-पत्रों, अंशों के हस्तान्तरण, ऋण-पत्रों, प्रति-पत्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने वाले मुद्रांक-शुल्क की दर।
- ९२. समाचार-पत्रों के ऋय या विऋय पर तथा उन में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर।
- ९३. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध।
- ९४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच, ''परिमाप और सांख्यकी।
 - १९५. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के विषयों में से किसी के सम्बन्य में क्षेत्राधिकार और शक्तियां; नावाधिकरण-ेक्षेत्राधिकार।
 - ९६. किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों को छोड़ कर इस सूची में। कें विषयों से किसी के बारे में फीस।

सप्तम अनुसूची

९७. सूची (२) या (३) में से किसी में अवर्णित किसी कर के सिहत उन सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय।

सूची २ -- राज्यसूची

- १. सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु असैनिक शक्ति की सहायता के लिये संघ के नौ, स्थल या विमान बलों या किन्हीं अन्य बलों के प्रयोग को अन्तर्गत न करते हुए ।
 - २. आरक्षी, जिस के अन्तर्गत रेलवे और ग्राम आरक्षी भी है।
- ३. न्याय-प्रशासन ; उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का गठन और संघठन ; उच्चन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक ; भाटक और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सब भ्यायालयों में ली जाने वाली फीसें।
- ४. कारागार, सुधारालय, वोरस्टल संस्थायें और तद्र्प अन्य संस्थाएं और उन में निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रबन्ध ।
- ५. स्थानीय शासन अर्थात् नगर-निगम, सुग्रार-प्रन्यास, जिला-मंडलों, खनिज-विसिति प्राधिकारियों तथा स्थानीय रवशासन या ग्राम्य प्रशासन के प्रयोजन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां।
 - ६. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; चिकित्सालय और औषधात्य।
- ७ भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थ यात्राएं।
- दः मादक पानों अर्थात् मादक पानों का उत्सादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, ऋय और विऋय ।
 - ९. अंगहीनों और नौकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता।
 - १० शव गाड़ना और कबरस्थान; शव दाह और इम्शान।
- ११ सूची १ की प्रविष्टि हों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिस के अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं।

भारत का संविधान

सप्तम अनुसूची

- १२. राज्य से नियंत्रित या वित्त-पोषितं पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य समतुल्य संस्थाएं, संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक स्मार्रक और अभिलेख।
- १३. संचार अर्थात् सड़कों, पुल, नौका घाट तथा सूची १ में अनुह्लिखित संचार के अन्य साधन ; ट्राम-पथ ; रज्जुपथ ; अन्तर्देशीय जल-पथ और उन पर यातायात, वैसे जल-पथों के विषय में सूची १ और सूची ३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए; यंत्र-चालित यानों को छोड़ कर अन्य यान।
- १४. कृषि, जिस के अन्तर्गत कृषि-शिक्षा और गवेषणा, मरकों से रक्षा तथा उद्भिद् रोगों का निवारण भी है।
- १५. पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नित तथा पशुओं के रोगों का निवारण ; शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसाय।
- १६. पश्वरोध और पशुओं के अनिचार का निवारण।
- १७. सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल, अर्थात् जल-सम्भरण, सिंचाई और नहरें, जल निस्सारण और बंध, जल-संग्रह और जल-शक्ति।
- १८. भूमि, अर्थात् भूमि में या पर अधिकार, भृवृति जिस के अन्तर्गत भूस्वामी और किसानों का सम्बन्ध भी है, तथा भाटक का संग्रहण; कृषि-भूमि का हस्तांतरण और अन्य संक्रामण; भूमि-सुधार्भ और कृषि सम्बन्धी उधार; उपनिवेषण।
 - १९. वन ।
 - २०. वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा।
 - २१ मीन-क्षेत्र।

भागातिक हा एक सप्तम अनुसूची

- २३ संघ के नियंत्रणाधीन विनियमन और विकास के सम्बन्ध में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खानों का विनियमन और खनिजों का विकास।
 - २४. सूची १ की प्रविष्टि ६४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग ।
 - २५. गैस, गैस-कर्मशालाएं।
 - २६. सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य क अन्दर व्यापार और वाणिज्य।
 - २७ सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वस्तुओं का उत्पादन, सम्भरण और वितरण।
 - २८ बाजार और मेले।
 - २९. मान स्थापन को छोड़ कर बाट और माप।
 - ३०. साहूकारी और साहूकार ; कृषिऋणिता का उद्धार ।
 - ३१. पान्थशाला और पान्थशालापाल।
- ३२ सूची १ में उल्लिखित निगमों से भिन्न निगमों का और विङ्व-विद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन ; व्यापारिक, साहि-त्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य अनिगमित समाजें और सन्यायें; सहकारी समाजें।
- ३३. नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए चल-चित्र, क्रीड़ा, प्रमोद और विनोद।
 - ३४. पण लगाना और जुआ।
- ३५. राज्य में निहित या उस के स्ववश में की कर्मशालाएं, भूमि और भवन।
- ३६. सूची ३ की प्रविष्टि ४२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मं के प्रयोजनों के अतिरिक्त सम्पति का अर्जन या अधिग्रहण।

- ३७. संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन ।
- ३८. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद् हैं तो, उस के सभापति और उपसभा-पित के वेतन और भत्ते।
- ३९. विधान-सभा और उस के सदस्यों और सिमितियों की तथा, यदि विधान-परिषद् हो तो, उस परिषद् और उस के सदस्यों और सिमितियों की शिक्तयां, विशेषाधिकार और उन्मुवितयां, राज्य के विधान-मंडल की सिमितियों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यवितयों की उपस्थिति बाध्य करना।
 - ४०. राज्य के मन्त्रियों के वेतन और भत्ते ।
 - ४१. राज्य-लोक सेवाएं, राज्य-लोकसेवा-आयोग।
- ४२. राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात् राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि में से देय निवृत्ति-वेतन।
 - ४३. राज्य का लोक-ऋण।
 - ४४. निखात निधि।
- ४५. भूराजस्व जिस के अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेखों का बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिये और स्वत्व-अभिलेखों के लिये परिमाप और राजस्व का अन्य-संक्रामण भी है।
 - ४६. कृषि-आय पर कर।
 - ४७. कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क
 - ४८. कृषि-भूमि के विषय में सम्पत्ति-शुल्क।
 - ४९ भूमि और भवनों पर कर।
- ५० संसद् से, विधि द्वारा, खनिज-विकास के सम्बन्ध में लगाई गई परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकार पर कर।

- ५१. राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर से प्रतिशुल्क—
 - (क) मानव उपभोग् के लिथे मद्यसारिक पान ;
 - (ख) अफीम, भांग, और अन्य पिनक लाने वाली औषियां और स्वापक किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ कर जिन में मद्यसार अथवा इस प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तिविष्ट हो।
- ्र किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लियें नस्तुओं के प्रवेश पर कर।
 - ५३ विद्युत के उपभोग या विऋय पर कर।
- ५४. समाचार-पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के ऋय या विऋय पर कर।
- ५५. समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़ कर अन्य विज्ञापनों पर कर।
- ५६. सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर कर।
- ५७ सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यंत्रचालित हों या न हों तथा जिन में सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन ट्रामगाड़ियां भी अन्तर्गत हैं, कर।
 - ५८. पशुओं शीर नौकाओं पर कर।
 - ५९ पथ-कर।
 - ६०. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर।
 - ५१. प्रतिव्यक्ति-कर।

- ६२. विलास वस्तुओं पर कर, जिन के अन्तर्गत आमोंद, विनोद, पण लगाने और जुआ खेलने पर भी कर हैं।
- ६३. मुद्रांक-शुल्क की दरों के सम्बन्ध में सूची (१) के उपबन्धों में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़ कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क की दर।
- ६४. इस सूची में के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध।
- ६५. इस सूची के विश्यों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शवित्रज्ञां।
- ६६. किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्कों को छोड़ कर इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में शुल्क।

सची ३ -- समवीं स्ती

- १. दंड-विधि जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत दंड-संहिता के अन्तर्गत हैं किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विषयों के विरुद्ध अपराधों को छोड़ कर तथा अअसैनिक शक्ति की सहायतार्थ नौ, स्थल और विमान बलों के प्रयोग को छोड़ कर।
- २. दंड-प्रिक्तया जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के **प्रारम्भ प**्दंड-प्रिक्तया-संहिता के अन्तर्गत हैं।
- ३. राज्य की सुरक्षा से, सार्वजिनक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने से संसक्त कारणों के लिये निवारक निरोध; ऐसे निरुद्ध व्यक्ति।
- ४. कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा इस सूची की प्रविष्टि ३ में उल्लिखित कारणों से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक राज्य नसे दूसरे राज्य को हटाया जाना।

भारत का संविधान

- ५. विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अवयस्क; दत्तक-ग्रहण; इच् आपत्र, इच्छापत्रहीनत्व और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन; वे सब विषय जिन के सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पिहले अपनी स्वीय विधि के अधीन ये।
- ६. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरण; विलेखों और दश्तावेजों का पंजीयन।
- ७. संविदा जिन के अन्तर्गत भागिता, अभिकरण, परिवहन-संविदा और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं भी हैं किन्तु कृषि-भूमि सम्बन्धी संविदाएं नहीं हैं।
 - ८ अभियोज्य दोष।
 - ९ दिवाला और शोधाक्षमता।
 - १०. न्यास और न्यासी।
 - ११. महाप्रशासक और राजन्यासी।
- १२. साक्ष्य और शपथें; विधि, सार्वजिनिक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों का अभिज्ञान।
- १३. व्यवहार-प्रित्रया, जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर व्यवहार-प्रित्रया-संहिता के अन्तर्गत हैं, परिसीमायें और मध्यस्य-निर्णय।
- १४. न्यायालय-अवमान, किन्तु जिस के अन्तर्गत उच्चतमन्यायालय का अवमान नहीं है।
- १५. आहिण्डन, अस्थिरवासी और प्रवाजी आदिमजातियां।
- १६. उन्माद और मनोवैकल्य जिस के अन्तर्गत उन्मत्तों और मनोविकलों के रखने या उपचार के स्थान भी हैं।
- १७ पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण ।

- १८. खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अपिमश्रण।
- १९. अफीम विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५९ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए औषि और विष।
 - २०. आर्थिक और सामाजिक योजना।
 - २१. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, गुट्ट और न्यास।
 - २२. व्यापार-संघ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद।
 - २३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नौकरी और बेकारी।
- २४. श्रमिकों का कल्याण जिस के अन्तर्गत कार्य की शर्ते, भविष्य-निधि, नियोजक-उत्तरवादिता, कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निवृत्ति वेतन और प्रसूति सुविधाएं भी हैं।
 - २५. श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्षण।
 - २६. विधि-वृत्तियां, वैद्यक वृत्तियां और अन्य वृत्तियां।
- २७. भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण , अपने मूळ निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों की सहायता और भ्यनविस ।
 - २८. पूर्त और पूर्त-संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक धर्मस्व और धार्मिकं संस्थाएं।
- २९ मानवों पशुओं और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रामिक और सांसर्गिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फैलन का निवारण।
- ३०. जीवन सम्बन्धी सांख्यकी, जिस के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीयन भी है।
- ३१. संसद्-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन ।
- ३२. राष्ट्रीय जल-पथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों वे अधीन रहते हुए अन्तर्देशीय जल-पथों पर यंत्र-चालित यानों विषयक नौ-वहन

और नौ-परिवहन तथा ऐसे जल-पथों पर पथ-नियम, तथा अन्तर्देशीय जल-पथों पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन ।

३३. जहां संसद् से विधि द्वारा किन्हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण लोक-हित में इष्टकर घोषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापार और वाणिज्य तथा उन का उत्पादन, सम्भरण और वितरण।

३४. मूल्य-नियंत्रण।

३५. यंत्र-चालित यान जिन के अन्तर्गत वे सिद्धान्त भी हैं जिन के अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है।

३६. कारखाने।

३७. वाष्पयंत्र।

। ३८. विद्युत ।

्३९. समाचार-पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय .

पुरातत्त्व सम्बन्धी स्थान और अवशंष।

। ४०. संसद् से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित से भिन्न

- ४१. विधि द्वारा निष्काम्य घोषित सम्पत्ति की कृषि भूमि सहित अभिरक्षा, प्रबंग और व्ययन।
- ४२. संघ के या राज्य के या किसी अन्य सार्वजिनक प्रयोजन के लिये अर्जित या अधिगृहीत सम्पत्ति के लिये प्रतिकर निर्घारण करने के सिद्धान्त तथा वैसे प्रतिकर के दिये जाने का रूप और रीति।
- ४३. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य सा जिनक अभियाचनाओं की, जिस के अन्तर्गत भूराजस्व बकाया और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली।
- प्रेर. न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों को छोड़ कर अन्य मुद्रांक-शुल्क, किन्तु इस के अन्तर्गत मुद्रांक-शुल्क की दरें नहीं हैं।

४५. सूची २ या सूची ३ में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच और सांख्यकी।

४६. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के अयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां।

४७. इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इन के अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं।

अष्टम अनुसूची

[अनुच्छेद ३४४ (१) और ३५१]

३ विस

- **१.** अस् निया
- २. उड़िया
- ३. उर्दू
- ४. कन्नड
- ५. कश्मीरी
- ६ गुजराती
- ७. तामिल
- ८ तेलुगु
- ९. पंजाबी
- ् १०. बंगला
 - ११. मराठी
 - १२ मलयालम
 - १३. संस्कृत
 - १४. हिन्दी

भारत के संविधान

का

पारिभाषिक-शब्दावित-कोष

भारत की संविधान-सभा के अध्यक् द्वारा निमंदित अखिल-भारत-भाषा-विशेषइ-सम्मेलन द्वारा खीकुत

LIST OF THE MEMBERS OF THE LANGUAGE CONFERENCE

1. The Honourable Shri G.S. Gupta-Chairman.

	1. The Honourable	Snri G.S. Gupta—Unairman.
	 Shri Tirathnath Sharma. Dr. B.K. Barua. 	Assamese.
	 Shri Patanjali Bhattacharyya. Shri Chapala Kant Bhattachary 	ya. } Bengali.
	6. Shri Kikubhai Desai. 7. Shri Muni Jina Vijai Ji.	}. Gujarati.
•	8. Shri Gopal Chandra Sinha. 9. Dr. Raghuvira, M.C.A. 10. Shri Lakshmi Narayan Sudhan 11. Shri Yadunandan Bharadwaj. 12. Shri Ram Chandra Varma.	su. Hindi.
	13. Shri Kaka Sahib Kalelkar.	Kanada, Marathi & Gujarati.
	14. Shri T.N. Shrikanthiah.15. The Honourable Shri R.R. Diw	akar. } Kanada.
	16. Prof. Jia Lal Kaul. 17. Shri Mirza Arif.	} Kashmiri.
	 Shri Achyutha Menon. Shri Godeverma. 	Malayalam.
	20. Shri S.N. Banhatti.21. Dr. M.G. Deshmukh.	} Marathi.
	22. Prof. Artaballabh Mahanty. 23. Sjt. Chintamani Acharya.	} Oriya.
,	24. Principal Teja Singh. 25. Gyani Gurmukh Singh Musafir, l	I.C.A. Punjabi.
	26. Shri K. Balasubrahmanya Iyer27. Dr. Kunhan Raja.28. Mahamahopadhyaya Giridhar Si	
	29. Dr. Mangal Deva Sastri.30. Dr. Babu Ram Saxena.	
	31. Shri. L.K. Bharathi, M.C.A.32. Shri Sethu Pillai.	} Tamil.
	33. Shri Lakshmi Narayana Rao.34. Shri Ramanujam.	} Telugu.
	35. Qazi Abdul Ghaffar. 36. Prof. Abdul Qadir Sarwari.	} Urdu.
	 Shri M. Satyanarayana, M.C.A. Shri Jaichandra Vidyalankar. Shri Rahul Sankrityayan. Shri Y.R. Date. Dr. Suniti Kumar Chatterji. 	Expert Translation Committee.

NOTE ON ROMAN TRANSLITERATION

- 1. All FATS have been denoted by short vowels.
- 2. (a) All nasals except at the end of the word have been represented by m.
 - (b) At the end of the word nasal has been represented by n.
- 3. विसर्जनीय has been represented by h.
- 4. टबर्ग and तवर्ग have been represented in the same way, that is, by t, th, d, dh and n respectively.
- 5. (a) \approx has been represented by r,
 - (b) pprox has been represented by ksh,
 - (c) \exists has been represented by c
 - (d) s has been represented by ch,
 - (e) π has been represented by jn,
 - (f) $\bar{\epsilon}$ has been represented by r,
 - (g) श and स have been represented by s, and
 - (h) a has been represented by sh.

CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA

Equivalents for Terms used in the Constitution of India

English Terms with Equivalents in Devanagari Characters	Equivalents in Roman Characters	Alternatives Accepted
1	2	3
. A		
Abandonment.—परित्यजन,	Parityajana	पिस्याग, Parityaga
Abridge.—न्यूनन	Nyunana	
Abrogate.—निराकरण	Nirakarana	
Access.—प्रवेश	Pravesa	
Account.—लेखा	Lekha	१, गणना, Ganana २. कणकु, Kanaku
Accrue.—प्रापण	Prapana	प्रोद्भवन, Prodbhav ana
Accrued.—प्राप्त	Prapta	१ प्रोद्भूत, Prodbhuta उपार्जित, Uparjita
Accusation.—अभियोग	Abhiyega	, 1
Accused.—अभियुक्त	Abhiyukta	
Acquisition.—अर्जन	Arjana	
Act (n.)-—अधिनियम	Adhiniyama	चट्टम, Cattama
Acting (e.g. Chairman).— का iकारी	Karyakari	
Actionable wrong.— अभियोज्य दोष	Abhiyojya dosha	
Adaptation.—अन्कलन	Anukulana	
Addressed.—सम्बोधित	Sambodhita	
Adherence.—अनुषक्ति •	Anushakti	
Ad hoc तदर्थ	Tadartha	
Adjourn.— १ स्थगन	1 Sthagana	१ अभिदान, Avadhi-
२ स्थगित करना	2 Sthagita	dana
	karana	२ कालदान, Kaladarı

. 1	2	3
Administer.— प्रशासन	Prasasana	
${f Administered.}$ —प्रशासित	Prasasita	
Administration.—प्रशासन	Prasasana	
Administrative.— प्रशासनीय	Prasasaniya	
Administrative functions.— प्रशा- सनीय कृत्य	Prasasaniya krtya	
Administrator- General.—महा-	Maha-	•
प्रशासक	prasasaka	
Admiralty.—नौकाधिकरण	$egin{aligned} Naukadhi-\ karana \end{aligned}$	नावधिकरण, $Nava$ - $dhikaran$
Admissible.—ग्राह्य	Grahya	
${ m Adoption.}$ —दत्तक-ग्रहण	$egin{aligned} Dattaka-\ grahana \end{aligned}$	दत्तक-स्वीकरण, $Dattaka$ -s $vikaran$
Adulteration.—अपिमश्रण	Apamisrana	
Adult suffrage.—वयस्क मताधिकार	Vayaska-mata- dhikara	
Advance.—अग्रिस धन	$Agrima\ dhana$	पेशगी, $Pesagi$
Advice.—मंत्रणा	Mantrana	∫ उपदेश, Upadesa सलाह, Salaha
Advise.—मंत्रणा देना	Mantrana dena	
Advisory Council.—मंत्रणा परिषद्	$egin{array}{c} Mantranu \ Parishad \end{array}$	
Advocate.—अधिवक्ता	Adhivakta	
Advocate-General.—महाधिवक्ता	Mahadhivakta	
Affect prejudicially.—प्रतिकूल प्रभाव डालना	Pratikula prabhava dalana	प्रतिकूल असर डालना, Pratikula asara dalana
Affirmation.—प्रतिज्ञान	Pratijnana	
Agency. — अभिकरण	Abhikarana	
Agent.—अभिकर्त्ता	Abhikartta	
Agreement.—करार	Karara	चुकती, Cukati
Air force.—विमान बल	Vimana bala	3 ,
Air navigation.—विमान परिवहन	Vimana pari- vahana	
Air traffic.—विमान यातायात	V imana yata- yata	

1 ·	2	3
Airways.—वायु पथ	Vayu patha	
Alien.—अन्यदेशीय	${m Anyadesiya}$	
Alienate—अन्य-संकामण	Anya- samkramana	
Alienation.—अन्य-संक्रामण	Anya-samkra- mana	परकीकरण, Paraki karana
f Allegation.—अभिकयन	Abhikathana	आरोप, $Aropa$
Allegiance.—নিষ্ঠা	Nishtha	
Allocation.—बटवारा	Batavara	
f Allot.—वंटन	Vamtana	
Allotment.—बांट	Bamta	
Allowances.—भत्ता	Bhatta	
${f Amendment}$. $oxdot$ संशोधन	Sam sodhana	
Amnesty. —सर्वेक्षमा	Sarvakshama	
Amount.—राश्चि	Rasi	
Ancillary.—सहायक	Sahayaka	
Annua!, — ব, পিক	Varshika	
Annual Financial Statement.— वाषिक वित्त-विवरण	Varshika-vitta- vivarana	
Annuities.—वार्षिकी	Varshiki	
Annulment.—रह् करना	Radda karana	
Appeal.—अपील	Apila	
Appear.— उपस्थित होना	$\stackrel{-}{U}_{pasthita}$ hona	
Appended.—संलग्न	Samlagna	
Application.—१. प्रयुक्ति, २. लागू होना,	1. Prayukti,	
३. आवंदनपत्र	2. Lagu hona,	
Appointment.—नियुक्ति	3. Avedanapatra Niyukti	
Appropriation.—विनियोग	•	
Appropriation bill — विनियोग विभेयक	Viniyoga Viniyoga vidhe- yaka	
Approve.—अनुमोदन करना	Anumodana karana	
Approval.—अनुमोदन	Anumodana	

1	. 2	3
Arbitral tribunal.—मध्यस्थ-न्याया-	Madhyastha-	
विकरण	nyayadhikar	ana
Arbitration.—मघ्यस्थ -निर्णय	Madhyastha- nirnaya	
Arbitrator.—मध्यस्थ	Madhyastha	
Area.—क्षेत्र	Kshet ra	
Armed Forces.—सशस्त्र बल	Sasastra bala	
Arrest.—बन्दी करना	Bandi karana	त्रग्रहण, Pragrahana
Article.—अन्च्छेद	Anuccheda	and if I ragrantance
Assemble.— समवेत होना	Samaveta hona	सम्मिलित होना, Sam- milita hona
Assembly.—सभा	Sabha	
\mathbf{Assent} . $$ अनुमित	Anumati	
f Assessment.—निर्घारण	Nirdharana	तीर्व, $Tirva$
Assignment.—सौंपना	Saumpana	
Association.—सन्या	Samtha	
Assurance of property.—संपत्ति	Sampatti	
हस्तान्तरण-पत्र	hastantarana pattra	
As the case may be.—यथास्थिति	Yatha sthiti	यथाप्रसंग, Yathapra- samga
Attach.—कुर्की	Kurki	टांच, $Tamca$
Attorney-General.—महा-न्यायवादी	$Maha ext{-}nyaya ext{-} vadi$	
Audit.—लेखा-परीक्षा	$Lekha ext{-}pariksha$	गणना-परीक्षा, Gana- na-pariksha
Auditor-General.—महा-लेखा- परीक्षक	$Maha ext{-}Lekha ext{-} \ parikshaka$	1
Authentication.—प्रमाणीकरण	Pramani- karana	
Authorise.—সাधिकृत	Pradhikrta	
Authority.—प्राधिकारी	Pradhikari	
Autonomous.—स्वायत्त	Svayatta	
Autonomy.—स्वायत्तता	Svayattata	
Award.—पंचाट	Pamcata	
Rail	В	
Bail.—जामिन Bailot.—१. चलाका	Jamin	
्र श्रह्माका-पद्धति	1. Salaka, 2. Salakapaddh	गूढ़-पत्र, ati Gudha-patr

Elegot Finding Total C	- I	I I
1	2	3
Bank.—वेंक	Baimką	
Banking.—महाजनी	${\it Mahajani}$	
Bankruptey.—दिवाला	Divala	
Bar.—हकावट	Rukavata	
Benefit.—हित	Hita	
Betting.—पण लगाना, पणकिया	Pana lagana,	
	Panakriya	
Bi-cameral.—दोघरा	Doghara	द्विगृही, Dvigrhi
Bill.—विधेयक	\cdot $Vidheyaka$	ৰিল, $Bila$
Bill of exchange.—विनिमय-पत्र	Vinimaya-pat	ra
Bill of indemnity.—परिहार-विघेयक	Parihara- vidheyaka	क्षतिपूर्ति-बिल्ल, $Kshatipurtti-bila$
Bill of lading.—वहन-पत्र	$egin{aligned} Vahana-\ patra \end{aligned}$	
Board.—मंडली	Mandali	बोर्ड, Borda
Body.—निकाय	Nikaya	,
Body, corporate. – निगमनिकाय	$egin{aligned} Nigama- \ nikaya \end{aligned}$	
Body, governing.—शासीनिकाय	Sasinikaya	
Bona vacancia.— स्वामिहीनत्व	Svami- hinatva	
Borrowing.—उधार-ग्रहण	$Udhara-\ grahana$	
Boundary.—सीमा	Sima	
Broad casting.—प्रसारण	Prasarana	
Busir ess.—कारबार	Karabara	
Bye-clection.— जपनिवचिन	Upanirvacana	
Bye-law.—उपविधि	Upavidhi	
. <u>C</u>		
Calling.—आजीविका	Ajivika	
Camp.—शिविर	Sivira	
Candidates. अभ्यर्थी	Abhyarthi	उम्मेदवार Umme-
Cantonment. कटक	Vatalor	davara
	Kataka	छावनी, Chavani
Capacity.—सामर्थ्य	Samarthya	-1

1	2	3
Capital.—मूलधन	Muladhana	पूंजी, Pumji
Capital value.—मूलधन-मूल्य	Muladhana- mulya	
Capitation tax.—प्रतिव्यक्तिकर	Prativy akti-kara	
Carriage परिवहन	Parivahana	
Casting vote.—निर्णायक मत	Nirnayaka mata	<i>t</i>
Cattle pound.— पशु-अवरोध	Pasu- avarodha	कांजी हौस, $Kamji$ hausa
Cause.—वाद	Vada	
Cause of Action.—वाद-मूल	Vada- $mula$	•
Census.—जन-गणना	${\it Jana-ganana}$	
Certral Intelligence Bureau.— केन्द्रीय गुप्त वार्त्ता विभाग	Kendriya guptavartta- vibhaga	
Certificate.—प्रमाण-पत्र	Pramana-patra	
Certiorari.—उत्प्रेषण-लेख	Utprcshana- $lekha$	
Cess.—उपकर	Upakara	
Chairman.—सभापति	Sabhapati	•
Charge.—भार, भारित करना	Bhara, Bharita karana	
Charge (Cr.).—दोषारोप	Dosharopa	अभियुक्ति, Abhiyukti
Charity.—पूर्व	Purta	दातन्य, Datavya
Charitable and religious endowments.—पूर्त, धार्मिक धर्मस्व	Purta- dharmika dharmasva	, ,
Charitable institutions.—पूर्व- संस्था	Purta-Samstha	
Cheque.—चेक	Ceka	
Chief.—मुख्य	Mukhya	
Chief-Commissioner. —मुख्य आयुक्त	Mukhya • Ayukta	
Chief-Election-Commissioner.— मुख्य निर्वाचन आयुक्त	Mukhya Nirvacana Ayukta	
Chief-Indge. मुख्य न्यायाधीश	Mukhya Nyayadhisa	

1	2	3
Chief Justice.—मुख्य न्यायाधिपति	Mukhya Nyayadhipa	ti
Chief Minister.—मुख्यमंत्री	Mukhya- mantri	
${ m Citizenship.}$ —नागरिकता	Nagarikata	पौरत्व, Pauratva
Civil.—१. व्यवहार, २. असैनिक	 Vyavahara, Asainika 	
'Cıvil Court.—१. व्यवहार न्यायालय	1. Vyavahara Nyayalaya	दीवानी, Diwani व्यवहार अदालत,
२. व्यवहारालय	2. Vyavaharalay	$a egin{array}{c} Vyavahara \ Adalata \end{array}$
Civil power.—१. व्यवहार-शक्ति	1. Vyavahara- sakti	
२. असैनिक-शक्ति	2. Asainik-sakti	
·Civil wrong.—व्यवहार- विषयक अपकृत्य	Vyavahara- vishayaka apakrtya	व्यवहार-विषयक दोष, Vyavahara-visha yaka dosha
Claim.—दावा	$egin{aligned} Dava \end{aligned}$	9 411-44 4001144
Clarification.—स्पष्टीकरण	(Spashti- karana)	
Clause.—खण्ड	Khamda	•
Code.—संहिता	Samhita	
Coinage.—टकरा	Tamkana	
Colonization.—उपनिवेशन	Upanivesana	
Commerce.—वाणिज्य	Vanijya	
Commercial.—वाणिज्य-सम्बन्धी	Vanijya- sambandhi	
Commission.—आयोग	Ayoga	
Commissioner.—आयुक्त	Ayukta	
Committee.—समिति	Samiti	
Committee, Select.—प्रवर-समिति	Pravara-samiti	
Committee, Standing.—स्थायी समिति	Sthayi samiti	
Common goodसार्वजनिक कल्याण	Sarvajanika kalyana	
Common Sealसामान्य मुद्रा	Samanya स mudra	ामान्य मुहर, Samanya muhara
Communicate.—संचार करना	Samcara- karana	
		•

1	2	3
Communication, means of.— संचार साधन	Samcara- sadhana	
Community.—१. लोक समाज २. समुदाय	Loka-samaja, Samudaya	
Commute.—लघकरण	Laghukarana	
Company.—समनाय	Samavaya	कम्पनी, $Kampan$
Compensation.—प्रतिकर	Pratikara	
Competent.—सक्षम	Sakshama	क्षमताशील, $Kshamatasila$
Complaint.—फरियाद	Fariyada	
Comptroller and Auditor Ge- neral.—नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक	Niyantraka- Maha-lekha- parikshaka	
Compute.—प्रंगणना	Samganana	
Concurrence.—सहमति	Sahamati	
Concurrent List.—समवर्ती सृची	Samavarii Suci	
${f Condition.}$ —शर्त	Sarta	
Conditions of service.—सेवा की शर्त	Seva ki sarter	ı
Conference.—सम्मेलन	Sammelana	
Confidence, want of.—विन्वास का अभाव	Visvasa ka abhava	
Conscience.—अन्तःकरण	Antahkarana	
$\mathbf{Consent.}$ $-$ सम्मित	Sammati	
Consent, previous.—पूर्व सम्मति	Purva samma	$tm{i}$
Consequential.—आनुषंगिक	Anushamgika	
Consideration.—विचार	Vicara	
Consolidated Fund.—संचित निधि	Samcita Nidi	hi
Constituency.—निर्वाचन-क्षेत्र	Nirvacana- kshetra	
Constituency, territorial.—प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र	Pradeshika	
Constituent Assembly.— संविधान- सभा	Samvidhana-	
'Constitution.—संविधान	Sabha Samvidhana	

1	2	3
	Vanijya-duta	
Consultation.—परामर्श	Paramarsa	
Construe.—अर्थ करना	Artha karana	
Consumption. —उपभोग	Upabhoga	
Contact.—संपर्क	Samparka	
Contagious.—सांसर्गिक	$\widehat{Samsargika}$	
Contempt.—अवमान	Avamana	
Contempt of court.— न्यायालय- अवमान	Nyayalaya- avamana	
Context.— संदर्भ	Sam darbha	प्रसंग, Prasamga
Contingency Fund.—आकस्मिकता- निधि	$A kasmikata- \ nidhi$	
Contract.—संविदा	Samvida	
Contravention,—प्रतिक्लता	Pratikulta	उल्लंघन, $Ullamghana$
Contribution.—ग्रंशदान	${\it Amsadana}$	
Control.—नियंत्रए	Niyamtrana	
Controversy.—प्रतिवाद	Prativada	
Convention.—अभिसमय	Abhisamaya	
Conveyance.—हस्तान्तरपत्र	Hastantara- $patra$	
Convicted.—सिंह -दोष	$Siddha ext{-}dosh$	्रदोषप्रमाणित, Dosh { pramanita
Conviction.—दोषसिद्धि	Doshasiddhi	अभिशस्त, Abhisas
Cooperative society.—सहकारी संस्था	Sahakari Samstha	समवाय संस्था, Samo
Copy.—प्रतिलिपि •	$Pra^{\imath}ilipi$	प्रतिकृति, Pratikrti
Copyright.—प्रतिलिप्यधिकार	$Pratilipy a-\ dhikara$	कृतिस्वाम्य, $Kr\!ii$ - $svamya$
Corporation.—निगम	Nigama .	
Corporation, Sole.—एकल निगम	$\it Ekala\ nigama$	
Corporation, tax.—निगम-कर	$Nigama ext{-}kara$	
Corresponding.—तत्स्थानी	Tatsthani	
Corrupt.—भ्रन्ट	Bhrashta	
Cost.—गरिव्यय	Parivyaya	खर्च, <i>Kharca</i> लागत, <i>Lagata</i>
Council.—परिषद्	Parishad	

1	2	3
Council of Ministers – मंत्रि-परिषद्	Mantri- parishad	
Council of States.—राज्य परिषद्	Rajya- parishad	
Council, Regional.— ।देशिक-परिषद्	Pradesika- parishad	•
Council, Tribal.—जनजाति-परिषद्	Janajati- parishad	
Countervailing duty प्रति-शुल्क	$ar{Prati-sulka}$	
Court.—न्यायालय	Nyayalaya	
Court of Appeal.— पुनर्विचार- न्यायालय	Punarvicara- nyayalaya	अपील-न्यायालय, Api - la - $nyayalaya$
Court, Civil.— व्यवहार-न्यायालय	Vyavahara- nyayalaya	
Court, Criminal.—दंड-न्यायालय	Danda- nyayalaya	
Court, District.— जिला-न्यायालय	Jila-nyayalaya	मंडल-न्यायालय, Man- dala-nyayalaya
Court, Federal.— फेंडरल-न्यायालय	Fedaral- nyayalaya	aww-ngagwa gu
Court, High.— उच्चन्यायालय	$Uccanyayalaya \$,
Court, Magistrate.— दंडाधिकारी- न्यायालय	Dandadhikari- nyayalaya	
Court Martial.—सेना-न्यायालय	Sena-nyayalaya	1
Court of wards.—प्रतिपालक-अधिकरण	$Pratipalaka-\ adhikarana$	
Court, Revenue.—राजस्व-न्यायालय	Rajasva- nyayalaya	
Court, Session.— सत्तृ-न्यायालय	Sattra- nyayalaya	
Court, subordinate.—अधीन_न्यायालय	Adhina nyayalaya	
Court, Supreme.—उच्चतम-न्यायालय	Uccatama- nyayalaya	•
Credit.—प्रत्यय	Pratyaya,	\int साल , $Sakha$ ्रित , $Pata$
Credit.—आकलन	Akalana	1119 2 00000
Orime.—अपराघ	A $puradha$	

1	2	3
Criminal.—१. अपराधी, २. आपराधिक	Aparadhi, Aparadhika	दंड सम्बन्धी, Danda sambandh
Criminal law.—दंड-विधि	$\overset{ extbf{-}}{Danda-vidhi}$	
Currency.—चल अर्थ	Cala artha	चलावणी, Calavani
Custody.—अभिरक्षा	$\it Abhiraksha$	\int निरोध, $Nircdha$ े कावल, $Kavala$
Custom duty.—बहि:-शुल्क	Bahih-sulka	सीमा-शुल्क,
'Custom, frontier.— शुल्क-सीमान्त	Sulka-simanta	Sima-sulka
Custom.—हिं	Rudhi	आचार, $A cara$
	D	~
Dealings.—ब्यवहार	Vyavahara	लेना देना, Lena dena
Debate.—वाद-विवाद	Vada- $vivada$	
Debentures.—ऋण-पत्र	Rna-patra	
Debit.—विकलन	Vikalana	
Debt.—ऋण	Rna	
Decision.—विनिश्चय	Viniscaya	
Declaration घोषणा	Goshana	
Decree.—आज्ञप्ति	Ajnapti	डिकी, $Dikri$
Dedicate.—समर्पण	Samarpana	
Deed.—विलेख	Vilekha	
Defamation.—मानहानि	Manahani	
Defence. —प्रतिरक्षा	Pratiraksha	
Deliberate. —पर्यालोचन	Paryalocana	
Delimitation.—परिसीमन	Parisimana	
Demand.—मांग	Mamga	अभियाचना, $Abhiyacana$
Demarcation.—सीमांकन	Simamkana	•
Demobilisation.—सैन्य वियोजन	Sainya-viyojan	a
Deprived.—वंचित करना	Vamcita karana	वियुक्त करना, Viyu- kta karana
Deputy Chairman.—उपसभापति	Up a sabhapati	
Deputy Commissioner.—उपायुक्त	$_{arphi}Upayukta$	मण्डलायुक्त, Mandalayukta

1		3
Deputy President.—उपराष्ट्रपति	. U parashtra- pa ti	
Deputy Speaker.—उपाध्यक्ष	${m Upadhyaksha}$	
Descent.—उद्भव	$m{U}dbhava$	
Derogation.—अल्पीकरण	Alpikarana	
Design.—ह्रपांकण	Rupamkana	नक्ष, $Naksh$
Detrimental.—अहित कारी	Ahitakari	
Diplomacy. —राजनय	Rajanaya	
Direction.—निदेश	Nides a	
Disability.—निर्योग्यता	Niryogyata	
Discharge.—निर्वहन	Nirvahana	
Discipline.—अनुशासन	Anusasana	•
Disciplin vry.—अनुशासन सम्बन्धी	$Anusasana \ sambandhi$	शिस्त, Sista
Discovery.—प्रकट करना	Prakata karan	a
Discretion.—स्विविवेक	Svaviveka	
Discrimination.—विभेद	Vibheda	
Discussion.—चर्चा	Carca	
Dismiss.—पदच्युत करना	Padacyuta karana	
Disperse.—विसर्जन	Visarjana	
Dispute. —विवाद	Vivada	
Disqualification.—अनहंता	Anarhata	
Disqualify.—अनहींकरण	Anarhikarana	
Dissent.—विमति	Vimati	
Dissolution. —विघटन	Vighatana	
Distribution.—वितरण	Vitarana	विभाजन $, \ V_i bha jana$
District.—जिला	Jila	ਸਾਫ਼ਲ, Mandala
District Board. — जिला-मंडली	$oldsymbol{Jila-mandali}$	
District Council.—जिला-परिषद्	${oldsymbol{\it Jila-parishad}}$	
District Fund.—जिला निधि	Jilanidhi .	•

Labhamsa

1	2	3
Divorce.—विवाह-विच्छेद	Vivaha-viccheda	
Documents.— लेख्य	Lekhya	दस्तावेज, $Dastavejoldsymbol{a}$
Domicile.—अधिवास	Adhivasa	
Domiciled.—अधिवासी	Adhivasi	
Dulness.—मतिमान्द्य	Matimandya	
During good behaviour.— सदाचार पर्यन्त	Sadacara par- yanta	
_During the pleasure of the President.—राष्ट्रपति प्रसाद पर्यन्त	Rastrapati prasada par- yanta	
Duty १. श्ल्क,	1. Sulka,	वरी, $\dot{V}ari$
२. कर्तव्य	2. Kartavya	
Duty, custom.—सीमा-शुल्क	Sima- $sulka$	
Duty, death.—मरण-शुल्क	Marana-sulka	
Duty, estate.—सम्मत्ति -शुल्क	Sampatti-sulka	
Duty, excise.—उत्पादन-शुल्क	$Utpadana-\ sulka$	
Duty, export — निर्यात-शुल्क	Nirya!a-sul ka	
Duty, import.—आयात-शुल्क	$Ayata ext{-}sulka$	•
Duty, stamp मुद्रांक-शुल्क	$Mudramka-\ sulka$	
Duty, succession.—उत्तराधिकार-शुल्क	U ttaradhikara- sulka	
	E	
—————————————————————————————————————	Arthika	
Education.—शिक्षा	Siksha	•
Efficiency of administration.— प्रशासन-कार्यक्षमता	Prasasana- karyakshamata	प्रशासन कार्यपट्ता, 1 Prasasana- karyapatuta
Elect निर्वाचन (V.)	Nirvacana	
Elected — निर्वाचित	Nirvacita	चुने हुए, Cune hue
Election.—निर्वाचन	Nirvacana	
Election Commissioner.— निर्वाचन-आयुक्त	$Nirvacana-\ Ayukta$	•
Election, direct.—प्रत्यक्ष निर्वाचन	Pratyaksha nirvacana	

1	2.	3
Election, general.—साधारण निर्वाचन	Sadharana	
Election, indirect.—परोक्ष निर्वाचन	nirvacana Paroksha	:
Election tribunal.— निर्वाचन अधिकरण	nirvacana Nirvacana adhikarana	
Electoral roll.—निर्वाचक-नामावली	Nirva caka-	
Electoral rolls.—निर्वाचक-गण	na mavali Nirvacaka gana	
Eligibility.—पात्रता	Patrata	
Eligible.—पात्र होना	$Patra\ hona$	
Emergency.—आगात	Apata	
Emergent.—आपाती	Apati	
Emigration.—उत्प्रवास	Utpravasa	
Emoluments.—उपलब्धियां	Upalabdhiyan	
Employer's liability.— नियोजक-दातव्य	$Niyojaka-\ datavya$	नियोजक-उत्तरवादिता, $Niyojaka$ - $uttara$ -
Enact.—अधिनियम	Adhiniyama	vadita
Encumbered estate—भारप्रस्त- सम्पदा	Bharagrasta sampada	•
Endorse. — १. पृष्ठांकन, २. अंकन	1. Prshthankana 2. Amkana	
Endorsed.—१. पृष्ठांकित, २. अंकित	1. Prshthamkita, 2. Amkita	
Endowment.—धर्मस्व	Dharmasva	
Engagements.—वचन-बन्ध	Vacana-bandha	
Engineering.—यन्त्र-शास्त्र	$Yantra ext{-}sastra$	
Enterprise.—उद्यम	Udyama	•
Entitled.—हक्क होना	Hakka hona	
Entrust.—न्यस्त	Nyasta	सौंपना, Saumpana
Entry.—प्रविष्टि	Pravishti	दाखला. Dakhala
Equality.—समता	Samata	and and a contract
Equal Protection of Laws.— विधियों का समान संरक्षण	Vidhiyon ka samana sam rakshana	
Escheat.—राजगामी	Rajagami	•
Establishment.— १. स्थापना,	1. Sthapana,	संस्थापन,
२. स्थापन करना	2. Sthapana	Sams thap ana
Estates.—संपदा	karana Sampada	

. 1	2	3
Estimates.—आंक Evidence.—साध्य	Amka Sakshya	प्राक्कलन Prakkaland
Excess profit अतिरिक्त लाभ	Atirikta labha	
Exclude—अपवर्जन करना	Apavarjana , karana	
Exclusion. •अपवर्जन	A pavarjana	
Exclusive jurisdiction.—अनन्य क्षेत्राधिकार	Ananya kshetradhikara	
Executive.—कार्यपालिका	Karyapalika	
Executive power.—कार्यपालिका-	K aryapalika- sakti	
Exempt.—मुक्त	Mukta	
Exercise.—प्रयोग	Prayoga	अनुष्ठान,
Ex officio.—पदेन	Padena	Anushthana
Expenditure.—व्यय	Vyaya	
Explanation.—व्याख्या	Vyakhya	स्पष्टीकरण, Spashtikarana
Explosives.—विस्फोटक	Visphotaka	•
Export.—निर्यात	Niryata	
$\mathbf{E}\mathbf{xtend.}$ —विस्तार	Vistara	
External Affairs.—वैदेशिक कार्य	Vaidesika Karya	•
Extradition.—-प्रत्यर्पण	Pratyarpana	राज्यक्षेत्रातीत वर्त्तन,
Extra territorial operations.— राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्त्तन	Rajyakshetra- titapravart- ana	Rajya kshetrati- ta vartana
F		
Factory.—कारखाना	Karakhana	
Faith.—धर्म	Dharma	প্রৱা, Sraddha
Fare.—भाड़ा	Bhara	किराया, Kiraya
Federal Court.—फेडरल न्यायालय	Fedaral nyaya- laya	,

1	2	3
Fees.—देय	Deya	फीस Fis
Finance.—वित्त	Vitta	
Finance bill.—वित्त-विधेयक	Vitta-vidheyaka	ļ
Finance Commission,—वित्तायोग	Vittayoga	•
Financial.— वितीय	Vittiya	
Financial obligation.—वित्तीय भार	Vittiya bhara	
Financial statement.—वित्तीय विवर्ण	$Vittiya \ vivarana$	
Fine.—अर्थ-दण्ह	Artha-danda	जुर्माना किया,
Fishery.—मीन-क्षेत्र	${\it Mina-kshetra}$	Jurmana Kiya मीन-पण्णै
Forbid.—निषेध	Nishedha	$Mina ext{-}pannai$
Forbiddenনিখিৱ	Nishiddha	
Forces.—बल	Bala	
Foreign Affairs.—विदेशीय कार्य	Videsiya Karya	
Foreign exchange.—विदेशीय विनिमय	V idesiya vinimaya	
Form.—१. €प	1. Rupa	फारम _ः
२. प्रपत्र	2. Prapatra	Farama
Formula.—- ধুন	Sutra	
Formulated.—सूत्रित	Sutrit	
For the time being.—तत्समय	Tatsamaya	
Freedom.—१. स्वतन्त्रता	1. Svatantrata	आज्।दी, A 2 adi
२. स्वातन्त्र्य	2. Svatantrya	-it-field Trefomb
Freights.—वस्तु भाड़ा	Vastu-bhara	•
Frontiers.—सीमान्त	Simanta	

EQUIVALENTS FOR C	ONDITIONAL	
.1	2	3
Function.—कृत्य Function, administrative— प्रशासनीय कृत्य	Krtya Prasasaniya kr	·tya
\mathbf{Fund} .—निघि	Nidhi	
Fund, sinking.—निक्षेप-निधि	Nikshepa- $nidhi$	
Future market.—वायदा बाजार	Vayada bazara	
G		
Gambling.—द्यूत	Dyuta	जुझा, Jua
Gazette.—सूचना-पत्र	Sucana-patra	गजट, Gajata
General Election.—साधारण निर्वाचन	Sadharana Nirvacana	
Govern.—शासन करना	Sasana karana	
Governance.—-शासन	Sasana	
Government.— १. सरकार २. शासन	 Sarakara, Sasana 	
Government of a State.—राज्य की सरकार	Rajya ki Sarakara	
${f Government}$ of ${f India.}$ —भारत सरकार	Bharata Sarakara	
Governor.—राज्यपाल	Rajyapala	
Grant.—अनुदान	Anudana	
Grant-in-aid.—सहायक अनुदान	Sahayaka anudana	
Gratuity.—उपदानै	Upadana	
Guarantee.—प्रत्याभृति	$Pratyabhu^ti$	
Guardian.—संरक्षक	Samrakshaka	
Guidance.—मार्ग-प्रदर्शन	Marga- pradarsana	

1	2	3
i	H	
Habeas Corpus.—बन्दी प्रत्यक्षीकरण	Bandi Praty kshikarana	a-
Handicrafts.—हस्तशिल्प Hazardous.—संकटमय	Hasta-silpa Samkatamaya	दस्तकारी Dastalami
Headman.—मुखिया	Mukhiya	•
High Court.—उच्चन्यायालय	Uccanyayalay	<i>ja</i>
Honorarium.—मानदेय	Manadeya	संभावना, Sam - $bhavana$
House.—सदन	Sadana	Orbai O Corpci
House of People.—लोक-सभा	$Loka ext{-}Sabha$	

I

Illegal.—अवैध	Avaidha	
Illegal Practice.—अवैधाचरण	Avaidha carana	
Immunity.—उन्मुक्ति	Unmukti	
Impeachment.—महाभियोग	Mahabhiyoga	
Implementing.—परिपालन	Paripalana	
Impose.—आरोपण	Aropana लगाना,	Lagana
Imprisonment.—कारावास	Karavasa कैद, K	aida
Improvement trust.—सुधार- प्रन्यास	Sudhara pranyasa	
Incapacity.—असमर्थता	$egin{aligned} A samarthata \end{aligned}$	
Incidental.— प्रासंगिक	Prasamgika	
Incompetency.—अक्षमता	Akshamata	
Incompetent. – अक्षम	Akshama	
Incorporation.—निगमन	Nigamana	
Incumbent of an office.—पदधारी	Padadhari	
Indebtedness.—ऋग प्रस्तता	Rnagrastata	
Industry.— उद्योग	Udyoga	
Ineligible.— अपात्र	Apatra	
Ineligibility.—अपात्रता	Apatrata	
Infants.—যিষ্	\bar{Sisu}	
Infectious.—स्रोकामिक	Samkramika	

1	2	3
Influence.—प्रभाव	Prabhava	
Influence undue,—अयुक्त प्रभाव	Ayukta prabhava	
Inheritance.—दाय	Daya	
Initiate.—उपक्रमण	Upakramana	•
Injury.—क्षति	Kshati	
Inland waterways.—अन्तर्देशीय जलपथ	Antardesiya jalapatha	
Inoperative.—अप्रवृत्त	Apravrtta	
Inquiry.—परिप्रश्न	Pariprasna	जांच, Jamca
${f Insolvency}$.— दिवाला	Divala	•
Inspection.—पर्यवेक्षरण	${\it Paryavekshana}$	
Institution.—संस्था	Samstha	
Instruction.—ং. যিলা	1. Siksha	C
२. अनुदेश	2. Anudesha	हिदायतें, Hidayalen
Instrument.—लिखत	Likhata	
Insurance.—बीमा	Bima	
Intercourse,—समागम	Samagama	वृद्धि, Vrddhi
Interest.—व्याज	Vyaja	सूद, Suda
International.—अन्तर्राष्ट्रीय	An tarrashtriya	
Interpretation.—निर्वचन	Nirvacana	
Intestacy—इच्छापत्रहीनत्व		निर्वसीयता, N <i>ir.</i> vasiyata
Intestate.—इच्छापत्रहीन	Icchapatrahina	निर्वसीयता, $Nirvasiyata$
Introduce.— पुरःस्थापन	Purah sthapana	
Introduction.— पुरःस्थापना	Purah sthap ana	
Invalid अमान्य	\boldsymbol{Amanya}	
Invalidity pensions.—असमर्थता- निवृत्ति वेतन	Asamarthata- nivrttivetana	
Investigation.— अनुसंघान	Anusamdhana	
Involve.—अन्तर्ग्रसन	An targrasana	
Involved.—अन्तर्गस्त	Antargrasta	
Irregularity — अनियमिता	Aniyamita	
Issue,—वाद-पद	Vada- $pada$	•

1	2	3
J		,
Joining Time.—योगकाल	Yogakala	
Joint family.—अविभक्त कुटुम्ब	$Avibhakta \ kutumba$	अविभक्त परिवार, Avibhakta parivara
udge.—न्यायाधीश	Nyayadhisa	•
Judge, Additional.—अपर न्यायाधीश	$egin{aligned} Apara & Nyaya-\ dhis a \end{aligned}$	
Judge, extra.—अतिरिक्त न्यायाघीश	Atirikta nyaya- dhisa	
Judgment. – निर्णय	Nirnaya	
Judicial power.—न्यायिक शक्ति	$Nyayika\ sakti$	
Judicial proceeding—न्यायिक कार्यवाही		न्यायिक कार्यरीति, Nyayika karyariti
Judicial stamp.—न्यायिक मुद्रांक	Nyayika mu- dramka	
Judiciary.—न्यायपालिका	Nyayapalika	
Jurisdiction.—क्षेत्राधिकार	Kshetradhikara	
Justice, Chief.—मुख्य न्यायाधिपति	Mukhya Nya- yadhipati	
L	1	
Labour.—श्रम	Srama	
Labour Union.—श्रमिक संघ	Sramika samgh	a
Land records. – भू-अभिलेख	Bhu- $abhilekha$	
Land revenueभू-राजस्व	Bhu- $rajasva$	
Land tenures भू-धृति	Bhu- $dhrti$	
${f Law}$.—বিधি	Vidhi	
Law of Nations.—राष्ट्रों की विधि	$egin{aligned} Rashtron \ ki \ Vidhi \end{aligned}$	
Legal.—विधि सम्बन्धी	oananı	कानून सम्बन्धी, $Kanuna\ sambands$
Legislation.—विधान	Vidhana	
Legislative power.—विद्यायिनी शक्ति	Vidhayini sakti	
Legislative Assembly.—विधान-सभा		<i>t</i> .
Legislative Council.—विद्यान-परिषद्	shad	
Legislature. — विघान-मण्डल	$Vidhana ext{-}man ext{-} \ dala$	

1	2	3	
Letters of credit.——प्रत्यय-पत्र	Pratyaya-patra		
Levy.—-१. आरोपण २. उद्ग्रहण	1. Aropana 2. Udgrahana	उगाहना, Ugahana	
Liability.—दायित्व	Dayitva		
Libel.—अपमान-लेख	Apamana-lekha		
Liberty.—स्वाधीनता	Svadhinata		
Licences.—अनुज्ञप्ति	Anujnapti	लाइसेंस, Livence	
Lieutenant Governor.—उपराज्यपाल	Uparajyapal		
Limitation.—परिसीमा	Parisima		
List.—सूची	Suci		
List, Concurrent.—समवर्ती स्ची	Samarartti suci		
List, State.—राज्य-सूची	$Rajya ext{-}suci$		
List, Union,—संघ-सची	Samgha-suci		
Livelihood.—जीविका	Jivika		
Loans.—उधार	Udhara		
Local area.—स्थानीय क्षेत्र	Sthaniya kshetra		
Local authorities.—स्थानीय प्राधिकारी	Sthaniya pradhikari	•	
Local board.—स्थानीय-मंडली	Sthaniya mandali	स्थानीय गण, Sthaniya Gana	
Local body.—स्थानीय निकाय	Sthaniya nikaya		
Local Government.—स्थानीय शासन	Sthaniya Sasana		
Local Self Government.—स्थानीय स्वशासन	Sthaniya Svasasana		
Lock up.—बन्दीखाना	Bandikhana		
Lower House.—प्रथम सदन	Prathama Sadana		
Lunacyउन्माद	Unmada		
Lunatic.— उन्मत्त	Unmatta		
. M			
Maintain.—१. पोषण	1. Poshana		
२.बनाये रखना	2. Banae rakhana		
Maintenance.—पोषण	Poshana		

1	2	3
Major.—वयस्क Majority.—बहुमत Mandamus.—परमारेश Manufacture.—िनर्गण Maritime shipping.—समुद्र-नौवहन Maternity relief.—प्रसूति-सहायता	Vayaska Bahumata Paramadesa Nirmana Samudra- nauvahana Prasuti- sahayata	प्रसूति-साहाय्य, Prasuti sahaya
Member.—सदस्य Memo.—ज्ञाप Memorandum.—ज्ञापन Memorial.—स्मारक Mental deficiency.—मनो-वैकल्य Mental weakness.—मनो-दौबंल्य Merchandise marks.—पण्य चिह्न Merchandise marine.— विणक-पोत Message.—संदेश Migration.—प्रवजन Military.—१ सेना २. सैनिक	Sadasya Jnapa Jnapana Smaraka Mano-vaikalya Mano-daurbulya Punya cihna Vanik-pota Samdesa Pravrajana 1. Sena 2. Sainika	
Mind, unsound.—विकृत-चित्त Mineral.—खनिज Mineral resources.—खनिज-सम्पत् Mining settlement.—खनिवसति Minister.—मंत्री Minor.—अवयस्क Minority.—अल्पसंख्यक-वर्ग Misbehaviour.—कदाचार Modification.—रूपभेद	Vikrt-citta Khanija Khanija-sampat Khani-vasati Mantri Avayaska Alpasamkhyaka- varga Kadacara Rupabheda	
Money चन विधेयक	Dhana Dhana vidheyaka	

1	2	3
Money-lender.—साहूकार Money lending,—साहूकारी Morality.—सदाचार Mortgage.—बन्धक Motion. —प्रस्ताव Motion for Consideration.— विचा- रार्थ प्रस्ताव Motion of Confidence.—विश्वास प्रस्ताव Motion of No-confidence.— अविश्वास-प्रस्ताव Municipal area.—नगर-क्षेत्र Municipal Committee.—नगर-समिति Municipal Corporation.— नगर-निगम Municipality.—नगर-पालिका Municipal tramways.—नगर-रथ्यायान	Sahukara Sahukari Sahukari Sadacara Bandhaka Prastava Vicarartha prastava Visvasa-prastava Avisvasa- prastava Nagara-kshetra Nagara-nigama Nagara palika Nagara-rathya- yana	

N

Nation.—राष्ट्र National highways.—राष्ट्रीय राजपथ	Rastra Rashtriya
Naturalisation.—देशीयकरण	rajapatha Desiyakarana
Naval.—नौसेना सम्बन्धी	$Nausena \ sambandhi$
Navigation.—नौ-परिवहन	Nau-parivahana
Newspapers. समाचार-पत्र	Samacara-patra
Nominate.—नामनिर्देशन	Namanirdesana मनोनयन,
Notice.—१. सूचना २. सूचनापत्र	1. Sucana, 2. Sucana-patra
Notice in writing.— लिखित सूचना	Likhita sucana
Notification.—अधिसूचना	$\pmb{Adhisu}{cana}$.

1	2	3
	0	
Obligation.—आभार	Abhara	
Occupation.—उपजीविका	Upajivika	धंघा, Dhamdha
Octroi.—चुंगी	Cumgi	
Offence.—अपराध	Aparadha	
Office.—पद	Pada	
Officer.—पदाधिकारी	$Padadhikari\ $	
Official residence.—पदानास	Padavasa	
Opinion.—अभिप्राय	Abhipraya	राय, Raya
Order.— १ आदेश	1.~Adesa	
२.व्यवस्था	2. Vyavastha	
Order in Council.— परिषद् आदेश	$Parishad ext{-}ades a$	
Order standing.—स्थायी आदेश	Sthayi Adesa	
${f Ordinance}$ अध्यादेश	Adhyadesa	
Organization.—संघटन	Samghatana	
$0 \mathrm{wn}$.—स्वामी होना	Svami hona	
Owner.—स्वामी	Svami	
Ownership —स्वामित्व	Svamitva	
	P	
Pardon.—क्षमा	Kshama	
Parliament.—संसद्	Samsad	
Party.—पक्ष	Paksha	
Partnership.—-भागिता	Bhagita	
Pass.—पारण	Parana	
Passed.—पारित	Parita	तीणे, I'irna
Passport.—पारपत्र	Para-patra	
Patents.—एकस्व	Ekasva	
Payवेतन	Vetana	
Peace,—शान्ति	Santi	
Pecuniary jurisdiction.—आर्थिक क्षेत्राधिकार	Arthika kshe- tradhikara	
Penalty.—शास्ति	Sasti	
Pending—१ छम्बत २ छम्बमान	1. Lambita, 2 Lambamana	

1	2		3
Pension.—निवृत्ति वेतन	Nivrtti vetana		
People.—लोक	Loka	जनता,	Janata
Permission.—अनुज्ञा	Anujna		
Permit.—अनुज्ञा	Anujna	परमट,	Permat
Perpetual succession.—शास्वत उत्तराधिकार	Sasvata Uttara dhikara		
Perquisite.—परिलब्धि	Parilabdhi		
Person.—व्यक्ति	Vyakti		
Personal law.—स्वीय विधि	Sviya vidhi		
Petition.—याचिका	Yacika	अर्जी,	Arji
Piracy.—जल-दस्युता	$Jala ext{-}dasyuta$		
Plead.—वकालत करना	V akalata karana		
Pleader.—वकील	Vakila		
Police.—आरक्षक	Arakshaka		
Police Force.—आरक्षक बल	Arakshaka Bala		
Police Station.—थाना	Thana		
Policy of insurance.—बीमा-पत्र	Bima-patra		
Port quarantine.—पत्तन निरोधा	$Pattana \ nirodha$		
Possession.—स्ववश	Svavasa	कब्जा,	Kabja
Posts.— ∫ १. पद े २. स्थान	1. Pada 2. Sthana	जगह,	Jagaha
Power.—शक्ति	Sakti	•	
Preamble.—प्रस्तावना	Prastavana		
Preference.— अधिमान	Adhi mana		
Prejudice. —प्रतिकूल प्रभाव	$Pratikula \ prabhava$		
Preside.—पीठासीन	Pithasina	भ्रध्यासी	नि,
		Adh	yasina
President.—राष्ट्रपति	Rashtrpati		
Presiding officer.—अधिष्ठाता	Adhish that a		
Preventive detention.—निवारक निरोघ	$Nivaraka \ nirodha$		
Prime Minister.—प्रधान मंत्री	$Pradhana\ Mantri$	•	

	• • •	
	2	3
Prison.—कारावास	Karavasa	ਯੇਲ, $Jela$
Prisoner.—काराबन्दी	Karabandi	कैदी, Kaidi
Privileges.—विशेषाधिकार	Vise shadhikara	-
Procedure.—प्रिकया	Prakriya	1
Process.—आदेशिका	Adesika	
Proclamation.—उद्घोषणा	Udghoshana	
Proclamation of Emergency.— आपात की उद्घोषगा	Apata ki udghoshana	
Production.—उत्पादन	Utpadana	
Profession.—वृत्ति	Vrtti	पेशा, Pesa
Profit.—लाभ	Labha	1411, 1 600
Prohibited.—স্বিষিত্ত	Pratishiddha	
Prohibition.—प्रतिषेध	Pratishedha	
Prohibition, writ of.—प्रतिषेध-लेख	Pratisheda- lekha	
Promissory note.—प्रामिसरी नोट	Pṛamisari nota	वचन-पत्र, Vacana-patra
Promulgate.—प्रख्यापन	Prakhyapana	part of
Propagate.—प्रचार करना	Pracara karana	
Property. —१, सम्पत्ति; २. रिक्थ	1. Sampatti 2. Riktha	बास्ति $Asti$
Proportional representation.— अनुपाती प्रतिनिधित्व	Anupati prati- nidhitva	
Proposal.—प्रस्यापना	Prasthapana	
Prorogue — सत्तावसान	Sattravasan a	
Prosecution.—१, अभियोजन २, अभियुक्ति	 Abhiyojana, Abhiyukti 	
Provided.—परन्तु	Parantu	
Provident fund.—भविष्य निधि	Bhavishya	
Province.—प्रान्त	$nidhi \ Pranta$	
Provision — उपबन्ध		
Proxy.—प्रतिपन्नी	Upabandha Pagtingtui	
Publication अकाशन	Pratipatri Prakasana	

1	. 3	3
Public debt.—राष्ट्र-ऋण	Rashṭra-rna	
Public emands.—सार्वजनिक अभियाचना	Sarvajanika abhiyacana	सरकारी अभियाचना, Sarakari abhiyacana
Public health.—लोक स्वास्थ्य Public notification.—	Loka-svasthya	aonigacana
सार्वेजनिक अधिसूच ना-	Sarvajanika adhisucana	लोकअधिसूचना $Loka$
Public Order.— सार्वजनिक व्यवस्था	Sarvajanika vyavastha	Adhisucana
Public Service.—Commission लोक-सेवायोग	Loka-sevayog a	
Public Services.— लोक सेवाएं	Loka-sevayen	
Punish.—दंड देना	Danda dena	
Purporting to be done.—कर्तुंमभिन्नेत	Kartumabhi- preta	
Q		
Qualification.—अहंता	Arha!a	
Quarantine — निरोधा	Nirodha	
Question of Law.—विधि-प्रश्न	$Vidhi ext{-}prasna$	
Quorum,—गणपूर्त्ति	Ganapurti	
Quo warranto.—अधिकार-पृच्छा	$Adhikara-\ precha$	
R		
Railway.—रेल	Rela	•
Ratification.—अनुसमर्थन	Anusa marthana	
Ratify.—अनुसमर्थन	Anusa marthana	
Reading, first.—प्रथम पठन	Prathama	
Reading, second.—द्वितीय पठन	pathana Dvitiya Pathana	
Reading, third.—तृतीय पठन		
Receipt.—प्राप्ति	$Trtiya\ pathana$	

1	2	3
Receipt (paper).—पावती Recommend.—सिपारिश करना Recommendation.—सिपारिश	Siparisa karana Siparisa	तीव, Rasida
\mathbf{Record} ,—अभिलेख	Abhilekha	
Record, court of.—अभि लेख-न्यायालय	Abhilekha- nyayalaya	
Record of rights.—अधिकार अभिलेख	Adhikara abhilekha	
Recruitment.—भर्ती Recurring.—आवर्त्तक Redemption.—विगोचन	Bharti Avaritaka Vimocana	
Redemption charges.—-विमोचनभार	$Vimocana\ bhara$	
Reference.—निर्देश	Nirdesa	
Reformatory.—सुधारालय	Sudharalaya	
Refundable to.—लौटाये जाने वाली	Lautaye jane- vali	
Regional Commissioners.—प्रादे- शिक आयुक्त		
Regional Councils.—प्रादेशिक-परिषद्	Pradesika parishad	
Regional Fund.—प्रादेशिक निधि	$egin{array}{c} Pradesika \ Nidhi \end{array}$	
Register.—पंजी	Pamji	
Registered.—१. पंजीबद्ध २. निबद्ध	1. Panjibaddha 2. Nibaddha	नौंदना, Naundana
Registration.—१. पंजीयन २. पंजीबन्धन ३. निबन्धन	1. Panjiyan 2. Panjibandhan 3. Nibandhana	
Regulate.—विनियमन	Viniya mana	
Regulation.—विनियम	Viniyama	
Relevancy.—सुसंगति	Susamyati	
Relevant —सुसंगत	Susamgata	
Remedy.—उपचार	Upacara	
Reminder.—अनुस्मारक	Anusmaraka	r
Remission.—परिहार	Parihara	
Removal.—हटाना	Hatana	
Remuneration.—पारिश्रमिक	Parisramika	
Rent		गान, Lagana

1	2	3	
Repeal.—निरसन	Nirasana		
\mathbf{Report} . – प्रतिवेदन	Prative dana		
Representation.—प्रतिनिधित्व	Pratinidhitva		
Representative. –प्रतिनिधि	Pratinidhi		
Reprieve.—प्रविलम्बन	Pravilambana		
Repugnance.—विरोध	Virodha		
Repugnancy.—विरोध	Virodha		
Repugnant.—विरुद्ध	Viruddha		
Requisition.—-अधिग्रहण	Adhigrahana		
Research.—गवेषणा	Gaveshana	शोघन,	Sodhana
Reservation. रक्षण	Rakshana		
Reserved forest.—रक्षित वन	Rakshita vana		
Resignation—पदत्याग	Padatyaga		
Resolution.—संकल्प	Samkalpa		
Respites.—विराम	Virama		
Restriction—निर्बन्धन	Nirbandhana		
Retire.—निवृत्त होना	Nivrtta hona		
Retirement.—निवृत्ति	Nivrtti		
Revenue.—राजस्व	Rajasva	आगम,	Agama
Review.—पुर्नावलोकन	Punarvilokana		
Revision.—पुनरीक्षण	Punarikshana		
Revoke.—प्रतिसंहरण	Pratisamharana		
Reward पारितोषिक	Paritoshika		
Rights.—अधिकार	Adhikara		
Rule. — नियम [ै]	Niyama		
Rule of the road.—क्य-नियम	Patha-niya ma		
Ruler.—्वासक	Sasaka	•	
	S		
Safeguard. रक्षा-कृत्च	Raksha-kavaca	-6	
Salary.—वेतन	Vetana	पार्त्राण,	Paritrana
Sale.—विकय	V etana V ikraya		
Sanction.— मंजूरी			
Sanction, previous. पूर्व मंज्री	Manjuri Purva manjuri		
	***	•	

1	2	3
 Savings.—व्यावृत्ति	Vyavrtti	
Schedule.—अनुसूची	Anusuci	
Scheduled area.—अनुसूचित क्षेत्र	Anusucita Kshetra	
Scheduled Caste.—अनुसूचित जाति	Anusucita Jati	
Scheduled Tribes,—अनुसूचित जनजाति	$Anusucit ext{-}Jana\ Jati$	अनुसूचित आदिम जाति Anusucita adim
Seal,—मुद्रा Seats,—स्थान	Mudra Sthana	jati
Sections.—विभाग	Vibhaga	
Security.—प्रतिभूति	Pratibhuti	
Sentence.—दंडादेश	$Dandad_{\mathcal{CSA}}$	
Service.— सेवा	Seva	
Service charges.— सेवा-भार	Scva-bhara	
Session.—सत्ता	Sattra	
Share.—अंश	Amsa	
Sheriff.—गेरीफ	Serif	
Single trans ferable vote. — एकल संक्रमणीय मत	Ekala Samkra- maniya Mata	
Sinking Fund.—निक्षेपनिधि	Nikshepa nidhi	
Sitting.—उपवेशन	Upavesana	बैटक, Baithak
Slander.— अपमान-वचन	Apamana- vacana	404, Danmar
Social·custom.—सामाजिक रूढ़ि	Samajika rudhi	
Social Insurance.—सामाजिक बीमा	Samajika bima	•
Social Service.—सामाजिक मेवा Sovereign.—प्रभु	Samajika seva Prbhu	
Sovereign Democratic Republic. — संपूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य	Sampurna Prabhutva Sampanna Loka!antraimak	ca
Sovereignty.—प्रमुता	$Ganarajya\ Parbhuta$	
Speaker.—अध्यक्ष	Adhyaksh	
Speech, freedom of.—वाक्-स्वातन्त्र्य	Vak-s $vatantrya$	
एक्सा-कमचारा वृत्द	Karmacarivrnda	
Stamp duties.—मुद्रांक-शुल्क	Mudramka-sulka	

2 1 5 Standing orders.—स्थायी Sthayi adesa State - राज्य RajyaState funds.—राज्य-निधि Rajya-nidhi Stock exchange - श्रेष्ठि-चत्वर Sreshthi-catvara Sub-division.—उपविभाग Upa-vibhagaSubject.—१. अधीन, 1. Adhina, २. विषय 2. Vishaya Vada vishaya Subject matter.—वाद विषय Subordinate officer —अधीन अधिकारी Adhina adhikariUttaradhikaraSuccession — उत्तराधिकार UttaradhikariSuccessor, -- उत्तराधिकारी Vyavahara lana Sue.—व्यवहार लाना MatadhikaraSuffrage — मताधिकार Vyavahara vada Suit, Civil.—व्यवहार वाद AhvanaSummon.—आह्वान AdhikshanaSuperintendence.—अधीक्षण Superintendent.—अधीक्षक AdhikshakaSupplementary.—अनुपूरक Anupuraka Supplementary grant.—अनुप्रक Anupurakaanudanaअनुदान Supreme Command.—सर्वोच्च Sarvocca samadesaSupreme Court,—उच्चतमन्यायालय Uccatama. nyayalaya Suspend.—निलम्बन Nilambana Suspension.—निलम्बन Nilambana

 \mathbf{T}

Taxes.—कर

Tax, Callings.—आजीविका -कर

Tax, Capitation.—प्रतिव्यक्ति-कर

Tax, Corporation.—निगम-कर

Tax, Employment.—नौकरी-कर

Naukari-kara

Naukari-kara

1	2	3
Tax, Entertainment.—प्रमोद-कर	Pramoda-kar a	
Tax, Export.—निर्यात कर	Niryata Kara	
Tax, Profession,—वृत्ति-कर	Vrî ti - $kara$	
Tax, Income.—आय-कर	Aya- $kara$	
Tax, Sales.—विकय-कर	V ikraya-kara	
Tax, Terminal.—सीमा-कर	Sima-kara	
Tax, Trades.—व्यापार-कर	Vyapara-kara	
Technical training.—शिल्पी प्रशिक्षण	Silpi-prasi- kshana	
Tenant. —िकसान	${\it Kisana}$	•
Tender, legal.—विधि-मान्य	Vidhi-manya	
Tenure.—पदाविध	Padavadhi	
Term.— निबन्घन	Nibandhana	
Territorial charges.—प्रादेशिक भार	Pradesika bhara	
Territorial Jurisdiction.—प्रादेशिक	Pradesika	
क्षेत्राधिकार	kshetradhikara	
Territorial Waters .—जल-प्रांगण	Jala-pramgana	
Territory.—राज्य-क्षेत्र	$Rajya ext{-}kshetra$	
Tidal waters .—বলা-সল	Vela-jala	
	_	न्वार जल, $Jwara$
Title.—हक्क	Hakka	jala
Tolls —पथ-कर	Patha-kara	
Trade.—व्यापार	Vyapara	
Trademarks.—व्यापार चिह्न	Vyapar cihna	
Trade Union.—कार्मिक संघ	Karmika Sam- gha Yatayata	व्यापार संघ, Vyapara Samgho
Traffic. – यातायात	Manava-pan-	
Traffic in human beings.—मानव- पणन	ana	
Training.—সৃशिक्षण	Prasikshana	
Tramcar.—रथ्यायान	Rathyayana	
Tramway.—द्राम	Trama .	ट्रामगाड़ी , Tramagadi
Tranquillity.—प्रशान्ति	${\it Prasanti}$	
Transfer.—१ स्थानांतरण, २ हस्तान्तरण	1 Sthanantaran 2 Hastantaran	

1	2	3
Transition.—संक्रमस्य	Samkramana	
Transport.—परिवहन	Parivahana	
Transportation.—निर्वासन	Nirvasana	
Treasure troves.—निखात-निधि	Nikhata-nidhi	
Treaty.—सन्धि	Samdhi	
Tribal Area.—जनजाति-क्षेत्र	Janajati- kshetra	
Tribe.—जन-जाति	Jana-jati	
Tribunal.—न्यायाधिकरण	Nyayadhi- karana	•
Triennial.—त्रैवार्षिक	Traivarshika	
Trust.—न्यास	Nyasa	
	υ	
Undischarged.—अनुन्मुक्त	Anunmukta	
Unemployment.—बेकारी	Bekari	
Union — संघ	Samgha	
Unit.—एकक	Ekaka	
Unsoundness of mind.— चित्त-विकृति	Citta-vikrti	
,	V	• .
Vacancies.—रिक्त स्थान	Rikta sthana	
Vacancy.—१, रिक्ति, २. रिक्तता	1. Rikti, 2. Riktata	
Vagrancy.—आहिडन	Ahindana	बावारागर्दी, Avaragardi
Validityमान्यता	Manyata	•
Vice-President.—उपराष्ट्रपति	$U_{\it f}$ arashtra $_{\it f}$ at	
Village Councils —ग्राम-परिषद्	Grama-parishad	
Violation.—अतिक्रमण	Atikramana	•

1	2	3
isas.—द्रष्टांक	Drshtamka	वीसा, $Visa$
Vocation.—व्यवसाय	Vyavasaya	
Void.— शून्य	Sunya	
Vcte.—на	Mata	
Vote, casting.— निर्णीयक मत	$egin{aligned} Nirnayaka \ mata \end{aligned}$	
Voter — मतदाता	Matadata	वोट-दाता,
Votes on account.—लेखानुदान	Lekhanudana	Vota-data गणनानुदान,
Votes of credit.—प्रत्ययानुदान	Pratyaya- nudana	Ganananudana
	w	
Wage.— मजूरी	Majuri	
Wage, living निर्वाह-मजूरी	$Nirvaha- \ majuri$	
Warraut. अधिपत्र	Adhipatra	
Will.—इच्छा-पत्र	Iccha-patra	\int विल, Wil े वसीयत, $Vasiyata$
Winding up.—समापन	Samapana	Carriery / worgana
Writ.—लेख	Lekha	

श्रे

अक्षम.—Incompetent अक्षमता.—Incompetency अग्रिम धन.—Advance अतिक्रमण.—Violation अतिरिक्त न्यायाधीश .—Judge, extra अतिरिक्त लाभ. -- Excess profit अधिकरण.—Tribunal अधिकार.—Right अधिकार-अभिलेख.—Record of rights अधिकार-पुच्छा .—Quo warranto अधिग्रहण.—Requisition अधिनियमन(n).—Actअधिनियम (v.).—Enact अधिपत्र.—Warrant अधिभार.—Sur-charge अधिमान.—Preference अधिवक्ता.—Advocate अधिवास.—Domicile अधिवासी.—Domiciled अधिष्ठाता.—Presiding officer अधिस्चना .-- Notification अवोक्षक.—Superintendent अधीक्षण.—Superintendence अधीन.—Subject अधीन अधिकारी.—Subordinate Officer अधीन न्यायालय.—Subordinate Court अध्यक्ष.—Speaker अध्यादेश.—Ordinance अध्यासीन होना.—Preside अनन्य क्षेत्राधिकार.—Exclusive Jurisdiction अनर्हता.—Disqualification

अनहीं करण. — Disqualify

अनियमिता.—Irregularity अनुकलन —Adaptation अनुच्छंद.—Article अनुज्ञप्ति.—Licence अनुज्ञा (v.)—Permit, अनुज्ञा (n.).—Permission अनुदान. - Grant अनुदेश.—Instruction अनुन्मुक्त.—Undischarged अनुपाती प्रतिनिधित्व.—Proportional representation अनुपूरक.—Supplementary अनुपूरक अनुदान.—Supplementary grant अनुमति. —Assent अनुमोदन (v.).—Approve अनुमोदन (n.).— Approval अनुशासन .—Discipline अनुशासन सम्बन्धी. —Disciplinary अनुषक्ति.— Adherence अनुष्ठान. — Exercise अनुसमर्थन (n.)—Ratification अनुसमर्थन (v.) - Ratify अनुसंधान (v.)—Investigate अनुसंधान (n.)—Investigation अनुस्मारक.—Reminder अनुसूचित क्षेत्र.—Scheduled area अनुस्चित जनजाति.—Scheduled Tribe अनुसूचित जाति.—Scheduled Caste अनुसूची.—Schedule अन्तर्ग्रसन्.—Involve अन्तग्रंस्त.—Involved अन्तर्देशीय जलपथ.—Inland waterway अन्तर्धिय.—International अन्तःकरण.— Conscience बन्य-देशीय.—Aliens अन्य-संक्रामण (v.)—Alienate

अन्य-संक्रामण (n.).—Alienation अपमान लेख.—Libel अपमान-वचन.--Slander अपमिश्रण.—Adulteration अपर-न्यायाघीश.— Additional-judge अपराध---Crime अपराध.—Offence अपराधी.—Criminal अपवर्जन (v.).—Exclude अपवर्जन (n.).—Exclusion अपात्र.—Ineligible अपात्रता.—Ineligibility अपील.—Appeal अपील न्यायालय.—Court of Appeal अप्रवृत्त.—Inoperative अभिकथन.—Allegation अभिकरण.-Agencyअभिकर्त्ता.— Agent अभिप्राय.—Opinion अभियाचनाः—Demand अभियुक्त.—Accused अभियुक्ति.— Charge अभियुक्ति.—Prosecution अभियोग.—Accusation अभियोजन.—Prosecution अभियोज्य दोष.—Actionable wrong अभिरक्षा.—Custody अभिलेख.—Record अभिलेख न्यायालय. —Court of record अभिशस्त.—Convicted अभिशस्ति.—Conviction अभिसमय.—Cor vention अभ्यर्थी.—Candidate अमान्य.-Invalid अयुक्त प्रभाव.—Undue influence अर्जन -- Acquisition

अभी —Petition वर्ष करना.—Construe

अर्थ दण्ड.—Fine अर्हता.—Qualification अल्पसंख्यक वर्ग.—Minority अल्पीकरण. — Derogation अवधिदान.-Adjournअवमान.—Contempt अवयस्क.—Minor अविभक्त कुटुम्ब.—Joint family अविभक्त परिवार.—Joint family अविश्वास-प्रस्ताव.— Motion of no confidence अवैध.— Illegal अवैधाचरण.—Illegal practice असमर्थता.—Incapacity असमर्थता-निवृत्ति वेतन-.- Invalidity pension असैनिक.—Civil असैनिक शक्ति.—Civil power अहितकारी.—Detrimental अंकन. —Endorse अंकित.—Endorsed अंग.—Unit अंश.—Share अंशदान.— Contribution

आ

आकलन (v).—Credit
आकस्मिकता निधि.—Contingency Fund
आचार.— Custom
आजादी.—Freedom
आजीविका.—Callings
आजीविका-कर.—Callings tax
आजीविका-कर.—Callings tax
आजीविका-कर.—Order
आदेश.—Order
आदेशिका.—Process
आनुषंगिक.—Consequential
आपराधिक:—Criminal

आपात.—Emergency आपाती.—Emergent आपात की उद्घोषणा Proclamation of emergency

आभार.—Obligation
आय-कर.—Income tax
आयात-शुरुक.—Import duty
आयुक्त.—Commissioner
आयोग.—Commission
आरक्षक.—Police
आरक्षक.—Police Force
आरोप.—Allegation
आरोपण करना.—Impose
आरोपण.—Levy
आर्थिक.—Economic
आर्थिक क्षेत्राधिकार.—Pecuniary
jurisdiction

आवर्त्तंक.—Recurring आवारागरदी.—Vagrancy आवेदन-पत्र.—Application आस्ति.—Property आह्विन.—Vagrancy आह्वान.—Summon

इ

इच्छा-पत्र.—Will इच्छा-पत्रहीन.—Intestate इच्छा-पत्र होनत्व.—Intestacy

उ

उगाहना.—Levy (v)
उच्चतमन्यायालय.—Supreme Court
उच्चत्यायालय.—High Court
उत्तराधिकार.—Succession
उत्तराधिकार-शुल्क.—Successionduty
उत्तराधिकारी.—Successor
उत्तराधिकारी.—Liability

उत्पादन.—Production उत्पादन-शुल्क.—Excise duty उत्प्रवा -- Emigration उत .—Certiorari उद्.. ग.—Levy (n.) उद्घोषणा.—Proclamation उद्भव.—Descent उद्यम.—Enterprise उद्योग.—Industry उधार.—Loan उधार-ग्रहरा.—Borrowing उन्मत्त.—Lunatic उन्माद.—Lunacy उन्मुक्ति.—Immunity उपकर.—Cess उपक्रमण.—Initiate उपचार.—Remedy उपजीविका.—Occupation उपदान. Gratuity उपदेश.—Advisory डपनिर्वाचन.—Bye-election उपनिवेशन.— Colonization उपबन्ध.—Provision उपभोग. - Consumption उपराज्यपाल.—Lieutenant Governor उपराष्ट्रपति.—Deputy President उपराष्ट्रपति.—Vice President उपलब्धि.—Emolument उपविभाग.—Sub-division उपवेशन.—Sitting उपविधि.—Bye-law उपसभापति. -Deputy Chairman उपस्थित होना.—Appear उपाध्यक्ष.—Deputy Speaker उपायक्त.—Deputy Commissioner उपायोजन.—Employment

चपाजित.—Accrued

सम्मेदवार.— Candidate सन्लंघन.— Contravention

沤

ऋण.— Debt ऋणग्रस्तता.— Indebtedness ऋण-पत्र.—Debenture

ए

एकक.—Unit एकल निगम.—Corporation, Sole एकल संक्रमणीय मत.—Single transferable vote एकस्व.—Patent

क

कटक.—Cantonment
कणक्.—Account
कदाचार.—Misbehaviour
कब्जा.—Possession
कम्पनी.—Company
कर.—Tax
करार.— Agreement
कर्तव्य.—Duty
कत्त्त्वां मिन्नप्रेत.—Purporting to be done

कमंचारी-वृन्द—Staff
कानून सम्बन्धी.— Legal
कारखाना. Factory
कारबार.—Business
कारागार.—Prison
काराबन्दी.—Prisoner
कारावास.—Imprisonment
कार्मिक संघ.—Trade Union
कार्यं.— Business
कार्यकारी.— Acting
कार्यपालिका शक्ति.—Executive power

कालदान.—Adjourn कावल.—Custody कांजी हौस.—Cattle pound किराया.—Fare किसान.—Tenant कुर्की—Attach.

कृति स्वाम्य.— Copyright कृत्य.—Function केन्द्रीय गुप्त-वात्ती विभाग-—Central Intelligence Bureau कैद.—Imprisonment कैदी.—Prisoner

ম্বারি.— Injury ম্বারিপুর্নি ৰিল্ল.—Bill of indemnity

क्षमताञ्चाली.—Competent क्षमा.—Pardon क्षेत्र.—Area क्षेत्राधिकार.—Jurisdiction

ख

खनिज.—Mineral खनि-नसति.— Mining settlement खनिज-सम्पत्.— Mineral resources खर्च.—Cost खंड.—Clause

ग

गचट.—Gazette
गणना.—Account
गणनानुदान—Vote on account
गणना-परीक्षा.—Audit
गणपूर्ति.—Quorum
गवेषणा.— Research
गृह पत्र.—Ballot

ग्रीम-परिषद्.—Village Council ग्राह्म.—Admissible घ घोषणा.—Declaration

च

चट्टम.—Act(n.)
चर्चा.—Discussion
चल अथं.—Currency
च्रेचलावणी.—Currency
चित्तविकृत्ति.—Unsoundness of mind
चिन्ह.—Mark
चुकती.—Agreement
चुने हुए.—Elected
चुंगी.—Octroi
क.—Cheque

छ

छावनी.—Cantonment

ল

जगह.—Post
जनगणना.—Census
जन-जाति.—Tribe
जनजाति-क्षेत्र.—Tribal Area
जनजाति-परिषद्.—Tribal Council
जल-दस्युता.—Piracy
जल-प्रांगण.—Territorial waters
जामन.—Bail
जांच करना.—Inquire
जिला-गण.—District
जिला-गण.—District Board
जिला-निधि.—District Fund
जिला-न्यायालय.—District Court
जिला-परिषद्.—District Court

जीविका.—Livelihood जु**बा.**—Gambling जुर्माना किया.—Fined जेल.—Prison ज्वार-जल.—Tidal waters

ज्ञ

ন্নাদ—Memo ন্নাদন.—Memorandum

5

टंकण.—Coinage टांच.—Attach

ट्राम.—Tramway ट्रामगाड़ी.—Tramcar

ड

डिकी.—Decree

त

तत्समय.—For the time being तत्स्यानी.—Corresponding तद्यं.—Ad hoc तीणं.—Passed तीवं.—Assessment तृतीय पठन.—Third reading त्रैवाषिक.—Triennial

थ

थाना.—Police Station

द

दत्तक-ग्रहण.—Adoption दत्तक-स्वीकरण.—Adoption दस्तकारी.—Handicraft दस्तावेग.—Document दंड देना.—Punish दंड-न्यायालय —Criminal Court दंड-विधि.—Criminal law दंड-सम्बन्धी.—Criminal दंडादेश.—Sentence

दंडाधिकारी-न्यायालय.— Magistrate's Court

दाखला —Entry दातव्य.—Charities दाय.—Inheritance दायित्व.—Liability दावा.—Claim दिवाला.—Bankruptcy दिवाला.—Insolvency दीवानी.—Civil दीवानी-अदालत. — Civil Court दृष्टांक.—Visas देय.—Fee देशीयकरण.— Naturalisation दोघरा.— Bi-cameral दोष-प्रमाणित.—Convicted दोष-सिद्धि.—Conviction दोषारोप.- Charge (Cr.) चूत.—Gambling दिगृही.— Bi-cameral द्वितीय-पठन.—Second reading

ध

घन.— Money धन-विधेयक.--Money-bill धर्म.—Faith धर्मस्व.—Endowments षंघा.—Occupation

न

नक्ष.— Design नगरक्षेत्र.- Municipal area नगर-ट्रामवे.-Municipal Tramway नगर-निगम.—Municipal Corporation नगर-पालिका.—Municipality नगर-रध्यायान—Municipal Tramway नगर-समिति.— Municipal Committee नागरिकता.—Citizenship नाम-निदर्शन -- Nominate

निकाय.—Body

निक्षेप-निधि.—Sinking Fund निखात-निधि.—Treasure trove

निगम.— Corporation

नावधिकरण. - Admiralty

निगम-कर.— Corporation tax

निगमन. - Incorporation

निगम-निकाय .—Body, Corporate

निदेश. — Direction निधि.—Fund

निबद्ध.—Registered निबन्धन. — Registration

निबन्धन. — Term

नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक.—Comptroller and Auditor-Genera

नियन्त्रण.—Control नियम.—Rule नियुक्ति.—Appointment नियोजक-उत्तरवादिता. - Employer's liability

नियोजक-दातव्य.—Employer's liability

निरसन.—Repeal निराकरण करना.—Abrogate निरोघ.—Custody निरोघा.—Quarantine निर्णय.—Judgment

निर्णायक मत.—Casting vote

निर्देश.—Referecce निर्धारण.—Assessment

निर्बन्धन.—Restriction निर्माण.—Manufacture निर्यात.—Export निर्यात-कर.--Export tax निर्यात-शुल्क.—Export duty नियोंग्यता.—Disability निर्वचन.—Interpretation निर्वसीयत.—Intestate निर्वसीयता.—Intestacy र्रिनर्वहन.—Discharge निर्वाचक-गण.— Electoral college निर्वाचक नामावली.—Electoral rolls निर्वाचन (v.). - Elect निर्वाचन (n.).— Election निर्वाचन-अधिकरण.—Election Tribunal निर्वाचन-आयुक्त.—Election Commissioner निर्वाचन-क्षेत्र.—Constituency निर्वाचित.—Elected निर्वासन.—Transportation निर्वाह मजूरी.— Living wage निलम्बन (v.).—Suspend निलम्बन(n.).—Suspension निवारक-निरोध.—Preventive detention निवृत्त होना.— Retire निवृत्तिः—Retirement निवृत्ति-वेतन.—Pension निषेध.—Forbid निषद्ध.—Forbidden निष्ठा. —Allegiance नौंदना. —Register (v) नौकरी.—Employment नौकरी-कर.—Employment-tax नौकाधिकरण.—Admiralty नौ-परिवहन.—Navigation नौ-सेना सम्बन्धी. -Naval न्यस्त करना.—Entrust न्यायपालिका.—Judiciary

न्यायाधिकरण.—Tribunal न्यायाधिपति.—Justice न्यायाधीश.—Judge न्यायालय.— Court न्यायालय-अवमान.—Contempt of court न्यायिक-कार्यरीति.—Judicial proceeding न्यायिक-कार्यवाही.— Judicial proceed-न्यायिक मुद्रांक. — Judicial stamps न्यायिक शक्ति.—Judicial power न्यास.—Trust न्युनन.—Abridge प पक्ष.—Party पण लगाना.—Bet पण किया. —Betting पण्य चिह्न.—Merchandise Mark पत.—Credit (n.) पत्तन-निरोधा.—Port quarantine पथ-कर.— Toll पथ-नियम.—Rule of the road पद.—Post पद.—Office पदच्युत करना.—Dismiss पदत्याग.—Resignation पदधारी.—Incumbent of an office-पदाधिकारी.—Officer पदावधि.—Tenure पदावास. — Official residence पदेन.—Ex-officio

परकीकरण.—Alienation

परमादेश.—Mandamus

परन्तु.—Provided

परमट.—Permit (n.)

परामर्श.— Consultation Abandonment परित्यजन. परित्याग .- Abandonment परित्राण.—Safeguard परिपालन.— Implement 'परिप्रश्न.— Inquiry परिलब्ध.—Perquisite परिवहन.— Transport परिवहन.-- Carriage · परिव्यय .-- Cost परिषद.—Council परिषद् आदेश.—Order in Council परिसीमन. —Delimitation परिसोमा.—Limitation परिहार.— Remission परिहार विधेयक.—Bill of Indemnity परोक्ष निर्वाचन.—Indirect election पर्यवेक्षरा.—Inspection पर्यालोचन.—Deliberate पश-अवरोध .- Cattle Pounds पंत्राट.—Award पंजी.—Register पंजी.—Registered पंजीबन्धन.— Registration पंजीयन.—Registration पात्रता. - Eligibility पात्र.—Eligible पार-पत्र.—Passport पारण.— Pass पारित.—Passed पारितोषिक.—Reward 'पारिश्रमिक.—Remuneration पावती.—Receipt (paper) पीठासीन होना.—Preside पीठासीनपदाधिकारी.—Presiding officer पुनरीक्षण.—Revision

पुनर्विचार-स्यायालय.—Court of Appeal

पुनर्विलोकन.—Review पुरःस्थापन.—Introduce पुरःस्थापनाः—Introduction पूर्त.—Charity प्तं घामिक धर्मस्व.— Charitable and religious endowment पूर्त संस्था.—Charitable institution पूर्व मंज्री.— Previous sanction पूर्व सम्मति.—Previous consent पूंजी.— Capital पृष्ठांकन.— Endorse पृष्ठांकित.—Endorsed पेशगी .- Advance पेशा.—Profession पोषण.—Maintenanco पोषण करना. - Maintain पौरत्व.—Citizenship प्रकट करना.—Discovery प्रकाशन.—Publication प्रित्रया. -- Procedure प्रस्यापन. -Promulgate प्रग्रहण.—Arrest प्रचलित.—Current प्रचार करना.— Propagate प्रतिकर.—Compensation प्रतिकूल असर डालना.—Affect prejudicially प्रतिक्लता. -- Contravention प्रतिक्ल प्रभाव. -- Prejudice प्रतिकुल प्रभाव डालना. — Affect prejudicially प्रति-कृति.—Copy प्रतिज्ञान.—Affirmation

प्रतिनिधि.—Representative

प्रतिपत्री— Proxy

प्रतिनिधित्व.—Representation

प्रतिपालक अधिकरण.—Court of wards प्रतिभृति.—Security प्रतिरक्षा.—Defence प्रतिलिपि.—Copy प्रतिलिप्यधिकार.—Copyright प्रतिवेदन.--Report प्रतिव्यक्ति-कर.—Capitation tax प्रतिषिद्ध.—Prohibited प्रतिषेध.—Prohibition प्रति-शुल्क.—Countervailing duties प्रतिषेध लेख.—Writ of prohibition प्रतिसंहरण.—Revoke प्रत्यक्ष निर्वाचन. - Direct election प्रत्यय.—Credit प्रत्यय-पत्र.—Letters of credit प्रत्ययान्दान.—Votes of credit प्रत्यपंण.—Extradition प्रत्याभृति.—Guarantee प्रथम पठन.—First reading प्रथम-सदन.—Lower House प्रधान-मंत्री.—Prime Minister ячя.—Form प्रभाव.-Influence ян.—Sovereign प्रभृता.—Sovereignty प्रमाण-पत्र .—Certificate प्रमाणीकरण.—Authentication प्रमोद-कर.—Entertainment tax प्रयक्ति.—Application प्रयोग.—Application, प्रयोग.—Exercise प्रविलम्बन.—Reprieve प्रवर-समिति.—Select Committee प्रविष्ट.—Entry

प्रवेश.—Access

43 प्रवेशन —Accession प्रवर्जन.—Migration प्रशान्ति.—Tranquillity प्रशासन.—Administration प्रशासन.—Administer प्रशासन कार्यक्षमता.—Efficiency of administration प्रशासन कार्यपटता.—Efficiency of administration प्रशासनीय.—Administrative प्रशासनीय कृत्य.—Administrative functions. प्रशासित.—Administered प्रशिक्षण.—Training प्रसंग.—Context प्रसारण.—Broadcasting प्रसृति साहाय्य. Maternity relief प्रसृति सहायता.—Maternity relief प्रस्ताव.—Motion प्रस्तावना.—Preamble प्ररथापना.-Proposal प्राक्कलन.—Estimate प्रादेशिक आयक्त.—Regional Commissioner प्रादेशिक क्षेत्राधिकार.—Territorial jurisdiction प्रादेशिक निधि.—Regional Fund प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र.—Territorial constituency प्रादेशिक परिषद्.—Regional Council प्रादेशिक भार.—Territorial charges प्राधिकार.—Authority (ab.) प्राधिकारी.—Authority (con.) प्राधिकत.—Authorised प्रान्त.—Province प्राप्या. - Accrue प्राप्त होना.-Accrue

.44 EQUIVALENTS FOR CONSTITUTIONAL TERMS प्राप्ति.—Receipt भागिता.—Partnership प्रामिसरी नोट.—Promissory note भाटक.—Rent प्रासंगिक.—Incidental भाड़ा.—Fare 'प्रोद्धवन.— Accrue भार.—Charge 'प्रोद्धत.—Accrued भारग्रस्त सम्पदा.—Encumbered estates भारत सरकार.—Government of फ India फरियाद.— Complaint भारित करना.—Charge 'फारम.— Form भू-अभिलेख.—Land Records 'फीस.—Fees भ्-षृति.—Land tenures 'फेडरलन्यायालय.—Federal Court भू-राजस्व.—Land Revenue ञ्रष्ट.—Corrupt ·बंटवारा.—Allocation # बनाये रखना. - Maintain (v.) ·बनाये रखना.—Maintenance (v.) मजूरी.—Wage ·बन्दी करना.—Arrest मण्डल.—District ंबन्दी प्रत्यक्षीकरण.—Habeas Corpus मण्डल न्यायालय.—Court, District ·बन्धकं.—Mortgage मण्डलाधीश.—Deputy Commi-बल.— Forces ssioner ·बहि:शुल्क.—Custom duty मण्डलायुक्त.—Deputy Commi. बहुमत.—Majority ssioner बांट.—Allotment मण्डली.—Board ंबिल.—Bill मत.—Vote -बीमा.—Insurance मतदाता. -Voter -बीमा-पत्र.—Policy of insurance मतदान.—Voting मताधिकार.—Suffrage ·बेकारी.— Unemployment मतिमान्द्य.—Dullness -बैठक.—Sitting मध्यस्थ-न्यायाधिकरण.-Arbitral tribunal बेंक.-Bank मध्यस्थ .—Arbitrator बोर्ड-Board मध्यस्थ-निर्णय.—Arbitration मनोदौर्बल्य. — Mentai weakness मनोनयन .--Nominate H मनोवैकल्य.-Mental defficiency मत्ता.--Allowance

मन्त्रणा.—Advice

मन्त्रणा देना.-Advise

मन्त्रणा-परिषद्.—Advisory Council

भविष्य-निधि —Provident Fund

नर्ज -- Recruitment

मन्त्रि-परिषद्.—Council of Ministers मन्त्री.—Minister मरण-शुल्क.—Death duty महाजनी.—Banking महाधिवक्ता. —Advocate-General महान्यायवादी.—Attorney-General महाप्रशासक.—Administrator General महालेखापरीक्षक.—Auditor-General ्रमहाभियोग.---Impeachment मंजरी.—Sanction मानदेय.—Honorarium मानव-पण्य.—Traffic in human beings मान-हानि.—Defamation मान्यता.—Validity मार्ग-प्रदर्शन.—Guidance मांग.—Demand मीन क्षेत्र Fishery मीन-पण्णै.—Fishery मुक्त. - Exempt मुखिया. —Headman मुख्य—Chief मुख्य-आयुक्त.— Chief Commissioner मुख्य-निर्वाचन-आयुक्त.—Chief Election-Commissioner मुख्य-न्यायाधिपति. -Chief Justice मस्य-न्यायाधीश. -Chief Judge मुख्य-मंत्री.—Chief Minister मुद्रा.— Seal मुद्रांक-शुल्क.—Stamp duty मूलधन.—Capital

यन्त्र-शास्त्र.—Engineering याचिका.—Petition यातायात.—Traffic योगकाल.—Joining time

₹

रक्षरा.—Reservation रक्षाकवच.—Safeguard रक्षित बन.—Reserved forest रथ्यायान.— Tramcar रह करना.—Annulment रसीद.—Receipt राजगामी.—Escheat राजनय.—Diplomacy राजस्ब.—Revenue राजस्व-न्यायालय.—Revenue Court राज्य.—State राज्य की सरकार.—Government of a State राज्य-क्षेत्र .—Territory राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन—Extra territorial operation राज्य-निधि.—State Fund राज्य-परिषद्.—Council of States राज्यपाल.—Governor राज्य-स्ची.—State-List राय.—Opinion राशि.—Amount राष्ट्र.—Nation राष्ट्-ऋण.—Public debt राष्ट्रपति.—President राष्ट्रपति-प्रसाद पर्यन्त.— During the pleasure of the President राष्ट्रीय-राजपथ .-National highways राष्ट्रों की विधि.—Laws of Nations

ग्यास्थिति.—As the case may be

म्लघन-मृत्य.—Capital value

रिक्तता.—Vacancy
रिक्त स्थान.—Vacancy
रिक्त.—Vacancy
रिक्त.—Vacancy
रिक्सथ —Property
रुकावट.—Bar
रूढ़ि.—Custom
रूप.—Form
रूपभेद.—Modification
रूपांकन.—Design
रेल.—Railway

ल

लगान.—Rent लगाना.—Impose ऋष्करण.—Commute लम्बमान.—Pending लम्बित.—Pending लाइसेंस.—Licence लागत.—Cost लाग होना.—Application (n) लाभ.—Profit लाभांश.—Dividend लिखत.—Instrument लिखित स्चना.—Notice in writing लेख.—Writ लेखा.—Account लेखा-परीक्षा.—Audit लेखान्दान.—Votes on accounts लेख्य.—Document लेना देना.—Dealings लोक.—People लोक-अधिसूचना.—Public notification लोकसभा.—House of the People स्रोक समाज.—Community लोक-सेवायें.—Public Services लोक-सेवायोग.—Public Service Commission कोक स्वास्थ्य.—Public health

व

वकालत करना.—Plead वकील.—Pleader वचन-पत्र.—Promissory note वचन-बन्ध.—Engagement वणिक्-पोत.---Merchant marine वयस्क.—Major वयस्क-मताधिकार.—Adult suffrage वरी.—Duty वसीयत.-Will वस्तु-भाड़ा.—Freight वहन-पत्र .—Bill of lading वंदन.—Allot वाक्-स्वातन्त्र्य.—Freedom of speech वाणिज्य.—Commerce वाणिज्य-दूत.—Consul वाणिज्य सम्बन्धी.—Commercial वाद.—Cause वाद-पद.—Issue वाद-प्रतिवाद.—Controversy वाद-मूल.—Cause of action वाद-विवाद.—Debate वाद-विषय.—Subject matter वायदा बाजार-— Future market वायु-पथ.—Airways वाषिक. — Annual वार्षिक-वित्त-विवरण.—Annual financial statement वार्षिकी.—Annuities

विकलन.—Debit (v.)
विकलन.—Debit (v.)
विकल-चित्त.— Unseund mind
विकय.—Sale
विकय-कर.—Sales tax
विघटन.—Dissolution
विचार.—Consideration
विचारायं प्रस्ताव.—Motion for
consideration

वितरण.—Distribution वित्त .—Finance

वित्त-विधेयक.—Finance bill

विसायोगं. —Finance-Commission

वित्तीय.—Financial

वित्तीय भार.—Financial obligation

बित्तीय विवरण.—Financial statement

विदेशीय कार्य.—Foreign Affairs

विदेशीय विनिमय.—Foreign exchange

विधान.—Legislation

विधान-परिषद्.—Legislative Council

विधान-मंडल.—Legislature

विधान-सभा.—Legislative Assembly

विधायिनी शक्ति.—Legislative power

ावधि.—Law

विधि-प्रश्न.—Question of law

विधि-मान्य.—Legal tender

विधियों का समान संरक्षण.—Equal

protection of law

विधि सम्बन्धी.—Legal

विधेयक.—Bill

विनियम.—Regulation

विनियमनः—Regulate

विनिमय-पत्र. — Bill of exchange

विनियोग. —Appropriation

विनियोग-विधेयक.—Appropriation bill

विनिश्चय.—Decision

विभाग.—Section

विभाजन.—Distribution

विभेद.—Discrimination

विमति.—Dissent

विमान-परिवहन.—Air navigation

विमान-यातायात.—Air traffic

विमान-बल. —Air Forces

विमोचन.—Redemption

विमोचन-भार.—Redemption charges

वियुक्त.—Deprive

विराम.—Respite

विरुद्ध .--Repugnant

विरोध.—Repugnance

विरोध.—Repugnancy

विल.—Will

विलेख.-Deed

विवरणी.—Return

विवाद.—Dispute

विवाह-विच्छेद.—Divorce

विशेषाधिकार.—Privilege

विश्वास-प्रस्ताव.—Motion of confidence

विश्वास का अभाव.--Want of

confidence

विषय.—Subject

विसर्जन.—Disperse

विसंगत.—Irrelevant

विस्तार.—Extend

विस्फोटक.—Explosive

वीसा.—Visas

वृत्ति.—Profession

वृत्ति-कर.—Profession tax

वृद्धि.—Interest

वेतन.—Pay

वेतन.—Salary

वेलई.—Employment

वेला-जल.—Tidal waters

वैदेशिक कार्य.—External Affairs

वोटदाता.—Voter

वंचित करना.—Deprive

व्यक्ति.—Person

व्यपगत होना.- Lapse
व्यय.—Expenditure
व्यवसाय.—Vocation
व्यवस्था.—Order
व्यवहार.—Civil
व्यवहार.—Dealings
व्यवहार-अदालत.—Civil Court
व्यवहार न्यायालय.—Civil Court
व्यवहार न्यायालय.—Civil Procedure
व्यवहार प्रक्रिया संहिता.—Civil Procedure
व्यवहार प्रक्रिया संहिता.—Civil Procedure

व्यवहार लाना.—Sue
व्यवहार-वाद.—Civil Suit
व्यवहार-विषयक अपकृत्य.—Civil wrong
व्यवहार-विषयक दोष.—Civil wrongs
व्यवहार-विषयक दोष.—Civil power
व्याख्या.—Explanation
व्यापार.—Trade
व्यापार कर.—Trades Tax
व्यापार-विह्न.—Trade mark
व्यापार-संघ.—Trade Union
व्यावृत्ति.—Savings

ज

शक्ति.—Power
शतं.—Condition
शलाका.—Ballot
शलाका-पद्धति.—Ballot
शाक्ति.—Peace
शास्त्रत उत्तराधिकार.—Perpetual succession

शासक.—Ruler शासन.—Governance शासन.—Govern

शासन .—Government शासी निकाय.—Governing body शास्त.—Penalty
शिक्षा.—Education
शिक्षा.—Instruction
शिल्पी-प्रश्निक्षण.—Technical training
शिवर.—Camp
शिवर.—Camp
शिवर.—Disciplinary
शुल्क.—Duty
शुल्क.—Duty
शुल्क-सीमान्त.—Custom Frontiers
शून्य.—Void
शेरिफ.—Sheriff
शोधना.—Research

श्रद्धा.—Faith श्रम.—Labour श्रमिक संघ.—Labour Union श्रोष्ठ चत्वर.—Stock-Exchange

श्र

स

सक्षम.—Competent
सत्त.—Session
सत्त्-न्यायालय.—Session Court
सत्त्त्वसन्त.—Prorogue
सदन.—House
सदस्य.—Member
सदाचरण-पर्यन्त.—During good
behaviour

सदाचार. —Morality
सन्था. —Association
सन्धि. —Treaty
सभा. —Assembly
सभापति. —Chairman
समता. — Equality
समपंण. — Dedicate
समवर्ती सूची. —Concurrent List
समवाय. — Company

समवाय संस्था.—Co-operative So-

समवेत होना.—Assemble
समागम .—Intercourse
समागम .—News paper
समापन.—Winding up
समिति.—Committee
समुदाय .—Community
समुद्र-नौवहन.—Maritime shipping
सम्पदा.—Estate
सम्पदा-शुल्क.—Estate-duty
सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य.—
Sovereign Democratic Republic

सम्मेलन.—Conference सरकार.—Government सरकारी अभियाचना.—Public demand सर्वेक्षमा.—Amnesty सर्वोच्च समादेश.—Supreme Command

सलाह.—Advise सशस्त्र बल.—Armed forces सहकारी संस्था.—Co-operative society

सहमति.—Concurrence
सहायक.—Ancillary
सहायक अनुदान.—Grants-in-aid
संकटमय.—Hazardous
संकल्प.—Resolution
संकल्प.—Transition
संगणना.—Compute
संघ.—Union
संघटन.—Organization
संघ-सूची.—Union List
संचार.—Communication
संचार करना.—Communicate
संचार-साधन.—Means of Communications

संचित निष्टि.—Consolidated fund
संदर्भ.—Context,
संदेश.—Message
संबोधित-—Addressed
सम्पत्ति.—Property
सम्पत्ति-हस्तान्तरण-पत्र.—Assurances of
property

म्पर्क.—Contact
सम्मति.—Consent
सम्भावना.—Honorarium
संरक्षक.—Guardian
संल्यन.—Append
संविदा.—Contract
संविद्यान.—Constitution
संविद्यान-सभा.—Constituent
Assembly

संशोधन.—Amendment संसद्.—Parliament संस्था.—Institution संस्थापन.—Establishment संहिता.— Code साक्ष्य.—Evidence साख.—Credit साधारए। निर्वाचन.—General Election सामर्थं.—Capacity सामाजिक-बीमा.—Social insurance सामाजिक रूढि.—Social custom सामाजिक सेवा.—Social service सामान्य मुद्रा.—Common seal सामान्य मृहर --- Common seal सार्वजनिक अधिसूचना.—Public Notification

सार्वजिनिक अभियाचना.—Public demand सार्वजिनक कल्याण.—Common good सार्वजिनक व्यवस्था.—Public order साह्कार.—Moneylender •

साहकारी .--Money lending सांसगिक.—Contaguous सांकामिक.-Infectious सिद्ध-दोष.—Convicted सिपारिश.—Recommendation सिपारिश करना.—Recommend सीमा.—Boundary सीमा-कर.---Torminal tax सीमान्त.—Frontiers सीमा-वाल्क.—Custom duty सीमांकन.—Domarcution सुधार-प्रत्यास.—Improvement Trust गुधारालय. --Reformatory ससंगत. Relevant सुसंगति .—Relevancy स्चना.-Notice सूचना-पत्र.—(lazette सुचना-पत्र .-- Notice स्ची.—List सुद.—Interest सुत्र.—Formula संत्रित.—Formulated · सेना.—Military सेना-न्यायालय.—Court Martial सेवा.—Service सेवा की शतं.--Condition of service सेवा-नियोजन.—Employment सेवा-भार.—Service charges सैनिक.—Military सैन्य-वियोजन.—Demobilization सौंपना.—Assign सौपना.—Entrust स्थगन.—Adjourn

स्थगित करना.—Adjourn

स्थान.—Post
स्थाना-तरण.—Transfer (n.)
स्थानीय क्षेत्र.—Local area
स्थानीय गण.—Local Board
स्थानीय निकाय.—Local body
स्थानीय प्राधिकारी.—Local authority
स्थानीय मंडली.—Local Board
स्थानीय शासन.—Local Government
स्थानीय स्वशासन.—Local Self Government

स्थापना.—Establishment स्थापित करना.—Establish स्थायी आदेश.—Standing Orders स्थायी समिति.—Standing Committee

स्पद्धीकरण.—Clarification
स्पद्धीकरण.—Explanation
स्पारक.—Memorial
स्वतन्त्रता.—Freedom
स्ववंत.—Possession
स्ववंवेक.—Discretion
स्वातन्त्र्य.—Freedom
स्वाधीनता.—Liberty
स्वामित्व.—Ownership
स्वामित्व.—Royalties
स्वामिस्व.—Royalties
स्वामिस्व.—Bona vacancia
स्वामी होना.—Own

स्वीय विधि —Personal law

हस्त-शिल्प.— $\mathbf{Handicraft}$
हस्तान्तर-पत्र.—Conveyance
हस्तान्तरण.—Transfer (n.)
हिदायतें.—Instructions